राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम् सत्र, १९६६ का २२वां दिवस [संख्या १८

शनिवार,
दिनांक १९ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.७ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(यातायात, सिंचाई, स्वास्थ्य, उद्योग, राजस्व, पंचायत, सार्वजनिक निर्माण, राजकीय उद्योग, विद्युत्, विकास, योजना, चिकित्सा एवं अकाल सहायता-विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री तेजाराम ।

राजस्थान रोडवेज की बसें

३५७. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्ष १९६५-६६ में राजस्थान रोडवेज निगम की कितनी गाडियां कितनी बार रास्ते में फैल हुईं ? सूचना डिपोवार देने की कृपा करें ।

(२) क्या इन गाडियों के फैल होने का कारण निगम के वर्कशॉप्स में दक्ष मिस्त्रियों व कारीगरों का अभाव है और इस कारण गाडियों को भारी नुकसान होता है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह): (१) अप्रेल सन् १९६५ से जनवरी सन् १९६६ तक निगम की गाडियों के रास्ते में खराब होने की सूची डिपोवार सदन के पटल पर रखदी गई है ।

(२) जी हां । योग्य टेक्निकल कारीगरों का अभाव है और दूसरे मैकेनिकों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत: यह सूची जो दी है वह गाडियों की खराब होने की गिनती है या जितनी डिपो में गाडियां खराब हुई, वह है ?

श्री भीमसिंह : ये ब्रेक-डाउन के नम्बर हैं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आपने कहा मिस्त्रियों और कारीगरों का अभाव है तो आपका क्या काइटेरिया है उनको रखने का ?

श्री अध्यक्ष : इसकी पहले बहुत बहस हो चुकी है । श्री जुझारसिंह ।

पंचायत समिति क्षेत्र, सांगोद में सिंचाई के साधन

३५८. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या बारिश की कमी के कारण पंचायत समिति, सांगोद क्षेत्र में इस वर्ष विभाग

(श्री जुझारसिंह)

द्वारा पम्पिंग सैट्स बांटे गए हैं? यदि हां, तो किन किन स्थानों पर और किन किन शर्तों के साथ?

(२) विभाग की उपरोक्त स्कीम से सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र में कितनी कितनी भूमि सिंचित हो जाने की सम्भावना है?

(३) सांगोद पंचायत समिति क्षेत्र में लघु सिंचाई व लिफ्ट इरिगेशन के लिए कितने स्थानों का सर्वे कर लिया गया है और किस किस स्थान पर?

(४) क्या सरकार इस क्षेत्र में सिंचाई के साधनों को देखते हुए छोटे-छोटे पिक-अप वेयर या चैक डेम बनाकर अधिक व शीघ्र सिंचाई के प्रोग्राम हाथ में लेने का विचार रखती है और यदि हां, तो किन किन स्थानों पर?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) जी नहीं, बांटे नहीं गए अपितु सिंचाई विभाग द्वारा उमरदा, रेलावदा, कुन्दनपुरा, ढिगी तथा बिजलिया में पम्पिंग सैट्स लगाए गए हैं। शर्तों का प्रश्न नहीं उठता है।

(२) जो पम्प विभाग ने लगाए हैं तथा जो और लगाए जायेंगे उनसे करीब ५००० एकड भूमि सिंचित होने की सम्भावना है।

(३) सांगोद पंचायत समिति में लघु सिंचाई के अन्तर्गत १७ स्थानों का प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया गया है, जिनके नाम हैं:—

१ हरिपुरा मोजी, २ मोरया हेडी, ३ कोवेन, ४ चरा, बन्धजा, ५ ढोडी, ६ खुशहालीपुरा, ७ गुडला, ८ गुवावदा, ९ पालकिया, १० कुराडिया कलां, ११ अडूसा, १२ कुन्दनपुरा, १३ मण्डिता, १४ थुनपुर, १५ खोन्दा, १६ सलोनियां, १७ राजगढ।

(४) भौगोलिक तथा प्राकृतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिस्थिति के कारण छोटे छोटे पिक अप वियर तथा चैक डेम बनाना तकनीकी दृष्टिकोण से अधिक लाभप्रद नहीं होगा।

श्री जुझारसिंह: आपने यह तो मन्जूर किया है कि १७ जिलों का सर्वे कराया और करीब ५ हजार एकड में इससे सिंचाई कर सकते हैं। तो यह लिफ्ट का ही मामला है। अगर पिक अप वियर नहीं करते हैं तो भी ५ हजार एकड की सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, तो क्या इनसे आप लिफ्ट करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री नाथूराम मिर्धा: जी हां, यही तो कर रहे हैं।

श्री जुझारसिंह: अभी तो आपने ४-५ जगह ही लगाये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा: १४ पम्प लगाये हैं और यह तो बहुत जल्दी जल्दी में काम शुरू हुआ था और फसलों में पानी देने के लिए लेट हो रहे थे। आगे के लिए काम चालू रहेगा।

श्री अध्यक्ष: इसमें सिंचाई की क्या रेट है?

श्री नाथूराम मिर्धा: इसके बारे में यह अर्ज है कि जो खर्चा पडता है हमारे वहां वर्किंग एक्सपेन्सेज होंगे उसी हिसाब से चार्ज करते हैं। कितना एरिया एक पम्प सिंचाई करता है उसका कितना खर्चा आता है, उसके अनुसार रेट डिस्ट्रीब्यूट करके करते हैं। कोई कॉमन रेट नहीं रखी है; न लाभ और न हानि हो, इसी

(श्री नाथूराम मिर्धा)
आधार पर रेट रखी है। जो नई व्यवस्था कर रहे हैं वह कॉस्ट के ऊपर ही कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कितनी आती होगी मगर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह अलग अलग जगह पर अलग अलग रेट्स हैं। कितना हैड है और कितना लिफ्ट है इसके ऊपर डिपेन्ड करता है। जितना पानी कम उठाना पड़ेगा उतना ही पैसा कम आयेगा और जितना ऊंचा ज्यादा उठाना पड़ेगा उतना ही पैसा ज्यादा आयेगा।

श्री अध्यक्ष : फिर भी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : निश्चित नहीं कह सकते।

श्री जुझारसिंह: अभी आप ४ रुपये बीघा के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं फ्लेट रेट से और काश्तकार इसी उम्मीद पर तैयार हैं। अगर खर्चा ज्यादा हुआ तो कम्पेरेटिवली दूसरी स्कीम्स हैं इरिगेशन की उसी हिसाब से चार्ज करना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कमिटमेन्ट में आपके सामने नहीं करूंगा क्योंकि आखिर बडे पैमाने पर इस लिफ्ट की व्यवस्था को हम करना चाहते हैं और यदि आपके बताए सिद्धान्त को मान लिया तो इसका लगातार घाटा उठाना स्टेट के लिए सम्भव नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : खर्च कितना आ रहा है ? इसमें किन किन बातों को शामिल किया है ? स्टॉफ है, डेप्रिसिएशन है; यानि किन किन बातों पर खर्चा शामिल किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इसका बहुत पैसा नहीं होता पम्प ऑपरेटर है, ड्राइवर है जिनका खर्चा ज्यादा नहीं है। जिस हिसाब से पम्पिंग के मेन्टीनेन्स का होता है वह वाजिब होता है, उसमें ज्यादा बोझ नहीं पड़ता।

श्री जुझारसिंह : जो डीजल से एन्जिन चलता है उससे खर्चा ज्यादा आता है। वहां दो-तीन मील पर बिजली उपलब्ध है और सांगोद क्षेत्र में १३-१४ गावों में बिजली है तो इन साधनों को देखते हुए क्या कृषि मंत्री गवर्नमेन्ट से कोशिश करेंगे कि यह बिजली की फेसेलिटीज जहां हैं और जहां पानी को लिफ्ट करना हो तो इसको वहां एक्सटेन्ड कर दिया जावे जिससे जो इनका रेकरिंग खर्चा है वह कम हो जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जहां बिजली की सुविधा है और खर्चे में पोसाता है और बोर्ड ने बिजली देने की व्यवस्था की तो जहां बिजली नजदीक में है उसको लेने की कोशिश करेंगे।

प्रश्न संख्या ३५९

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ३६०

श्री अब्दुलजब्बार।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ३६१

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या ३६२

श्री मथुरेशविहारी माथुर।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

श्री मोहनराज।

Page No. 4

बांध का निर्माण, बाली

३६३. **श्री मोहनराज** (बाली) [श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) द्वारा पूछा गया] : क्या मंत्री, सिंचाई विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बाली कस्बे के पास नदी को बाढ़ से होने वाले कटाव को रोकने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा नदी के किनारे पर गत वर्ष बांध कार्य किया गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्माण-कार्य अधूरा पड़ा है और कार्य पूरा न होने तक कस्बे की आबादी को खतरा बना हुआ है ?

(३) क्या यह सही है कि ठेकेदार काम छोड़ कर चला गया है, इसी वजह से काम रुका हुआ है ?

(४) क्या सरकार स्वयं अथवा अन्य ठेकेदारों के मार्फत उक्त अधूरे कार्य को पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण होने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(१) जी हां।

(२) जी हां, किन्तु वहां की आबादी को खतरे की सम्भावना नहीं है।

(३) जी हां।

(४) जी हां, यह कार्य आगामी वर्षा के पहले पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

पंचायत समिति, उनियारा की आय

३६४. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति, उनियारा की वार्षिक निजी आमदनी कितनी है ?

(२) पंचायत समिति, उनियारा में १९६४-६५ व १९६५-६६ में अपनी निजी आय बढ़ाने के क्या क्या साधन जुटाये हैं और दोनों वर्षों में आय कितनी हुई ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :
(१) अनुमानतः ३०,००० रु०

(२) कर लगाये गये हैं जिनसे क्रमशः २६,८०८.८३ पैसे व १८,३३०.६४ पै० आमदनी हुई है।

श्री दिग्विजयसिंह : यह आमदनी हुई है, यह किन किन करों से हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह राजस्व पर कर, व्यवसाय पर कर और शिक्षा उप-कर।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या शिक्षा-कर पंचायत समिति के द्वारा लगाया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : विकास अधिकारी ने यह भी लिखा है कि अभावग्रस्त क्षेत्र होने से वसूली नहीं हो सकी, लेकिन तीन तरह के करों से आमदनी हुई है, राजस्व पर कर, व्यवसाय पर कर और शिक्षा पर कर।

श्री दिग्विजयसिंह : शिक्षा-कर से कितनी वसूल हुआ है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास इसकी डिटेल नहीं है। आपने आमदनी पूछी, मैंने वह

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दे दी। अब अलग अलग किस मद में कितनी हुई, ये फीगर्स नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बतायें कि यह आमदनी निजी होती है उसको पंचायत समिति वाले किस तरह से खर्च करें उसके बारे में कोई हिदायत या पाबन्दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, इस तरह के नियम हैं कि वह किस तरह से खर्च कर सकते हैं। अगर कोई खास काम में खर्च करना चाहें तो राज्य सरकार से उसकी अनुमति हासिल करनी पड़ती है।

प्रश्न संख्या ३६५

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढावरिया।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३६६

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री मोहनराज।

न्याय पंचायतों में योग्य क्लर्कों का प्रावधान

३६७. **श्री मोहनराज** (बाली) [श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) द्वारा पूछा गया] : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि राजस्थान में न्याय पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन व अन्य कार्यालय संबंधी खर्चे के लिये आवश्यक राशि उपलब्ध न होने से उनका कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है ?

(२) क्या राज्य सरकार को ज्ञात है कि न्याय पंचायतों में योग्य एवं प्रशिक्षित लिपिक (क्लर्क) न होने के कारण भी उनका कार्य संतोषजनक प्रगति नहीं कर रहा है ?

(३) क्या राज्य सरकार न्याय पंचायतों के कार्यालयों में कार्य करने हेतु योग्य क्लर्क के लिये उपयुक्त वेतन दिये जाने का प्रावधान करने का विचार रखती है ?

पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या विचाराधीन है सरकार के ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नम्बर (३) में पूछा है कि क्या राज्य सरकार न्याय पंचायतों के कार्यालयों में कार्य करने हेतु योग्य क्लर्क के लिए उपयुक्त वेतन दिये जाने का प्रावधान करने का विचार रखती है? वही है।

श्री भीमसेन : इसके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो सादिक अली कमेटी ने सिफारिश की थी सरकार ने उनको मन्जूर कर लिया है और अब उसको इम्प्लीमेंट करना है।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : अभी न्याय पंचायतों में जो सेक्रेटरीज होते हैं वे इसी के द्वारा नियुक्त होते हैं, आप गवर्नमेन्ट की तरफ से नियुक्त करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रश्न केवल तनख्वाह का है, नियुक्ति का नहीं है। इसके लिए अलग नोटिस चाहिए।

श्री भीमसेन : सरकार ने कौन कौनसी सिफारिशें मंजूर की हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : न्याय पंचायतों के सिलसिले में जो रिक्मन्डेशन की थी माननीय सदस्य ने उनको रिपोर्ट में देखा होगा। अगर आप चाहें तो मैं दुबारा आपके सामने पढ़ दूं।

श्री भीमसेन : इसके संबंध में दो-तीन रिक्मंडेशन्स ही थीं, वही पढ़ कर सुना दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : "Government should ensure adequate secretarial assistance......" the Government has accepted this recommendation.

"In order to cover the cost of establishment, the Government should sanction Rs. 1,000 per annum to every Nyaya Panchayat as grant through the Panchayat Samiti. The expenditure over and above Rs. 1,000 should be met by the Panchayat Samiti and should be reimbursed by the Government in next financial year." This has been accepted.

"The Nyaya Panchayats should frame their own budget without reference to Panchayat Samitis. The court fees should be payable and the stamps supper imposed with 'Panchayat Raj' on them." This is accepted.

"Income from fine and fees should go to the Government." Accepted but the income from fines should go to the Nyaya Panchayats.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह डिसेन्ट्रेलाइजेशन जब से हुआ है तब से न्याय पंचायतों में जो व्यवस्था रही उसके कारणों को देखते हुए वहां पर पेमेन्ट नहीं होने से अव्यवस्था हो रही है, उसके लिए क्या कदम उठाए ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा, अव्यवस्था तो हुई नहीं है। पैसे की कमी है इसलिए सैक्रेटरीज नहीं रख सकते हैं और उनको और खर्चों में दिक्कत आती है, इसलिए यह व्यवस्था की गई है जो मैंने बताई।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या ऐसे आदेश हैं कि जहां न्याय पंचायत के हैड क्वार्टर्स हैं वहां के सैक्रेटरी न्याय पंचायत के सैक्रेटरी नहीं होने चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह जरूरी नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : कौनसा ऐसा प्रावधान दिया हुआ है कि न्याय पंचायत का सैक्रेटरी हैडक्वार्टर पर है वहां का सैक्रेटरी पंचायत का भी काम करेगा जिससे वेतन में भी फायदा मिले।

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। मैं समझता हूं कि यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री जुझारसिंह (बेचट) : जब आपने तनख्वाह बढाने और पे-स्केल फिक्स करने के लिये तय कर दिया है तो इसके साथ ही साथ आप यह भी तय करेंगे कि इनकी कोई लीगल क्वालिफिकेशन हो जिससे वह पंचायत का काम एफीशियेन्सी से चला सकें।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो मैंने अभी कहा कि एल. डी. सी. की तनख्वाह दी जायेगी। अब उस क्वालिफिकेशन में जो आदमी मिलेगा उसी को लेंगे। कानूनी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है।

श्री गोविन्दसिंह (चिड़ावा) : एक ही सैक्रेटरी दो-तीन न्याय पंचायतों में काम करेगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा है कि सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट को हमने इम्प्लीमेन्ट किया है और शायद माननीय सदस्य ने इस रिपोर्ट को पढ़ा नहीं है।

ग्राम बीछंडी में बिजली की लाइन

३६८. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया]: क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील में बीछेड़ी ग्राम में माणिक्यलालजी वर्मा के खेत पर बिजली दी गई है?

(२) यदि हां, तो इसके लिए कितनी लम्बी लाइन ले जाई गई? वहां पर कितने कुओं पर बिजली दी गई व इसमें कितना खर्चा हुआ?

(३) क्या यह सच है कि गुड़ली ग्राम में गये हुए खंभों को वापस मंगा कर यह लाइन लगाई गई?

(४) क्या यह सच है कि गुड़ली को मिलने वाली बिजली के अधिकार को छीन कर किसी व्यक्ति विशेष के लिए बिजली ले जाई गई?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल वैद) :

(१) जी हां।

(२) यह लाइन बीछेड़ी ग्राम को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत बिजली देने के लिये खींची गई थी। कुओं को बिजली पहुंचाने के लिये केवल पांच सौ फुट के लिये आगे बढ़ाई गई है देवारी से बीछेड़ी तक। पूरी लाइन पर करीब २५ हजार रुपयों का खर्चा हुआ है। इस लाइन पर कुल १० कुए हैं पर बिजली अभी तक एक ही कुए को दी गई है, दूसरे कुओं के लिये डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये हैं उनकी रकम जमा होते ही कनेक्शन दिये जावेंगे।

(३) जी नहीं, गुड़ली तक भी लाइन खेंच दी गई है।

(४) जी नहीं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : इसका क्या कारण है जिनकी पहले से दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं उनको तो बिजली नहीं दी गई ....

श्री चन्दनमल वैद : मैं बता चुका हूं कि दस आदमियों ने बिजली की मांग की थी और उनको डिमांड नोटिस दे दिया गया है। ज्यों ही वे पैसा जमा करायेंगे उनको बिजली मिल जायेगी।

Page No. 8

श्री हरीप्रसाद शर्मा : इनको बिजली अभी तक क्यों नहीं दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद : मैंने आपको बताया कि इन दस आदमियों ने अभी तक पैसा जमा नहीं कराया है। जब वे पैसा जमा करायेंगे तभी तो बिजली मिलेगी। बिना पैसों के बिजली थोड़े ही मिल जाएगी। और भी जो बिजली लेना चाहेंगे सबको बिजली मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री नाथूलाल करोल।

जयपुर-चाकसू-दौलतपुरा रूट

३६९. **श्री नाथूलाल करोल** (चाकसू) : [श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवारामगढ) द्वारा पूछा गया]: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से इस प्रश्न को मैं पूछ लेता हूं।

क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सही है कि जयपुर से चाकसू व कोटखावदा होता हुआ दौलतपुरा तक प्राइवेट बसों के लिये रूट कायम हैं।

(ख) क्या यह सही है कि इस रूट पर जो गाडियां चलती हैं वे सिर्फ कोटखावदा तक ही जाती हैं और आगे जाना बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री यातायात (श्री भीमसिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, मोटर मालिकों ने स्वेच्छा से कोटखावदा से आगे जाना बन्द कर दिया है। यह नियमानुसार एक अपराध है और उनके विरुद्ध रीजनल ट्रांसपोर्ट आथोरिटी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : पहले तो वहां तक गाड़ी जाती थी।

श्री भीमसिंह : जी हां।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जब पहले जाती थी तो अब भी जानी चाहिये ?

श्री भीमसिंह : जरूर जानी चाहिए। लेकिन चूंकि वे नहीं ले जा रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

कोटा शहर में गंदे नाले को भरवा कर जमीन का बेचान।

३७०. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) [श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया]: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा शहर में मोहन थियेटर के पास स्थित गंदा तालाब क्या मंडी कमेटी क्षेत्र में है ? अगर हां, तो कब से ?

(२) क्या यह सत्य है कि उक्त तालाब के आस-पास आबादी है तथा मुख्य सड़क भी वहीं से गुजरती है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त तालाब के सड़ने के कारण उस जगह बीमारी फैलने का डर बना रहता है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त तालाब को भरवाने के लिए तखमीना बनाया गया है ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(५) क्या यह सही है कि अगर वह तालाब भरवा दिया जावे तो वह भूमि अच्छे मूल्य पर बिक सकती है ?

(६) अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) :(१) कोटा शहर में मोहन थियेटर के पास स्थित गंदा तालाब राजकीय नजूल भूमि है और यह राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ. ७ (१८७) एल. एस. जी. बी.-५८ दिनांक ८-१०-५६ की शर्त नं. ५ के प्रभाव से ही नजूल भूमि घोषित हुई है जिसकी बिक्री आदि का प्रबन्ध स्थानीय मण्डी कमेटी करती थी पर अब राज्य सरकार ने चाहारदीवारी के अन्दर की तमाम भूमि नगर परिषद् कोटा में निहित कर दी है जिसमें गंदा तालाब नामी भूमि भी शामिल है।

(२) जी हां।

(३) यह बात सही है कि उक्त तालाब में गन्दगी रहती है।

(४) ऐसी जानकारी राज्य सरकार को नहीं है।

(५) जी हां।

(६) प्रश्न ही नहीं उठता। यह उत्तरदायित्व नगर परिषद् कोटा का है।

श्रीमती नगेंद्रबाला (छबड़ा) : यह नगरपरिषद् कोटा को देने के आदेश कब हुए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आदेश १० मार्च, १६६६ को हुए हैं।

प्रश्न संख्या ३७१

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३७२

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३७३

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

अविकसित क्षेत्रों का विकास

३७४. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:— क्या सरकार के ध्यान में है कि उत्तर प्रदेश तथा अन्य कई राज्यों में चौथी योजना में अपने अविकसित क्षेत्रों के द्रुतगति के विकास हेतु योजना "Plan for Accelerated Development of Backward areas" तैयार की है ? अगर हां तो क्या सरकार राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों की तरक्की हेतु उक्त प्रकार की योजना बनाना उचित नहीं समझती ?

योजना-मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : जी नहीं। राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए योजना का समावेश चौथी योजना में किया जायेगा। राज्य सरकार इन क्षेत्रों के लिए कोई अलग योजना बनाने का विचार नहीं रखती है।

श्री भीमसेन : जो आपने उत्तर में यह कहा कि 'जी नहीं' तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट से जानकारी प्राप्त की है कि बैकवर्ड एरियाज के डेवलपमेंट के लिए कोई योजना नहीं बनाई है ?

श्री मथुरादास माथुर : जी हां ।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय बिल्कुल असत्य जवाब दे रहे हैं । यू. पी. गवर्नमेंट ने बैकवर्ड एरिया के डेवलपमेन्ट के लिए अलग से प्लान बनाया है और माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं . . .

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इतना ही आसान है जितना माननीय सदस्य इसको समझते हैं । बैकवर्ड एरिया के लिये प्लान तैयार करते समय प्लानिंग कमीशन की तरफ से इस तरह के इंस्ट्रक्शन्स आए थे कि फोर्थ प्लान में बैकवर्ड एरिया का अलग से चैप्टर होना चाहिए और पांच कैटेगरीज के अन्दर बैकवर्ड एरिया को इंडीकेट किया जाय । ये पांच कैटेगरीज यह थीं:

1. Desert areas.

2. Chronically draught affected areas.

3. Hill areas including border areas.

4. Areas with high concentration of tribal population.

5. Areas with high density of population, low levels of income, employment and living.

ये जो पांच कैटेगरीज प्लानिंग कमीशन के द्वारा दी गई तो इसके आधार पर राजस्थान का सर्वे किया गया हमारे डाइरेक्टर ऑफ इकोनोमिक एण्ड स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्ट के द्वारा और उसके अनुसार इन डिस्ट्रिक्स को ऊपर बताई कैटेगरी के अनुसार बांटा गया । पहली कैटेगरी में हैं जैसलमेर, दूसरी में है बीकानेर, तीसरी कैटेगरी में नागौर, चौथी में डूंगरपुर और बांसवाड़ा और पांचवीं कैटेगरी में बाड़मेर और जालोर । इस तरह से कैटेगरीज बना कर हमने भेज दिया, लेकिन इसके बारे में अभी तक जो एक्स्ट्रा असिस्टेंस आनी है उसका इण्डीकेशन नहीं आया है । हमारी उनसे कोरेस्पोंडेन्स चल रही है । जब तक इसके बारे में हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन न मिले कि जो कैटेगरीज बताई हैं उसके अनुसार स्कीम्स तैयार की जायं और उसके लिए इतना फण्ड अलॉट किया जाता है तब तक इसको कैसे फाइनल किया जा सकता है ?

जहां तक डेजर्ट एरिया के डेवलपमेन्ट का सवाल है राज्य सरकार भारत सरकार पर जोर डाल रही है कि वह इसकी जिम्मेदारी उठाए और इसके लिए एक अलग से सैल कायम किया जाय । और मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेन्ट ने एक सेंट्रल डेजर्ट डवलपमेन्ट बोर्ड कायम भी कर दिया है और इसके लिए दस करोड़ रुपये उन्होंने ईयरमार्क किए हैं फोर्थ प्लान में । लेकिन अभी तक हमारे पास इसका इण्डीकेशन नहीं आया है कि इतना अमाउण्ट इसके लिए स्पेशियली अलॉट होगा ।

श्री भीमसेन : राज्य सरकार उनके इण्डीकेशन की इन्तजार करेगी या अपने एरिया के डेवलपमेन्ट के लिए अपना प्लान बना कर भारत सरकार को पेश करना नहीं चाहती ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपसे निवेदन किया कि डेजर्ट डेवलपमेन्ट के बारे में

Page No. 11

(श्री मथुरादास माथुर)
भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने एक डिफरेंट प्लान बनाया है और फोर्थ प्लान में वे इसको करना चाहते हैं। बाकी जो बेकवर्ड एरिया के प्लान का सवाल है उसके लिए तो जब तक इण्डीकेशन न मिले स्कीम तैयार करने का सवाल खड़ा नहीं होता, क्योंकि जब तक हमको यह मालूम न हो कि इस स्पेशियल वर्क के लिए कितना फण्ड मिलेगा हम किस आधार पर स्कीम तैयार कर सकते हैं। वैसे जो प्लान में प्रायोरिटीज के आधार पर स्कीमें हैं वे तो हैं हीं ?

श्री रावतराम (सादूलपुर) : यह जो आपने पांच केटेगरीज रखी हैं तो छटी केटेगरी और रख कर चूरू को भी शामिल क्यों नहीं कर लेते ?

श्री मथुरादास माथुर : यही तो मुश्किल है। ये केटेगरीज तो सर्वे के आंकड़ों के आधार पर की जाती हैं। यों तो सभी बैकवर्ड हो जायेंगी इसीलिए इस पर खास तौर से ध्यान रखा गया कि डिस्ट्रिक्स में आपस में कोई झगड़ा खड़ा न हो।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल।

आदिवासी क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या

३७५. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ तहसील का अधिकतर भाग आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासियों के क्षेत्र में कितने ही ऐसे गांव हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या है ?

(२) क्या यह भी सही है कि पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले लोगों को एक एक दो दो मील से पानी लाना पड़ता है ? यदि हां, तो उनकी समस्या पर क्या विचार किया गया है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि पहाड़ी एरिया के रहने वाले मनुष्यों को ऐसा गंदा पानी पीना पड़ता है जिसमें से जंगली जानवर पशु, मवेशी आदि पानी पीते हैं ? अगर हां, तो इस तरफ क्या कदम उठाया जा रहा है ?

विकास मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) कुछ पहाड़ी क्षेत्र में रहने वालों को दो तीन फर्लांग दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। ६६ गांवों के लिए पीने के पानी के कुएं बनवाने के लिए राशि दी जा चुकी है। उसमें से ३३ कुओं का कार्य पूरा हो चुका है।

(३) कुछ पहाड़ी क्षेत्र में खोरों का गन्दा पानी पीने के काम में लेना पड़ता है। पंचायत समिति द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत शेष सभी गांवों में पीने के पानी की सुविधा हेतु योजना बना ली गई है।

श्री हरलाल मीणा : ऐसे कितने गांव हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको अर्ज किया कि ६६ गांव तो ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए कुए बनवाने हेतु राशि दी जा चुकी है। और ३३ कुओं का काम भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र और हैं जिनमें पानी पीने की दिक्कत है। पंचायत समिति क्षेत्र में ६६ गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) यह जो आपने बताया कि ६६ गांवों में राशि

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
दी गई है और उसमें से ३३ कुए बन गए हैं तो वे ३३ गांव कौन से हैं ? यह ३३ गांव में है या जैसे आबादी में रहते हैं उसी तरह से है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गांव वही होते हैं जहां आबादी होती है। आबादी को ही गांव कहते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मेरा पूछने का मतलब यह है कि जो कुए बने हैं उसमें सभी बिरादरी वालों के लिए हैं या उन स्थानों के लिए हैं जहां शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए विशेष अनुदान देकर खुदवाए हों। जैसे आदिवासी क्षेत्रों के लिए कुएं बनवाए गए हैं तो ये भी उसी में हैं क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह प्रश्न ही आदिवासी क्षेत्रों के सम्बन्ध में है और उन्हीं के बारे में मैंने बताया है। अब आप गांवों की सूची चाहते हैं तो उस के लिए मुझे नोटिस की आवश्यकता है।

श्री हरलाल : जो आपने कहा कि ६६ गांव ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या है तो ऐसे गांव तो और भी बहुत हैं जिनमें पीने के पानी की समस्या है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको बताया कि ६६ गांव तो ऐसे हैं जहां पानी की दिक्कतें हैं और ६६ गांव ऐसे हैं जिनके लिए इन्तजाम हो चुका है।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन—सु०) : जैसा आपने कहा कि ६६ गांवों में पानी की दिक्कत है तो उस परेशानी को दूर करने के लिए सरकारने कुछ सोचा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इसके बारे में बता चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

चूरू जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिये सुविधाएं

३७६. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:——

(१) उद्योग विभाग द्वारा चूरू जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए क्या क्या सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

(२) उद्योग विभाग द्वारा चूरू जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए कितनी संस्थायें चलाई जा रही हैं और उनमें क्या क्या शिक्षा दी जाती है ? प्रत्येक प्रकार के कार्य के प्रशिक्षण में कितने कितने शिक्षार्थी हैं ?

उप-मंत्री उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए चूरू जिले में ६ प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण के लिए छात्रों को निम्न प्रकार छात्र-वृत्ति दी जाती है, ३० रु० चूरू वालों को व ४० रु० मासिक बहर से आने वालों को। समाज कल्याण के औद्योगिक केन्द्र में प्रशिक्षण समाप्त करने पर प्रत्येक सफल प्रशिक्षणार्थियों को २०० रु० की सहायता औजार आदि के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No. 13

सांचोर में पी० डब्ल्यू० डी० विश्रामगृह

३७७. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि सांचोर में पी० डब्ल्यू० डी० विश्रामगृह में अभीतक सिर्फ दो कमरे बने हुए हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि सांचोर एक बोर्डर तहसील होने से एक साथ कई सरकारी अधिकारी आते रहते हैं और उनके ठहरने के लिये सिर्फ यही विश्राम-गृह है ? अगर हां, तो क्या उनको ठहरने की दिक्कत नहीं पेश आती ?

(३) अगर उपरोक्त विश्राम गृह छोटा होने से ठहरने की कठिनाई होती है, तो क्या सरकार एक कमरा और विश्रामगृह में शीघ्र ही बनाना उपयुक्त समझेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) कभी कभी ठहरने की दिक्कत होती है।

(३) इस वर्ष एक कमरा बना दिया गया है, बाकी कार्य अर्थाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

लाखेरी एवं गरमपुरा को बिजली का कनेक्शन एवं उसका भुगतान

३७८. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी ग्राम व गरमपुरा पंचायत क्षेत्र के निवासियों को गांधीसागर की बिजली देना प्रारम्भ कर दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो लाखेरी ग्राम व गरमपुरा क्षेत्र में अब कितने बिजली के कनेक्शन्स दिये जा सके हैं ?

(३) क्या यह सही है कि बिजली के बिल के भुगतान करने हेतु एक माह में दो दिन २८ व २९ तारीख विभाग के द्वारा नियत किये गए हैं और इस कार्य के लिये सवाई माधोपुर से किसी व्यक्ति को भेजा जाता है जो समय पर नहीं पहुंचता है और बिल भुगतान करने में बाधायें आती हैं ?

(४) क्या यह सही है कि लाखेरी, गरमपुरा, इन्द्रगढ़ में बिजली सम्बन्धी कार्य के लिये सवाई माधोपुर जाना पड़ता है और इस प्रकार छोटी-सी खराबी सुधारने हेतु भी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं ?

(५) क्या यह सही है कि लाखेरी में बहुत बड़ा स्टेशन है ? यदि हां, तो वहां से दफ्तर हटाये जाने का कारण क्या है ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) :

(१) जी हां।

(२) २४० कनेक्शन।

(३) (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, इन्द्रगढ़ से जूनियर इन्जीनियर भेजा जाता है और भुगतान में कोई बाधाएं नहीं आती हैं।

(४) जी नहीं।

Page No. 14

(श्री चन्दनमल वैद)

(५) लाखेरी में केवल २४० कनेक्शन ही हैं, वहां से दफ्तर हटाये जाने का कारण यह है कि न तो कोई बड़ा कन्जूमर है सिवा एक फैक्टरी के, जिसके लिये सहायक अभियन्ता रखा जाय। सवाई माधोपुर बड़ा कस्बा है और कनेक्शन भी ज्यादा हैं इसलिये बजाय लाखेरी के दफ्तर सवाई माधोपुर रखा गया है व पावर हाउस भी है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि लाखेरी में कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी फाइलें कम्प्लीट हो गई हैं ६-६ महीने से और उसके बाद में भी उनको कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं इसकी निगरानी कर लूंगा और अगर ऐसी बात है तो जरूर उनको कनेक्शन मिलना चाहिए।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जैसा कि मैंने पूछा है और आपने मन्जूर किया है कि बिल का पेमेन्ट कराने के लिए २८-२९ तारीख को समय पर नहीं पहुंच पाते हैं इससे लोगों को काफी दिक्कत होती है।

श्री चन्दनमल वैद : आप यह चाहते हैं कि दो बढ़ाकर ३-४ हो जायं, तो इसका इन्तजाम कर दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या ३७९।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

(विराम)

श्री मोहर सिंह।

लालगढ़ कातर सड़क का निर्माण कार्य

३८०. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) लालगढ़ से कातर तक सड़क का निर्माण कार्य कब चालू किया गया ? इस पर कितना रुपया खर्च किया गया ? इसकी लंबाई क्या है ?

(२) इसका निर्माण कार्य कब से बन्द है ? इसकी क्या वजह है ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस सड़क की हालत बहुत खराब है और इसमें जगह जगह गड्ढे पड़ जाने के कारण आवागमन के योग्य नहीं रही है ?

(४) इस सड़क के लिये ली जाने वाली भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया या नहीं ? यदि दिया गया तो कब और कितना ? यदि नहीं, तो कब तक दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : (१) इस सड़क का कार्य १९५५-५६ में आरम्भ कराया गया था। इस सड़क को पूर्ण करने में २,६७,९५५ रु० व्यय हुआ है। यह सड़क १३ मील लम्बी है।

(२) सड़क का कार्य पूर्ण हो गया है।

(३) यह सड़क बावला पत्थर की है। कहीं कहीं सड़क पर ऐसे गड्ढे हो गये हैं जिससे आवागमन में कोई रुकावट नहीं होती।

(४) जी नहीं। अवार्ड प्राप्त होने पर मुआवजा दिया जा सकेगा।

श्री मोहरसिंह : एवार्ड प्राप्त करने के लिए कब लिखा गया था।

Page No. 15

श्री परसराम मदेरणा : इसमें शायद लिखा ही नहीं गया है अभी तक ।

श्री मोहरसिंह : कौनसी योजना में लिखा जायेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : योजना का प्रश्न नहीं है । अभी तक नहीं लिखा है । इस प्रश्न पर बातें हो रही हैं । अफसर लेवल पर इस चीज को देख रहे हैं और देखेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था की जाय ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : ५५-५६ में सड़क बनी है और उसमें गड्ढे पड़ गये हैं और आप कहते हैं कि आवागमन में रुकावट नहीं होती है यह कैसे जाना आपने ? ५५-५६ के बाद क्या आपने इसकी रिपेयर की है ?

श्री परसराम मदेरणा : चार मील २ फर्लांग को मेटल्ड कराया । ८ मील ६ फर्लांग पर समय समय पर रिपेयर्स होती रहती हैं । ८ मील ६ फर्लांग सड़क पर बाविलो स्टोन है तो यह पत्थर दुर्बल है इसलिए गड्ढे पड़ गये । इस साल २५ हजार रुपये फर्मानेंट हैड के अन्दर सेंक्शन हो गये हैं और काम अभी चालू है ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

जिला बीकानेर के गांवों को बिजली देने का कार्य

३८१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के गांव मूंडसर, तेजरासर, नोरंगदेसर, लूणकरणसर, कालू आदि को बिजली देने हेतु सर्वे किया जा चुका है ? अगर हां, तो उक्त गांवों को बिजली ले जाने का कार्य कब हाथ में लिया जायेगा ?

उप-मंत्री, विद्युत् (चन्दनमल वैद) : जी हां । योजनायें बनाई जा रही हैं ।

श्री भीमसेन : जब इनका सर्वे कराया जा चुका है तो इनको योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : किसी भी प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं किया गया है । अगली जो योजना बन रही है जब तक वह नहीं निकल जाये तब तक कैसे कह सकते हैं कि शामिल होंगे या नहीं ।

श्री भीमसेन : क्या सरकार को मालूम है कि सर्वे कराने पर लूणकरणसर और तेजासर की स्कीम को रेम्युनरेटिव पाया गया है तो अगले साल लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री चन्दनमल वैद : अर्थाभाव के कारण सारी स्कीमों को एक साथ नहीं लिया जा सकता है । अगले साल योजना बनेगी तो जिन गांवों का सर्वे हो चुका है उन पर विचार किया जायगा ।

श्री अध्यक्ष : ५-१० खम्भे तो लगा दें ।

श्री मोहनराज !

पाली जिले के अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत का कार्य

३८२. **श्री मोहनराज** (बाली) [श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) द्वारा पूछा गया] : क्या मंत्री, अकाल सहायता विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इस वर्ष पाली जिले के कुल कितने ग्रामों में अकाल की स्थिति की घोषणा हुई है ?

Page No. 16

(श्री तेजाराम गहलोत)

(२) इस अकालग्रस्त क्षेत्र की जनता को राहत देने हेतु कितने सस्ते अनाज व घास की दुकानें कहां कहां खोली गई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) लोगों को जीवननिर्वाह हेतु मजदूरी दिलाने के क्या कोई राहत कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रारम्भ किये गये एवं प्रस्तावित कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) इस वर्ष पाली जिले के कुल १०६ गांवों को अकाल ग्रस्त घोषित किया गया।

(२) सस्ते गल्ले की २६ दूकानें खोली गई हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(३) जी हां। प्रारम्भ किये गये एवं प्रस्तावित कार्यों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री तेजाराम गहलोत : जो कुछ सूची आपने दी है उस सूची के पास ५ मील के अन्दर जो अभावग्रस्त गांव नहीं आते हैं तो उन गांवों में सरकार काम खोलने के लिए क्या विचार रखती है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सूची प्रस्तावित और स्वीकृत कार्यों की पेश की है उनमें से तीन कार्य तो पी० डब्लू० डी० द्वारा लगाये जा रहे हैं और तीन कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। उसके बाद भी कुछ क्षेत्र एसे रह गये हैं कि जहां कार्यों की आवश्यकता है उनके लिए जिलाधीशों से दूसरे प्रस्ताव मांगे हैं। प्रस्ताव आते ही स्वीकृत कर दिये जायेंगे।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो पिछले अकाल के अन्दर कार्य अधूरे रह गये हैं और उनके पास में अभावग्रस्त क्षेत्र हैं तो उन्हीं कार्यों को सरकार वापिस क्यों न हाथ में ले; जैसे रायपुर की सड़क है तो उसके अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, तो मैं यह निवेदन करूंगा कि बजाय नये प्रस्ताव मंगाने के और नये हिस्से में कार्य शुरू करने के जो अधूरे कार्य हैं उनको ले लिया जाय तो वे कार्य भी पूरे हो जायेंगे और उन गांव वालों को भी राहत मिल जायेगी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पहले ही फैसला किया जा चुका है और उसके बारे में जिलाधीशों को भी लिखा जा चुका है कि जो कार्य पिछले अकाल में अधूरे रह गये हैं उनको प्राथमिकता दी जायेगी बशर्ते कि अभावग्रस्त इलाके में हों। जो कार्य अभावग्रस्त क्षेत्रों में, अध्यक्ष महोदय, नहीं हैं उनको प्रोग्राम में लिया जाना संभव नहीं है।

श्री तेजाराम गहलोत : अभावग्रस्त गांव बिल्कुल ही नजदीक हैं, एक मील के अन्दर हैं और उन अभावग्रस्त क्षेत्रों में प्लान का काम नहीं है तो उसको लेने में सरकार को क्या एतराज है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके बारे में सोचा जा रहा है कि ऐसे क्षेत्रों में काम चलता है और अभावग्रस्त क्षेत्रों के लोग

Page No. 17

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

आने को रजामन्द हैं तो राज्य सरकार को कोई एतराज नहीं होगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि ये जो कार्य आपके चल रहे हैं उसमें कई जगह जो उनके वेजेज, उनके रुपये, उनके पैसे हैं उनको बांटने के लिए रूल्स हैं उनके बावजूद भी सवा या डेढ महीने तक पैसे उनको नहीं बंटते हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न जुदा है, लेकिन जैसा आपने बताया कि फेमिन कोड के अन्दर भी और राज्य सरकार के दायित्वों के अनुसार भी ७-८ दिन में उनको वेजेज बंट जाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं व्हीकल की कमी की वजह से या स्टाफ की कमी की वजह से कहीं रह जाता है तो वर्तमान में सब जिलाधीशों को पाबन्द कर दिया गया है कि अगर जीप की कमी हो तो पंचायत समिति की जीप या दूसरे डिपार्टमेंट की जीप को रिक्वीजिट करके अपना कार्य चला सकते हैं । १० जीपें विभाग ने खुद खरीदने का फैसला किया है । उसके बाद भी अगर कमी रहती है तो अगला कदम किराये पर लिये जाने का फैसला किया जा सकता है; लेकिन अभी तक जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा जिलाधीश अजमेर की तरफ से ऐसी कोई भी मांग या शिकायत नहीं आई कि उनके पास स्टाफ की कमी या जीप की कमी के कारण से बंटवारे में देरी हुई है । अगर यह बात होगी तो उसकी व्यवस्था की जायेगी ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं उप-मंत्री को यह बतला दूं कि कलेक्टर से नहीं आई, यह बात एक है और कलेक्टर ने नहीं भेजी और वहां पर वेजेज समय पर नहीं बंटी हैं । यह मेरी जानकारी में है । मैं सरपंच और सबके लेटर्स आपको पेश कर सकता हूं । ये लोग फेमीन में काम करने आये और काम करने के बाद उनको फेमीन कोड के कानून के मातहत पैसों का बंटवारा नहीं हुआ और कलेक्टर भी शिकायत नहीं करे, ऐसी हालत के अन्दर मैं समझता हूं कि रिलीफ देने की जो मन्शा है फेमीन कोड के अन्दर वह फेल हो जाती है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तभी तो काम करने आते हैं घर छोड कर । उसके बाद भी पैसा नहीं मिले और रोटी नहीं मिले तो जिस परपज के लिए काम है उसमें फेल्योर है । यह सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है । कलेक्टर गलत है । पैसा नहीं बंटा है । सब डेढ महीने तक पैसा नहीं बांटते हैं ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी १५-२० मिनिट इन्होंने मुझे जानकारी दी थी तो मैंने जाकर जिलाधीश को पाबन्द किया है कि क्यों भुगतान नहीं हो रहा है, उसके बारे में तुरन्त इत्तला दी जाय । अगर उनकी गलती है तो जरूरी तौर पर उनके सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे ।

श्री बालचन्द डागा (किशनगढ) : उनकी गलती नहीं है गवर्नमेंट की गलती है कि सेन्क्शन होकर पैसा जल्दी नहीं आता है । अभी जिन क्षेत्रों में काम चल रहा था उस काम को बन्द कर देना पड़ा है इसका कारण यह है कि कलेक्टर के यहां पर पैसा नहीं है । जब यहां से पैसा मन्जूर होकर जायेगा तो काम चालू किया जायेगा । महीने–महीने

(श्री बालचन्द डागा)

भर तक तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, महीने दो महीनों तक तनख्वाह नहीं चुकती। किसी और वजह से नहीं चुकती ऐसी बात नहीं है, पैसा नहीं होने की वजह से नहीं चुकती। आप मंजूर करके भेजती नहीं हैं, आप भेजें तो काम चले।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह बात सही नहीं है। जिलाधीश की ओर से कुछ कमी रही होगी इसलिये स्वीकृति नहीं आई। जैसे ही वे सूचना भेजते हैं तुरन्त स्वीकृति दे दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : श्री अल्दाराम।

श्री अल्दाराम मीणा (सुमेरपुर-सु.) : पाली तहसील में कुछ आदिवासी एरिया हैं जिसमें कंटिन्युअसली तीन साल से अकाल पड़ रहा है। फेमिन का काम वहां पर शुरू नहीं हुआ यहां तक कि आदिवासी गांव छोड़ कर मजदूरी करने के लिये अहमदाबाद की ओर जा रहे हैं, गये हैं। उनकी मवेशी का यह हाल है कि मवेशी मर रही हैं। हमने मंत्रीजी से भी यह अर्ज किया था कि हमारे इस साइड में आदिवासी एरिया है वहां के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिये। लेकिन गये टाइम भी रिलीफ नहीं मिला और अब भी कुछ काम नहीं हुआ है। काम के लिये कहते हैं तो तहसीलदार इधर उधर दूसरी तरफ काम करता है, लेकिन इस एरिया में काम नहीं खोला जाता।

श्रीमती कमला बेनीवाल : पिछले अकाल के बारे में मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि दो तीन बार मैं खुद उनके क्षेत्र में गई हूं, जनप्रतिनिधियों से मिली हूं, काम भी देखा है, कोई शिकायत नहीं आई कि उनके जिले में काम नहीं हुआ। आज की जो स्थिति है उसमें इस जिले की आवश्यकता के अनुसार कितना पैसा होना चाहिये काम करने के लिये उतने पैसों के लिये जिलाधीश ने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। टैस्ट वर्क के बाद जो प्रस्ताव भेजे थे, वही हैं। आगे के लिये प्रस्ताव क्यों नहीं भेजे इसके लिये विभाग द्वारा जवाब तलब किया जा रहा है।

श्री अल्दाराम मीणा : मंत्रीजी वहां पर पधारी थीं, लेकिन काम फेमिन का उस जगह हुआ है जहां जवाई कमान्ड एरिया है और वहां पर अकाल का सवाल नहीं है। क्योंकि वहां पर गेहूं वगैरह होते रहते हैं वहां पर तो कुछ काम हुआ है, लेकिन जहां पर गेहूं नहीं होता, बरसात भी नहीं होती वह आदिवासी एरिया है और लोग गांव छोड़ कर जा रहे हैं वहां पर एक फूटी कौड़ी का भी काम नहीं हुआ है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं फिर निवेदन करना चाहती हूं कि मैंने वहां पर जिला परिषद् की मीटिंग की थी, पंचायत समिति की भी की थी, आपके सामने सभी आफिसर्स बुलाये थे, आपके यहां का कार्य देखा था इसके अलावा कार्य के बारे में पूछताछ की थी उस समय आपको कोई शिकायत नहीं थी आज कैसे आपको शिकायत हो सकती है?

श्री अल्दाराम मीणा : मैंने गये साल भी शिकायत उसी तरह की थी, पार्टी मीटिंग में भी शिकायत की थी, पाली तहसील के आदिवासी एरिया में कुछ काम नहीं हुआ दो साल हो गये कंटीन्युअसली, लोग गांव छोड़ कर चले गये।

Page No. 19

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस साल की बात में जरूर मानती हूं, लेकिन पिछले साल की बात सही नहीं है।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : क्या यह सही है कि माननीय सदस्य ने इस बारे में कुछ लिखित में भी आपको दिया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मुझे याद नहीं पड़ता।

श्री अल्दाराम मीणा : लिखित में भेजा है, ग्राम पंचायत की तरफ से प्रस्ताव भेजा है। आदिवासी लोगों पर रहम करके क्या वहां पर कुछ काम खोलने की कृपा करेंगे ?

प्रश्न संख्या ३८३

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३५६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६०

श्री अब्दुल जब्बार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६१

श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६२

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६५

श्री उमरावसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३६६

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३७१

श्री बिरदाराम।

(अनुपस्थित)

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु०) : श्री डाबरिया का प्रश्न संख्या ३६५ ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ले लिया जाय।

आगरा में सम्पत्ति

३६५. **श्री उमरावसिंह डाबरिया** (बनेड़ा) [श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) द्वारा पूछा गया]: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार की आगरा में कितनी संपत्ति थी जो भूतपूर्व राजाओं द्वारा सरकार को प्राप्त हुई थी ? इस संपत्ति की अनुमानित लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इस संपत्ति में से कुछ संपत्ति को राज्य सरकार ने बेची ? यदि हां, तो कौनसी संपत्ति, कितने में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार और भी संपत्ति को बेचना चाहती है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री परसराम मदेरणा) : संपत्तियों की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री परसराम मदेरणा)

(३) जी हां।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : कुल लागत नहीं बताई, कितनी लागत थी ?

श्री परसराम मदेरणा : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री भीमसेन : सूची पढ़ दी जाय तो अच्छा रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, ५ मिनट पढ़ने में लग जायेंगे। अलग अलग लागत और बिक्री की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री श्रवणलाल : प्रश्न के भाग (३) का उत्तर दुबारा दे दें तो अच्छा हो।

श्री परसराम मदेरणा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह।

ग्राम पंचायत भगवानपुरा द्वारा नरसरी स्थापित करने हेतु भूमि अवाप्ति का प्रस्ताव

३७२. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम पंचायत भगवानपुरा (पं.स. कुचामन) ने नरसरी स्थापित करने के लिये सरकार के पास भूमि अवाप्ति हेतु कोई प्रस्ताव व योजना भेजी है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा समस्त कानूनी कार्यवाही सम्पन्न करली गई है ? यदि हां, तो आगे कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है ?

श्री पंचायत मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी हां। दिनांक २१-१०-१९६३ को भूमि अवाप्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

(२) जी नहीं, पंचायत ने उक्त भूमि खरीद ली, इसलिये अवाप्ति की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : इसमें विलम्ब करने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आवश्यकता नहीं है। दूसरे से खरीद ली है, इसलिये एक्वायर करने की जरूरत नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : पंचायत ने प्रस्ताव पास करके भेजा है, लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही भी हो गई, उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि जरूरत नहीं है, यह कहां तक सही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दोनों ही सही हैं। पंचायत ने प्रस्ताव पास करके भेजा था कि जमीन एक्वायर की जाय। उसके बाद प्राइवेट नेगोशियेशन से पंचायत ने जमीन खरीद ली। अब एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये दोनों ही सही हैं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या यह सही है कि उक्त जमीन शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी ने बेची है इसलिये ट्रांसफर नहीं हो सकती ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के

Page No. 21

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किसी आदमी की जमीन किसी दूसरे आदमी को नहीं बेची जा सकती, लेकिन यह जमीन एक इंस्टीट्यूशन ने ली है और काम में भी ली है; एक्वायर तो तब की जाय जब आवश्यकता हो। आपने तो पहले ही ले ली।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन की पंचायत को आवश्यकता है, पंचायत समिति ने स्कीम को कार्यान्वित करने के लिये ऋण दिया है, अनुदान किया है, योजना चल रही है; उसके बावजूद भी सरकार ने पंचायत के प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि आपकी मंशा यह है कि गलत ट्रांसफर हुआ है और एक्वीजीशन करवा कर रेगुलराइज करवाना चाहते हैं तो साफ बतावें। गवर्नमेन्ट आप की मंशा समझ कर कार्यवाही करे। एक तरफ प्रस्ताव पास कर दिया और दूसरी तरफ जमीन ले ली। इस लिये एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है। लीगेलिटी से हमसे एक्वायर करवाना चाहते हैं तो मंशा साफ बतावें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मंशा साफ है या नहीं, लेकिन आप तो यह बता दीजिये कि यह ट्रांसफर इलीगल है या नहीं?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून की मंशा यह है कि शिड्यूल्ड ट्राइब या शिड्यूल्ड कास्ट की जमीन दूसरी जाति के आदमी को नहीं बेची जा सकती। यह जमीन किसी आदमी को न बेच कर पंचायत को बेची है। प्राइवेट निगोशियेशन करके संस्था ने ली है।

श्री भैरोंसिंह : कानून की मंशा यह नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब की जमीन किसी दूसरे को बेची जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब की जमीन दूसरे किसी व्यक्ति को नहीं बेची जा सकती, लेकिन यह जमीन एक इंस्टीट्यूशन को बेची गई है।

श्री भैरोंसिंह : कानून के अनुसार यह जमीन ट्रांसफर की जा सकती है या नहीं, आपकी राय क्या है?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून है उसमें राय नहीं दी जाती। महरबानी करके देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं कानून की एक एक बात बताता रहूं यह काम मेरा नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : सरकार ने एक्वीजीशन क्यों नहीं किया? कौनसी बाधा थी?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कहते हैं कि पंचायत ने स्वयं ने लिख कर भेजा है कि एक्वायर करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : पंचायत ने प्रस्ताव नहीं भेजा। योजना चालू कर दी. एक हजार रुपया खर्च कर दिया ...

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर एक्वीजीशन की क्या आवश्यकता है?

श्री हनुमानसिंह चौधरी : राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अनुसार पंचायत को इस जमीन पर खातेदारी राइट नहीं मिल सकता। रेकार्ड ऑफ राइट में नाम तभी आयेगा जबकि जमीन एक्वायर की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : यही तो मंत्री जी ने कहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब आलरेडी जमीन पंचायत के कब्जे में है, पंचायत पैसा दे चुकी है, तो एक्वायर कैसे हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो मंत्री महोदय ने कहा, आप साफ बतायें कि आप क्या चाहते हैं ?

श्री हनुमानसिंह चौधरी : एक्वायर कराना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आलरेडी वह जमीन पंचायत के कब्जे में है, पैसा दे चुके हैं, फिर एक्वायर कैसे होगी ?

श्री हनुमानसिंह चौधरी : जब खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं तो कब्जा कैसे होगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : खातेदारी राइट्स के लिये कब्जा नहीं होता है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सार्वजनिक हित का मामला है। इस पर पैसा भी काफी खर्च हो चुका है। कोई कानूनी बन्दिश नहीं है तो फिर सरकार के सामने आपत्ति कौनसी आती है जिसके तहत एक्वीजिशन नहीं किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा !

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ३७३!

भूपालसागर शूगर मिल्स में गन्ने की खरीद

३७३. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : [**श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) द्वारा पूछा गया] : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भूपालसागर शूगर मिल्स में गन्ने की खरीद के लिये पानडियों के वितरण का क्या नियम है ? उसकी एक कॉपी सदन की मेज पर रखें।

(२) गन्ने की खरीद व उसकी कीमत के चुकारे का क्या नियम है ?

(३) ३१ जनवरी, १९६६ तक कितना रुपया किसानों का देना बाकी है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) भूपालसागर शूगर मिल्स में गन्ने की खरीद का संबंध मिल व काश्तकारों के बीच लेन-देन का है। इसके लिये सरकार को नियम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे फैक्टरी से सूचना प्राप्त करने पर यह पाया गया कि फैक्टरी के प्रतिनिधि, उनके गन्ना सेन्टरों पर गांवों के काश्तकार के प्रतिनिधि को पानडियां देते हैं और उन्हीं तारीखों में फैक्टरी उन सेन्टरों पर गन्ना खरीद कर लेती है।

(२) गन्ने की खरीद का उत्तर पैरा १ में अंकित किया गया है और चुकारे की विधि मिल द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर पानडियों के मुताबिक अवकाश के दिनों

(श्री चन्दनमल वैद)
को छोड़ कर फैक्टरी गेट पर किया जाता है और गन्ना खरीद सैन्टरों पर मिल के प्रतिनिधि भी पेमेन्ट करते हैं।

(३) ३१ जनवरी, १६६६ तक मिल से प्राप्त सूचना के आधार पर १५८२,२०० रुपयों का गन्ना काश्तकारों से खरीदा गया और दिनांक ६-३-६६ तक १५,४८,२०० रुपयों का चुकारा किया गया है।

प्रश्न संख्या ३७६

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८३

श्री लक्ष्मीचन्द !

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

फूड इंसपेक्टर के विरुद्ध शिकायत की जांच

३५६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चूरू जिले में कितने फूड इंसपेक्टर हैं व उनके हैड क्वार्टर कहां-कहां हैं, उनके मातहत कौन-कौन सा इलाका है ?

(२) क्या यह सही है कि श्री मांगीलाल फूड इंस्पेक्टर सन् १६५३ से लगातार इसी जिले में है ?

(३) क्या यह सही है कि डूंगरगढ के नागरिकों की शिकायत पर इसका ट्रांसफर करके इसको चूरू भेजा गया था। यदि हां, तो फिर डूंगरगढ हैडक्वार्टर बना कर इसी इंस्पेक्टर को वपिस डूंगरगढ क्यों लगाया गया ?

(४) क्या यह सही है कि डायरेक्टर मेडिकल ने डूंगरगढ हैड क्वार्टर हटा कर श्री मांगीलाल को चूरू हैडक्वार्टर पर रखा था तथा डूंगरगढ जो पहले रतनगढ के इंस्पेक्टर के नीचे था उसे सुविधा की दृष्टि से वापिस रतनगढ के नीचे रखा था ? यदि हां, तो उस आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(५) क्या यह सही है कि माननीय मन्त्री महोदय ने डायरेक्टर के आदेश को कैंसिल करके डूंगरगढ हैडक्वार्टर बना कर वहां श्री मांगीलाल को ही पोस्ट किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि उक्त फूड इंस्पेक्टर को अपने क्षेत्र में दौरा करने हेतु डूंगरगढ से जाने में सरकार को ज्यादा टी. ए. व डी. ए. देना पड़ता है चूंकि डूंगरगढ चूरू से दूर एक कोने में पड़ने के कारण उसे डूंगरगढ से वाया रतनगढ ही जाना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार क्यों नुकसान उठा रही है ?

(७) क्या यह सही है कि इस इंसपेक्टर के खिलाफ काफी शिकायतें हैं ? यदि हां, तो उसे चूरू जिले से बाहर क्यों नहीं भेजा गया ?

उत्तर

(१) चूरू जिले में ५ फूड इंसपेक्टर हैं जिनका हैडक्वार्टर व इलाके निम्न प्रकार हैं :

१. श्री कल्याणसिंह :—हैडक्वार्टर परिहारा क्षेत्र, पी. एस. ओ. परिहारा।

२. श्री मोहनसिंह :—हैडक्वार्टर सांडवां क्षेत्र, पी. एस. ओ. सांडवां।

३. श्री इन्द्रजीतराय :—हैडक्वार्टर सागू, पी. एस. ओ. सागू।

४. श्री हरिप्रकाश माथुर :—हैडक्वार्टर रतनगढ, कस्बा रतनगढ राजलदेसर, छापर, डूंगरगढ नगरपालिका तारानगर मय तहसील तारानगर।

५. श्री मांगीलाल :—हैडक्वार्टर चूरू तहसील चूरू (देहात), नगरपालिका चूरू राजगढ, सुजानगढ व बीदासर।

(२) जी नहीं। सन् १९५६ में वैक्सीनेटर से सैनीटरी इंसपेक्टर के पद पर प्रमोशन होने पर जोधपुर से डूंगरगढ जिला चूरू आया और सन् १९५७ में फूड इंसपेक्टर के अधिकार दिये गये। बीच बीच में स्थानान्तर भी हुए और वापस चूरू में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हैल्थ स्टाफ में लगाया गया।

(३) जी हां। किन्तु जनता की मांग पर उसे वापस चूरू से डूंगरगढ लगाया गया। किन्तु अभी वर्तमान में दिनांक २५-२-६४ से इसका हैडक्वार्टर चूरू में है।

(४) जी हां। आज्ञा की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) जी हां। जनता की मांग पर सरकार की आज्ञा से यह परिवर्तन हुआ।

(६) वर्तमान में जो मांगीलाल फूड इंसपेक्टर का हैडक्वार्टर चूरू में है अतः डूंगरगढ उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वैसे प्रशासनिक दृष्टि से हैडक्वार्टर पर जाने व आने से टी. ए. व डी. ए. में थोड़ा अन्तर हो सकता है किन्तु इस मामले में ऐसा भी नहीं रहा, सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ।

(७) जैसा आइटम २ में बताया गया है इंसपेक्टर के स्थानान्तरण भी हुए हैं किन्तु शिकायतों के साथ साथ जनता की मांग तथा काम की तारीफ होने से स्थानान्तरण किया जाना उचित नहीं समझा गया। कोई शिकायत आयेगी तो नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शेड्स तथा प्लाट्स का अलॉटमेन्ट

३६०. **श्री अब्दुल जब्बार खां** (निम्बाहेडा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) इण्डस्ट्रियल एस्टेट जयपुर में कुल कितने शेड्स तथा प्लाट्स हैं ?

(२) क्या शेड्स तथा प्लॉट्स का एलॉटमैन्ट किन्हीं रूल्स के अनुसार हुआ है ?

(३) इंडस्ट्रियल एस्टेट में ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज या ओनर्स हैं जिन्हें एक से ज्यादा प्लाटस व शेड्स अलॉट हुए हैं ?

(४) कितनी अर्जियां वास्ते प्राप्त करने प्लॉट्स विभाग के पास पैंडिंग हैं तथा कितने कितने समय से ?

(श्री अब्दुल जब्बार)

(५) राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज को कितने शेड्स दिये हुए हैं? तथा वे किस काम में आ रहे हैं?

(६) ऐसी कितनी इंडस्ट्रीज या इन्डस्ट्रीज ओनर्स हैं जिन्हें शेड्स या प्लाट्स १९६४ में एलॉट हुए हैं तथा अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है तथा किन कारणों से?

उत्तर

(१) इंडस्ट्रियल एस्टेट जयपुर में ६४ शेड्स और २८ प्लाट्स हैं।

(२) जी हां।

(३) १८ इंडस्ट्रीज।

(४) ६ अर्जियां विभाग के पास प्लॉट्स के लिये पेंडिग हैं जिनकी तारीख निम्न प्रकार है :–

क्रम संख्या	अर्जी प्राप्त होने की तारीख
(१)	८-५-६५
(२)	३०-६-६४
(३)	३-७-६५
(४)	२१-८-६५
(५)	२१-६-६५
(६)	१६-६-६५

इसके अतिरिक्त एक अर्जी शेड के लिये १३-५-६४ से पेंडिंग है।

(५) शेड्स दिये गये हैं उद्योगों के लिये कच्चे माल के गोदाम के लिये काम आ रहे हैं।

(६) कोई नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

खरीफ की नष्ट हुई फसल से प्रभावित काश्तकारों को राहत, तहसील मांगरोल

३६१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील मांगरोल में १३-१०-६५ को हवा और पानी के प्रकोप से खरीफ की फसल नष्ट हो गई?

(२) क्या सरकार ने प्रभावित काश्तकारों को कोई राहत दी है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(१) जी नहीं, केवल एक आना दो आना नुकसान हुआ था।

(२) सूक्ष्म हानि (एक आना व दो आना) होने से सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रोडवेज के लिए बसों की खरीद

३६२. **श्री मथुरेश बिहारी माथुर** (बांदीकुई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान स्टेट रोडवेज के लिये अब तक कुल कितनी बसों की खरीद की गई है? वर्ष १९६५ में कितनी बसें खरीदी गईं?

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

(२) इस समय कुल कितनी बसें खराब होकर पड़ी हैं ?

(३) कितनी बसों की खरीद के ऑर्डर अभी दिये हुए हैं ?

उत्तर

(१) अभी तक ४११ गाड़ियां खरीदी हैं। जिनमें से २८ गाड़ियां मध्य बोडी बन कर सन् १९६५-६६ में आईं जबकि आदेश ३० गाड़ियों के थे। दो गाड़ियां और आने को हैं।

(२) माह जनवरी सन् १९६६ के अन्त तक खराब गाड़ियों की संख्या १८० थी।

(३) ११५ चेसिस के आदेश दिये जा चुके हैं। जिसमें से ७० लोलेंड तथा ४५ मर्सेडीज हैं।

थरमल वाटर स्टेशन बनाने की योजना

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि पलाना लिगनाइट खान पर थरमल पावर स्टेशन बनाने की योजना विचाराधीन है ?

(२) क्या यह सही है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिये वहां ट्यूब वैल खोदे गये हैं ?

(३) यदि हां, तो कितने कुए खोदे गये और उन कुओं में कितने घनफुट पानी की प्राप्ति हुई ?

(४) क्या यह सही है कि जो पानी निकला उसकी स्थिरता की जांच अटोमिक तरीके से कराया जाना आवश्यक है ?

(५) यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराली गई ? यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

(६) यदि नहीं, तो जांच कराने में विलम्ब क्यों हुआ ? कब तक इस जांच के परिणाम मालूम हो सकेंगे ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) तीन कुए खोदे गये। मुख्य अभियंता (हैल्थ) ने सलाह दी है कि अगर हर एक कुए का ठीक तरह विकास किया जाय तो हर कुआ १२,००० गैलन पानी एक घंटे में निकालेगा।

(४) पानी की स्थिरता की जांच के लिये अटोमिक प्रयोग भी एक प्रकार का साधन है।

(५) अटोमिक इनरजी द्वारा जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है।

Page No. 27

(राजकीय उद्योग मंत्री)

(६) प्रश्न नहीं उठता ।

जालौर-आकोली व सियाना-बलदूर सड़क का निर्माण

३७१. **श्री विरदाराम फुलवारिया** (जालौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार जालौर से आकोली व सियाना होती हुई बलदूर तक पक्की सड़क का निर्माण करवाने की योजना बना रही है ?

(२) अगर यह निर्माण कार्य विचाराधीन है तो कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

(३) अगर इस सड़क के निर्माण का फिलहाल विचार नहीं है तो कब तक यह सड़क बनने की संभावना है ?

उत्तर

(१) जी नहीं । जालौर से आकोली तक ग्रेवल रोड बनी हुई है बाकी आकोली से बरलूट वाया सियाना रोड का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता ।

टी. बी. क्लिनिकों का मेडिकल विभाग को हस्तान्तरण

३७६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर, बीकानेर एवं जयपुर के मेडिकल कालेजों के अन्तर्गत चलने वाले टी. बी. क्लिनिकों को मेडिकल विभाग को हस्तान्तरित करने के लिये सरकार ने आज्ञा दी थी ?

(२) यदि हां, तो यह आज्ञा कब दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार की आज्ञा होने के बावजूद भी इन मेडिकल कालेजों के प्रिंसिपलों ने विभाग को ये क्लिनिक हस्तान्तरित नहीं किये ?

(४) क्या यह सही है कि यदि विभाग के अन्तर्गत टी. बी. क्लिनिक चलाये जायें तो यूनीसेफ (UNICEF) के द्वारा रियायत दी जाती है ? यदि हां, तो वो रियायत कितनी होती है ?

(५) क्या यह सही है कि मेडिकल विभाग को हस्तान्तरित नहीं किये जाने के कारण उदयपुर, बीकानेर और जयपुर के क्लिनिक इस रियायत से वंचित रह रहे हैं ।

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) यह आज्ञा सरकार के आदेश सं० एफ. १६ (२६) एम. पी. एच।६४ दिनांक २०-७-६५ को दी गई थी ।

(३) जी नहीं, बीकानेर तथा जयपुर को टी. बी. क्लिनिक संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के अधीन चल रही हैं, टी. बी. क्लिनिक उदयपुर के सम्बन्ध में प्रिन्सिपल ने स्पष्टीकरण चाहा था वह भेज दिया गया है तथा हस्तान्तरित करने के अन्तिम आदेश दे दिये गये हैं ।

(श्री चिकित्सा मंत्री)

(४) जी हां। यह सही है कि विभाग के अन्तर्गत चलने वाले टी. वी. क्लिनिक को युनिसैफ सहायता देती है जो इस प्रकार है :—

(अ) नान–रेकरिंग सहायता—

(१) एक १०० एम.ए.,७० एम. एल. एक्सरे की मशीन व फिल्म धोने का सामान;

(२) लेबोरेटरी का सामान जिसमें एक एक रेफरीजेटर भी शामिल है,

(३) दो मोटर गाडी।

यह सामान केवल नये स्थापित टी. बी. क्लिनिक को ही दिया जाता है।

अनुमानतः यह सामान २.५ लाख रुपये का होता है।

(ब) रेकरिंग सहायता :—

(१) टी. बी. के इलाज के लिये आई. एन. एच. की गोलियां।

(२) एक्सरे की छोटी ७० एम. एम. वाली फिल्म। यह सहायता ४००० टी. बी. के रोगियों तक के लिये प्रति वर्ष ३ से ५ वर्ष उपलब्ध हो सकती है अनुमानतः इनकी लागत ९६,०००)रु० तक आंकी गई है।

(५) जी नहीं।

पीपल्दा में फसल के कारण हुए नुकसान की पूर्ति हेतु सहायता

३८३. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील पीपल्दा में १३-१०-६५ को हवा और पानी के प्रकोप से खरीफ की फसल नष्ट हो गई जिसकी सूचना तहसीलदार व कलेक्टर को दी गई ?

(२) तहसीलदार द्वारा किये गये निरीक्षण में कौन-कौन से गांवों में कितना-कितना नुकसान हुआ पाया गया ?

(३) क्या सरकार संबंधित काश्तकारों को लगान में छूट व अन्य सहायता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, ऐसी सूचना तहसील में दिनांक २६-१०-६५ को प्राप्त हुई थी।

(२) तहसीलदार द्वारा किये गये निरीक्षण खसरा गिरदावरी खरीफ के समय किसी ग्राम में नुकसान होना नहीं पाया गया।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

ट्रैक्टर्स की जांच, जिला नागौर

७३. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) सन् १९६० से १९६४ तक नागौर जिले के यातायात निरीक्षक ने कितने ऐसे ट्रैक्टर्स का चालान किया, जो कृषि प्रयोजनार्थ क्रय हुए हैं, और भार ढोने व नियम विरुद्ध अन्य कामों में लिये जा रहे हैं ?

(२) सन् १९६० से १९६४ के दरमियान नावां तहसील के ऐसे कितने ट्रैक्टर्स का चैकिंग किया गया व कब-कब ?

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

(३) इस प्रकार के चैकिंग से सरकार को सालाना कितना मुनाफा हुआ ?

उत्तर

(१) सन् १९६० से १९६४ तक नागौर जिले में यातायात निरीक्षक ने कुल २७ ऐसे ट्रेक्टरों का चालान किया जो कृषि प्रयोजनार्थ बिके हैं और भार ढोने व नियम विरुद्ध अन्य कार्यों के लिये जा रहे थे।

(२) सन् १९६० से ६४ के दरमियान नावां तहसील के एक ट्रेक्टर दिनांक २५-४-६२ को यातायात निरीक्षक द्वारा चालान किया गया।

(३) इस प्रकार के चैकिंग से सरकार को सन् १९६० से ६४ तक करीबन १५७२) रुपये वसूल हुए हैं।

सिंचाई हेतु कुएं बनाने के लिये निःशुल्क सहायता

७४. **श्री मोहर्रसिंह (चूरू)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई हेतु कुएं बनाने के लिये सरकार की ओर से कोई निःशुल्क सहायता विशेष रूप से दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी सहायता दी जाती है ? इसके लिये क्या-क्या शर्तें हैं ? यदि नहीं, तो क्या सारे राजस्थान के लिये कोई समान रूप से सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो क्या और इसकी क्या शर्तें हैं ?

(२) क्या सरकार सिंचाई हेतु बनाये गये कुओं पर मोटर लगाने तथा ट्यूब वैल्स बनाने के लिये कोई निःशुल्क सहायता देती है ? यदि हां, तो कितनी और किन-किन शर्तों पर ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

हां सारे राजस्थान में कुओं के लिये ऋण निम्नलिखित शर्तों पर पंचायत समितियों द्वारा दिया जाता है :—

(१) कुल लागत का ५० प्रतिशत धनराशि ऋण के रूप में दी जाती है परन्तु इसके लिये ज्यादा से ज्यादा ४०००) रुपये तक का ऋण प्रत्येक काश्तकार को दिया जा सकता है।

(२) यह ८ साल में या १६ अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में ६½ प्रतिशत ब्याज दर से वसूल किया जाता है ?

(३) जी नहीं।

अकालग्रस्त क्षेत्रों (जिला टोंक) में सहायता की व्यवस्था

७५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) टोंक जिले की किस-किस तहसील के कितने-कितने गांव सन् ६५ में अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं ?

(२) उक्त अकालग्रस्त क्षेत्रों में कहां-कहां राहत कार्य शुरू किये गये ?

(३) उक्त अकालग्रस्त क्षेत्रों में अनाज, चारे व पीने के पानी की कहां-कहां

Page No. 30

(श्री जयनारायण सालोदिया)

विशेष व्यवस्थायें की गई ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(१) टोंक जिले की निम्नलिखित तहसीलों में सन् ६५ में अकाल घोषित किया गया—

(१)	तहसील टोंक	१४६	गांव
(२)	,, निवाई	१६६	,,
(३)	,, मालपुरा	१२६	,,
(४)	,, उनियारा	१५२	,,
(५)	,, देवली	६०	,,
(६)	,, टोडाराय-सिंह	२८	,,
	कुल	७१४	गांव

(२) निम्न तहसीलों में उनके आगे दी जगहों पर सिंचाई विभाग द्वारा तालाबों की मरम्मत का कार्य चालू कर दिया है :—

(१) तहसील उनियारा
- (१) रघुनाथपुरा
- (२) नया गांव
- (३) सावन-भादंया
- (४) अमीनपुरा
- (५) सईदाबाद
- (६) भीमगंज

(२) तहसील टोडारायसिंह
- (१) पन्द्राहेडा
- (२) उनियारा खुर्द
- (३) बरवास

(३) तहसील मालपुरा
- (१) सरदारपुरा
- (२) डिग्गी
- (३) दड़ावट
- (४) गनवर
- (५) बचंवर (नागसागर)
- (६) नाथजी बंधनिबल

(४) तहसील निवाई
- (१) बस्सी

निम्न तहसीलों में उनके आगे दी गई जगहों पर पथ एवं निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनवाने मरम्मत का कार्य चालू कर दिया गया है :—

(१) तहसील उनियारा
- (१) ककोड से नगर
- (२) अलीगढ़ से सोप

(मजदूर न मिलने से कार्य बन्द है)।

Page No. 31

(श्री अकाल सहायता मंत्री)

(२) मालपुरा तह० (१) टोरडी स्टेशन से कलमण्डा

(३) तहसील देवली (१) दुनी से आवां
(२) दुनी से नगरां

(४) तह० निवाई (१) झीलाय से बेहड़ (मजदूर न मिलने से कार्य बन्द है)

(५) तह० टोंक (१) नाथडी से सानोली
(२) टोंक से ऊभ (मजदूर न मिलने से कार्य बन्द है)।

(३) पीने के पानी के कुओं के गहरा करवाने हेतु तहसीलों को ३४,१००) रु० अलॉट किया गया है जिससे कि हर तहसील में जहां २ पानी की कमी है कुओं को गहरा कराया जा सके। अनाज की उपलब्धि हेतु निम्न जगहों पर अनाज की दुकाने खोलने की आज्ञा प्रसारित की जा चुकी है :

(१) तहसील निवाई :-(८) भिभलाई, दतवास, रोहोली भूण्डिया, ललवाडी, डागर थल, बेहड करेडा।

(२) तहसील मालपुरा :-पचेवर, आडली, टोरड़ी कलमण्डा, गनवर, (देशमा राजपुरा), काचोलिया नगर, लावा, चान्दसेन, लाम्बा हरिसिंह, डिग्गी, मालपुरा।

तहसील उनियारा :-उनियारा, अलीगढ, रान, पुरा ककोड, बनैठा, सूथड़ा, सुरेली, खातोली, गोठड़ा।

तहसील देवली :-चांदली, घाड, नगर।

तहसील टोडारायसिंह :--खरेडा, मोरबरवासे, दत्तोब, पीपलू, किराना, नानेर, सोहेला, हतोना, सोनवा, ताखोली।

चारे की निकासी इस जिले के राज्य सरकार की आज्ञा सं० एफ. ५(८) आर-सी। केटल। फीडर। ६३ दिनांक २२ नवम्बर, ६५ से पूर्ण रूप से बन्द है। घास व कड़बी, खाखला आदि के भाव प्रायः राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं है।

लैण्ड मोर्गेज बैंक, चित्तौड़गढ़

७६. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेडा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

लैण्ड मोर्गेज बैंक, चित्तौड़गढ़ ने जनवरी, १९६५ से दिसम्बर १९६५ तक कुल कितना कर्ज दिया ?

उत्तर

(१) लैण्ड मोर्गेज बैंक, चित्तौड़गढ़ ने जनवरी, १९६५ से दिसम्बर, १९६५ तक कुल ८७,०४५) रुपये का कर्ज दिया।

पं. स. निवाई के स्कूलों में अध्यापकों एवं छात्रों की संख्या

७७. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

पंचायत समिति निवाई के अधीन कितने स्कूल चलते हैं और उनमें कितने कितने अध्यापक व कितने-कितने लड़के व लड़कियां हैं ?

उत्तर

७६ शालाएं है जिनमें १३१ अध्यापक, २९६३ छात्र और ४५१ छात्राएं हैं।

(११.५३ म० प०)

विधान सभा के सम्मुख सुरजा जाट की भूख हड़ताल विषयक स्थगन प्रस्ताव

(श्री श्रवणलाल, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए।)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के द्वारा इस बात की सूचना दी थी कि राजस्थान विधान सभा ...

श्री अध्यक्ष : आपसे पहले माननीय सदस्य (श्री श्रवणलाल) ने दी थी।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज से दो दिन पूर्व एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना सदन में विचार करने के लिए दी थी जिसके अन्दर है कि श्री सूरजमल पुत्र रूपा जाट, खुरजा शेखावाटी वाला, जो कि करीब छः दिन से भूख हड़ताल पर अपनी असेम्बली के सामने बैठा हुआ है, के यहां पर तारीख १७ जनवरी, १९६४ को पन्द्रह व्यक्ति मय हथियारों के, बन्दूकों से लैस, ऊंट की सवारी सहित आये और उस गरीब किसान के घर पर एक डाकू के रूप में आकर उन्होंने उसकी लड़की को छीना और उसकी लड़की को छीन कर, उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसको ऊंट पर बिठा कर ले गये और घर वालों को एक कमरे में बन्द करके, उसका दरवाजा बन्द करके उस पर उन्होंने कुण्डी लगा दी। इस तरह से उस लड़की को वहां से उठा कर ले गये जिसके कारण वह बेचारा किसान आज मारा-मारा फिर रहा है। वह पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए गया, लेकिन वहां रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसने एस० पी० को इस बात के लिए लिखा, लेकिन उसने भी उसकी सुनवाई नहीं की। उसने मंत्रीजी को भी इसके लिए लिखा लेकिन उन्होंने भी सुनवाई नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, आज यह सरकार इस बात का ढिंढोरा पीटती है कि हम फौजियों के के लिए इमदाद देते हैं। जमीन के लिए और जितनी भी कानूनी कार्यवाही होती है उनके लिए, उनके रहने के लिए और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए। लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि यह इमदाद कैसे देती है? इस गरीब किसान का लड़का प्रहलादसिंह छम्ब-जोरियां क्षेत्र में देश की सेवा में है। उसके पास भी जब उसके पिता के पत्र इस सम्बन्ध में पहुंचे तो उसने भी ऑफिशियल-वे में लैटर लिखे, लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, १७ जनवरी, १९६४ से उस बेचारे किसान की लड़की फरार है, और वह एक ऐसे आदमी के पास में है जिसका नाम रामकरण जाट है। उसके मकान में रही वह लड़की और उसको पहले आठ दिन तक जंगल में रखा और जंगल में रखने के बाद वह रामकरण जाट के मकान में रखी गई

श्री अध्यक्ष : उसको कहां रखा, कहां नहीं रखा-यह आपकी शहादत का प्रश्न है। भूख हड़ताल पर बैठ कर पुराने मामले की ओर ध्यान आकर्षित किया है, वह काफी है।

श्री श्रवणलाल : मेरा निवेदन है कि एक व्यक्ति आज छः दिन से भूख-हड़ताल पर है क्योंकि उसकी लड़की १७ जनवरी, १९६४ से फरार है और जब यह सरकार इस तरह

(श्री श्रवणलाल)

का ढिंढोरा पीटती है कि वह फौजियों को इतनी सुविधा देती है कानूनी कार्यवाही के लिए, तो जब उसका लड़का छम्ब-जोरियां में देश की सेवा कर रहा है ऐसी स्थिति में भी सरकार उसके घर वालों को किसी प्रकार की सुविधा देने में असमर्थ रही है। मैं प्रार्थना करूंगा कि जो व्यक्ति भूख-हड़ताल पर बैठा हुआ है उससे पूर्ण जानकारी प्राप्त करके उसकी लड़की को बरामद करने की कोशिश करें। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस राज्य में इस बात को देख कर दुःख होता है

एक माननीय सदस्य : कांग्रेसी तो नहीं ले गये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप सुनिये तो। जो कांग्रेस राम-राज्य का नारा देती है, गांधी जी नारा दे गये हैं कि राम-राज्य ही भारत में हो सकता है और यही रावण के राज्य का विध्वंस कर सकता है, लेकिन आज कांग्रेस राज्य में इतना साहस नहीं रहा है कि एक जाट की बेटी भगवती को कुछ गुण्डे उठा कर ले जायं, वह इधर-उधर रोता फिरे, उसका लड़का देश की लाज बचाने को युद्ध में जूझता रहे, उस लड़की का भाई देश की लाज बचाने को युद्ध में जूझता रहे, उसके बाद भी आप यह कहें कि कांग्रेसी तो ले नहीं गये। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है और इस पर कांग्रेस सरकार को शर्म करनी चाहिए। वह आदमी छः दिन से विधान सभा के सामने भूख-हड़ताल पर बैठा हुआ है। वह कह रहा है कि उसने राजस्थान सरकार के और भारत सरकार के दरवाजे खटखटाये हैं लेकिन कोई नहीं सुनता है। न पुलिस वाले सुनते हैं और न सरकारी अधिकारी सुनते हैं। वह मजबूर हो कर विधान सभा के दरवाजे पर भूख-हड़ताल करके बैठा हुआ है, इसलिए अध्यक्ष महोदय, खास करके आपसे प्रार्थना है कि आप मंत्री महोदय को बाध्य करें कि वह कम से कम राजस्थान की लाज बचायें। और जो राजस्थान सरकार के माथे पर कलंक का टीका लगा है कि वह एक महिला की लाज बचाने में असमर्थ रही है, उसको आवश्यक कार्यवाही करके धो दे।

एक माननीय सदस्य : क्या वह लड़की शादी-शुदा है या कंवारी है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : शादी-शुदा है, जिसका पति भाभी से लगा हुआ है इसलिए परवाह नहीं करता है

श्री अध्यक्ष : आप दूसरे फैक्ट्स में मत जायं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : माननीय सदस्य ने कहा है, उनको कहता हूं, आप भी जाकर बात कर लीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, ध्यान इन्होंने आज आकर्षित किया है इसलिये इसकी जानकारी तो मुझे लेनी है, लेकिन जानकारी आपके हित में नहीं होगी-ऐसी जानकारी है। फिर भी मुझे यदि समय दिया जाय तो मैं कल इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से जानकारी की यह किडनेपिंग का केस है या एब्डक्शन का केस है, क्या अन्य विषमतायें हैं; इनकी निश्चित रूप से कल

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
जानकारी दूंगा ताकि जो भ्रांति है वह निर्मूल हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : जो भूख-हड़ताल का प्रश्न है उसको भूख-हड़ताल करने से आप हटा सकें तो मेरे ख्याल में उचित होगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जब मैं भ्रांति निर्मूल कर दूंगा तो शायद उसको भी सब्र मिल जाय जो भूख-हड़ताल करने वाला है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : लड़की अभी तक प्राप्त क्यों नहीं की गई ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें भूख हड़ताल का ही सवाल है, इसमें भ्रांति का सवाल नहीं है । एक आदमी भूख हड़ताल कर रहा है तो सरकार को सोचना चाहिए, आखिर वह चार दिन से·····

श्री हरिप्रसाद शर्मा : छः दिन से ।

श्री भैरोंसिंह : छः दिन से भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है । यदि यहां पर एडजोर्नमेन्ट मोशन मूव नहीं किया जाय तब भी सरकार को मिल-मिला कर जो भूख हड़ताल पर बैठा है उसको संतोष कराने की चेष्टा करनी चाहिए थी ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : सदन में एडजोर्नमेन्ट मोशन पर जो अपने सुझाव दिया है उसको भी मैं करके देखूंगा ।

श्री अध्यक्ष : वह आप अवश्य करें ।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन इन बातों का आप पर असर नहीं होता है । आपको उसे संतोष कराने की आवश्यकता थी । आखिर वह तम्बू लगा कर भूख-हड़ताल पर बैठा है, लेकिन आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है । जब तीन दिन से एडजोर्नमेन्ट मोशन की चर्चा होने लगी है फिर भी आप एक दिन का समय और मांगते हैं । यदि आपको एक दिन भी भूखा रहना पड़े तो आपको मालूम हो कि भूखा रहने का क्या मतलब है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : शाम तक दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : और तभी आपको मालूम पड़ेगा कि भूखा रहने से कितनी पीड़ा होती है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चार-पांच बजे तक मैं तैयार होकर आपको बता दूंगा । पांच बजे तक दे दूंगा तो फिर कल का सवाल पैदा नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद आपको इसके लिए ।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र ।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : सदन की मेज पर रख दूं ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : आप ही विराज जाइये सदन की मेज पर ।

श्री भैरोंसिंह : सदन की मेज पर आप भी विराजमान हो जाओ ।

श्री मानसिंह महार : आप विराजमान हो जाओ तो हमारा पिण्ड छूटे ।

(११.२६ म. पू.)

राजस्थान जन सेवा आयोग संबंधी अधिसूचन

(सदन की मेज पर रखना)

श्री माथुरादास माथुर (योजना मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२० (५) के अन्तर्गत नियुक्ति विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० १४ (८) नियुक्ति (क-४)।५६ दिनांक १८ नवम्बर, १६६५ को, जिसके द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फंक्शन्स) रेग्युलेशन्स, १६५१ में संशोधन किया गया है, मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

(१२.०० मध्यान्ह)

मांग संख्या १६ एव ३-चिकित्सा तथा गाड़ियों पर कर

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,६५,३६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री मथुरादास माथुर (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११-गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में लिये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,५४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

इन मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

मांग संख्या १६

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : (१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में डाक्टरों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री गंगासिह राठौड (जायल) : (२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागोर जिला के कठौती गांव की अस्पताल में तीन साल से डाक्टर न होने पर चर्चा के लिये)।

(३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डाक्टरों द्वारा झूंठी inquiry report देने की प्रथा पर चर्चा के लिये)।

(४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागोर जिले में चिकित्सा का कार्य सुव्यवस्थित ढंग से न होने के संबंध पर चर्चा के लिये)।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा) : (५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा क्षेत्र में बरती जाने वाली उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालयों में रेफ्रीजेटरों की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल मीणा (साराड़ा-सु.) : (७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—

(श्री देवीलाल मीणा)
चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में डाक्टरों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–(चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में से भारी आयुर्वेदिक औषधालय को वी श्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री श्रवणलाल (हिंडौन-सु०) : (९) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हिंडौन चिकित्सालय में दवाइयों के अभाव तथा बैडों की कमी से जनता अति परेशान है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : (१०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दौसा अस्पताल में मरीजों से दवाइयों के पैसे लेने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती सुमित्रा (झुंझुनूं) : (११) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी दुकानों पर दवाइयां उपलब्ध न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : (१२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर जिला के ग्राम गोनेर की (Dispensary में Doctor) में के न रहने पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : (१३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों में पांच सौ की आबादी वाले गांवों में शीघ्र औषधालय खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़) : (१४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामान्य नागरिकों की चिकित्सा पर होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु०) : (१५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जनरल अस्पताल में बिगड़ती व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : (१६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी विभाग में डाक्टरों के स्थानान्तरण पर चर्चा के लिये)।

(१७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आयुर्वेद विभाग में औषधालयों में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : (१८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) कम कर दिया जाय (गांवों में चिकित्सा संबंधी सुविधायें उपलब्ध नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (औषधि भंडागारों का कम संख्या में खोला जाना तथा इन भंडारों में औषधियों के नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : (२०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६– चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में व्याप्त निष्क्रियता एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३

(२१) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११– गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : (२२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६– चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मैडिकल स्टोर्स में दवाओं के न मिलने से राज्य कर्मचारियों की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३

(२३) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११– गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (परिवहन अधिकारी के कार्यालयों में होने वाली अनियमितताओं से जनता की परेशानियों पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

(२४) **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लूणकरणसर एवं कालू में डाक्टरों की नियुक्ति की जाय इस पर चर्चा के लिये) ।

(२५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६– चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नापासर डिस्पेन्सरी को नौरंगदेसर में स्थानांतरित करने में विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

(२६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६– चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (एस. पी. मैडीकल कालेज, बीकानेर में एम. एस. तथा एम. डी. आदि के अध्यापन की व्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

(२७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६– चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सिथल के नागरिकों द्वारा ३५ हजार रुपये की लागत का भवन तैयार करने के कारण वहां पर बी श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय खुलवाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३

(२८) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११– गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के कई मार्गों पर जरूरत से अधिक परमिट देने के कारण सरकारी मोटरों का पूरा उपयोग नहीं होने से राष्ट्रीय धन के दुरुपयोग को रोकने पर चर्चा के लिये) ।

(२९) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११– गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जावे (R. T. As. को मार्गों की आर्थिक क्षमता के अनुसार परमिट देने की प्रणाली के संबंध पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : (३०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६– चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दौसा D. M. & H. O. का आफिस दौसा से हटाने के संबंध पर चर्चा के लिय) ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : (३१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी मेडीकल स्टोर से औषधि अभाव पत्र देने में भेद भाव पर चर्चा के लिये)।

(३२) **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु.) : मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९— चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अस्पतालों में लेडी डाक्टर न होने से डिलीवरी केसेज में असुविधा होने पर चर्चा के लिये)।

(३३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गरीब परिवारों को विशेष चिकित्सा सुविधा व सहायता न मिलने पर चर्चा के लिये)।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : (३४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शफाखानों में रोगियों के लिये समुचित औषधियों के उपलब्ध नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री चौसरसिंह बाघेल (बेंगूं) : (३५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में डाक्टरों की व दवाइयों की कमी से इलाज ठीक नहीं होता इस पर चर्चा के लिये)।

(३६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में डाक्टरों की कमी को जल्द पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

(३७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगूं अस्पताल में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

(३८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बेंगू अस्पताल में दो साल तक डाक्टर की व्यवस्था नहीं की गई जिससे भारी हानि हुई, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३

(३९) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११—गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुराने रोड कर की वसूली न होने से मनमाना कर लगाया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री मोहनराज (बाली) : (४०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम रानी स्टेशन पर दवाखाना व ग्राम खोड में एड पोस्ट न खोलने पर चर्चा के लिये)।

(४१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बाली तहसील में आदिवासी ग्राम गोरिया में आयुर्वेदिक औषधालय न खोलने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : (४२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डाक्टरों की कमी दूर करने हेतु चिकित्सा शिक्षा में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करने पर चर्चा के लिये)।

(४३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम जनता व राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा में वरते जा रहे भेद भाव पूर्ण तरीकों पर चर्चा के लिये)।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

(४४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय चिकित्सालयों में उपयोग में आने वाली औषधियों एवं जरूरत की अन्य सामग्री के वितरण एवं निर्माण का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में करने हेतु चर्चा के लिये)।

(४५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में डाक्टरों की कमी को दूर करने की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : (४६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में भेषज और औषधियों की कमी के कारण रोगियों की परेशानी पर चर्चा के लिये)।

(४७) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आयुर्वेद औषधालयों में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिये)।

(४८) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पिड़ावा, इकलेरा, मनोहरथाना के अस्पताल में डाक्टरों की नियुक्ति न होने पर चर्चा के लिये)।

(४९) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण जनता के लिये चिकित्सा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(५०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सुनेल चिकित्सालय की दुर्दशा से जनता को होने वाली असुविधा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३

(५१) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर की वसूली पर विभाग द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु.) : (५२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में आयुर्वेदिक औषधालयों की कमी तथा वैद्य के अभाव पर चर्चा के लिये)।

(५३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सिकराय में चिकित्सालयों के अभाव से जनता की परेशानी पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : (५४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९– चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र-आपरेशन कैम्प्स लगाने के संबंध में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

(५५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा लगाए गए मेडिकल स्टोर की अव्यवस्था एवं कठिनाइयों के संबंध में चर्चा के लिये)।

(५६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करने के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

Page No. 40

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मांग संख्या ३

(५७) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (यातायात विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उसको दूर करने के उपायों पर चर्चा के लिये) ।

(५८) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बस ओपरेटर्स को विभाग द्वारा गाड़ियों की फिटनेस कराने में कठिनाइयों के संबंध पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : (५६) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बून्दी अस्पताल में रोगियों के लिये उचित व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

(६०) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लाखेरी में अस्पताल नहीं खोले जाने से देहात की ५० हजार जनता के लिये चिकित्सा सुविधा नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

(६१) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नैनवा व इन्दरगढ अस्पताल में लम्बे अरसे से डाक्टर नहीं होने के कारण जनता की कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

(६२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिवा जाय (लाखेरी के आयुर्वेदिक औषधालय व प्रथम श्रेणी का औषधालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

(६३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय आयुर्वेदिक विभाग की शिथिलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : (६४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सोजत औषधालय में X-ray की व्यवस्था नहीं की जाने पर चर्चा के लिये) ।

(६५) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६–चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सोजत औषधालय में Anti Rabic केन्द्र न होने से गत वर्ष ४ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३

(६६) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मोटर गाड़ियों के Fitness के प्रमाण-पत्र का एकाधिपत्य Fitness Inspector का होने पर चर्चा के लिये) ।

(६७) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर नगर की C. T. S. बसों के टिकट R. T. G. के, अनुसार न होने से यात्रियों से अधिक किराया लिया जाने के कारण बस के टिकटों पर स्टशनों के नाम व किराया लिखे जाने की आवश्यकता पर विभाग का ध्यान आकर्षित करने पर चर्चा के लिये) ।

(६८) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११–गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर C. T. S. बसों की हालत खराब होने पर व उनकी हालत सुधारने पर व Model Conditions लागू करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये) ।

(श्री तेजाराम गहलोत)

(६९) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११- गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर C. T. S. बसों को नम्बर of services मुख्य मार्गों पर हर १५ मिनट वाद चलें, इस तरह से निर्धारित करने पर चर्चा के लिये)।

(७०) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११- गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर C. T. S. बसों के मार्गों का नये सिरे से निर्धारण करने पर चर्चा के के लिये)।

(७१) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११- गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में C. T. S. बसों में निर्धारित किराया से यात्रियों से अधिक किराया वसूल करने पर विभाग द्वारा ध्यान न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री शृंगारसिंह (चेचट) : (७२) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सांगोद में डाक्टरों की कमी पर चर्चा के लिये)।

(७३) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९- चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति चेचट में चल रहे Private चिकित्सालयों को अनुदान नहीं देने पर चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : (७४) मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९- चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गरीबो व गांव वालों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३

(७५) मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११- गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आसीन्द गुलाबपुरा रूट पर बसों के अभाव व पुरानी गाड़ियों को Permit देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) :

७६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९- चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सालय व डाक्टरों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ) :

७७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९- चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काछोला तथा कोटडी में डाक्टरों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :

७८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९- चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (P. M. H. O. कोटा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

७९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९- चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सर्जिकल के सामान मंहगी कीमत के होने के उपरान्त भी खरीद करने पर चर्चा के लिये)।

८०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९- चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विक्टोरिया अस्पताल अजमेर में आपरेशन के हेंड ग्लोव्स की खरीद में हुए घोटालों पर चर्चा के लिये)।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

८१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सालाना सर्जिकल के सामान की खरीद में जंग लगे सामान की खरीद पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३

८२. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११-गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (रोड टैक्स की चोरी पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा):

८३. मांग संख्या १६, मुख्य शीषक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्रों में चिकित्सा के सम्बन्ध में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

श्री दुर्गालाल बाददार (हवामहल, जयपुर):

८४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार ने गावों में आवश्यकतानुसार चिकित्सालय नहीं खोले इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई):

८५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अस्पतालों में डाक्टरों एवं औषधियों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३

८६. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११-गाड़ियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गाडियों पर बकाया करों की वसूली में निष्क्रियता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १६

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली):

८७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों के लिए खोले गए Medical Stores में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३

८८. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११-गाडियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (Tempo का area of operation को बढाने के प्रश्न पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १६

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर):

८९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों के लिए खोले गये Medical Stores में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३

९०. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११-गाडियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (Tempo के area of operation बढाने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १६

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) :

६१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी कर्मचारियों के लिए खोले गए Medical Stores में दवाइयों की कमी पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३

६२. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११—गाडियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (Tempo के area of operation को बढाने के प्रश्न पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १६

श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ) :

६३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामान्य नागरिकों को चिकित्सा सम्बन्धी कठिनाइयों व डाक्टरों की कमी की ओर ध्यान नहीं देने पर चर्चा के लिए) ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) :

६४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सालय और औषधालयों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३

६५. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११—गाडियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गाडियों के कर की वसूली में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) :

६६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (उनियारा नगर, जिला टोंक, के अस्पताल की अव्यवस्था एवं नर्सों की कमी होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा राम गढ) :

६७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था करने में सरकार असमर्थ रही है इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३

६८. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११—गाडियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गाडियों पर लगाये गये करों की वसूली में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १६

डा० पोहूमल ईसरदास (अजमेर-पश्चिम) :

६९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (होमियोपैथी पद्धति को प्रोत्साहन देने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

१००. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अजमेर के जनरल हॉस्पिटल में पूरी मात्रा में दवाई न होना तथा बिस्तरों की कमी पर चर्चा के लिए) ।

(श्री पोहूमल ईश्वरदास)

१०१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा औषधालयों को पूर्ण ग्रान्ट्स न दिये जाने के कारणों पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) :

१०२. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११—गाडियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गाडियों पर कर वसूली से विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

श्री मानधातासिंह (महुवा) :

१०३. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११—गाडियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गाडियों पर टैक्सों की वसूली में हो रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १६

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :

१०४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डाइरेक्टर चिकित्सा विभाग के पद पर स्थायी निवियुत नहीं किए जा सकने पर चर्चा के लिए)।

१०५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक में क्षय रोग से दस हजार व्यक्ति पीडित हैं, किन्तु समुचित व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

१०६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टोंक जिले में चिकित्सा विभाग की आम व्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३

१०७. मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११—गाडियों पर कर में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गाडियों पर अवैधानिक कर वसूल करने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १६

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाडा) :

१०८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर में औषधालयों की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

श्री जोधराजसिंह (गुढा) :

१०९. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला झुंझुनू के कई ग्रामों में औषधालय न खोलने पर चर्चा के लिए) ।

रावत श्री उम्मेदसिंह (बाडमेर) :

११०. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए कोई सलाहकार समिति (Advisory Committee) न होने पर चर्चा के लिए) ।

१११. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चलिष्णु शल्य चिकित्सा इकाई (Mobile Surgical unit) का कार्य सन्तोषजनक न होने पर चर्चा के लिए) ।

११२. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६—चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजकीय जिला स्तरीय अस्पताल बाडमेर में जनाना डाक्टर (Lady doctor) का स्थान रिक्त होने पर चर्चा के लिए) ।

Page No. 45

(रावत श्री उम्मेदसिंह)

११३. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आइसोलेशन अस्पताल, जयपुर की सुचारू व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए) ।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) :

११४. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा राजगढ़ जिला अलवर में **x-ray** **plant** व आपरेशन थियेटर को आवश्यक सामान नहीं दिए जाने पर चर्चा के लिए) ।

११५. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजगढ़ के पुरुषों के अस्पताल की दुर्दशा पर चर्चा के लिए) ।

११६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा राजगढ़, जिला अलवर में चोथी पंच-वर्षीय योजना में भवन होते हुए ५० बेडों वाले अस्पताल खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़) :

११७. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

श्री जगनसिंह (दांतारामगढ़) :

११८. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में डाक्टरों के स्थानान्तरण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

११६. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सा विभाग में व्याप्त निष्क्रियता एवं अव्यवस्था पर चर्चा के लिए) ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : **अध्यक्ष** महोदय, मांग संख्या **१६**, मुख्य शीर्षक २६-पर मेरा कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है:

"मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (चिकित्सालयों में डाक्टरों के अभाव पर चर्चा के लिये) ।"

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य का मतलब तो बहुत ही वृहत है कि आज के युग में गांवों में गरीब लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है । आवश्यकता तो इस बात की थी, अध्यक्ष महोदय, कि आज इस युग में जब हम प्रजातन्त्र के युग में चल रहे हैं, अमीर और गरीब, मजदूर और किसान सब को समान रूप से सरकारी औषधालयों में उचित उपचार की व्यवस्था प्राप्त हो । परन्तु इसके विपरीत राजकीय औषधालयों में इलाज उनका होता है, उपचार की प्राथमिकता उन लोगों को मिलती है जो या तो उच्च अधिकारी वर्ग के लोग हों या कोई नेता लोग हों या फिर उनके कृपा पात्र हों । आज गरीब और साधारण जन समुदाय को सरकारी औषधालयों में उचित उपचार की व्यवस्था नहीं है । अध्यक्ष महोदय, सरकार का कर्तव्य है कि जितनी चिन्ता वह अन्न, जल और शिक्षा को विकसित करने के लिये करती है उतनी ही चिन्ता आपको अपनी जनता के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये करनी चाहिये । मगर मुझे दुख है कि हमारी सरकार इस बात की चिन्ता नहीं करती और सबसे अधिक दुःख इस बात के लिये है

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

कि प्रसुतिगृहों की सबसे अधिक उपेक्षा की गई है। अधिकांश नवजात शिशु और महिलाएं प्रसुतिगृह न होने से, जो उनको आवश्यक मेडिकल एड मिलनी चाहिये इसके न मिलने से, उस मेडिकल एड के अभाव में, कई महिलाएं और शिशु अकाल मृत्यु क शिकार होते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज हम कहते हैं कि खाद्यान्न समस्या बड़ी जटिल हो गई है, इसलिये अधिक अन्न उत्पादन होना चाहिये और युद्ध स्तर पर वह कार्य करना चाहिए मगर मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि शहरों में रहने वाले लोग अन्न उत्पादन नहीं करते। अन्न तो किसान और ग्रामीण महिलाएं ही उत्पादन करती हैं। जिस समय वे बीमार हो जाती हैं, उनके स्वास्थ्य और चिकित्सा का उनको कोई लाभ नहीं मिले तो वे फिर किस प्रकार से अन्न उत्पादन करेंगी? इसलिये अन्न की समस्या को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये आपने क्या उपाय किया है? मुझे कभी ऐसा लगता है और विशेष रूप से प्रसूतिगृहों के लिये कि आपका कोई इन्तजाम नहीं है और वह अभाव शूल के समान खटकता है। मैं तो यह कहूंगी कि यहां पर भी जो प्रसुतिगृह हैं वे भी पर्याप्त नहीं हैं। मुझे बीच में यह सूचना मिली थी कि जयपुर में जो जनाना हॉस्पिटल है उसमें इतनी भीड़ रहती है कि डिलीवरी के लिये एडमिशन नहीं मिलता और अध्यक्ष महोदय, इस दिक्कत की वजह से कई केसेज में लोगों को बड़ी तकलीफ रही और ऐसी स्थिति भी आई जिसमें लॉन पर बच्चे पैदा हुए। तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहूंगी, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि इन अस्पतालों की हालत ठीक हो और ग्रामीण महिलाओं के बारे में आपको विशेष ध्यान देना चाहिये। प्रसूतिगृह शहरों में खोलने से पहले आपको ऐसे स्थानों पर खोलना चाहिये जहां पर ग्रामीण जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। गांवों में वे ही पुरानी दाइयें हैं, उनके पास न कोई इन्सट्रूमेन्ट्स हैं और न वे उनसे काम कर सकती हैं और वहां गांवों की वही हालत है जो पहले रही है।

अध्यक्ष महोदय, जो हमारे जनरल हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं वहां पर डाक्टरों का अभाव है। आप मेडिकल कालेज एक के बाद एक खोलते चले जा रहे हैं उसके बाद भी यह अभाव कम नहीं हो रहा है। इतना होने के बावजूद भी जब डाक्टरों के लिये सरकार से प्रार्थना करते हैं तो जवाब यह मिलता है कि डाक्टरों की कमी है। मैं एक बात और पूछना चाहती हूं कि यहां पर शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं इसमें डाक्टरों की भरमार है। यहां पर डाक्टरों की फौज खड़ी है उसमें से आप हटा कर जिस जगह डाक्टर नहीं हैं क्यों नहीं लगाते; किन्तु आप उनको यहां से हटा कर दूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वे बाहर जाना नहीं चाहते। कोई भी व्यक्ति अपना आराम छोड़ना नहीं चाहता। मैं यह कहूंगी कि उनको आराम की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। कोई भी डाक्टर जो नौकरी करते हैं उनका पहला कर्त्तव्य यह होता है कि वह नौकरी पहले करें। क्यों नहीं ऐसे डाक्टरों को जिनकी यहां पर अधिक संख्या है उनमें से हटा कर गांवों में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर पर, जहां अधिक जरूरत है, लगाते? मेरा यह भी सुझाव है कि नया डाक्टर जो भी निकलता है उससे सीनियर डाक्टर के पास ही रखकर ट्रेन्ड करिये और जो डाक्टर १० या १२ वर्षों के ट्रेन्ड हैं उसको ऐसी जगह

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

भेजा जावे कि वह गांवों में जाकर काम करें। जो बिल्कुल अनट्रेन्ड हों या नये ही तैयार हुए हों उन्हें गांवों में भेजेंगे तो उनको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं होती है, उन्होंने प्रेक्टिकल काम नहीं किया इसलिये हमें किसी की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं करवाना है। जो अनुभवी डाक्टर हैं उनको गांवों में और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं वहां पर भेजे जावें। आपको किसी भी तरह से यह कमी **दूर करनी होगी। अध्यक्ष महोदय, १८ वर्षों में अन्य विकास कार्यों के साथ साथ चिकित्सा की ओर ध्यान नहीं गया तो यह ठीक नहीं है,** बल्कि स्वतन्त्रता के समय में सरकार के लिये यह एक बुरी बात है।

में कहूं, माननीय मंत्री नाराज नहीं होंगे। शाहबाद में तीन वर्षों से कोई डाक्टर नहीं है। बारां से शाहबाद ४५ मील दूर है। उसके आस-पास के क्षेत्र में ५-६ डिस्पेन्सरीज हैं। एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है, मगर वहां पर भी डाक्टर नहीं। १२-१३ मील पर एक डिस्पेन्सरी है वहां का डाक्टर है। बारां में आकर इलाज कराना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, तीन साल से कोई डाक्टर नहीं है। कल हमारे उप गृह मंत्री जब सरकार की तरफ से बोल रहे थे यह निश्चित है और में कहना चाहती हूं कि मुझे अधिकारियों से यह जवाब सुनने को मिला है कि वहां पर कोई जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? वहां पर जंगल है, वह क्षेत्र शहर से दूर है। उनको वहां पर दूसरी सुविधाऐं नहीं मिलतीं जो शहरों में मिलती हैं। वह डकैतों का क्षेत्र है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कभी भी सरकारी कर्मचारियों के साथ कोई वारदात नहीं हुई है। डाकुओं से तकलीफ है तो वहां के निवासियों को है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों को एक बहाना मिल गया है डकैतों के नाम का। अध्यक्ष महोदय, वहां पर डाक्टरों के नहीं होने से कई लोगों की मृत्यु हुई। सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के आंकडे तो आपको उपलब्ध हो जाते हैं लेकिन ग्रामीणों की मृत्यु के आंकडे आपको उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं। मैं नम्र निवेदन करना चाहती हूं कि आप इसकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। शाहबाद तो एक मेरी जानकारी में है जहां पर डॉक्टर नहीं है। मैं समझती हूं कि राजस्थान में कई जगह ऐसी होंगी और वे आपकी जानकारी में होंगी। इसलिये आपको जल्दी से जल्दी इन केन्द्रों को प्रोत्साहन देना चाहिये जो गांवों के हैं और शहरों से दूर है।

अध्यक्ष महोदय, मेडिकल विभाग के यदि किसी कार्य की प्रसंशा की जाय तो वह है सर्जिकल मोबाइल यूनिट। मैं इसकी प्रसंशा करती हूं। जहां जहां इन्होंने कैम्प लगाये हजारों गरीब लोगों को सुविधाऐं मिलीं हैं। काफी पेशेन्स से उन्होंने काम किया है। इसलिए जिस तरह से सर्जिकल मोबाइल यूनिट लोगों को लाभ पहुंचाता है उसी तरह से मेडिकल विभाग को दूसरी ओर भी ध्यान देना चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी बात निवेदन करना चाहती हूं। कहना तो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन कभी-कभी किसी बात के लिये मजबूर भी हो जाना पड़ता है। किसी काम को यदि हम नजदीक होते हुए भी नहीं कर पाते हैं तो फिर दूर की बात के लिये तो हमें स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिये। जयपुर

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

में आगरा रोड पर शहर से बाहर निकलते ही एक लेपर हाउस है, कोढी रोगियों का अस्पताल है। मैंने खुद ने वहां जाकर देखा, काफी लोगों की चर्चाओं के बाद, वहां २६ मरीज हैं, उनकी हालत काफी खराब है। उनके हाथ और पांवों में कुष्ठ है और उनके गले हुए अंग हैं। मैं समझती हूं कि मंत्री महोदय शायद अपने उत्तर में इसका जवाब देना पसंद करें तो उत्तर दें। मेरी समझ में वार्षिक खर्चा उस पर लाखों की संख्या में होना चाहिये। वहां उनके क्वार्टर्स बने हुए हैं, इन्चार्ज डाक्टर का वहां रेजिडेन्शियल क्वार्टर बना हुआ है, कम्पाउन्डर का रेजिडेन्शियल क्वार्टर बना हुआ है। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो डाक्टर सक्सेना वहां इन्चार्ज हैं, मैं व्यक्तिगत नामों में पड़ना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे इससे तकलीफ होती है, किन्तु वह बताना भी आवश्यक है २४ घंटों में केवल आधे घंटे के लिये वहां पहुंचते हैं। रेजिडेन्शियल क्वार्टर मिलता है तो चौबीसों घंटे वहां रहना चाहिये, पर दिन में आधे घंटे के लिये पहुंचना कहां तक ठीक है? इस आधे घंटे में भी वह वहां क्या करते हैं, यह करते हैं कि वह गोलियां दे देते हैं, उन गोलियों को मरीज बांट लेते हैं। वे मरीज ड्रेसिंग अपने हाथ से करते हैं, एक मरीज दूसरे मरीज की ड्रेसिंग कर देता है। तो क्यों नहीं इन मरीजों में से ही किसी मरीज को कम्पाउन्डर की ट्रेनिंग दे कर उसे कम्पाउन्डर बना दिया जाता और डाक्टर को वहां से हटा कर इस खर्चे को खत्म कर दिया जाता, या क्यों नहीं डाक्टर को ड्यूटी से पाबन्द किया जाता? क्यों नहीं मेडिकल विभाग के अधिकारियों ने वहां जाकर उसे देखा? यहां का हास्पिटल भी जब आपसे नहीं सुधरता तो राजस्थान में दूसरी जगहों पर तो क्या आशा की जा सकती है। उन मरीजों के लिये जो खाना मिलता है, उस खाने को मैंने खुद ने देखा। २६ मरीज वहां पर हैं और उनके लिये जो सब्जी बनती है वह ८ आदमी खायें तो भी शायद कम हो, इतनी-सी सब्जी बनती है, कहां गई बाकी की सब्जी, कहां गई रोटियां, क्यों नहीं मिलतीं उन मरीजों को औषधियां? डॉक्टर साहब से पूछा तो कहा कि क्या करें, जो मिलता है वही देते हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति शायद जिनका आपने भी नाम सुना होगा, श्री बी. एल. अजमेरा, वे काफी सेवा-भावी हैं। उनको पता चला तो उन्होंने लेपर हाउस को देखा और उन्होंने इस बात की कोशिश की कि व्यक्तिगत रूप से रोगियों की जितनी सेवा कर सकें करें। दो चार बार जाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि उन रोगियों के पैरों में तकलीफ होती है, वे चल नहीं सकते, उन्होंने सोचा कि इन रोगियों के लिये ऐसे जूते बनने चाहियें जिनसे कि इनको तकलीफ न हो और चल-फिर सकें। उन्होंने डॉक्टर सक्सेना से बात की तो उन्होंने कहा कि ओफिशियली तो इसके लिये खर्चा नहीं है, तो इस पर श्री अजमेरा ने ४०० रुपया डॉक्टर साहब को दिया और कहा कि इन मरीजों के लिये ऐसे जूते बनवा दीजिये। अध्यक्ष महोदय, अगर डॉक्टर की जानकारी में है कि आॅफिशियली ऐसा काम नहीं कर सकते तो उन्हें ऐसे मामले में नहीं पड़ना चाहिये और रुपया नहीं लेना चाहिये था, पर आज ६ महीने होने को आये रुपये दिये हुए, जब कि कहा गया था कि एक दो महीने में जूते पहुंचा देंगे, पर आज तो

(श्रीमती नगेन्द्र बाला)

नहीं पहुंचाये हैं। विभाग की ओर से कुछ किया नहीं जाता, सच्चे दिल से कोई करना चाहे तो उसे मौका नहीं दिया जाता। मैं यह बात क्यों कहना चाहती हूं? मैं इस लिये यह बात कहना चाहती हूं कि मैंने मंत्री महोदय से भी एक चिट्ठी लिख कर निवेदन किया था; मंत्री महोदय के साथ जुबानी बात-चीत करने का समय नहीं मिला, बात-चीत करने का समय मिलता तो शायद अवश्य वे इसे देखते। मैंने चिट्ठी में लिखा था कि आप इस लेपर हाउस की सरप्राइज विजिट अवश्य कर लें। पर शायद उन्हें समय नहीं मिल पाया, अब भी वे इसे अवश्य देखें।

श्री अजमेरा ने इसके बाद बार-बार डॉक्टर सक्सेना को लेटर लिखा और पूछा कि आखिर मरीजों के लिये जूते बनवाने के बारे में क्या व्यवस्था हो रही है, हमने तो मरीजों की तकलीफ को दूर करने की वजह से पैसा दिया था। डॉक्टर एक दूसरे पर इसे टालते रहे—ऑरथोपेडिक्स में एक डॉक्टर हैं कासलीवाल उन्होंने कहा कि हम ऑफिशियली ऐसा कर नहीं सकते। श्री अजमेरा ने कहा कि आप वह रुपया वापिस दे दीजिये, जब जूते बन जाएं और रकम की आवश्यकता होगी तुरन्त आपको वापस भेज दिया जाएगा, किन्तु इस पर डॉक्टर कासलीवाल का जवाब मिला कि अगर आप ऐसी बात करेंगे तो यह लेपर हाउस बन्द हो जायगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात क्यों कहना चाहती थी? आगरा रोड, मेन रोड है ज्यों ही हम शहर से बाहर निकलते हैं वहां ठीक रोड से लगा हुआ यह हॉस्पिटल बना हुआ है। जो विजिटर्स बाहर से आते हैं, खास तौर से जो फोरनर्स आते हैं, जो सब से ज्यादा इस बीमारी से डरते हैं और चौकते हैं, उनकी निगाह इस हॉस्पिटल के सामने लिखे बोर्ड पर पड़ती है। विभाग को चाहिये कि या तो वहां से इस हॉस्पिटल को हटा लें या ऐसी जगह रखें जहां से आने वाले विजिटर्स की निगाह में नहीं आवे, या इसमें आवश्यक समुचित प्रबन्ध करना चाहिये। जयपुर शहर में देखते हैं तो हजारों लेप्रोसी के मरीज पड़े होंगे, इन सबके लिये व्यवस्था नहीं कर पाते तो इसे खत्म कर दीजिये, इस खर्च को कम कर दीजिये, दूसरी जगह चले जावेंगे।

अध्यक्ष महोदय, लेडी डॉक्टर्स की कमी भी एक बहुत गम्भीर विचारणीय विषय है। जहां जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खुले हैं, उन सेन्टर्स पर एक लेडी डॉक्टर का होना आवश्यक है। एक मिडवाइफ की व्यवस्था भी हो जब तक प्रसूतिगृह वहां स्थापित नहीं कर सकते तब तक इस व्यवस्था से सहायता मिल सकती है, हालांकि प्रसूतिगृहों को प्राथमिकता देनी चाहिये पर वह अर्थाभाव के कारण जब तक नहीं कर सकें तब तक के लिये ऐसे केन्द्र पर एक लेडी डॉक्टर उपलब्ध हो, एक मिड वाइफ उपलब्ध हो तो यह समस्या कुछ अंशों में हल हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, एक बार मैं इन नितान्त आवश्यक बातों को दोहराना चाहूंगी कि गांवों में जहां दूर-दूर तक शहर पास में नहीं है वहां डॉक्टर्स का प्रबन्ध किया जाय, शहाबाद में तीन साल से डॉक्टर नहीं है, वहां पर डॉक्टर की व्यवस्था की जाय। प्रसूतिगृह खोले जायं, लेडीज हॉस्पिटल्स में सफाई आदि की समुचित व्यवस्था की जाय। जयपुर के नजदीक

Page No. 50

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)
हॉस्पिटल की मैंने चर्चा की, मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय स्वयं एक दफा विजिट करें। हस्पताल का मतलब यह है कि आसपास का वातावरण ऐसा होता है कि उतनी सफाई और शुद्धता, स्वच्छता लोग नहीं रख सकते इसलिये मरीज को हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं, पर हॉस्पिटल की यह हालत हो गई है कि स्वस्थ व्यक्ति वहां किसी मरीज से मिलने के लिये, मरीज को पूछने के लिये जाय तो बीमार हो जाय। वहां आस-पास में गंदगी, कीचड़, जाले छाये हुए हैं, यह साधारण बात है। फोर्थ क्लास सर्वेन्ट एक की जगह दो कर दें तो गरीबों को काम मिल जायेगा और सफाई हो जायेगी। अधिकारी डॉक्टर से बात करते हैं कि सफाई क्यों नहीं है तो कहते हैं कि सरकार है आपको पैसा नहीं है व्यवस्था नहीं है। यह और सुनना पड़ता है।

इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि मेडिकल विभाग को पाबन्द किया जाय कि कम से कम स्वच्छता की तरफ ध्यान दे ताकि कोई आदमी पूछने जाय तो वह बीमार नहीं हो जाय।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासिंह।

श्री गंगासिंह (जायल) : अध्यक्ष महोदय, इन १५-१६ सालों में चिकित्सा में बढ़ोतरी हुई है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। किन्तु साइन्स के डेवलपमेन्ट को ध्यान में रखते हुए तथा दूसरे राज्यों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, तथा संसार में मेडिकल साइन्स में जो डेवलपमेन्ट हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए विचार करें तो इस राज्य में चिकित्सा का सुचारू रूप से प्रचार नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जयपुर को ही लीजिये, जयपुर राजधानी होने के नाते यहां सब प्रकार के रोगों की दवाइयां मिलनी चाहियें पर यहां सब रोगों की दवाइयां नहीं मिलती हैं। यहां पर अगर देखा जाय तो जो सुविधाएं जिन रोगियों को मिलनी चाहियें, उन रोगियों को वह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। एक्सपर्टस की भी कमी यहां महसूस की जा रही है। जहां तक डिस्ट्रिक्ट्स का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट्स में तो देखा जाय तो सिर्फ मामूली अस्पतालों के सिवाय सब अस्पतालों में चिकित्सा की कमियां महसूस करेंगे।

इस जिले की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नागौर जिला डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है, वहां मुख्य अस्पताल है, वहां पर अभी तक कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, यहां तक कि इस जिले के अंदर जहां रिप्रेजेंटेशन केबीनेट के लिहाज से जहां दो-दो, तीन-तीन मंत्री हों और वहां के जिला हैडक्वार्टर पर कोई लेडी डॉक्टर का इंतजाम न हो सके, यह कहां तक प्रशसंनीय है, यह मंत्री महोदय जान सकते हैं।

इस जिले के अंदर जो अस्पताल बने हुए हैं, सभी अस्पतालों में अभी डॉक्टर तक नहीं पहुंचा है। कठौती गांव में जो अस्पताल है वह रूरल एरिया में है, जहां पर काफी रोगी आते हैं और वेडरूम्स तो प्रोवाइड किए गए हैं तीन साल से, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है। यहां पर जल्दी से जल्दी कोई डॉक्टर भेजने की व्यवस्था करवाएं।

(श्री गंगासिंह)

इसके साथ आपका ध्यान कुछ मुद्दों पर दिलाऊंगा जो डाक्टर लोग इन्जरी रिपोर्ट्स देते हैं, वे काफी हद तक गलत देते हैं यहां तक कि उनको साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अदालतों में इस तरह के रिमार्क्स भी कहीं कहीं आते हैं कि इन्जुरी रिपोर्ट कन्फ्लिक्टिंग आती हैं और संशय पैदा करती हैं। वे ऐसी रिपोर्ट देते हैं कि अदालतों या इन्क्वायरी में साबित न हो सकें और यह डॉक्टरों का ट्रेन्ड हो गया है कि वे झूठी इन्जुअरी रिपोर्ट देते हैं। इसलिए ऐसे ट्रेन्ड को आप दबाएं, नहीं तो लोगों को न्याय मिलना मुश्किल हो जायगा।

जायल भी तहसील हैडक्वार्टर है और पंचायत हैडक्वार्टर है, यहां पर अस्पताल नहीं है। वहां के लोगों को ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी बहुत असुविधाएं होती हैं यहां तक कि अगर जायल में कोई सरकारी कर्मचारी रोगग्रस्त हो जाता है तो उसको नागौर तक आना पड़ता है। इसलिए कम से कम पंचायत समिति हैडक्वार्टर या तहसील हैडक्वार्टर पर कम से कम एक अस्पताल खोलने की जरूर व्यवस्था करें।

जो हमारी अस्पतालों के अन्दर गड़बड़ियां होती हैं उनके अन्दर दवाइयां सुव्यवस्थित रूप से रोगियों को नहीं मिलती हैं और जो दवाइयां आती हैं वे अस्पताल से ब्लैक मार्केट में जाती हैं और ब्लैक मार्केट से पैसे कमाए जाते हैं। कम से कम इसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाएं और जो दवाइयां अस्पताल में हैं वे रोगियों को ही मिलें।

जहां जिला हैडक्वार्टर है वहां कुछ ऐसी प्रथा सी हो गई है कि डाक्टरों के बीच आपस में तनातनी पैदा होती है। मैं इन दिनों की तो नहीं कह सकता, लेकिन पिछले एक साल में, करीब १०-१२ साल तक डाक्टरों का नागौर में आपस में झगड़ा रहा। एक डॉक्टर जिस मरीज को देख लेता था तो उस मरीज को दूसरा डाक्टर नहीं देखता था और आपस में गड़बड़ी होने के कारण मरीजों को काफी हद तक नुकसान हुआ। इस तरह की प्रथा नागौर में ही नहीं दूसरी जगहों पर भी है। इसके लिए डाक्टरों के अन्दर कुछ पार्टीबाजी न हो, इस सम्बन्ध में आपको व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

आयुर्वेद औषधालयों का जहां तक प्रश्न है, मैं समझता हूं कि उनका संगठन बराबर ठीक ढंग से नहीं हुआ है। हमारे जिले के अन्दर आयुर्वेद औषधालय जैसे बनने चाहिएं वे नहीं बने। हमारा बहुत बड़ा इलाका जो रेतीला हो गया है, २०-२० मील में कोई औषधालय नहीं, अस्पताल न होने के कारण मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि इन स्थानों के अन्दर जो बड़ा इलाका है वहां अस्पताल नहीं खोल सकते तो आयुर्वेद औषधालय ही ८-१० मील के एरिया में एक एक खोलने की व्यवस्था करें।

हमारे अस्पतालों के अन्दर रोगियों पर काफी ध्यान नहीं दिया जाता, उसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि कम से कम आपके डाक्टरों द्वारा हर रोगी को सुव्यवस्थित ढंग से देखना बहुत जरूरी हो जाता है। करीब मैं साल भर पहले की घटना बताता हूं कि नागौर में एक पागल कुत्ते ने एक आदमी को काटा। वह नागौर अस्पताल में आया था। डाक्टर ने कमजोर इंजेक्शन पांच सी० सी० का दे दिया, नतीजा क्या होता है, दस सी० सी० इंजेक्शन न देने के कारण उस आदमी में पागलपन

Page No. 52

(श्री गंगासिंह)
आ गया और थोड़े समय के बाद वह आदमी मर गया....

श्री अध्यक्ष : इंजेक्शन लगने के बाद मर गया ?

श्री गंगासिंह : जी हां। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब डॉक्टर को यह महसूस हो जाता है उसको पागल कुत्ते ने काटा है तो सही ढंग से उसका इलाज करते....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बागौर में पागल कुत्ते बहुत हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अभी तक तो हम मालपुरा में ही समझ रहे थे।

श्री मथुरादास माथुर : हमने सब जयपुर भेज दिए।

श्री अध्यक्ष : उनके काटे हुए भी हैं।

श्री गंगासिंह : अगर सही इंजेक्शन लग जाता तो इलाज हो जाता, परन्तु इस कमी के कारण, डॉक्टर की निग्लीजेंस के कारण, डॉक्टर पर इल्जाम लग गया और....

श्री दामोदरलाल व्यास (चिकित्सा मंत्री) : मरीज का नाम बताएं।

श्री गंगासिंह : मुझे मालूम नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सारी बात मुझे डिटेल में बताएं How am I to find out from my department.

श्री भैरोंसिंह : मरीज का नाम मुआलाल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जांच तो आप करें।

श्री गंगासिंह : राजस्थान के अन्दर प्रचलित बीमारी कैंसर है। राजस्थान में कुछ भी इलाज का प्रबंध नहीं है। यहां के रोगियों को बंबई आदि स्थानों पर जाना पड़ता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये जो नई तरह की बीमारियां आती हैं उन पर ध्यान दिया जाय और सुव्यवस्थित इंतजाम किया जाय।

जहां तक रोगियों को प्रयोगशालाओं का संबंध है, कम से कम जिला हेडक्वार्टर पर प्रयोगशाला खोलना आवश्यक है जिसके कारण लोगों को जयपुर जोधपुर में न आना पड़े।

श्री रविशंकर याज्ञिक (पिंडवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जनता को निःशुल्क शिक्षा और चिकित्सा प्रदान करना एक कल्याणकारी राज्य का पुनीत कर्त्तव्य होता है। मैं यह मानता हूं कि इस दिशा में शहरी क्षेत्रों में सरकार ने काफी प्रगति की है लेकिन जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का सवाल है, जितनी प्रगति होनी चाहिए, उतनी प्रगति सरकार ने नहीं की है। आबादी के अनुपात से देखा जाय तो चिकित्सा क्षेत्र में जितना पैसा सरकार शहरों में खर्च करती है उसका दसवां भाग भी गांवों के अन्दर नहीं खरचती है। आज गांवों में चिकित्सालयों की हालत यह है कि मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं जहां इस समय चार डिस्पेन्सरीज हैं उनमें से पिंडवाड़ा में डॉक्टर नहीं है, रोहेड़ा में नहीं है, नादिया में नहीं है। श्री दलपतसिंह के क्षेत्र में अनादरा के अंदर अस्पताल को १७ साल हो गए आज तक डॉक्टर नहीं आया, यह हालत गावों के अस्पतालों की है। यही नहीं, जो पैसा दवाइयों के लिए रखा जाता है वह इतना कम है कि फी व्यक्ति के पीछे साल में दो आना भी

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

खर्च नहीं किया जाता है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि उस तरफ आप ध्यान दें और कम से कम गांवों में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर डॉक्टर समय पर पहुंचा हो।

एक तरफ शहरों के अन्दर अस्पतालों में डॉक्टरों की भरमार रहती है। दूसरी तरफ दस दस साल तक गांव के एक छोटे से दवाखाने में डॉक्टर नहीं पहुंचता है तो, अध्यक्ष महोदय, आप ही सोचिये कि वहां की जनता की क्या हालत होती होगी।

मेरी तहसील में तीन दवाखाने हैं, अस्पताल हैं। एक लाख की आबादी है। रोहिडा के अन्दर डिस्पेन्सरी हैं उसका बजट केवल २८००) रु० और पिंडवाड़ा का बजट सिर्फ ३५००) का। आपही समझिये कि कुल पांच हजार की रकम में आप एक लाख की जनता में क्या सहायता पहुंचा सकते हैं? यही नहीं अध्यक्ष महोदय, रोहिडा ग्राम में एक दानवीर श्री हरिरामजी व्यास ने एक मेटरनिटी केन्द्र खुलवाया था। १५ हजार रुपया उन्होंने खर्च किया, बिल्डिंग बन गयी। डॉक्टर की मदद से बेडिंग की व्यवस्था भी करदी। लेकिन जब तक वहां क्वालिफाइड मिडवाइफ न हो यह बिल्डिंग और बेड बेकार पड़े रहते हैं। जिस व्यक्ति ने यह पैसा खर्चा हैं वह इसलिये खर्चा हैं कि वहां की जनता को औरतों की प्रसूति के समय सुविधा मिले। डिलिवरी केसेज का यह हाल होता हैं कि जब दस दस पन्द्रह पन्द्रह की तादाद में लोग सिरोही नहीं पहुंच सकते हैं तो उन औरतों की मृत्यु हो जाती हैं। इसलिये मेरा अब भी सरकार से पुर जोर निवेदन हैं कि रोहिडा मेटरनिटी अस्पताल में मिडवाइफ शीघ्र भेजें।

गांव में रेफ्रिजरेटर नहीं हैं। ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो रेफ्रिजरेटर में रखनी पड़ती हैं। जैसे पागल कुत्ता काटता हैं तो १४ दिन का कोर्स होता हैं। गांवों में पागल कुत्ते के केसेज ज्यादा होते हैं। भूला ग्राम का किसान

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): पागल कुत्ते सिरोही में ही होते हैं?

श्री रविशंकर याज्ञिक: आपके यहां भी बहुत हैं।

एक गांव के किसान के बच्चे को पागल कुत्ता काटता हैं तो वह अपने बच्चे को लेकर सिरोही जाय। थोड़े दिन वहां रहे, सौ दो सौ रुपये खर्च करे तो इलाज हो सकता हैं। मेरा सुझाव हैं कि जिस जगह गांव में डिस्पेन्सरी हैं वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं हैं तो वहां पर मिट्टी के तेल से चलने वाले रेफ्रिजरेटर दिये जाएं ताकि उनमें दवाइयां रखी जा सकें और जनता का अधिक फायदा हो सकता हैं।

अब मैं सिरोही अस्पताल के बारे में बोलता हूं। १८ वर्ष हुए सिरोही जिले की डिस्पेन्सरी के लिये उसकी व्यवस्था के लिये एक पैसा खर्च नहीं किया गया। बिल्डिंग की कमी हैं। बाहर से लोग आते हैं, ठहरने के लिये कोई व्यवस्था नहीं। लोग पेडों के नीचे सोते हैं। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, एक जिले के हैडक्वार्टर में आंखों के इलाज के लिये और दांतों के इलाज के लिये आई क्लिनिक और डेन्टल क्लिनिक की कोई व्यवस्था नहीं। होता क्या हैं, अध्यक्ष महोदय, वहां के लोग जोधपुर आने के बजाय पालनपुर गुजरात में जाते हैं। इससे उनके मानस पर बुरा असर पड़ता है। सिरोही इलाका फ्रन्टियर इलाका हैं। अगर सिरोही के अस्पताल और स्कूलों में वाजिब व्यवस्था

Page No. 54

(श्री रविशंकर याज्ञिक)

नहीं करते हैं तो पालनपुर में जाते हैं। वहां के लोग कहते हैं कि आबू को लेकर राजस्थान में क्या भला हुआ ? तो लोगों के मानस पर बुरा असर पड़ता है। सिरोही बोर्डर एरिया है, उसको देखते हुए वहां पर अस्पताल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिये। जब तक वह नहीं होती हैं तो लोग दुःखी होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं गत चार साल से देख रहा हूं कि जब टैक्स का सवाल आता है, सब टैक्स किसान क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जाते हैं। कभी कहते हैं ऊंट पर लगाओ, बकरी पर टैक्स लगाओ, पानी पर टैक्स लगाओ, घोघोडी पर टैक्स लगाओ। लेकिन जब खर्च करने का सवाल आता है तो ऐसा कहते हैं कि नहीं है। यह ऐसा क्यों कहते हैं ? मेरा सरकार से कहना है कि गरीब लोगों पर कृपा करके गांवों के अन्दर जो अव्यवस्था है अस्पतालों की उसको मिटाइये, अच्छा करिये और एक भी गांव में ऐसा अस्पताल न हो जहां कि डॉक्टर और मिडवाइफ न हो। रोहिडा के मेटरनिटी अस्पताल में कम से कम मिडवाइफ जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें।

श्री देवीलाल मीणा (सराडा-सु०) : अध्यक्ष महोदय, मेरे कट मोशन्स इस विषय में है कि सराडा तहसील में डॉक्टर की व्यवस्था नहीं होने से मरीजों को काफी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर झाडोल में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर भी खुला हुआ है लेकिन डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। उसके लिये उदयपुर जाना पड़ता है। बसों में जगह नहीं मिलती है। मरीजों को चार चार घंटे उसी हालत में रहना पड़ता है। मरीज उस स्थिति में मरने की हालत में हो जाता है। दो साल से बहुत अधिक मरीजों को उदयपुर में प्राइवेट जीपों द्वारा ले जाकर एडमिट कराया गया। सराडा में दो साल हो गये डॉक्टर भी नहीं, नर्स भी नहीं। औरतों के प्रसूति होती है तो कम से कम नर्स की जरूरत तो पड़ती ही है। वैसी हालत में औरतों को उदयपुर पहुंचने में मदद नहीं मिलती। इसलिये सराडा तहसील में डॉक्टर और नर्स को व्यवस्था होनी चाहिये। इसके लिये माननीय मंत्रीजी को आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि वहां पर जल्दी से जल्दी डॉक्टर और नर्स भेजने की व्यवस्था करनी चाहिये।

प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के सब सेन्टर खोलने की व्यवस्था है। दो साल हो गये लेकिन वे सेन्टर अब तक नहीं खुल पाये हैं। कोई व्यवस्था नहीं हुई है।

आयुर्वेद मंत्रीजी का ध्यान आपके द्वारा उस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं, कि वह पहाड़ी क्षेत्र है। वहां के लोग बड़े हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते हैं इसलिये देशी आयुर्वेदिक दवा लेकर वे अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। छोटी मोटी बीमारी के लिये आयुर्वेदिक औषधि गुणकारी भी अधिक है। पहाड़ी क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है। कोई खोलने की व्यवस्था नहीं है। मंत्री महोदय से भी कहा डाइरेक्टर साहब से कहा, लेकिन फिर भी, ध्यान नहीं दिया है। सरवर में औषधालय नहीं है, ढंकावाला में औषधालय नहीं है। बहुत बड़ी २ पाले हैं आदिवासियों की। दो दो ढाई ढाई हजार की आबादी है लेकिन कोई औषधालय नहीं है। सेमारी क्षेत्र में मिलाकर २५ हजार की जन संख्या है। आयुर्वेद का एक औषधालय है। गत वर्ष आयुर्वेद मंत्रीजी ने माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने उन्होंने

(श्री देवीलाल मीणा)

घोषणा की कि बी श्रेणी का कर दिया जावेगा और दो हजार रुपया भवन निर्माण के लिये दिया जावेगा। डाइरेक्टर साहब से कहा था कि इसको बी श्रेणी का कर दिया जाय, काफी मरीज आते हैं, लेकिन आज तक मंत्रीजी और विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिये पहाड़ी इलाका होने से भी गरीबों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाय।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन-सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुर्वेद के संबंध में कटौती के प्रस्ताव हैं।

वैसे चिकित्सा के बारे में मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा। स्वास्थ्य के लिये चिकित्सा का होना अत्यंत आवश्यक है; जिसका स्वास्थ्य ठीक है वह सब काम करने के लिये ठीक रहेगा। हमारी सरकार ने कुछ योजना बनायी है। वह योजना यह है कि सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल स्टोर्स से दवाइयां मिलेंगी; वह इसलिये किया गया कि पहले जो भ्रष्टाचार होता था उसको रोकने के लिये यह किया गया उसके साथ साथ इस योजना के अन्दर तीन मेडिकल स्टोर्स खोले जाने वाले थे उनमें से केवल दो ही स्टोर्स खोले गये हैं वहां पर हालत यह है कि वह स्टोर सुबह आठ बजे से सायंकाल ६ बजे तक खुला रहता है। शाम के ६ बजे के बाद वह बन्द हो जाता है। ऐसी सूरत में जो कर्मचारी वहां दवाई लेने जाते हैं उनको दो-दो घंटा क्यू में लगना पड़ता है, तब कहीं जाकर उनको दवा मिल पाती है। माननीय अध्यक्ष बीमारी का पता नहीं पड़ता कि किस समय बीमारी आ जाय; जैसे आज हार्ट फेल की बीमारी चली है, उसका एक दम उपचार नहीं किया जाय तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज इस बीमारी का व्यक्ति यदि स्टोर में दवा के लिये खड़ा हो जाता है और उसका दो घंटे के बाद नम्बर आता है तो उस समय में उसका प्राण निकल सकता है। इसलिये ऐसे स्टोर्स से जहां बीमार को दवाई लेने के लिये घंटों खड़ा रहना पड़ता है, उससे क्या लाभ है ?

इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, मान लो कोई आदमी रात्रि के समय अचानक बीमार हो जाता है तो उसको इन स्टोर्स से दवाई नहीं मिल सकती और दूसरी जगह से तब तक नहीं ला सकता जब तक कि उसको एन० ए० सी० नहीं मिल जाता। आपने जो योजना के तहत सरकारी स्टोर्स खोले हैं उन स्टोर्स से सरकारी कर्मचारियों को जिस प्रकार से परेशानी होती है, दो दो घंटे क्यू में खड़ा रहना पड़ता है इससे बड़ी दिक्कतें होती हैं, इसके सिवाय सुबह ८ बजे से शाम को ६ बजे के अलावा दवाई नहीं मिलती हैं; यह सरकार की नीति ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारे हिन्डोन में काफी पुरानी स्टेट के समय की बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें प्राइमरी हैल्थ सेन्टर है, वहां की आबादी २५ हजार की है। वहां एक ही डॉक्टर, दो कम्पाउन्डर और ६ बेड हैं, वहां का डॉक्टर महीने में छः सात दिन इधर उधर टूर पर जाता है। डॉक्टर एक है, उसके टूर में जाने के कारण क्या होता है कि अनेक मरीज आ जाते हैं वहां एकत्र हो जाते हैं जो कम्पाउन्डर वहां होते हैं उनसे उनका इलाज नहीं होता उनसे मरीजों का सही उपचार होना चाहिये वह नहीं हो पाता।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार गांव में रहने वाले लोग यह भावना लेकर चलते हैं

(श्री श्रवणलाल)

कि हम सरकारी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, वहां ठीक इलाज हो सकता है, अच्छी देखभाल होगी। लेकिन जब यह आशा लेकर वह यहां आता है तो, उसको बैठने के लिए जगह नहीं, बैड की व्यवस्था नहीं इसके अलावा दवाइयां पूरी नहीं मिल पाती तो वह निराश होकर चला जाता है। अभी अभी हमारे मंत्री महोदय हिण्डोन पधारे थे। हमने वहां पर हमारे अस्पताल की जो आवश्यकता है वह उनको बतायी थी, वे वहां आश्वासन देकर आये कि एक डाक्टर और दस बेड्स बढ़ायेंगे। इस आश्वासन के अनुसार वे वहां के लिए एक डाक्टर बढ़ाने औषधियां आदि पहुंचाने की कृपा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ वहां पर छोटे छोटे गांवों के अन्दर दो तीन सेन्टर्स खोल रखे हैं। वे सेन्टर खोलने के लिए तो खोल दिये योजनाएं बना दी, लेकिन होता क्या है कि वहां पर कम्पाउन्डर बैठा हुआ है, नर्सेज बैठी हुई हैं, वे दवाइयों की इन्तजार करते हैं। मैंने कई जगह जाकर देखा है कि नर्सेज और कम्पाउन्डर्स बैठे रहते हैं। उनका कहना है कि दवाइयां जो छोटी मोटी होती है वे तो हम बांट देते हैं; लेकिन जिस प्रकार की दवाइयां भेजी जानी चाहिएं वे नहीं आती, सरकार से मेरा निवेदन है कि जनता के लिए उचित मात्रा में दवाइयां भेजकर उन लोगों को भी, जो गांवमें रहते हैं चिकित्सा की सुविधा प्रदान करेगी।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, सवाई मानसिंह अस्पताल में जो कम्पाउन्डर्स हैं उनमें से २७ को फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर कर दिया गया। जो पहले फर्स्ट ग्रेड में थे उनको सेकेन्ड ग्रेड में कर दिया गया, १२ फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर्स को दूसरी जगह लगा दिया गया है।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो व्यवस्था अच्छे ढंग से चल रही थी, दवाइयां जो पहले मिलती थीं कर्मचारियों को, आपकी जो यह योजना है, उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है।

कुछ कम्पाउन्डर्स ऐसे हैं जिनको जिस कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया गया है उनसे वह कार्य नहीं लिया जाता है। उनको ऐसी जगह लगा दिया है जिसकी उनको जानकारी नहीं और जो उस काम को जानते हैं उनको दूसरी जगह लगा रखा है। मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर निवेदन करूंगा कि मेडिकल स्टोर में ६ कम्पाउन्डर्स को लगा रखा है। स्टोर्स में २ किचन में २ मेंन्टल आफिस में २, बैन्डेज के अन्दर ४ जो व्यक्ति जिससे सम्बन्धित हैं उनको उस जगह न बैठाकर दूसरी जगह बैठा दिया है। यह किसी भी तरह से फायदे वाली बात नहीं हो सकती।

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर जितने भी प्रशिक्षण होते हैं। उनके इन्चार्ज जिनको बना रखा है वे ट्रेन्ड नहीं होते हैं। जब हमारे पास ट्रेन्ड मौजूद हैं, काफी पुराने कम्पाउन्डर्स मोजूद हैं तो अनट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स को कई सालों से एक जगह पर नियुक्त करना कहां तक उचित है?

हमारे मंत्री महोदय को सोचना चाहिए कि ट्रेन्ड कम्पाउन्डर के स्थान पर अनट्रेन्ड कम्पाउन्डर को बैठाने की क्या जरूरत है?

इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, आयुर्वेदिक औषधालयों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री श्रवणलाल)

आयुर्वेद विभाग के अन्दर सिवाय वैद्यों को ट्रान्सफर के इधर उधर लड़ाने के सिवाय इस विभाग के अन्दर कोई काम नहीं। इस का एक नमूना मैं आपके सामने रखूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से एक बात जानना चाहूंगा कि आपकी जानकारी में ऐसे कम्पाउन्डर्स हैं जो ट्रेन्ड हैं और सर्विस में नहीं हैं।

श्री श्रवणलाल : वे अनट्रेन्ड हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : ट्रेन्ड कम्पाउन्डर्स ऐसे हैं क्या जो सर्विस में नहीं हैं ?

श्री श्रवणलाल : सर्विस में हैं, लेकिन एक ही जगह जिनको कई सालों से लगा रखा है।

मैं कह रहा था कि आयुर्वेद विभाग ऐसा है जिसमें अनेकों घटनाऐं ऐसी मिलेगी कि जिनमें एक वैद्य का एक जगह से दूसरी, तीसरी और चौथी जगह तबादला हो जाना आम बात है। धांधली बाजी चलती रहती है। एक घटना का उल्लेख मैं कर देता हूं अपने यहां की। १२-७-६३ को एक वैद्य का ट्रान्सफर शेरपुर किया गया और शेरपुर वाले का वहां। शेरपुर गया तो वहां वाले ने चार्ज नहीं दिया, बल्कि इन्सपेक्टर से मिल मिलाकर अपना ट्रान्सफर कैन्सिल करवा दिया। अब वापिस वह वैद्य शेरपुर आता है तो उसे वहां भी चार्ज नहीं मिला। जब वहां गया तो उसे आसानी से चार्ज नहीं मिला, इन्सपेक्टर से कहा-सुनी करने पर मिला। पर दो महिने बाद उसने ऊपर से मिल मिलाकर कैन्सिल करवा दिया। वह वापिस चार्ज देने आया तो उसने भी सोचा कि इसने मुझे हैरान किया तो मैं भी इसको हैरान करूं। उसने भी उसे चार्ज देने में आना कानी की। इस बीच वह बिचारा कहीं एक दो दिन की छुट्टी पर गया तो उधर वह इन्सपेक्टर के जरिये वहां का चार्ज ले लेता है। अब छुट्टी से वापिस आने पर देखता है कि वह तो चार्ज लेकर बैठ गया है। वह इन्सपेक्टर के पास जाता है, कहता है, ऐसा कैसे हुआ; इन्सपेक्टर कहता है मुझे तो पता ही नहीं। फिर कहता है यहां तो ऐसा ही चलता रहता है। अब वह अपने उधर गया तो वहां भी चार्ज नहीं मिलता है उसको।

अध्यक्ष महोदय, वह आज मारा मारा फिरता है। इन्सपेक्टर के यहां से डाइरेक्टर के यहां पहुंचता है। पंचायत से सर्टीफिकेट भेजता है। आता है जाता है, फिरता है पर उसे चार्ज नहीं मिलता। यही नहीं, उसे इस तरह करते करते आठ महीने हो जाते हैं, और तनख्वाह भी नहीं मिलती है। इसके बाद क्या होता है कि उसका ट्रान्सफर फिर किसी दूसरी जगह किया जाता है। यह हालत है इस विभाग की।

श्री दौलतराम सारण : क्या नाम है उस वैद्य का ?

श्री श्रवणलाल : बद्रीप्रसाद। तो इन बातों की तरफ मंत्री लोग भी ध्यान नहीं देते। डाइरेक्टर साहब का तो कहना ही क्या है ? मंत्रीजी कहें तो डाइरेक्टर नहीं मानते, डाइरेक्टर कहें तो मंत्रीजी नहीं मानते। दोनों में विवाद चलता रहता है।

श्री भीमसेन : डाइरेक्टर और मंत्रीजी के बीच में सेक्रेटरी और है।

श्री श्रवणलाल : सेक्रेटरी की भी वहां नहीं चलती।

Page No. 58

(श्री श्रवणलाल)

महावीरजी में हेल्थ सेन्टर है। बहुत यात्री दूर दूर से आते हैं, अच्छा कस्वा है। जहां की जनसंख्या भी अधिक है। पर दवाइयों को देखते हुए इतनी कम दवाइयों का उपयोग किया जाता है जो नहीं के बराबर है।

आशा है वहां दवाइयों का अधिक से अधिक उपयोग करने की कृपा करेंगे।

श्री मूलचन्द चौधरी (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १६ पर मेरा कटौती प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, दौसा में डॉक्टर एक इन्जेक्शन लगाने का करीबन दो तीन रुपया लेता है जब कि इन्जेक्शन की कीमत १ या १॥ रु० हो और खुद के पास से लगाता है। फिर इन्जेक्शन लगाकर कहता है कि बाजार में से दवाइयां लेकर आओ। तो ऐसा अन्याय हो रहा है और बाहर से आने वाले मरीजों के साथ सौतेला व्यवहार कर रखा है। गरीब किसान-मजदूरों का कोई भी इलाज नहीं होता वहां। एक बार आलूदा का एक किसान साथ लेकर मैं गया। पर उसके लिये कह दिया कि इसका इलाज नहीं करूंगा।

तो श्रीमान अध्यक्ष महोदय, उस मरीज को डी० एम० एच० ओ० के पास ले गया। उनकी चिट्ठी लेकर बड़े अस्पताल आया। उसके ११ टांके लगे। ऐसा अन्याय हो रहा है। ऐसे मरीज की भी वे देखभाल नहीं करते। तो ऐसे डॉक्टरों का वहां रखना वाजिब नहीं है, सेवाभावी डॉक्टर को आप वहां भेजें। छोटी छोटी समस्याएं ऐसी कर रखी हैं कि गरीब किसान आता है तो उसकी ओर ध्यान नहीं देते। यह बड़े दुःख की और शर्म की बात है।

अब डी० एम० एच० ओ० का दफ्तर का ट्रान्सफर वहां से होने के आदेश हो गये हैं। यह ठीक नहीं है। यह दफ्तर वहां रहना चाहिये।

एक्सरे की एक मशीन वहां पर है। पन्द्रह हजार की मशीन है, पर बेकार पड़ी है। उसे सुधारकर ठीक करना चाहिये।

१६ हजार की आबादी है, किसानों का क्षेत्र है इस वजह से प्रार्थना है कि इन बातों पर मन्त्री महोदय जल्दी से जल्दी ध्यान देकर वहां की हालत को सुधारने की कृपा करें।

श्रीमती सुमित्रा (झुन्झुनू) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव है; सरकारी मेडिकल स्टोरों पर दवाइयां पूरी तरह से नहीं मिल पाने पर चर्चा करने के बाबत।

वैसे तो एक माननीय सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। उन्होंने भी इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला है। परन्तु मैं भी इस बारे में इसकी अहमियत को देखते हुए कुछ निवेदन करना आवश्यक समझती हूं। जयपुर शहर की पांच लाख जनता के लिये जो सिर्फ तीन मेडिकल स्टोर्स सरकार द्वारा खोले गये हैं वे यहां की जन संख्या को देखते हुए बहुत कम हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि मेडिकल स्टोर जो ये हैं केवल सरकारी कर्मचारियों के लिये हैं, पांच लाख जनता के लिये नहीं हैं।

श्रीमती सुमित्रा : इसके लिये धन्यवाद। मेरा मतलब यह है कि इन सरकारी स्टोरों पर जिस तरह की भीड होती है और जिस तरह से एक मामूली से मामूली दवा लेने के लिये भी तीन-तीन चार-चार घंटे वहां क्यू में लगकर

(श्रीमती सुमित्रा)

इन्तजार करने की परेशानी उठानी पड़ती है और फिर भी पूरी की पूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं, बल्कि औषधि-अभाव प्रमाणपत्र मिलता है, इसके बारे में निवेदन करना चाहती हूं।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि एक बीमार अपेन्डिसाइटिस से पीड़ित है अथवा कॉलिक पेन हो रहा है। चार घंटे तक लगातार स्टोर पर इन्तजार करने के बाद औषधि अभाव का प्रमाण-पत्र लेकर दूसरी दूकान से यदि कंथेडिन का इन्जेक्शन लाता है तो मैं समझती हूं कि जो थोडा सा भी मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं और जो मां-बाप अपने लड़के के दुःख दर्द का अनुभव करते हैं उस असह्य पीड़ा को देखने का, तो शायद वे भी इस व्यवस्था के कटु आलोचक बन जाते।

मैं यह भी कहना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, कि जो वहां पर अव्यवस्था चल रही है वह और भी दुःखदायी है बहुत कम दवाइयां वे उपलब्ध करा पाते हैं। चार-पांच घंटे इन्तजार करने के बाद भी औषधि-अभाव का ही प्रमाणपत्र मिल पाता है और आखिर में दवा वहीं बाजार से खरीदनी पड़ती है। तो वहां चार-पांच घन्टे अपने बरबाद करो और फिर बाजार में से जाकर दवा लाओ। इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि बीमार को इतनी देरी से दवा मिलने से उसकी क्या हालत हो सकती है? तो कहना यह चाहती हूं कि या तो आप उन स्टोरों से सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध कराए या उसे तुरन्त वहां से जवाब मिल जाया करे, औषधि-अभाव प्रमाण पत्र तुरन्त दे दिया जावे ताकि उसे चार-चार, पांच-पांच घंटे बरबाद न करने पड़े।

एक निवेदन और करना चाहती हूं कि जो व्यवस्था यह स्टोरों की है, वह आई०ए० एस० कर्मचारियों के लिये क्यों नहीं की गई? उनको इससे एग्जम्प्ट क्यों किया गया? वे किसी भी प्राइवेट दूकान से दवा खरीद सकते हैं और फिर उनके लिये यह भी आवश्यक नहीं कि जो आपकी लिस्ट में दवाएं हैं वही रिएम्बर्स हो, कोई भी दवा उनको रिएम्बर्स हो सकती है और नियमानुसार उसे वे रिएम्बर्स करवा सकते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य में यह भेदभाव क्यों? कम वेतन पाने वालों में और अधिक वेतन पाने वालों में इस प्रकार का अलग अलग भेदभरा वर्ताव क्यों? मैं समझती हूं, यह मानवीय दृष्टिकोण से भी अनुचित है।

मैं मानती हूं कि पहले जो व्यवस्था थी, उसमें कुछ लोग गड़बड़ी करते थे और झूंठे बिल बनाकर सरकार को नुकसान पहुंचाया करते थे। इसमें डॉक्टर लोग भी शामिल होते थे, दुकानदार भी शामिल होते थे। पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि उनके इस कुकृत्यों की सजा दूसरे कर्मचारियों को, जो निर्दोष हैं, ऐसा नहीं करते हैं, दी जाय। उनको आप पकड़ते और कठोर से कठोर सजा उनको देते। पर उन पर कोई कठोर कार्यवाही करने की अपनी असमर्थता के कारण और कुछ सरकारी पैसे के दुरुपयोग को बचाने की इच्छा के कारण इस प्रकार सारे ही निर्दोष कर्मचारियों को इस तरह की परेशानी में डालना कोई आपका सामाजिक न्याय नहीं है।

अतः बहुत ही विनम्रता के साथ मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह जो व्यवस्था लागू की है उसे सुधारने की बात सरकार सोचे और यह महसूस करने की कोशिश करे कि इसे जिस मंशा से लागू किया है उसे यह व्यवस्था कहां तक पूरा कर पाई है।

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा कि आई० ए० एस० अफसरों में और अन्य सामान्य कर्मचारियों में रिएम्बर्स करने में भेदभाव बरता जाता है, उनको स्टोर से दवा लेने का बन्धन नहीं है, और कोई भी दवा कहीं से भी ले लें तो वह सब रिएम्बर्स उनको हो जाती है, तो यह मैं कुछ समझा नहीं। मेरी जानकारी में तो ऐसा कोई भेदभाव नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : आप बता दीजिये कि क्या मेडिकल स्टोर से आई० सी० एस० या आई० ए० एस० अफसरों के लिये दवाइयां खरीदना जरूरी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बिलकुल जरूरी है। यहां तक कि मिनिस्टरों के लिये भी वहीं से लेना जरूरी है। वहां से बिना ली हुई दवा या वहां से बिना औषधि-अभाव-पत्र लिये खरीदी गई दवा रिएम्बर्स नहीं होती, उसमें चाहे अफसर हो या सामान्य कर्मचारी।

श्रीमती सुमित्रा : मिनिस्टरों के लिये हो सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको किसी ने गलत सूचना दे दी है। कोई अधिकारी हो, कोई मिनिस्टर हो; उसके लिये वहां से दवा लेना कतई जरूरी है। मैं कहता हूं न ....

श्रीमती सुमित्रा : आप यह भी स्पष्टीकरण कर दीजिये कि जो दवाइयां रिएम्बर्स होने योग्य दवाइयों की सूची में नहीं हैं, क्या उन दवाइयों को भी रिएम्बर्स करा लेने की छूट इन आई० ए० एस० अधिकारियों को नहीं है ? क्या वे कोई भी कहीं से दवा लेकर रिएम्बर्स करा सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर दूं : These medical facilities apply to all I.A.S. or otherwise.

श्रीमती सुमित्रा : आप फिर पूछ लीजिये। मेरी जानकारी जहां तक है आई० ए० एस० अधिकारियों के लिये कोई भी दवा रिएम्बर्स करा लेने की छूट है।

श्री अध्यक्ष : नियमानुसार, आपने यह कहा था शुरू में।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन कर दिया है काफी स्पष्ट रूप से।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : अध्यक्ष महोदय, अकसर गांवों में डॉक्टरों का अभाव है। कम्पाउन्डर लोग रहते हैं जो अच्छी तरह से चिकित्सा नहीं कर सकते।

गोनेर में डॉक्टर अवश्य है। पर डॉक्टर साहब १५-२०-२५ रोज छुट्टी पर गये तो पीछे कोई डॉक्टर नहीं रहा, तो कम्पाउन्डर साहब ठीक तरह से दवा न दे सके। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने डिस्पेन्सरियां खोली, दवाइयां भी थोड़ी बहुत दी, पर उनका भी उपयोग अगर डॉक्टर के अभाव में न हो सके तो फिर इस सब का क्या लाभ है जनता को ? तो किसी भी तरह से सरकार को डॉक्टरों का पूरा प्रबन्ध करना चाहिये।

दूसरी अर्ज यह है कि आयुर्वेद विभाग ने काफी औषधालय खोले, पर दवाइयां उन पर कतई नहीं हैं। मैं यहां तक कहूंगा मिनिस्टर साहब से कि वहां लवणभास्कर चूर्ण भी नहीं मिलता जो सस्ते से सस्ता होता है। शीतोपलादि चूर्ण का भी अभाव है।

Page No. 61

श्री दौलतराम सारण (उप-मंत्री, आयुर्वेद) : कौन से औषधालय में नहीं मिलता ?

श्री नाथूलाल करोल : किशनपोल बाजार में ।

एक माननीय सदस्य : उनके पेट की शिकायत है ।

श्री दौलतराम सारण : मैं अभी दख्वास्त कर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : पेट की शिकायत उनकी दूर करवाइये ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मन्त्रीजी (उपमन्त्री) को खुद को शिकायत है पेट की ।

श्री नाथूलाल करोल : तो मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं । चाकसू में दवाइयों का कतई अभाव है । निम्बोडिया में आपका औषधालय है, पर दवाइयां वहां पर भी जीरो है । मेरा नम्र निवेदन है कि दवाइयों की व्यवस्था औषधालयों में जरूर करानी चाहिये ।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव है आयुर्वेद पर । देहातों में ज्यादा से ज्यादा औषधालय खोलने के बारे में ।

अध्यक्ष महोदय, एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिये यह बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जायं और खास तौर से उन इलाकों में, जहां अस्पताल नहीं हैं, डिस्पेंसरियां भी नहीं हैं और बीस बीस मील के घेरे में कोई अस्पताल या औषधालय भी नहीं है । ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग आज आजादी के १९ साल, १९ साल बाद भी लोक-कल्याणकारी राज्य से प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं भी प्राप्त न कर पावें, यह हमारे लिये बड़ा शोचनीय विषय है ।

सरकार ने एक बात बताई कि उनका लक्ष्य है जिला हैड क्वार्टर पर 'अ' श्रेणी का औषधालय खोलने का, १४ हजार की जन संख्या पर ग्राम औषधालय, और आठ हजार की जन संख्या पर एक औषधालय खोलने का और यह सब तीसरी पंचवर्षीय योजना तक हो जावेगा, ऐसा कहा गया ।

अध्यक्ष महोदय, १४ हजार की जन संख्या पर एक औषधालय खोलने का मतलब है उस १४ हजार की आबादी के क्षेत्र में उस तरफ दस बारह गांवों का होना । आज जिस तरह का वह रेगिस्तानी एरिया है उसमें दस-दस, बारह-बारह मील दूरी पर एक-एक गांव मिलेगा । तो इस तरह से औषधालय खोलने का मतलब यह हुआ कि एक औषधालय से दवा लेने के लिये उस इलाके के एक किसान को बीस-बीस और पच्चीस-पच्चीस मील दूर जाना पड़ेगा । यह व्यवस्था हम उन किसान भाइयों के लिये कर रहे हैं जिनसे आज हम अपेक्षा करते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा अन्न हमारे लिये पैदा करें ।

अध्यक्ष महोदय, आज अर्बन एरिया में खास तौर से बड़े बड़े शहरों में, मैं समझता हूं, हो सकता है, कम व्यवस्था हो, पर फिर भी कह सकता हूं कि आज पर्याप्त रूप से अर्बन एरिया के नागरिक उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा रहे हैं । पर आज हमको इस बात पर विचार करना होगा कि यह अर्बन और रूरल का अन्तर हम कब तक बनाये रखेंगे ? यह भेदभाव हम कब मिटा पावेंगे ?

(श्री रावतराम)

आज हम रूरल और अर्बन एरिया से बराबर के टैक्स वसूल करते हैं, बल्कि शहरों में बसे लोगों से, किन्हीं माने में अधिक टैक्स गांव वालों से वसूल करते हैं ऐसी स्थिति में जहां चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की सुविधाएं हम उनको उनके अनुपात से नहीं दे सकें तो यह हमारी सरकार के लिये, क्या बताऊं, सरकार को खुद सोचना चाहिये और इसके लिये आगे कदम उठाने चाहियें।

जहां तक मैडिकल सुविधाओं का प्रश्न है, यह खर्चीली व्यवस्था है। इसके जरिये हम जल्दी से हर सामान्य नागरिक तक नहीं पहुंच सकते इतने गांवों में। पर जहां तक आयुर्वेदीय सुविधाओं का सवाल है वह हम कर सकते हैं, इसमें खर्च कम है और गांव के लोगों का मानस भी इसके अनुकूल है।

अब आयर्वेद के बजट से मेडिकल का बजट कई गुना अधिक है। ठीक है, मेडिकल में आज वैज्ञानिक खोज-शोध अधिक है। पर फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आयुर्वेद को यदि इसी तरह से अछूता छोड दिया गया तो हम आज गांवों में बसी हमारी अधिक से अधिक आबादी को चिकित्सा सम्बन्धी राहत नहीं दे पावेंगे। इस पर गहराई से सरकार को विचार करना है।

यह भी बताया गया कि राजस्थान के निर्माण के समय १०-११ लाख का आयुर्वेद का बजट था जो बढ़ कर आज एक करोड़ तक पहुंच गया है और इस तरह से आयुर्वेद आज दिनों दिन प्रगति करता जा रहा है। यह ठीक है। खुशी की बात है। पर फिर भी मैं समझता हूं हमारी विस्तृत आवश्यकताओं को देखते हुए यह बजट भी कम है। इस पर हमें सोचना होगा। और आगे आने वाली चौथी योजना में स्पष्ट दृष्टिकोण यह होना चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा गांव में आप औषधालय खोलें।

आज गांव में जहां शिक्षा के बारे में हम पांच सौ की आबादी तक पहुंच गये हैं वहां आयुर्वेद के औषधालय को भी हमें पांच सौ की आबादी तक पहुंचाना है। अगर इतना न कर सकें तो कम से कम एक हजार की आबादी के गांवों तक तो हमें चौथी योजना में औषधालय लेकर पहुंचना ही चाहिये। १४ हजार की आबादी को ही अभी तक आप कवर कर पाये हैं। यह भी आंकड़ों की बात है। वास्तव में आप इतना भी पहुंच पाये हैं या नहीं, यह मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे।

तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चौथी योजाना में सरकार मेरे इस सुझाव पर उदारता से विचार करे। यह विकासशील युग है। आज शहरों में लोगों को सारी चिकित्सा सुविधाएं, अच्छी से अच्छी, आधुनिकतर मेडिकल चिकित्सा-सुविधाएं उपलब्ध हैं तो क्या देहातों में रहने वाले किसान के लिये, जो रात-दिन हमारे लिये मेहनत करता है, हम आयुर्वेद की सुविधाएं भी नहीं दे पावेंगे।

चौथी योजना में आयुर्वेद के लिये कितना प्रोवीजन रखा है और क्या हम तब तक एक हजार की आबादी के गांव तक पहुंच पावेंगे या नहीं पहुंच पावेंगे, अथवा पहुंच पावेंगे तो कहां तक पहुंच पावेंगे, यह सब माननीय मन्त्री महोदय हमें बताने की कृपा करें। अगर हम यह कर पाये तो हम गांव के किसान की अधिक से अधिक सेवा कर सकेंगे और अभिमान के साथ यह भी कह सकेंगे कि गांव में और शहर में असमानता की बात नहीं की है हमने।

(श्री गवतराम)

आपने पंचायत समितियों में एक एक हेल्थ सेन्टर दिया है। मैं मानता हूं कि डॉक्टरों की कमी है। पर थोड़े दिन बाद वे भी मिलने लग जावेंगे। पर उनकी भी स्थिति आपको सुधारनी चाहिये। आज हालत यह है कि वर्षों से पंचायत समिति में मन्जूरी हो गई, पर डॉक्टर नहीं गया तो इस उपेक्षावृत्ति को भी जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिये। सरदार शहर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर तो रूरल एरिया में नहीं आता। सरकार जवाब दे कि कस्बे में ले जाकर क्यों स्थापित कर दिया? वहां ऑलरेडी था। १८७ गांव हैं। सरदार शहर में क्या आप प्राइमरी हेल्थ सेन्टर नहीं रख सकते?

कूप का सवाल है इसी तरह। पैसा गांव के लोगों से जमा करवा लिया, पर अभी तक लटकाये हुए हैं। पंचायत समिति ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास करके भी भेज दिया। सार्वजनिक संस्थाओं ने भी प्रस्ताव भेज दिये। तो इस तरह से गांव के लोगों के प्रति आप उपेक्षावृत्ति को दूर करें। उस गांव में लोगों ने दस हजार रुपया इकट्ठा किया। आप शहर के लोगों से एक पैसा भी नहीं मांगते। अगर चार लाख का भी खोल दें तो एक पैसा नहीं मांगते और गांव के लोगों से कहते हैं कि दस हजार लाओ। उन्होंने दस हजार जमा भी करवा दिया, पर अब भी आप लटका रहे हैं। तो इन सारी बातों की तरफ हमें ईमानदारी से सोचना चाहिये। हमें गांव और शहर के लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिये। सरकार को चाहिये कि गांव के लोगों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मिलें और समय पर मिलें। यह चौथी योजना में आप अवश्य सोचें।

(१.०० म. प.)

श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी चिकित्सा के सम्बन्ध में कट मोशन संख्या ३० है और खास तौर से सामान्य नागरिकों के उपचार के सम्बन्ध में है।

सबसे पहले अर्ज करूं कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं चित्तौड़गढ़ वहां के अस्पताल में डॉक्टरों की काफी कमी है और दवाइयों की भी कमी है।

वहां के स्थानीय नागरिकों ने हमारे मन्त्री महोदय के समक्ष एक रिप्रेजेन्टेशन के रूप में निवेदन भी किया है और मन्त्री महोदय ने आश्वासन भी दिया। पर वह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ।

कस्बों में डिस्पेन्सरियां हैं, पर दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। आम लोगों को सही तरीके से उपचार नहीं मिल पाता। अतः प्रार्थना है कि वहां पर भी कृपया डाक्टरों की और दवाइयों की जिला स्तर पर और देहाती कस्बों के स्तर पर जैसी होनी चाहिये, व्यवस्था करने की कृपा करें।

दूसरी बात बस्सी डिस्पेन्सरी के बारे में निवेदन कर दूं। ५२ में आपने यह खोली। ५० हजार की बिल्डिंग सरकार को भेंट की। आज ५२ से ६६ हो गया, एक पैसा भी सरकार ने उस बिल्डिंग के मेन्टीनेन्स में नहीं लगाया। दिनों दिन उसकी हालत खस्ता हो रही है, और इस बात की तो मुझे खुशी है कि इस साल उन्होंने २०,००० रुपये खर्च के लिये ऑर्डर किये हैं उसके परिवर्तन और परिवर्द्धन के सिलसिले में और वह रुपया समय समय पर लगाया जाये और वहां पर डॉक्टर और कम्पाउन्डर्स के रहने की व्यवस्था हो जाये तो

Page No. 64

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

ज्यादा अच्छा रहेगा। खास तौर से वहां पर पूरी दवाइयां मिले, क्योंकि वह २० हजार की जन संख्या को कवर करता है और अलावा में अर्ज करूं कि राज्य सरकार के वहां पर दो प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं; एक तो सावा में और दूसरा गंगराल में। सावा की हालत यह है कि वहां पर डॉक्टर नहीं हैं, मोटर नहीं, वहां के सब सेन्टर में मिडवाइफ नहीं है और न वह पूरा मकान ही बना है। किसी जगह मकान बन रहा है तो सरकारी चंदा अभी तक नहीं मिला है। गंगराल प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में भी यही हाल है। तो मैं आशा करूंगा कि सरकार उधर ध्यान देगी।

साथ ही साथ यह भी अर्ज करूंगा कि चिकित्सा बहुत भारी अहमियत रखता है जनजीवन के साथ में। यह एक तकनीकी बात है और उसमें विशेषतः मैं मोटे रूप से अर्ज करना चाहता हूं। उदयपुर में एक बार एक कैंसर का बीमार भरती हुआ सितम्बर, अक्टूबर में और उसका फिजिकल टैस्ट नहीं होते हुए भी उसका आपरेशन किया गया और ऑपरेशन करते करते बिजली गायब हो गई और ६ घन्टे के बाद में वह लाश ही ऑपरेशन थियेटर से बाहर निकली। यह वहां की व्यवस्था है। ऐसा सुना गया है कि उसका फिजिकल टैस्ट भी नहीं हुआ।

यह मेरी प्रार्थना है कि आम नागरिकों के साथ जो सहूलियतें और टैकनीकल तरीके से बर्ताव करना चाहिये वह आपका विभाग नहीं कर रहा है। मैं अर्ज करूं कि यहां के सवाई मानसिंह अस्पताल में मैंने खुदने अपने बच्चे को भर्ती कराया और १० दिन तक उसका एग्जामिनेशन हुआ और १० दिन में भी मुझे वह सहायता नहीं मिली कि उसका एक्स-रे तक हो पाता। और मुझे वह एक्स रे बाहर से करवाकर लाना पड़ा। हालांकि नियम था कि एम० एल० ए० के परिवार के लिये फैसिलीटी थी, लेकिन नहीं मिली, मेरा पर्सनल अनुभव है और यहां पर मेडिकल कॉलेज है। वहां के लड़के रोगियों के टैस्ट के लिये आते हैं और टैस्ट इस किस्म का करते हैं कि रोगी वफात पा जाता है।

मेरे सामने एक गरीब आदमी सीरियस कन्डीशन में था उसको नाकों में नालियां दे दी गई और उसको लैट्रीन में ले जाकर उसको मुर्दा बता कर अलग किया गया। इसी तरह से गरीब मरीजों के साथ जिम्मेदारी का व्यवहार होना चाहिए वह आपके अस्पतालों में नहीं होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य इसकी डिटेल दें कि कौन मरीज था, किस वार्ड में था ?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : यह डॉक्टर सरीन के वार्ड में था और यह सितम्बर अक्टूबर की बात है। और मेरे ख्याल से ६ या १० नम्बर के बेड में था। याद नहीं है पूरा।

श्री दामोदरलाल व्यास : अस्पताल में मरीज मरते भी हैं, इलाज भी होता है, लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं कि टैस्ट नहीं करने की वजह से मर गया वह क्या बात है ?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : मेरे अर्ज करने का मतलब था कि कॉलेज के लड़के टैस्ट के लिये आये थे। उन्होंने उस आदमी के नाक के अन्दर नलियां डालीं और वे चुपचाप बातें करने के लिए बैठ गए। वह वहीं मर गया और उसे लैट्रीन में ले जाकर मुर्दा बताया गया।

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

इसी तरह से मैं अर्ज करूं कि मेरा भाई उदयपुर में कैंसर के लिए भर्ती हुआ और उसका साधारण ऑपरेशन बता कर ऑपरेशन के लिए थियेटर में उसे दाखिल किया गया। १५ मिनट के बाद वहां की बिजली गायब हो गई और ६ घन्टे के बाद उनको बाहर निकाला गया, वह भी लाश को। वह डॉक्टर कोटा जो कि सीनियर नहीं थे और कैंसर का बॉम्बे में इलाज होता है, लेकिन उन्होंने साधारण खिलवाड़ जैसा कर उनकी जान के साथ खेल खेला है। दूसरे मैं निवेदन करूं कि चिकित्सा में सबसे बड़ा पैसा है। एक कहावत भी है :

"टका धर्म टका कर्म, टका ही परमं पदम्।
यस्य गृहे टका नास्ति, बिन टका टक टकायते।

जिसकी जेब में पैसा है उसको सही इलाज मिल जाता है और जिसकी जेब में पैसा नहीं है उसको ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि साधारण जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए, उनका ठीक ढंग से उपचार करने के लिए आपके विभाग के कर्मचारियों को पूरा ध्यान देना चाहिए कि साधारण गरीब आदमी किस प्रकार से उपचार पा रहा है। यह शिकायत करना भी मैं गुनाह मानता हूं क्योंकि यह नाजुक है हर जनजीवन के साथ इसका संबंध है और वह जनजीवन किस तरह से खतरे में है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए आपको पूरा ध्यान देना चाहिए।....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की जानकारी माननीय सदस्य से लेना चाहता हूं। इन्होंने दो ऐसे केसेज बताये; एक तो सितम्बर-अक्टूबर का और एक अपने खुद के भाई का, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी कहीं शिकायत की ताकि मैं जानकारी कर लूं कि उसका क्या हुआ ?

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : मैं पूरे ब्यौरे के साथ आपको बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : शिकायत सुनता है क्या कोई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : शिकायत कोई सुनता नहीं है, इसकी भी शिकायत की क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो इसलिए जानना चाहता था कि यदि शिकायत की होती तो मैं उसकी जानकारी कर लेता।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मिनिस्टर साहब बतावें कि शिकायत सुनी जाती है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सुनी जाती है, करने वाला हो तो।

श्री चतुर्भुज उपाध्याय : मैं आयुर्वेदिक अस्पताल के लिए भी जिक्र करना चाहता हूं। वहां कहीं वैद्य नहीं है, तो कहीं दवाइयां नहीं हैं। जैसे नगरी में वैद्यजी नहीं हैं और कहीं पर १० मील का एरिया खाली पड़ा है। लोग मकान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन डिस्पेन्सरी नहीं खोली जाती है। मैं आयुर्वेद मंत्री से कहूंगा कि हमने कई दिनों से प्रार्थना-पत्र भेजा है कि वहां पर अस्पताल खोलो। साथ ही साथ चिकित्सा बहुत ही नाजुक चीज है। यह जीवन के साथ संबंध रखती है। मैं लोक-कल्याणकारी राज्य के लिए यह आग्रह करके चलूंगा कि गरीब आदमी को सस्ते से सस्ता और जिम्मेदारी से इलाज दें। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री विजयपाल कटारा।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु०) : माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे सामने चिकित्सा के बारे में बहस चल रही है। मेरे पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने इस लोक कल्याण-कारी राज्य का अनुभव बताया। लेकिन मैं इसे लोक कल्याणकारी राज्य नहीं मानता। यह लोक कल्याण का ढिंढोरा पीटकर गरीबों से बहुमत प्राप्त करने के अलावा और कोई जरिया नहीं है। आज इस जनजीवन के लिए, जिन्दा रहने के लिए दवाइयों की सबसे बडी समस्या सामने आई है। गरीब अपनी दवाई पूरी तरह से नहीं करा सकता है। आज के युग में जिंदा रहने के लिए अगर किसी व्यक्ति के पास में पांच पैसे नहीं होंगे तो वह जिन्दा नहीं रह सकता। क्योंकि पैसे की आवश्यकता पग पग पर पडती है। जहां हम सबसे पहले दरवाजे पर पहुचते हैं वहीं एक चपरासी अपनी जब गरम करने की कोशिश करता है। अगर उसको हमने ५ रुपये या २ रुपये दे दिये तो हमें दरवाजे में प्रवेश करने का मौका मिलेगा वर्ना आप घन्टों लाइन में खडे रहेंगे। यह ऐसी घटनायें गरीबों के लिए बहुत बडी समस्यायें हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए लोक कल्याणकारी राज्य के अन्दर सस्ती दवाइयां मिलें और उनका फायदा मिले। लेकिन दवाइयां सस्ती नहीं मिल कर सबसे ज्यादा महंगी दवाई आज के काल में मिल रही है हम जो गांव के गरीब लोग हैं हमको २०-३० मील चलकर बडे अस्पताल के सामने पहुंचना पडता है। ऐसी सूरत में सरकार को एक व्यवस्था करनी चाहिए कि वहां पर जनसंख्या के आधार पर एक अच्छा सा दवाखाना खोला जाये। २०-३० रुपया उसके आने-जाने में खर्च हो जाता है। और जब अस्पताल में पहुंचेंगे तो डॉक्टर साहबान अपना ट्रीटमेंट शुरू करेंगे और ट्रीटमेंट के साथ में वह एक चिट्ठी कर देंगे कि आप दवाई को बाजार से ले आइए, मैं दिकल स्टोर से। हमारे अस्पतालों में जो दवाइयां होनी चाहिए वे नहीं हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार किस लिए है ? सरकार जनता के लिए है। गांधीजी ने इस देश को आजाद कराया है और आजाद कराने के बाद इस देश से चले गए। उसके बाद में आपने यह ढिंढोरा पीटा कि हम इस समाज के अन्दर, इस प्रजातंत्र के अन्दर लोगों को जिन्दा रखेंगे और लोक कल्याण के काम करेंगे और लोक कल्याण के अन्दर जनता की सुख सुविधा की देखभाल करेंगे। लेकिन जनता को आज कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सुविधा मिल रही है तो सिर्फ मिनिस्टरों को, एम० एल० एज० को, आइ० ए० एस० और आर० ए० एस० के अफसरों को मिली है। यह मीडियम वर्ग के लोग तो बिल्कुल तबाह हैं। आज आप फाइल उठा कर देख लीजिये, मीडियम वर्ग के लोगों को कितनी मेडिकल के नाम पर दवाई मिली है और उसका कितना पैसा दिया गया है। आज एक पैसा भी उनको नहीं मिला है। एक साल पहले एक प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछा गया था और सारे मध्यम वर्ग के आंकडों को मालूम किया था। उसके अन्दर एक भी मध्यम वर्ग के आदमी को, एक भी चपरासी को दवाई का पैसा नहीं मिला था और मध्यम वर्ग के किसी सरकारी अफसर ने कोई भी दवाइयों के नाम से पैसा नहीं उठाया था। वे पैसा क्यों नहीं उठा सके, क्योंकि यह गरीब आदमी डॉक्टर को फीस अदा नहीं कर सकते थे। रिश्वत के पांच प्रतिशत दवाइयों के नहीं दे सकते थे। इन सारी चीजों की व्यवस्था करने का और इन सारी बातों का ध्यान रखने

(श्री विजयपाल कटारा)

का अधिकार दिया था जनता ने आपको कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन आपका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जब एक राजा चोरी करता है तो प्रजा और नीचे के लोग भी चोरी करेंगे। आप तो पांच साल में अपना दिमाग इस तरह का बनाते हैं कि हमको किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव के लिये कितना पैसा इकट्ठा करना है। यह जो आपकी परम्परा है, यह जो आपकी परिपाटी है इसने ऐसा कर दिया है कि जनता जो है उसको जान खतरे में है। आपको जीपों का खर्चा मिल जाता है, आपको दवाइयों का खर्चा मिल जाता है, टी० ए० और डी० ए० का पैसा मिल जाता है, आपको वैपन्स का पैसा मिल जाता है। लेकिन जो गरीब आदमी हैं, गांवों में रहते हैं और खेतों में काम करते हैं उसके लिए सिर्फ खेती ही सहारा है उसकी सारी व्यवस्था खेती से ही होती है। खेती से जो पैसा कमाता है उसी से उसे दवाई खरीदनी पड़ती है मेडीकल स्टोर्स से जो कि उन गरीबों को मिलनी चाहिए सरकारी दफ्तरों से, सरकारी स्टोर से, लेकिन वह दवाई उसकी जान बचाने के लिए आप नहीं दे पाये हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह जो जन जीवन खतरे में दिन-ब-दिन पड़ता जा रहा है, इस खतरे से उनको बचाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अगर आपने इस खतरे से उनको नहीं बचाया तो हो सकता है कि आप तो डूबेंगे ही लेकिन जनता को भी लेकर डूबेंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि इन बातों पर सबसे पहले आपको सोचना चाहिए।

डूंगरपुर के बारे में मैं जब से आया हूं तब से कह रहा हूं कि वहां पर कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। वहां कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है। वहां तो सिर्फ एक डिस्पेन्सरी के रूप में बना रखा है जिला भर में। तो जब से आया हूं मैं तब से कह रहा हूं कि वहां पर मेडिकल की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये और लेडी डॉक्टर होनी चाहिए। क्योंकि आज के युग में महिलाओं को जान और महिलाओं की इज्जत बचाना है तो लेडी डाक्टर का होना आवश्यक है। लेडी डाक्टर नहीं होगी तो वे कैसे बच सकती हैं। लेडी डाक्टर का किसी भी अस्पताल में होना बहुत जरूरी है। मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने भी अभी-अभी जोर डाला है कि लेडी डाक्टर होना चाहिए उन्होंने भी लेडी डाक्टर पर जोर डाला है। लेकिन जब हम इस बात को लेकर बोलना चालू करते हैं तो मिनिस्टर साहब इधर उधर की बातें करके टाल देते हैं। लेकिन आज महिलाओं के साथ में और जनता के साथ में आज जिस तरह का बर्ताव होता है, जिस तरह का बर्ताव महिलाओं के साथ आपके डाक्टर लोग करते हैं, कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऊपर के पद पर बैठे हैं और आप ही इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप भी ज्यादा दिन यहां पर नहीं रह सकेंगे। आपको इन बातों की सबसे पहले चिन्ता रखनी चाहिए। आज होता क्या है कि आपको इसकी कोई चिन्ता नहीं है। आप तो नीचे के अफसरों को बता देते हैं कि अस्पताल की यह व्यवस्था कर दो, यह दवाई कर दो लेकिन आपके अधिकारी लोग कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। अगर आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आप यह राज छोड़ दें ताकि दूसरी पार्टी व्यवस्था कर सके। कुछ साल तक वे भी देख सकें, और कुछ काम कर सकें लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं।

Page No. 68

(श्री विजयपाल कटारा)

(१. ३६ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह उपाध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन आप तो यहां सोचते हैं कि जब हमने जूते खाकर राज लिया है तो दूसरी पार्टी को भी जब जूते मारेंगे तभी राज मिलेगा। यह तो समझते हैं कि जब तक इनके सामने संघर्ष नहीं होगा, उनके अच्छी तरह से जूते नहीं पड़ेंगे तब तक इस कुर्सी से नहीं हटेंगे, क्योंकि यह कुर्सी ऐसी है कि इसको छोड़ना नहीं चाहते और हमेशा अपने लोग कल्याणकारी राज की बातें करके लोगों को गुमराह रख कर चलाना चाहते हैं। आपने कई नियम बना कर लोगों को परेशान किया है। आज आपके यहां खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है। डूंगरपुर में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग उसी एक तालाब में ही स्नान करते हैं और उसी का पानी पीते हैं। यह क्या व्यवस्था है आपकी? जब अंग्रेजों का राज था तब अंग्रेजों के टाइम में भी डूंगरपुर में दूर दूर से कुओं से पानी लाया जाता था, नदी से सरकार पानी लाती थी। लेकिन आज उसी एक तालाब से ही लोग पानी लेते हैं। उसी में स्नान करते हैं और उसी का पानी पीते हैं। यह हालत है हमारे डूंगरपुर की। वहां खाटों का भी बड़ा अभाव है। डूंगरपुर में कितने लोग भर्ती होने आते हैं लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वही भर्ती हो पाते हैं, गरीबों को कोई स्थान नहीं है अस्पताल में। आप गरीबों का राज कहते हैं लेकिन कहां है गरीबों का राज? गांधीजी अगर होते तो कुछ हम कह सकते थे कि जनता का राज होता लेकिन इस युग से गांधीजी चले गए। उसके बाद यह गरीबों का राज नहीं अमीरों का राज है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर में अस्पताल के संबंध में पूरी व्यवस्था करें।

दूसरी बात यह है कि आप डाक्टर भेज देते हैं तो ऐसे डाक्टरों को भेज देते हैं, जिनको हिन्दी नहीं आती है। वे सिर्फ अंग्रेजी समझते हैं जबकि वहां के लोग हिन्दी पूरी नहीं जानते वे अंग्रेजी कहां से जानेंगे। बिछीवाड़ा में आपने एक मदरासी डाक्टर भेज दिया जो वहां के लोगों की बोली बिलकुल नहीं समझता था और वैसे ही दवाइयां लिख देता था। वहां पर दवाइयां भी नहीं हैं। आपने वहां पर हैल्थ सेन्टर का विभाग बना रखा है, लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से सीमलवाड़ा में है। वहां भी दवाइयां नहीं हैं और खाटों की भी कमी है, खाटें भी नहीं हैं। यह आदिवासी एरिया है, वहां पर लोगों का अस्पताल में आने जाने में ही काफी रुपया खर्च होता है। अगर कोई अस्पताल में आना चाहे तो उसका चालीस पचास रुपया खर्च हो जाता है। इसलिए अगर डूंगरपुर जिले में अस्पतालों की पूरी व्यवस्था हो तो लोगों का आने जाने का खर्चा बच सकता है।

अब मैं आयुर्वेद के बारे में कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद में आज क्या है। भीखाभाई और डायरेक्टर के बीच में ही आयुर्वेद चलता है। न तो भीखाभाई की बात डायरेक्टर साहब मानते हैं और न डायरेक्टर उनके आदेशों का पालन करता है। आयुर्वेद विभाग की ऐसी हालत हो रही है कि उसको कोई देखने वाला नहीं है। जितने भी अस्पताल आपने डूंगरपुर में खोले हैं तो वे कहीं तो पटसाल में हैं तो कोई किसी स्कूल के कमरे में है। जहां न कोई नर्सों के बैठने की जगह है, न कम्पाउण्डरों के बैठने की जगह है, न कोई

जयपाल कटारा)

रों की व्यवस्था है। वहां पर जब आप र भेजते हैं तो कोई डाक्टर जाने को नहीं होता है इसलिए जब तक आपके ों की पूरी ढंग से व्यवस्था नहीं होगी ंव वहां आपका कोई भी अस्पताल तरह से नहीं चल सकेगा। जो ताल हैं उनको ठीक ढंग से चलाने की ाश की जाय, नहीं तो अस्पतालों को तोड़ सरकार जो उन पर नाजायज खर्चा करती सको बचाया जाय। न तो वहां दवाइयां वहां पर संतोषजनक काम है। इसलिए से ही जहां पर दवाखाने खोलें, स्कूल खोलें इनमें बिल्डिंग की फैसिलिटी पूरी दी जाय। फैसिलिटी जब तक न हो तब तक दवा- नहीं खोलें। वहां पर डाक्टर नहीं पहुंचता दवा नहीं पहुंचती है ऐसी स्थिति नहीं होनी हिए।

इसी तरह से सागवाड़े का जो अस्पताल में वहां पर खाटों का भी अभाव है, वहां टर का भी अभाव है, हर प्रकार की चीजों वहां पर अभाव है। इस अभाव की पूर्ति ने की कोशिश करें।

डूंगरपुर का जो अस्पताल है वह सी गरी का आपने बना रखा है। आपको रपुर के अस्पताल को ए या बी के टेगरी का ना चाहिए तब जाकर वहां के लोग फायदा सकेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा इन छोटी-मोटी बातों पर अब अधिक से धिक ध्यान देकर जन-जीवन को जो खतरा पन्न हो गया है उस जन-जीवन को बचाने की कोशिश करेंगे तो हम आपके बड़े आभारी गे।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज चिकित्सा जैसे महत्व-पूर्ण विषय पर चर्चा है और हमारे आयुर्वेद मंत्री दिल्ली में न जाने कहां कहां मीटिंगों की सैर करते फिर रहे हैं। भाग्य से वर्ष में एक बार तो इस बात पर चर्चा करने का मौका आता है, यह हम जानते हैं कि कहने का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है, लेकिन एक प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत इस विभाग की जो कुछ कमियां हैं, जो कुछ धांधलियां हैं, मंत्री महोदय से कहूं। उपाध्यक्ष महोदय, उप-मंत्री भी नहीं हैं इसलिए मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आयुर्वेद और चिकित्सा पर जो बहस हो रही है वह एक भैंस के आगे मृदंग बजाना है।

श्री दामोदरलाल व्यास (चिकित्सा मंत्री): आपकी पूरी बातें सुन कर जवाब देंगे और आपकी तसल्ली करेंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): आयुर्वेद मंत्री तो हैं ही नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास: हैं, बैठे हैं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय: अभी मंत्री महोदय ने कहा है वह बिल्कुल सही है। यह उनका खुद का विभाग नहीं है। आयुर्वेद के बारे में उनको जानकारी नहीं है। पुराने मंत्री जो अपने आपको धन्वन्तरी समझते हैं उनको ही उस विभाग का पता नहीं है, तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहूंगा कि आप उपमंत्री महोदय को आदेश दें—यह मैं मानता हूं कि उपमंत्री को कुछ पावर्स नहीं हैं, ये मंत्री महोदय कुछ काम नहीं करते हैं और दूसरों को भी नहीं करने देते हैं। अधिकार उप-मंत्रियों को नहीं दे रखे हैं लेकिन नाम मात्र के लिए अपने प्रति-निधि के रूप में जवाब देने के लिए चाहे वह

(वैद श्री गोविन्द सहाय)
कुछ भी हो, टालने वाला हो, आयें । उससे वयवस्था ठीक हो पायेगी या नहीं । मैं सदन में आपकी मारफत मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उनके विभाग की सही जानकारी डिप्टी मिनिस्टर देंगे उसको वे अमल में लायेंगे या नहीं लायेंगे ऐसी आशा नजर नहीं आती है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, (उपमंत्री, आयुर्वेद विभाग, श्री दौलतराम सारण) उनको अगर फुरसत नहीं मिलती है तो काम करना चाहते हैं तो सारण साहब के पास टाइम है । लोग कहते हैं कि उपमंत्रियों के पास काम नहीं है । थोडा बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो उनको मंत्री महोदय करने नहीं देते हैं । मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जनता की छाती पर आयुर्वेद के नाम पर क्यों बैठा रखा है, क्यों उनको कुर्सी से चिपका रखा है । सुखाडिया साहब भीखाभाई को पिछडे वर्ग का होने के नाते मंत्री बनाये रखना चाहते हैं तो चिकित्सा जैसे स्थान के लिए उपयुक्त समय देने वाले व्यक्ति ही इस पद के लिए उपयुक्त हैं ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विषय जो कि जन-जीवन के लिये सबसे बडी चीज है उसका मंत्री ऐसा हो कि सदन होता रहे और वह कहीं हो और वह सभा सम्मेलन में माला पहनने के लिए पहुंच जाय और उनके जो व्यक्ति हैं उनको साक्षात धनवन्तरी बताया करें ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत उप-मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब आपको पता नहीं तो जवाब आप क्या देंगे ? मेरा यह निवेदन है कि आयुर्वेद जैसे महत्वपूर्ण विषय जो शुरू से ही अति प्राचीन काल से भारतवर्ष की सेवा करता आ रहा है, उस महत्वपूर्ण विषय को आप एक खिलवाड न समझ कर और केवल एक राजनैतिक स्टन्ट समझ कर न टालें । यह मैं आपको मारफत उपाध्यक्ष महोदय, उपमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने हमको कहा कि मैं सारा जवाब दूंगा तो मैं एलोपेथी के मामले में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सवाई माधोपुर के बारे में पिछली बार भी कहा, उसके पिछली बार भी कहा, परन्तु मैं समझता हूं कि साधारण सा यह कह कर कि डाक्टर्स नहीं हैं, टाल देते हैं ।

सवाई माधोपुर की जन संख्या साढे नौ लाख है । वह एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है । राजस्थान में जन संख्या की दृष्टि से उसका पांचवा स्थान है किन्तु वहां पर केवल करौली सब डिविजन में एक अस्पताल है जो कि प्राचीन स्टेट के टाइम का है । सन ५७ से एक स्कीम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने की चल रही है लेकिन आज तक सरकार उसको पूरा नहीं कर पाई है। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर साढे नौ लाख की जनसंख्या कहां जाये ? करौली एक स्थान है जहां कि सिर्फ दो-तीन डाक्टर रहते हैं । वहां आज तक लेडी डाक्टर नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, या तो उन अस्पतालों को बन्द करवा दें क्योंकि उनमें न तो डाक्टर आप भेजते हैं न दवाइयां देते हैं, लेडी डाक्टर यह कह कर मिलती नहीं हैं भेजते नहीं हैं । एक तरफ तो आप जब बाहर जाते हैं तो अपनी स्पीच में यह कहते हैं कि ८० पर्सेन्ट लोग देहातों में रहते हैं और २० पर्सेन्ट शहरों में रहते हैं। लेकिन आप सिर्फ २० पर्सेन्ट जनता के लिए सारे साधन उपलब्ध करते हैं, रोड्स भी, बिजली भी

(वैद श्री गोविन्द सहाय)

चिकित्सा भी, और सारी सुविधाएं उस २० पर्सेन्ट के लिए उपलब्ध करते हैं। ८० पर्सेन्ट जनता चिकित्सा और दूसरे साधनों से विमुख रहती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, करौली अस्पताल की जो हालत हैं, यह ठीक हैं कि वर्तमान में जो डाक्टर वहां पर हैं वे सज्जन और नेक हैं, बाकी वहां डाक्टर्स की कमी है, लेडी डाक्टर की कमी हैं। उस अस्पताल में आज तक लेडी डाक्टर नहीं पहुंची हैं। भूतपूर्व मंत्री महोदय थे उनसे भी निवेदन किया था। गंगापुर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जगह है जो कि पूरे जिले के मध्य में हैं। वहां पर एक डाक्टर हैं जब कि दो डाक्टर्स का वहां स्थान हैं। वहां पर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर हैं वजीरपुर के नाम से क्योंकि म्युनिसिपल एरिया में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर नहीं रह सकता हैं। वजीरपुर की जनता ने १० हजार रुपये इकट्ठे किये और सरकार ने वायदा किया था कि वे १० हजार रुपये देकर बिल्डिंग बनवा देंगे। लोगों ने बिल्डिंग बनवा दी लेकिन राज्य की ओर से कोई कार्य-वाही नहीं की गई। वहां पर एक कम्पाउन्डर रख रखा हैं। उसको भी गत वर्ष पृथक कर दिया गया हैं, तो विभाग से आदमियों ने मिल कर कम्पाउन्डर को पुनः नियुक्त करवाया हैं। इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आज बहुत सारे जिलों में डाक्टर नहीं हैं, लेडी डाक्टर नहीं हैं, आखिर आप कब तक यह कहेंगे? आज १८ वर्ष हो गये यह कहते हुए कि डाक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। आप एक स्कीम को लेकर चलिये कि इतने दिनों में डाक्टर्स की कमी पूरी करके रहेंगे। अगर यहां नहीं होंगे तो बाहर से मंगायेंगे। यह कह देना कि डाक्टर्स नहीं हैं, लेडी डाक्टर्स नहीं हैं तो यह तो राजा लोग भी कहते थे, तो आप में और उनमें क्या अन्तर हुआ? आप एक कल्याणकारी राज्य की दुहाई देते हैं कि आप हर आदमी को चिकित्सा, घर, मकान व रोटी देंगे, बापू का सिद्धान्त था कि गरीबों को चिकित्सा मिले, मकान मिले, कपड़ा पहनने को मिले। लेकिन इसके विपरीत आपके राज्य में सारी चीजें हैं। चिकित्सा का नाम नहीं हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय कहते हैं कि देहाती इलाका हैं, पिछड़ा इलाका हैं तो सवाई माधोपुर का जो जंगली इलाका है चम्बल की सीमा पर वहां क्या हालत हैं कि डाकुओं की वजह से कोई अधिकारी पहुंचता नहीं है: वहां पर यातायात के साधन नहीं हैं। वहां आदमी क्या करे? क्या वह खत्म हो जाये? वहां पर आप बम्बार्डमेंट करवा दें जिससे कि वहां पर न कोई रहेगा और न यह सारा होगा।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप शहरों के चिकित्सालय को देखते ही हैं, इनके बजाय देहातों के चिकित्सालयों को भी देखें। लेकिन वहां पर जाने को मंत्री महोदय तकलीफ नहीं करते हैं। जहां पर उनकी कार पास हो जाये वहां तो वे चले जायेंगे····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन जहां रेत होगा तो नहीं जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खास मुद्दा तो अभी बाकी है मंत्री महोदय से कहना। मंत्री महोदय ने कहा था कि वे सारा जवाब देंगे तो उसके बारे में निवेदन किया हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप गंगापुर जाते हैं तो डाक बंगले में ठहरते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : दस मिनिट तक तो केवल भूमिका हुई है।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मैं तो दूसरे सब्जेक्ट्स पर कम बोलता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : ५ मिनिट में भूल को समाप्त कर दीजिये ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ८० परसैन्ट जनता को सहायता पहुंचाना चाहते हैं तो केवल जहां पर मोटर पहुंचती है वहीं तक न जाकर और आगे भी जाइये, देहात में भी आप मुकाम करिये। कम से कम महीने में दस दिन तो बाहर निकलिये और देखिये कि जनता को कितनी दिक्कत है कितनी तकलीफ है। कम से कम आप मैं से पांच मंत्री भी महीने में दस दिन के लिए बाहर जाने का लक्ष्य बना लें तो आपको वस्तु स्थिति का पता लग जाय। इसके बिना वस्तु स्थिति आपको मिलती नहीं है। दूसरे पक्ष के मेम्बर विरोधी पक्ष के आदमी कोई बात कहते हैं तो आप समझते हैं वे आलोचनात्मक दृष्टि से कह रहे हैं। मैं चिकित्सा जैसे विषय के बारे में आलोचना की दृष्टि से नहीं कहता। लकिन आपने ठेका लिया है, ठेकेदार बने हैं तो लक्ष्य तय करिये कि कितने दिनों में आप डाक्टर भेज सकेंगे। कितने दिनों में डाक्टरनियों को भेज सकेंगे, कितने दिनों में नरसेज की व्यवस्था कर लेंगे इसके लिये आप तय करिये।

मैं अब, उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद के मामले में निवेदन करना चाहता हूं हालांकि मंत्री जी आज यहां पर नहीं हैं फिर भी एक वैद्य होने के नाते निवेदन करना चाहता हूं कि १८ वर्ष देश को स्वतन्त्र हुए हो गए लेकिन आयुर्वेद की कोई खास तरक्की नहीं हुई। पहले हमारे यहां ब्रिटिश शासन था और मुगल साम्राज्य था उस समय जो आयुर्वेद की स्थि थी वैसी ही स्थिति आज है उसमें विशे अन्तर नहीं है। आज एलोपैथिक डाक्टर वे भी भारतीय हैं लेकिन उनकी शिक्षा-दीक्ष पाश्चात्य प्रणाली पर है इसलिये उनको वै के प्रति डाह रहती है, उनके प्रति सौतेल व्यवहार है जैसे एक आदमी के, ... और होती हैं और उनके आपस में नहीं बनता उसी तरह से डाक्टरों और वैद्यों में आपस नहीं बनता है। मैंने कई बार देखा है f डाक्टर यह समझते हैं कि आयुर्वेद अवैज्ञानि है, यह उनकी भूल है। यदि यह अवैज्ञानि थी तो इतने दिनों तक लोगों की सेव कैसे कर सकते? आज मैडिसिन के नाम कु भी रख दें लेकिन कैम्फर, आयर वगैरह आयुर्वेद में भी काम आते हैं मुश्क आज भी दिल को ताकत नहीं देती क्या? अगर आयुर्वेद अवैज्ञानिक होता त इसकी इतनी उन्नति नहीं होती। आयुर्वे बहुत प्राचीन पद्धति है। इस समय यह इसलि पिछड़ा हुआ है कि इसको जितनी सहायता औ प्रोत्साहन मिलना चाहिये था उतना नहीं मिला हमारे देश को आजाद हुए १८ वर्ष हो गए लेकिन एलोपैथिक को और आयुर्वेद क जो पैसा मिलता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहां जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय भी दो आयुर्वेदिक कालेज थे एक उदयपुर में और, दूसरा जयपुर में और आज भी वही दो कालेजेज चल रहे हैं इस पर भी आप लम्बा-चौड़ा ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने इतने वैद्य निकाल दिये लेकिन मैं, उपाध्यक्ष महोदय आपके जरिये मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि दो कालेज जो पहले चल रहे थे वे ही आज चल रहे हैं और आप जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि १४ हजार या १४ सौ की आबादी पर एक अस्पताल खोलेंगे उसकी पूर्ति के लिये

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

आपको वैद्य कहां से मिलेंगे दो कालेजों से तो वैद्य पूरे पड़ेंगे नहीं। फिर इन वैद्यों का ग्रेड ऐसा है जो एक क्लर्क के बराबर है। आपकी तरफ से इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है कि हमने आयुर्वेद के लिये मंत्री अलग कर दिया है लेकिन गुजरात ने जो आदर्श उपस्थित किया है उसको देखिये। वहां पर शुद्ध आयुर्वेद की प्रगति के नाम की जो पुस्तिका छपी है उसको उठा कर देखिये। आप तो आयुर्वेद की प्रगति के बारे में अभी तक विचार ही कर रहे हैं और कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की पहले स्थापना की है। वैद्यों के ग्रेड्स के बारे में भी वे यह मानकर चलते हैं कि इनको अच्छा ग्रेड मिलना चाहिये। लेकिन अपने यहां पर वैद्यों को ग्रेड एक क्लर्क के बराबर मिलता है। एक आदमी हायर सेकेन्डरी पास करके पांच साल तक आयुर्वेद की पढ़ाई करता है तब कहीं वैद्य बनता है उसको वही तनख्वाह मिलती है जो एक मैट्रिक पास क्लर्क को मिलती है।

मैं आयुर्वेद मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि मैंने छात्रावास के बारे में आपसे प्रश्न पूछे थे और उनका जवाब भी आपने दिया लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ चल कर आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रावास को देखिये और यह देखिये कि वहां पर किस तरह की व्यवस्था है। मैं परसों वहां गया था। मेडिकल कालेज के छात्रावास में और आयुर्वेदिक कालेज के छात्रावास में स्वर्ग और नर्क का अन्तर है। मुझे वहां जाकर शर्म आई। पास में ही गन्दा नाला बहता है और हरिजन मेहतरों के लिये जो क्वार्टर्स बने थे वे उनसे छीन कर एक एक कोठड़ी में दो दो विद्यार्थियों को बसा रखा गया है। न लाइट की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी की तरफ से दूसरा कोई नहीं बोलेगा। ५ मिनट का समय और चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जितनी बातें आपने फरमाई हैं वे बजट भाषण के समय भी कही थीं।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : उस समय नहीं कही थीं।

श्री उपाध्यक्ष : और भी कई बोलने वाले हैं। खैर आप दो मिनिट और बोल लें।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : छात्रावास की व्यवस्था के बारे में मैं निवेदन कर रहा था। वहां पर क्या हालत है यह मैं देखकर आया हूं। वहां पर हर मंत्री जाते हैं वे यही आश्वासन देते हैं कि फेकल्टीज जल्दी हो बनायेंगे लेकिन होता कुछ नहीं है। ग्रेड आप बढ़ाते नहीं हैं वहां पर ३५० छात्र हैं लेकिन उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है। जो सब वैद्य ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं है उधर कालेज की यह हालत है, इधर औषधालयों की भी इसी तरह की हालत है। जहां तक वैद्यों की पदोन्नति का सवाल है, सरकार की तरफ से आदेश जारी हो जाते हैं कि जो आदमी नीचे थे वे आगे रख दिए जाते हैं। आगे वाले चिल्लाते रहें कि हमने कौनसा अपराध किया है जो हमको क्यों नहीं पदोन्नति का चान्स दिया गया। उस पर एक आदेश फिर जारी कर दिया कि पीछे वालों

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)

को तरक्की बाद में देदी जावेगी पहले पुरानों को दी जायगी ।

श्री दौलतराम सारण : आप एक दो उदाहरण देकर बताइये ।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : आप जानते ही हैं ।

श्री दौलतराम सारण : (उप-मंत्री, आयुर्वेद) : मैं क्या जानता हूं या नहीं, इससे मतलब नहीं है । आपको जानकारी है तो उदाहरण देकर बताइये ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उदाहरण नहीं मिल रहा हो तो बाद में बता देना ।

(२ म. प.)

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : अभी कुछ दिन पहले बारह जूनियर वैद्यों को सीनीयर वैद्यों को छोड़कर प्रमोशन दे दिया गया । वह सरकार के पास ज्ञापन लेकर गए कि आपने जूनियर वैद्यों को 'ए' श्रेणी का वैद्य कैसे बना दिया हमें पीछे कैसे रख दिया, उनके लिए आदेश कैसे दे दिया । यह आपके नोटिस में है और आप इस तरह से बात पूछ रहे हैं जैसे आपकी जानकारी में नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, फिर गवर्नमेन्ट से आदेश हुए कि जो सीनियर वैद्य हैं उनको स्थान दे दिया जायगा । उसके बाद फिर जूनियर वैद्यों का प्रतिनिधि मिला तो उनको कह दिया गया कि जब तक गवर्नमेन्ट के आदेश न मिलें तब तक आप वहीं रहो । यह सारी बातें आपकी जानकारी में हैं

श्री दौलतराम सारण : आप अपनी बात कहें । मेरी जानकारी में क्या है, क्या नहीं है–उसको रहने दें ।

वैद्य श्री गोविन्द सहाय : आपकी जानकारी में है । यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे वैद्यों के प्रतिनिधि, जिनके साथ ज्यादती हुई है और अन्याय हुआ है, आपसे मिले हैं । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मंत्री महोदय को निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि आप आयुर्वेद विभाग को उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं, आयुर्वेद जगत को उत्थान की ओर लेजाना चाहते हैं और उनके साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि आपको आयुर्वेद की फैकल्टी बनानी चाहिए । अभी आपने एक आर. ए. एस. ऑफिसर को इस विभाग के जॉइन्ट डाइरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है । इनको कोई टैक्निकल अनुभव प्राप्त नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह साफ प्रतीत होता है कि सरकार के मंत्री और आयुर्वेद विभाग के डाइरेक्टर में आपस में झगड़ा रहता है । आपका कहना है कि नहीं, तो मैं पूछता हूं कि इस आयुर्वेद विभाग के जो डाइरेक्टर हैं जो इसका विशेष अनुभव रखते हैं और इन ज्वाईन्ट डाइरेक्टर से काफी ज्यादा रखते हैं फिर एक नॉन-टैक्निकल व्यक्ति को नियुक्त करने के क्या मायने हैं ? क्या डाईरेक्टर ट्रान्सफर वगैरा नहीं कर सकते ? क्या आयुर्वेद मंत्री ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते? फिर क्या कारण है कि एक आर.ए.एस. व्यक्ति को, जो नॉन-टैक्निकल व्यक्ति है, जो आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं जानता है उसको वहां पर ट्रांसफर वगैरह करने को रखा है ? क्या एलोपैथी के डाक्टरों का ट्रांसफर मंत्री महोदय खुद नहीं करते हैं ? फिर इसमें क्या बात हो गई कि एक आर. ए. एस. व्यक्ति को इस बात के लिए इसमें लगाना पड़ा?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता

(वैद्य श्री गोविन्दसहाय)
हूं कि यह जो सारी इस तरह की गडबडियां हैं, यह आयन्दा भी आपकी जानकारी में न आयें, तो इसके उत्थान के लिए आप शीघ्रातिशीघ्र फैकल्टी बनायें ।

छात्रावास के लिए मेरा निवेदन है कि आप कहते हैं कि छात्रावास के लिए मकान बनाना चाहते हैं । वह कह कर आप इस समस्या को टाल नहीं सकते हैं । आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि जहां रहते हैं वहां रोज सांप निकलते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

वैद्य श्री गोविन्दसहाय : और वहां पर अंधेरा रहता है । क्या आप इस तरह आयुर्वेद का उत्थान करना चाहते हैं ? यह बड़े शर्म की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया !

श्रीमती गौरी पूनिया (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा में मेरा भी एक कटौती प्रस्ताव है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले १८ वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है-- इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भेद भाव काफी बरता जाता है, इस बात पर मेरे से पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है, इसलिए मैं अधिक विस्तार में न कह कर नागौर जिला का उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूंगी ।

नागौर जिला में एक भी लेडी डाक्टर नहीं है । वहां पर अन्दाजन दस लाख की पापूलेशन होगी । हम यह मान कर चलें सकते हैं कि इस पापूलेशन में आधी भी महिलाएं हों तो पांच लाख महिलाओं के लिए एक भी लेडी डाक्टर का न होना बड़े शर्म की बात है । मैं आपको बताना चाहूंगी कि वैसे भी नागौर जिले में लेडी डाक्टर तीज त्योंहार हो है । आप पिछला रिकार्ड उठा कर देख लीजिए, वहां पर कभी कोई लेडी डाक्टर जमकर नहीं रही है ।

इसके साथ ही मैं प्राइमरी हेल्थ सेन्टर डेगाना की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । पिछले पांच वर्षों से, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी माकूल व्यवस्थाओं के बारे में, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर की सुव्यवस्थित व्यवस्था के बारे में, कहते कहते मेरी जबान घिस गई है लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के कानों पर जूं भी नहीं रेंगती है, वह इस कान से सुनते हैं और उस कान से निकाल देते हैं

श्री भवनलाल (हिण्डौन-सु०) : आदतें पड़ गई हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : पहले स्वास्थ्य मंत्री दूसरे थे, अब दूसरे हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपके ही विभाग की बात कह रही हैं ।

श्रीमती गौरी पूनिया : आपके लिये नहीं कहा है, आपकी तो बड़ी मेहरबानी रही है । मेरे एक प्रश्न पूछने के बाद में एक दो हजार रुपये डेगाने के लिए दिलाये हैं ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इनसे पहले के लिए कह रही हैं ?

श्रीमती गौरी पूनिया : अब आप यह समझ लीजिये । उपाध्यक्षजी, मैं कहते कहते

(श्रीमती गौरीपूनिया)

थक गई लेकिन उस पर बिल्कुल गौर नहीं किया गया। डेगाना के प्राइमरी हैल्थ सेन्टर की जो बिल्डिंग है वह पांच साल से बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में पड़ी हुई है। उसको देख कर कोई अनजान आदमी पिंजरा पोल का ही अन्दाज लगा सकता है, क्योंकि उसके चारों ओर अहाता नहीं है, न वहां डॉक्टरों के रहने के लिए क्वार्टर हैं और चौकीदार के लिए भी वहां क्वार्टर नहीं है। इसलिए गाय और आवारा जानवर वगैरह घुस आते हैं और अहाते में घूमते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि कोई अनजान आदमी इसे देख कर पिंजरा पोल का ही अन्दाज लगा सकता है।

इसके साथ साथ डेगाना में परिवार नियोजन का केन्द्र पिछली बार खोला गया है। उस पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में वित्त मंत्री जी ने, बड़ा जैसे कोई आभार मेरे ऊपर किया हो, इस तरह मेरी अपनी मांग पर वहां पर परिवार नियोजन केन्द्र खोला था। मैं उनका वह आभार साल भर के बाद में लौटा देना चाहती हूं, क्योंकि इस परिवार नियोजन केन्द्र में कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं कह सकती हूं कि आज तक इस परिवार नियोजन केन्द्र में एक भी आदमी का ऑपरेशन नहीं हुआ है, इसके द्वारा कोई दवाइयां बांटी नहीं गई हैं। मैं नहीं कहती कि वहां डॉक्टर में कोई कमी है, लेकिन स्थिति यह है कि न तो समय पर साधन मिलते हैं और न समय पर दवाइयां मिलती हैं और न डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से उनको कोऑपरेशन ही मिलता है। डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर से उनको कोऑपरेशन नहीं मिलता है उसका एक उदाहरण पिछली २६ फरवरी का आपके सामने रखना चाहूंगी। पिछली २६ फरवरी को परिवार नियोजन का कैम्प डेगाना के पास सिरासना में लगाया गया। डी० एम० एच० ओ० का हुक्म था कि डॉक्टर वहां पर पहुंचे और हर तरह से अच्छी व्यवस्था कर दे और ऑप्रेशन उनकी उपस्थिति में होंगे। डॉक्टर वहां पहुंचा और उसने हर तरह का वहां पर प्रचार किया, लोग बाग इकट्ठे हुए, वहां करीब पांच सात सौ आदमी-औरतें इकट्ठी हुईं। इसके अलावा एक लिस्ट भी बनाई गई, उस लिस्ट में करीब ६० व्यक्ति ऐसे थे जो ऑपरेशन कराना चाहते थे और पच्चीस-तीस महिलायें ऐसी थीं जो लूप लगाना चाहती थीं। लेकिन जब २६ फरवरी आई, तो डी० एम० एच० ओ० नदारद और लेडी डॉक्टर भी नदारद जब D.M.H.O. पधारे थे डेगाना स्टेशन पर और आपने पूछा था कि डॉक्टर कहां है तब आपको बताया कि जो कैम्प सीरासना गांव में लगा है वहां गया है, तो आपने वहां जाने की तकलीफ नहीं फर्मायी। आप वापिस नागौर पधार गये और जो वहां पांच-सात सौ लोग इकट्ठे हुए थे और जो लोगों की ऑपरेशन कराने और लूप लगाने की लिस्ट बनी थी वह यों की त्यों रह गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को निवेदन करना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुई है उसका नमूना नागौर जिला है, और नागौर जिले को भी छोड़ें तो मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी ही मेरा माप-दंड है। उसके बारे में मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि कतई प्रगति नहीं हुई है। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि मैं गांव गांव में घूमती हूं तो इस तरह की बातें देखने में आती हैं; जैसे पंचायत समिति के पास परिवार नियोजन के सम्बन्ध में साधन और दवाइयां रहती हैं, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि पंचायत समिति के पास कोई ट्रेड स्टाक नहीं रहता है। ऐसी

(श्रीमती गोरांयुनिया)

स्थिति में उन दवाइयों का दुरुपयोग होता है। मान लीजिये कि पंचायत समिति और डॉक्टर में अच्छा सम्बन्ध है तो उन दवाइयों का उपयोग हो सकता है लेकिन यदि डॉक्टर अपनी चलाना चाहता है और पंचायत समिति अपना अधिकार जमाना चाहती है तो वहां पर इस प्रकार की दवाइयों पर, इस प्रकार के साधनों पर जो इस प्रकार धन खर्च किया जाता है तो वह व्यर्थ जाता है।

इसके साथ-साथ एक चीज और देखने में आई है और वह यह है कि समाज-कल्याण बोर्ड की ओर से गांवों में केन्द्र चलते हैं-जैसे क्राफ्ट और बाल-बाडी की शिक्षा दी जाती है। उसके साथ साथ इस वर्ष फेमिली प्लानिंग का भी उनके बजट में कुछ प्रावधान रखा है। मेरा विश्वास है कि यहां भी अनट्रेण्ड दाइयां होती हैं, जो दवाओं का नाम भी नहीं पढ सकती हैं, वह साधनों का उपयोग करना स्वयं ही नहीं जानती हैं तो फिर दूसरों को क्या बता सकती हैं। मेरा सुझाव है कि नीम हकीम खतरे जान वाली संस्थाओं के लिए इस प्रकार का प्रावधान न करके इस केवल मेडिकल विभाग की जिम्मेदारी में रखें तब तो आप इस क्षेत्र में अपने लक्ष्य तक पहुच सकते हैं। वर्ना धन का दुरुपयोग ही होगा।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सुझाव है कि परिवार नियोजन एक अहम समस्या है क्योंकि हर योजना में हमारे देश में थोडी जनसंख्या बढ गई। जो जन.सख्या पहली पंचवर्षीय योजना के वक्त थी, वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में और बढ गई और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय थी वह तीसरी पंचवर्षीय योजना में और बढ गई। इसके समाधान के लिए हमको घर-घर में और गांव-गांव में जन-मानस तैयार करना होगा और समस्या को शुद्ध स्तर पर हल करना होगा। जैसा आप जानते हैं, १६०१ में हमारे देश में जन-संख्या थी २४ करोड वह १६६१ तक जाकर ४४ करोड़ हो गई और वह भी जब कि पाकिस्तान के बन जाने से काफी जन-संख्या भी अलग हो गई और उसके बाद अब ५०-५१ करोड़ हो गई है। यही हालत रही तो, उपाध्यक्ष महोदय, बीस-पच्चीस वर्ष में इस देश का क्या हाल होगा-इसकी कल्पना करने में ही मुझे डर लगता है। इसलिए मैं आपके द्वारा मंत्री जी का इस ओर ध्यान खींचते हुए निवेदन करूंगी कि इस देश की सत्तर प्रतिशत जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है इसलिए आप ग्रामीण जनता के साथ में विमाता जैसा व्यवहार करना बन्द कर दीजिये-और बातों में भले ही न करें लेकिन एक तो पीने के पानी की व्यवस्था और उसके बाद चिकित्सा के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ग्रामीण जनता के साथ विमाता जैसा व्यवहार करना बन्द करदें। वैसे अब ये लोग भी जागरूक हो गये हैं और स्वतंत्रता-प्राप्ति के हिसाब से तो अब ये बालिग भी हो गये हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह विद्रोह कर बैठें। इसलिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि १६६१ में ४४ करोड जन-संख्या हो गई थी और अब जन-संख्या ५०-५१ करोड़ के करीब है। अगर इसी तरह की रफ्तार रही तो बीस-पच्चीस साल में अस्सी करोड़-हो सकती है। अगर ऐसी ही गति रहती है तो मैं समझती हूं कि इस भारत का भविष्य विधाता के भरोसे ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुल प्रसाद शर्मा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) :

Page No. 78

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
यह गुरु भाई की तरफ निगाह उठ जाती है, हमारी तरफ भी निगाह उठ जाय ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : ये दस दफा खड़े हो चुके हैं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा-रामगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, इधर भी निगाह उठ जाय ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के ऊपर एक मांग रखी गई है मंत्री महोदय की तरफ से यहां पर, मैं उस पर अपने विचार रखना चाहूंगा । चिकित्सा की पद्धति के द्वारा जब कोई मनुष्य कोई न कोई रुग्णावस्था को पहुंचता है तो उसको वापिस सही स्थिति में लाने के लिए उसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है और बीमारी का इलाज करने वाले लोग हैं, उन्हें हम बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, डॉक्टरों को, वैद्यों को हम किसी पूजनीय व्यक्ति से कम नहीं मानते हैं, लेकिन आज-कल किस प्रकार से हो रहा है और जैसी मनोवृत्ति चिकित्सकों की हो रही है उसको देख कर बड़ा दुःख होता है । राजस्थान सरकार ने चिकित्सा पर काफी खर्च करना शुरू किया । पहले से ज्यादा हॉस्पिटल्स खोलने शुरू किये । खोले भी; चाहे वहां पर डॉक्टर काम करने को आपको न मिले । सरकार ने औषधालय भी खुलवाये हैं । जहां डॉक्टर नहीं हैं, वह तो एक बात है हो, लेकिन जहां पर डॉक्टर है उसकी स्थिति कैसी है वह मैं आपके सामने बताना चाहता हूं । मैं एक छोटी सी घटना आपके सामने कह दूं । हमारे बीकानेर हॉस्पिटल में अभी एक केस हुआ, एक बीमार का नाम मैं बताना नहीं चाहता । एक बहिन को भर्ती किया गया और उसको किस तरह से उठा कर अपने घर डॉक्टर ले गये, यह हमारे लिये शर्म की बात है और इस विभाग के लिये भी और इस रोगी के लिये भी कि जो बीमार बीमारी अच्छी कराने के लिये आये और उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार और ज्यादती है ।

एक माननीय सदस्य : कहां की बात है ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बीकानेर की बात है और इस डॉक्टर का नाम सभी को मालूम है । उनका नाम दवे साहब है । मैंने बीकानेर में जब सुना तो पता लगाया कि क्या हुआ और क्यों हुआ? तो यहां के लोगों ने कहा कि यहां तो हुआ ही करता है । मैंने पूछा कि कैसे हुआ करता है ? वे कहने लगे कि यहां पर इनके जिस प्रकार के इस विभाग के हैड होंगे उसी प्रकार के लोग नीचे वाले कार्य करेंगे; यथा राजा तथा प्रजा,' जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी । वहां पर इस विभाग के हैड हैं उनकी स्थिति भी इसी प्रकार की थी । बीकानेर में उनकी यह हालत है कि जब वे रंजाब से आये उस समय मामूली तौर से डॉक्टर थे । वे बीकानेर में रहे । बीकानेर में महाराज गंगासिंहजी ने इनको वहां से हटाया था, मगर फिर अपरन्त हॉस्पिटल में लोगों ने किसी तरह से इनको लगाया ।

अब तक बीकानेर के सम्बन्ध इनके रहे हैं । मद्रास में इन्होंने एल.एम.पी. को हों चाहे और किसी जगह गये हों, लेकिन अभी तक जब कभी वे बीकानेर में जाते हैं, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा दौरा बीकानेर का रहता है, उस समय ये कहां पर रहते हैं यह सभी को मालूम है । आप किसी से भी पूछलें कि वे कहां पर मिलेंगे तो आपको मालूम होगा कि वे फलां जगह पर मिलेंगे, वे जिस बहिन के यहां पर मिलेंगे मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता और न

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

मैंने उस बहिन का नाम बताया है, जिसके साथ ज्यादती की गई। यह बहिन जिसके यहां पर ये ठहरते हैं वह मेडिकल विभाग में सर्विस करती है और उसको बीकानेर का बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी को भी पूछ लें। यदि आपको उनको फोन करना है तो आपको रात को वे सर्किट हाउस में नहीं मिलेंगे। लोग कहते हैं कि अगर टेलीग्राम करना है या ट्रंक कॉल करना है तो सर्किट हाउस में करते फिजूल फालतू पैसा खर्च करना है। जब ऊपर के अफसरों का यह हाल है तो नीचे के सभी लोग बिगड़ेंगे और निश्चित तौर से बिगड़ेंगे। जिस किसी डॉक्टर का तबादला करवाना होता है वह बीकानेर में इस बहिन के पास जाता है और सेवा करता है और उसका तबादला कर दिया जाता है। यह निकम्मापन इस विभाग ने शुरू किया है। मैं समझता हूं कि यह डिपार्टमेन्ट के लिये शर्म की बात है और इससे हमें भी तो दुख होता है। मैं आपको निवेदन करूं कि आप वहां के दौरे में गये, सुजानगढ़ गये और आपने अपनी पुरानी गाड़ी वहां के डॉक्टर को बेच दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई मिनिस्टर अपनी गाड़ी डायरेक्टर को बेचे या डायरेक्टर अपनी गाड़ी तहसीलदार को बेचे, यह कहां तक उचित है। उनकी गाड़ी टूटी हुई और पुरानी गाड़ी किसी काम की नहीं, फिर भी सुजानगढ़ के डॉक्टर व्यास को बेची जो तीन हजार की भी नहीं थी। मैं तो यह कहूंगा कि अगर वह ८ हजार की गाड़ी थी तो भी व्यास को जो उनका मातहत था बेचना भद्दी बात थी। जब उन्होंने गाड़ी बेची और उन डाक्टर महोदय ने एक दम उनके पास पैसे रख दिये तो उनको मालूम हुआ कि ये तो पैसे वाले हैं। तो बीकानेर में उनकी विश्राम गृहस्वामिनी ने डॉक्टर साहब से कहा कि कुछ रकम मुझे दो नहीं तो हैरेस कर दूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, जितना पैसा था गाड़ी के नाम पर मैं दे चुका हूं। उसको चार महीने नहीं हुए, उसका फौरन तबादला कर दिया गया और उसकी जगह दूसरा डॉक्टर जोशी को भिजवा दिया गया; इसलिये मैं यह कहूंगा कि मर्जी आवे जिसका तबादला करवा दो। विश्राम-गृह-स्वामिनी के पास आप चले जावें तो डॉक्टर का तबादला करवा लो। जिस किसी डॉक्टर को अपना तबादला करवाना हो तो उसके पास पैसा पहुंच जावे, यह सारा मामला है और सभी को मालूम है। इसके लिये मुझे बहुत खेद है और बहुत दुख होता है क्योंकि मैं जीवन में कभी अविश्वास के लोगों की शिकायत नहीं करता। लेकिन जब से इस विभाग में श्रीमान् आये, बीकानेर में उनके छोटे भाई को निकाल दिया गया था, उसको आपने वापिस सर्विस में लिया। उनका भतीजा किसी कम्पनी में नौकर था। वहां से एक्स-रे की मशीनें सारी की सारी खरीद की गईं। उपाध्यक्ष महोदय चाहे हमें प्लेट नहीं मिलती हों, विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से मगर आपने सारी एक्स-रे की मशीनें मंगवा लीं। क्योंकि वहां पर उनका भतीजा था। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, चाहे आप अपने भाइयों को रखें, भतीजों को रखें। मैं तो यह कहूंगा कि जैसे आपके ऊपर वाले अधिकारी काम करेंगे, नीचे वाले वैसा ही काम करेंगे। जैसा ऊपर के अधिकारियों का कैरेक्टर होगा नीचे वालों का वैसा ही कैरेक्टर रहेगा। आप इस बात की जांच करवा लें कि उनके सबसे ज्यादा दौरे बीकानेर में होते हैं या नहीं और जब उनका दौरा बीकानेर में होता है तो शराब रोज आती है या नहीं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : दौरा कम करते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मेरी यह शिकायत है कि जब भी दौरा करते हैं तो बीकानेर अवश्य पधारते हैं। आपको कोई और शिकायत हो तो मैं कह नहीं सकता। इसलिये मैं यह कहूंगा कि अगर आपने विभाग को ठीक नहीं किया तो और भी इस प्रकार के कांड होंगे, कि नये कांड होंगे। जब नीचे वाले सभी लोग जानते हैं कि हमारे अधिकारी ऐसे हैं तो नीचे के आदमियों को क्या डर ?

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री) : मैं माननीय सदस्य को अर्ज करना चाहता हूं कि आप डॉक्टर के लिये कह रहे हैं वह खुद तो आकर अपना जवाब यहां दे नहीं सकता। आपको चाहिये था कि मुझे लिख देते या आप इसको मेरे नोटिस में लाते तो मैं आपको तसल्ली कराता। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो यहां पर डिफेन्ड नहीं कर सकता है उसके लिये कोई बात कहते हैं तो यह उचित नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आपने ऑब्जेक्शन जब प्रस्तुत किया जब उन्होंने सब कह दिया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं आपसे मिल लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी यह डिप्लोमेटिक चाल सर्विसेज के साथ अच्छी नहीं है कि पहले तो उनकी खड़पट्टी करवादें और बाद में यह कहदें कि हम उनकी हमदर्दी करते हैं। इसीलिये तो सर्विस क्लास में सरकार के प्रति नॉन-कॉन्फीडेन्स हो रहा है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : अभी माननीय सदस्य ने सुजानगढ़ के मामले में कहा है, वह बिल्कुल गलत कहा है और मैं उनको चेलेंज देता हूं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने सुजानगढ़ के मामले में गाड़ी की बात कही है।

श्री फूलचन्द जैन : इससे ज्यादा आपने कहा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : प्रोसीडिंग्ज पड़ी हैं, आप पढ़ लीजियेगा। आपको मालूम पड़े तो मुझे कह देना।

जैसा अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा कि मेरी जानकारी में लावें या मुझे लिख दें। मैं लिख कर दे दूंगा। फिर भी अगर बीकानेर में बीमार स्त्री को इस तरह ले जाते हैं और मैं समझता हूं कि आपको मालूम है। आपको यह नहीं बताया जावे कि आपके विभाग के हैड क्या करते हैं, तो मैं समझता हूं कि मैंने यह आपको बताया है और ऐसा बताना गलत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हॉस्पिटल्स बहुत बने हैं। सरकार ने इन पर काफी खर्चा किया है, लेकिन गावों में डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर गावों में हॉस्पिटलों में नहीं जाते हैं और कहा यह जाता है कि डॉक्टरों की कमी है। मैं यह कहूंगा कि डॉक्टर शहरों में बहुत हैं। या तो आप यह तय कर लें कि जो नया डॉक्टर आवे तो उसको पहले गावों में कुछ दिन अभ्यास यहां पर करवा कर गावों में भेज दिया जावे। ऐसा करेंगे तो डॉक्टर गावों में चले जावेंगे।

मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी में तीन हॉस्पिटल्स हैं जहां डॉक्टर नहीं है। कहीं डॉक्टर ज्यादा हैं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

तो कहीं है ही नहीं। अगर गवर्नमेन्ट गावों में डॉक्टरों को रखने के लिये ध्यान देगी तो गावों के लोगों को फायदा होगा अन्यथा बगैर डॉक्टर के गांवों में हॉस्पिटल बनाना बेकार होगा।

योग-साधन से भी कई प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। योग-साधन से मित्तव्ययता को भी निवृत्ति मिलती है। अब इसमें खर्चे का और व्यवस्था का ठीक इन्तजाम नहीं है, जिसपर राज्य सरकार ध्यान दे कि जहां पर कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है वहां पर योगी-सन्यासियों की तरह से इलाज हो। योगी-सन्यासी अपने ढंग से इलाज करते हैं। उसको कहा जावे कि खाने को डालडा दो तो वह यही है कि मेरे यौगिक साधनों में डालडा खाने को देने का कहीं प्रावधान नहीं रखा गया है इस लिए खाद्यान्नों को उनके हिसाब से परहेज से रखा जावे अन्यथा यौगिक केन्द्र रखने से कोई फायदा नहीं होगा।

आपने यौगिक केन्द्र एक बनाया है, इसमें ठीक तरह से अच्छा काम चलायेंगे तो और जगहों पर भी यौगिक केन्द्र खोलने पड़ेंगे, और जगहों पर भी यौगिक केन्द्रों की लोग मांग करेंगे और बिना दवा के लोग ठीक हो जायेंगे।

तो में यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में डॉक्टरों का इन्तजाम होना चाहिये। दवाइयों के भण्डार यहां खुले हुए हैं, वहां लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, इतने बड़े शहर में केवल दो-तीन भण्डार हैं, लोगों को क्यू में खड़ा रहना पड़ता है। सर्विसेज वालों को सुबह १० बजे ऑफिस पहुंचना पड़ता है और शाम को ६ बजे घर जाते हैं; कोई समय उनको नहीं मिलता, इसलिये यह आवश्यक है कि दवाइयों के भण्डार और खोले जायं। दो-तीन भण्डार होने के कारण इन लोगों को दो-दो, तीन-तीन घंटे क्यू में खड़े रहना पड़ता है और हम कहते हैं कि हम चिकित्सा में सहायता दे रहे हैं। इस तरह की सहायता से तो वह दो-दो, तीन-तीन घंटे क्यू में खड़ा रहेगा और गैर हाजिर हो जायगा। इन लोगों की इस दिक्कत को दूर करने के लिये और अधिक दवाइयों के भण्डार खोले जायं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री मानसिंह महार (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष: आपकी पार्टी की तरफ से एक साथ चार बोलेंगे क्या?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): ये आपस में तय कर लें तब तक में बोल देता हूं।

श्री मानसिंह महार: क्यों?

श्री मानसिंह महार: उपाध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष मेडिकल एण्ड हैल्थ की मांग प्रस्तुत हुई है। इसके बारे में उस पक्ष के भी काफी लोग बोले हैं। उनके विचारों से भी यही जाहिर होता है कि यह महकमा सही ढंग से नहीं चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह महकमा ऐसा है कि जिसके सिर नहीं है। में यह कहना चाहता हूं कि यह बिना सिर का महकमा है।

श्री भैरोंसिंह: पैर भी नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार: पैर-वैर तो हैं या नहीं, में नहीं कह सकता; पर यह हैड लेस डिपार्टमेन्ट है। इसके दो डाइरेक्टर्स तो रिटायर हो गये हैं पर कन्फर्म नहीं हुए।

(श्री मानसिंह महार)

तीसरा डायरेक्टर भी अधर-झूल लटकाया हुआ है। इसमें जो यह भारी गड़बड़ हो रही है इसका मुख्य कारण यह है कि डाइरेक्टर को कन्फर्म नहीं किया जाता है, क्योंकि कन्फर्म कर दें तो डाइरेक्टर मन्त्री महोदय की सुनें नहीं। अभी तो डाइरेक्टर के सिर पर तलवार लटकती रहती है कि यदि मैं जो मन्त्री महोदय हुक्म देते हैं वह नहीं करूंगा तो वे यह कर देंगे, वह कर देंगे।

तो मैं माननीय सदस्य, राजाखेड़ा से आने वाले मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम जिनको भी बनाना चाहें, मैं किसी की सिफारिश नहीं करता, जिस पर आपकी असीम कृपा हो उनको ही डाइरेक्टर बना कर कन्फर्म कर दीजिये। यह मैं इस लिये कहता हूं कि राजस्थान में यह हवा चल रही है कि कैबिनेट री-शफल होने वाली है और राजाखेड़ा से आने वाले मन्त्री महोदय का प्रमोशन भी होगा, कोई इम्पोर्टेन्ट पोर्टफोलियो दिया जायगा, क्योंकि वे ऐसा महसूस करते हैं कि जो पोर्टफोलियो इस समय उनके पास में है वह उनके लिये सम्मानजनक नहीं है। तो जाते जाते यह काम तो पूरा कर जाइये। तो जो सबसे बड़ी गड़बड़ इस विभाग में है वह यह है कि इस विभाग के डाइरेक्टर अनकन्फार्ड है।

दूसरा जो मामला है उसके बारे में मैं आज से नहीं, सन् १९५२ से कहता चला आ रहा हूं; वह यह है कि अस्पताल हैं, स्टाफ है, दोनों ही हैं, तो भले ही आप चल कर देख लीजिये वहां दवाएं नहीं हैं। अगर कहीं दवाई बची-खुची पड़ी है और अस्पताल की बिल्डिंग भी है तो वहां डॉक्टर नहीं है। आप चल कर देख लीजिये, मैं आपको बताऊंगा। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी नहीं होनी चाहिये। इस महकमें में आप कम से कम यह तय कर लीजिये कि अस्पताल कहीं होगा तो वहां पर डॉक्टर भी होगा, स्टाफ भी होगा और दवाइयां भी होंगी। अगर इन तीनों चीजों का सामन्जस्य नहीं होता है तो आपका अस्पताल खोलना बेकार है। वह अस्पताल अस्पताल नहीं, जनता को लाभ पहुंचाने वाली चीज नहीं, वह अस्पताल तो जनता को बरबादी करने वाली चीज होगी। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे देहातों के अस्पताल में दवाइयों की कमी है उसको दूर करने का प्रयत्न कीजिये, यह मैं कर-बद्ध प्रार्थना करता हूं।

दवाइयों के अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर एक डिफिकल्टी है वह फीमेल नर्सेज की है। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं मन्त्री महोदय को कि वहां फीमेल नर्सेज नहीं रखते हैं, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। किसी आदमी को सीरियस बीमारी होती है तो फौरन उसको जयपुर लाया जा सकता है या जिले के हैड क्वार्टर पर ले जाया जा सकता है पर गांवों के जच्चाखानों में अगर आप नर्सेज नहीं रखते हैं तो आप अपनी माताओं और बहिनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अगर फीमेल नर्सेज राजस्थान में नहीं मिलें तो आप राजस्थान के बाहर से लाइये, केरल से बहुत सी नर्सेज बुलाई हैं, वे ट्रेनिंग में हैं; तो मेरा निवेदन है कि राजस्थान की महिलाओं के हित के लिये यह आप कीजिये। आज जब कि एक महिला को भारत का प्रधान मंत्री बना दिया और हमारे यहां यह हाल है कि महिलाओं के लिये फीमेल नर्सेज नहीं हैं, यह बड़े दुख की बात है।

Page No. 83

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : मिनिस्टर लोग तो यहीं रहते हैं, उनका तो इलाज हो जाता है ।

श्री मानसिंह महार : मिनिस्टरों की बात छोड़िये, मिनिस्टर लोगों को तो कुएं में जाने दीजिये, आप क्यों इनकी बात करते हैं, मैं इनकी बात नहीं सुनना चाहता । इनके क्या कमी है, इनके घरों में डॉक्टर्स चपरासी की तरह घूमते हैं । यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं होती तो सब कुछ हो जाता । यह मिनिस्टर नहीं होते हैं तब तक तो जनता जनार्दन के सेवक बन जाते हैं और मिनिस्टर बनते ही खुदा के पैगम्बर बन जाते हैं, मिनिस्टर की मोटर पर लगी प्लेट इनकी पैगम्बरी का निशान है । ये जो लोग आन्दोलन करते हैं, उनको लाल प्लेट की मोटर जलाओ से आन्दोलन करना चाहिये और उस आन्दोलन में एक-आध मंत्रीजी भी जल जाय तो डरे और इनकी मोटरें दिमाग आसमान में घूमता है वह नहीं घूमे ।

इसलिये मैं कहता हूं कि गांवों की महिलाओं की भलाई के लिये गांवों में जच्चाखाने खोलें और वहां फीमेल नर्सेज की व्यवस्था करें ।

मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं, मौजूदा मेडिकल एण्ड हैल्थ के मंत्री हैं वे एक्सपर्ट हैं । मैं इनको आज से नहीं जानता, १९४५ से जानता हूं, पर जो बात है वह तो कहनी ही चाहिये, जो आम लोगों के दुःख दर्द की बातें हैं उनको सदन के समक्ष रखना ही चाहिये इसलिये रख रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : एक्सपर्ट किस बात के हैं ?

श्री मानसिंह महार : इस बात के एक्सपर्ट हैं कि कोई भी बात इधर से सुनी और उधर से निकाल दी । जबाब देंगे तो ऐसे प्रेम से देंगे कि ऐसा मालूम होगा कि मंत्रीजी बड़े सीरियस हैं, पर जवाब देते हैं तो उस मामले को एक दम गोलमाल ही कर देते हैं ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : जितना सीरियसली आप कहते हैं उतना ही सीरियसली वे भी जबाव देंगे ।

श्री मानसिंह महार : हमारे चेयरमैन साहब, आप तो उनकी पैरवी करोगे ही ।

हमको अमरीका सरकार से प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स खोलने के लिए काफी पैसा मिला है । इन सेंटर्स के लिए भी जो पैसा वहां से आता है उसमें भी हमारी सरकार इतनी गडबडी करती है कि मैं तो उसको क्रिमिनल वेस्ट कहता हूं, उस पैसे का सरकार क्रिमिनल वेस्ट करती है । अमरीका सरकार जो इन सेंटर्स के लिए पैसा देती है उनमें कुछ बातें उन्होंने रखी हैं, उन्होंने शर्तें रखी हैं । लेकिन इन इंटरनेशनल शर्तों को भी तोडने में हमारी सरकार एक्सपर्ट है । प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स खोलने के लिए सबसे बडी शर्त यह है कि ये सेन्टर वहां खुलेंगे जहां पर पहले अस्पताल न हों, लेकिन गोविंदगढ पंचायत समिति में इस सरकार ने अमरीका सरकार से धोखा करके कालाडेरा में सेंटर खोला, जहां पर पहले अस्पताल मौजूद था । उस अस्पताल में यह सेन्टर खोला गया । अमरीका सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिये गोविंदगढ ट्रांसफर किया । उस समय के डाइरेक्टर ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज ने बहुत ऐतराज किया कि जब कालाडेरा में अस्पताल मौजूद है तो वहां सेंटर नहीं खुलना चाहिए,

(श्री मार्नसिंह महार)

लेकिन इस मंत्री की नहीं, इनसे जो पूर्व मंत्री थे उनकी मजबूरी थी, उनके पिट्ठुओं ने पूंछ हिलाई तो वह सेंटर कालाडेरा में खोला। और ऐसी जगह जहां अस्पताल नहीं था वहां खोलते तो जनता को लाभ हो सकता था। एक फोरिन देश, जो हमारी मदद करना चाहता है, उसके साथ धोखाबाजी की बात हो तो यह उचित नहीं है। यह वर्तमान हैल्थ मंत्री की बात नहीं है, यह उनके पूर्वजों की बात है। इसलिये इसकी कम से कम जांच करें। अभी आपके आका हाकिम बैठे होंगे, शाम को जब सदन में जवाब दें तो बताएं कि क्या किस्सा है।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स में कहीं जीप नहीं होती है, वह प्राइमरी हैल्थ सेन्टर क्या हुआ, अगर डॉक्टर के पास वाहन नहीं है। वह अस्पताल क्या हो गया जो एक पर्टीक्यूलर गांव को ही केटर करे। तो आप सेंटर खोलते समय वाहन का भी इंतजाम करें और उन डॉक्टरों को हिदायतें जारी करें कि आस-पास के गांवों में खूब घूमें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि कल परसों जनरल डिस्कशन में भी कहा था फैमिली प्लानिंग के बारे में, इसलिये उस चीज को यहां छोड़ता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि फेमिली प्लानिंग को अगर सफल बनाना है तो ट्रेजरी बेंचेज पर जितने आदमी बैठे हैं वे अगर, जिनको तीन से अधिक बच्चे हो गए हों, वे वेसोक्टामी ऑपरेशन जरूर करवाएं।

श्री भैरोंसिंह : जिनके दो-तीन से ज्यादा बच्चे हो गए वे मंत्री पद के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए ?

श्री मानसिंह महार : जिन्होंने अधिक संतान पैदा की हैं उनको कुछ खाने-पीने का जरिया होना चाहिए और ऐसे बच्चों की भी किस्मत है। आपकी तरह थोड़े ही है कि एक ही बच्ची है वह भी न मालूम किसी आशीर्वाद से पैदा हुई, इसलिए आपको चिंता नहीं। मुझे तरस आता है जिनके मेरी तरह ८-८, ९-९ बच्चे हैं, उनका क्या होगा, इसलिये यह शर्त नहीं लगाएं। तो मैं ऐसे मंत्रियों से कहूंगा कि वे ऑपरेशन करवाएं।

श्री भैरोंसिंह : तब तो आपका नम्बर आएगा।

श्री मानसिंह महार : मेरा नंबर नहीं आएगा।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जयपुर शहर में जो अस्पताल हैं वे बहुत कम हैं। इन अस्पतालों में जितने मरीज जाते हैं, उनकी हालत बहुत खराब होती है। यहां पर जब से मेडीकल कॉलेज खुला है तब से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और जयपुर के जनाना अस्पताल की हालत ऐसी खराब हुई है कि मैं मानता हूं कि इस संबंध में सरकार की मजबूरियां हैं; लेकिन फिर भी सुधार की बहुत गुंजाइश है।

सवाई मानसिंह अस्पताल एक ऐसी जगह है कि जिसमें अगर आप सही ढंग से इंतजाम करें, यहां पर मैं कोई लांछन नहीं लगाता कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार कर रही है, फिर भी गुंजाइश बहुत है। इस अस्पताल पर बहुत कुछ हो सकता है, आपके पास बहुत कमी है, इसमें सुधार करने की कोशिश करें। वहां पर खाने की जो व्यवस्था है मरीजों के लिये, वह भी ठीक

(श्री मानसिंह महार)

नहीं है। उसमें केवल वहां की मैनेजमेंट की ही गलती नहीं है। वहां जो दूध आता है, वह बहुत खराब आता है। वहां के मैनेजमेन्ट वालों से हमने बात की। हमने कहा, दूध खराब आता है तो वह बोले, "मानसिंह, किसको कहें, चोर की मां मटके में मुंह देखकर रोती है"। दूध ठेकेदार का आता नहीं है, हमारी दुग्ध वितरण योजना का आता है, अब वह योजना भी सरकार की, तब भी अगर दूध में पानी मिलाया जाय तो बताइये किसका दोष ? उस योजना के बहुत बड़े अधिकारियों से मैंने बातचीत की तो वे बोले–"दूध और पानी का ऐसा मेल है कि हम मजबूर हैं।" मंत्रीजी, आप हंसिए मत, मेरी पार्टी के माननीय सदस्य ने दो बोतलें सदन की मेज पर रखी हैं। परसों के दिन उन बोतलों का केमीकल एग्जामिनेशन हुआ। उसमें लिखा है कि पानी मिला हुआ है। वह स्थगन-प्रस्ताव एक-दो दिन में डिस्कस होगा। मैं जानता हूं कि सदन में जो कुछ कहा जायगा उसका होगा कुछ नहीं। पहले अच्छी पैकिंग बोतलों पर आती थी। अब दुग्ध वितरण योजना वाले इतने डाकू हो गए कि कागज का पैकिंग लगा कर फिर निकाल कर पानी मिलाते हैं। अब मुकदमा लगाएं तो पकड में आते नहीं, वे कहेंगे कि एडल्ट्रेशन कहां हुआ, कोई शिकायत करे कि दूध में पानी मिला हुआ है तो उसी को ही चोर बनाएंगे कि तुमने डाटा खोल कर उसमें पानी डाला है। यह हालत है उस योजना की।

तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जयपुर के अस्पतालों की हालत सुधारें। जब तक जयपुर के अस्पताल की हालत नहीं सुधरेगी तब तक आपके विभाग की वाहवाही नहीं होगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आपने दुकानें खोलीं। मैं जानता हूं कि आप प्रयत्नशील बहुत हैं और उसमें थोड़े कामयाब हुए, लेकिन उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। आपके सामने बहुत अड़चनें हैं। आपके ऊपर आपके लोगों का ही बहुत दबाव है, इसलिये अगर रीएम्बर्समेंट को बंद करके दूकान वाले मामले को सही ढंग से चलाना चाहें तो आपको इतनी दूकानें खोलनी चाहिए कि किसी को कहने की आवश्यकता न पड़े। अगर ज्यादा दूकानें खोलने में असफल होते हैं तो यह स्कीम आपकी फेल होगी और आपका काला मुंह करेगी, आप बदनाम होंगे। या तो ज्यादा दुकानें खोलने की व्यवस्था करें और अगर वह नहीं करते हैं तो फिर आप इन दूकानों को बंद करें।

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय.........

श्री मानसिंह महार : मैंने अभी कन्क्लूड ही नहीं किया है। पहले मैं कन्क्लूड तो कर लूं।

मैं यह तो रिएम्बर्समेन्ट के विषय में निवेदन कर रहा था।

मुझे किसी इन्डिविजुअल केस में नहीं जाना है। डॉक्टरों की बुराई नहीं करनी है। जो कुछ स्टाफ आपके पास है वह खराब नहीं है। खराबी है आपके सुपरविजन की। आप सुपरविजन सही ढंग से नहीं रख सकते हैं, इसलिये आपस में रगड़े-झगड़े चलते हैं। जयपुर में न हो, बाहर तो बहुत पार्टीबाजी होती है। इसलिये उन पर पूरा सुपरविजन

(श्री मानसिंह महार)

कीजिये। मेंडीकल कॉलेज में पक्षपात नहीं रखेंगे और सही तरीका रखेंगे तो उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है कि दो मेडिकल कॉलेज नये खोले और उनके खोलने से सरकार का खर्चा तो काफी बढा लेकिन सीट्स थीं वे नेग्लीजिबल बढी हैं। आपने जयपुर में सीटें कम कर दीं उसके बजाय दूसरी जगह कर दीं और दो नये मेंडीकल कॉलेज का नाम कर दिया। नाम कर देने से कुछ नहीं होता है। आपको सोचना चाहिए कि आपने सीटें कितनी बढायीं। आप यह सूचना दीजिये कि इतनी दो मेंडिकल कॉलेजेज में सीट्स बढायीं। तब आपकी नेकनीयती पर विश्वास होगा कि मेंडीकल कॉलेज में इतने अधिक लडकों की व्यवस्था की। मंत्रीजी यह बतायें तो संतोष होगा। दो मेंडीकल कॉलेज खोलें तो ओवर ऑल छात्रों की संख्या ३०-३५ बढी होगी।

एक माननीय सदस्य : २५ ही है।

श्री मानसिंह महार : मैं उसको दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा। दो सौ, तीन सौ छात्रों की संख्या बढी होगी तो यह सार्थक है।

श्री भैरोंसिह : माननीय उपाध्यक्ष...

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले कि माननीय भैरोंसिहजी को इजाजत दी जाय मैं एक पर्ची पढ देता हूं, जो मेरे पास आयी है। विशेष तौर से आज जब मेंडिकल मांग पर विचार चल रहा है तो यह पर्ची और विचारणीय है इसको पढ देता हूं।

श्री भैरोंसिह जी को आज डॉक्टर ने हार्ट परेशानी के कारण बोलने से मना किया है, किन्तु वे नहीं मान रहे हैं। अतः उन्हें नहीं बोलने दिया जाय स्वास्थ्य की दृष्टि से।''

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : डॉक्टर कौनसा है ?

श्री भैरोंसिह : वही जो चेयर पर है।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय ने इजाजत दे दी।

श्री उपाध्यक्ष : इजाजत इस शर्त के साथ है कि धीरे से बोलेंगे और संक्षेप में बोलेंगे।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसे तीन विभाग हैं जो तीनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक आयुर्वेद और दूसरा मेंडीकल, जिसमें आयुर्वेद वैसे शामिल है और एक ट्रान्सपोर्ट है। अच्छा तो यह होता कि ये दो विभाग अलग अलग समय के ऊपर वाद विवाद के लिये सदन में प्रस्तुत किये जाते। लेकिन जैसी भी व्यवस्था है उसके अनुसार चलने के लिये इस सम्बन्ध में आज ही कुछ विचार निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आल इन्डिया लेवल पर मेंडीकल पोइन्ट ऑफ व्यू से किसी भी आइटम के ऊपर अभी तक नहीं पहुंच पाया है। राजस्थान में डाक्टरों की कमी है, होस्पिटल्स की कमी है, होस्पिटल फेसिलिटीज की कमी है और उसके साथ साथ दवाइयों की भी कमी है। सेनिटेशन के लिये जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उसकी भी कमी है और उस सबका परिणाम

(श्री भैरोंसिंह)

राजस्थान की जनता को भोगना पडता है। आज उसके साथ जो कुछ भी हम खर्च कर रहे हैं उसका कितना उपयोग होता है उस सम्बन्ध में यदि थोडा सा विचार कर लिया जाय तो स्थिति और भी सामने आ जायगी। मेडीकल विभाग की आलोचना करने के खातिर से खडा नहीं हुआ हूं। और कम से कम कोई बीमार आदमी मेडीकल विभाग की आलोचना करता है तो वह खतरा मोल लेकर उसकी आलोचना करने का साहस करता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि यदि उचित ढंग से उसकी आलोचना की जाय तो हानि के स्थान पर निश्चित रूप से लाभ होगा।

मैं इसी सवाई मानसिंह होस्पिटल को अपने सामने रख कर, सदन के कई माननीय सदस्य वहां गये हैं, इतना कह सकता हूं कि उस होस्पिटल की बेड शीट्स, चद्दरें, उस होस्पिटल में मरीजों के पहनने के कपडे और उस होस्पिटल में मरीजों को मिलने वाली खुराक, इन तीनों का मुकाबला राजस्थान की जयपुर की जेल के कैदियों से किया जाय तो निश्चित रूप से कहूंगा कि कैदियों के कपडे, सोने-ओढने और बिछाने के कपडे, साफ और कैदियों की रोटियां अच्छी होंगी। इससे अधिक इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है और मंत्री महोदय स्वयं जानते होंगे, मैं ऐसा नहीं मानता कि नहीं जानते होंगे, काले रंग की बेड शीट। उसके साथ साथ दूध भी मिलता है। दूध कैसे मिलता है उसका उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन बिलकुल निकृष्ट टाइप का दूध मिलता है। अब आगे चलिये दवाइयों का हाल। उपाध्यक्ष महोदय, होस्पिटल में रहने वाला व्यक्ति होस्पिटल की दवाइयों से उसका इलाज नहीं हो सकता है। गरीब है तो ज्यादा दिन उसको अस्पताल में रहना पडेगा होस्पिटल में रह कर होस्पिटल की दवाइयों से इलाज कराना चाहे असंभव, होस्पिटल के रोगी को बाहर से दवाइयां खरीद कर इलाज कराना पडेगा, वह नहीं करा पाता है तो समय अधिक लगेगा या मरेगा। तकदीर से ठीक हो जावेगा तो हो जावेगा।

इसके अतिरिक्त इस राजस्थान की सरकार के पास इस प्रकार की शिकायत है कि मरीज ऑपरेशन टेबल पर है और डॉक्टर उससे पैसा लेता है। इस राजस्थान सरकार को यह भी मालूम है कि जयपुर कलेक्टोरेट के अधिकारी के बच्चे के पैर में कुछ गडबड हो गयी थी, पोलिया हो गया था। बांये पैर में पोलिया और बांये का आपरेशन होना चाहिये था, लेकिन दाहिने पैर का डाक्टर ने ओपरेशन कर दिया। मंत्री लोग राजा महाराजाओं की चर्चा करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि राजा महाराजाओं के राज्य में यदि कोई डाक्टर बांये पैर के आपरेशन के बजाय दाहिने पैर का आपरेशन कर देता तो वह डाक्टर हॉस्पिटल में नहीं रहता लेकिन जेलखाने में रहता। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ के बुद्धदेवजी के लडके को टिटानस हो गया। उसको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया और मुझे जानकारी मिली कि मंत्री महोदय ने टेलीफोन भी किया कि आक्सिजन दिया जाय। सलेन्डर भेज दिया उसमें आक्सिजन नहीं थी लेकिन इन्जेक्शन लगा दिया और उसके बाद उप मंत्री श्री निरंजननाथजी आचार्य वहां गये और उन्होंने आंखों से देखा कि ओक्सिजन के

(श्री भैरोंसिंह)

सलेन्डर में ओक्सीजन नहीं है लेकिन लडके को लगा हुआ है, लडका मर गया। आचार्य-जी बाहर निकले। शराब पीये हुए वार्ड बोय मिला। उन्होंने उसको कहा कि तुमने शराब पी रखी है। उसने उनको कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। यह तो मंत्री महोदय के साथ होता है टेलीफोन आप करते हैं उसके साथ होता है। पब्लिक के साथ क्या होता होगा आप सोच सकते हैं।

विजिटर्स कमेटी बना रखी है। चेयर-मैन है। ऑफिशियल और नोन-ऑफिशियल उसके मेम्बर हैं। एक दफा देखा था, फिर भी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। वार्ड में कभी चक्कर लगाया, कभी पेशेन्ट्स से पूछा कि डाक्टर से कोई उनको तकलीफ है ? नहीं पूछा। होस्पिटल्स में जायं तो डॉक्टर्स के आपस में गुट, कम्पाउन्डर्स के आपस में गुट, मेल और फिमेल नर्सेज के आपस में गुट। एक के ट्रीटमेन्ट में दूसरा दखल नहीं करेगा, यह सोचा जा सकता है कि एक के ट्रीटमेन्ट में दूसरा दखल न करे लेकिन गुट-बन्दी ऐसी आयी है जिससे पेशेन्ट्स की हेल्थ पर असर होने लगा है। कम्पाउन्डर्स और नर्सेज में मेल नहीं और इसलिये नहीं कि राज्य सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में यह मान कर चलती है कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमीनेशन नहीं करेगी। नर्सेज और कम्पाउन्डर्स मेल और फीमेल दोनों जब एक जगह ट्रेनिंग लेते हैं, एक प्रकार का काम करते हैं, एक प्रकार की ड्यूटी देते हैं उसके बावजूद भी दोनों के वेतन में अन्तर। एक का तो ९० से शुरू होता है, फीमेल नर्सेज का १३० रुपया होता है। यह समझ में नहीं आता कि जब मेल कम्पाउन्डर्स और फीमेल नर्सेज दोनों एक प्रकार की ड्यूटीज देती हैं तो उनके वेतन में अन्तर क्यों रखा गया ?

एक तरफ तो आप भारत सरकार को लिखते हैं कि केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में अन्तर नहीं होना चाहिये लेकिन इस प्रकार लिखने से पहले अपने विभाग में जो अन्तर चल रहा है उसको तो आप कम करते। आपके विभाग में मेल और फीमेल नर्सेज जिनकी ड्यूटी एक प्रकार की होती है फिर भी उनके वेतन में असमानता है। अजमेर से कई कम्पाउन्डर यहां आये उनका १९६० में एक बार प्रोवीजनल फिक्सेशन कर दिया गया, लेकिन आज तक उनका फाइनल फिक्सेशन नहीं हुआ है इस कारण उनको इन्क्रीमेन्ट नहीं मिलता। एक तरफ जहां कम्पाउन्डर्स और नर्सेज में असन्तोष है दूसरी तरफ बीकानेर की घटना से जिसमें एक डाक्टर द्वारा एक मरीज के साथ रेप करने के कारण जनता में बडा भारी असन्तोष है। यह बात माननीय मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि लोगों की आस्था इस चिकित्सा व्यवस्था के प्रति सरकारी डाक्टरों के प्रति निश्चित रूप से खतम हो रही है।

इसके साथ साथ में यह कहना चाहता हूं कि डाक्टर्स के अन्दर भी प्रोमोशन को लेकर बडा झगडा है। इसके कारण डाक्टरों को कोर्ट में जाकर रिलीफ सीक करना पडता है यह राज्य के लिये बडे दुर्भाग्य की बात है। एक किसी डाक्टर को प्रोमोशन देने के लिये गलत रूल बना दिये गये अगर उससे किसी के फन्डामेन्टल राइट्स को आघात पहुंचता है तो वह कोर्ट्स में जाकर उसके लिए रिलीफ सीक करता है। आखिर इस

Page No. 89

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार रिलीफ सीक करने के क्या कारण हैं इस पर सरकार को विचारना चाहिये। आखिर जो डाक्टर हैं वे बहुत बढ़िया पैसा पैदा करने में लगे हुए हैं उनके लिये इस प्रकार की स्थिति आवे यह बहुत बुरा है। मैं जब यह कह रहा हूं किसी के साथ दुश्मनी हो इस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मरीज दुख पाते हैं सरकार उनके लिये खर्च करती है उसके बावजूद भी जनता को आराम नहीं मिलता। माननीय मंत्री महोदय नये आये हैं उनको इन बातों के बारे में विचार करना चाहिये। इसी का परिणाम है कि मंत्री महोदय यह नहीं कह सकते कि राजस्थान में एक भी हॉस्पीटल ऐसा है जो परफेक्ट कन्डीशन में हो। एक भी हॉस्पीटल के बारे में वे नहीं कह सकते। किसी का सुपरवीज़न अच्छा नहीं है।

मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। लोगों के सामने कमाई का सवाल रहता है कि कमाई किस प्रकार से की जाये। मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट का सवाल सरकार के सामने आया। सरकार ने उसमें जो अनियमितता या कुछ गड़बड़ियां देख कर उनके लिये स्टोर्स खोलने की व्यवस्था की। यह व्यवस्था उचित है लेकिन अपूर्ण जरूर है। ज्यादा इस प्रकार के स्टोर्स खोल कर जो क्यू में खड़े होने की नौबत आती है वह नहीं है तो यह व्यवस्था ठीक है। साधारणतः किसी कार्य को सुधारने के लिए कोई काम किया जाय उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कुछ लोगों का इन्टरेस्ट खत्म हो गया सरकार को इस पोइन्ट पर विचार अवश्य करना पड़ेगा कि लोगों को दवाई प्राप्त करने के लिये तीन तीन घंटा क्यू में खड़ा रहना न पड़े, ज्यादा स्टोर्स खोलें, ज्यादा सेल्समेन अपोइन्ट करें, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिसपोज कर सके यह व्यवस्था आपको करनी चाहिये। अगर नहीं करेंगे तो अच्छी चीज के प्रति भी लोगों की शिकायतें बनती जायेंगी।

रिएम्बर्समेन्ट की बात क्यों पैदा हुई? डाइरेक्टर साहब के खिलाफ माननीय सदस्य बोल रहे थे। मैं उन बातों में नहीं जाता लेकिन एक लेटर पोस्ट ऑफिस, जयपुर के सी० पी० ओ० ने डाइरेक्टर महोदय को लिखा है, वह मैं आपको सुनाता हूं:

"The following authorised medical attendants are still following malafide practices in prescribing medicines and signing the re-imbursement bills.

1. Shri S. K. Sharma
2. Shri Jagat Ram
3. Shri Uma Yagnik
4. Shri Ramesh Sharma
5. Shri B. K. Sharma
6. Shri S. Khunteta
7. Shri K. C. Pareek"

यह लेटर २७ अक्टूबर, १६६५ का है जिसमें विस्तार से लिखा है कि किस प्रकार से रिएम्बर्समेन्ट के बिल बनते हैं, बीमारी क्या है, दवाई क्या प्रेसक्राइब कर दी जाती है। जो दवाई एक दिन में हजम नहीं कर सकते वह एक दिन के लिये दे दी जाती है इस तरह की बातों को लेकर एक बड़ा लम्बा-चौड़ा लेटर लिखा है। सारी इर्रेगुलेरिटीज किस प्रकार से रिएम्बर्समेन्ट बिल में होती हैं, किस प्रकार से झूठे बिल बनते हैं, झूठी दवाइयां प्रेस्क्राइब कर देते हैं। वह पत्र बहुत लम्बा है जिसको पढ़ कर हाउस का समय लेना नहीं चाहता उसमें और भी डाक्टर्स का रेफरेन्स है, माननीय मंत्री महोदय चाहेंगे तो दोनों लेटर्स उनको जानकारी के लिये दे दूंगा।

(श्री भैरोंसिंह)

अब प्रश्न यह आता है कि इनके खिलाफ शिकायतें होने पर भी इन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसके बजाय आपको मेडिकल स्टोर्स खोलने की व्यवस्था करने के लिये मजबूर होना पड़ा। मैंने पिछले साल भी एक शिकायत माननीय मंत्री महोदय को की उसके बारे में मंत्री महोदय ने बताया कि वह मामला एन्टीकरप्शन विभाग में चल रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं इस लिस्ट में डा० जैन का भी नाम है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मैं बताता हूं, इसमें तो है नहीं। दूसरे लेटर में है एस० के० जैन।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने मुझे इनके बारे में शिकायत की थी ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने एक नाम के लिये नहीं कहा था, इस प्रकार की शिकायतें निरन्तर आती रहती हैं। मैंने जब उसके बारे में एन्टीकरप्शन वालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहां ऐसी कोई जांच नहीं चल रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा था स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेन्ट एन्टीकरप्शन में जांच हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : इसके एस० पी० मि० परसानियां हैं उनसे भी जानने की कोशिश की, उन्होंने भी कहा कि इस प्रकार की हमारे यहां कोई इन्क्वायरी नहीं हो रही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपकी जानकारी के लिये निवेदन करदूं, इसकी इन्क्वायरी करके इसको चार्ज शीट भी दे दी है और कमिश्नर फोर डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरीज को इन्क्वायरी आॅफिसर मुकर्रर किया है इतने आदेश जारी हो गये हैं। एस. पी. स्पेशल एस्टेब्लिसमेन्ट की इन्क्वायरी रिपोर्ट पर यह एक्शन लिया है।

श्री भैरोंसिंह : उनका तो यह कहना था कि वे स्टेट गवर्नमेन्ट के एम्पलाई हैं इसलिये मैं उनके खिलाफ इन्क्वायरी नहीं कर सकता। उनका वह कहना भी ठीक था क्योंकि वे भारत सरकार से डेपुटेशन पर आये। भारत सरकार की स्पेशल एस्टेब्लिशमेन्ट ब्रांच के एस. पी. हैं। यह तो एक के खिलाफ एक्शन लेने की बात हुई, बाकी के खिलाफ भी एक्शन लेंगे, यह मैं आशा करके चलता हूं।

अब उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा मसला आपके सामने रखना चाहता हूं। टी. सी. एम. की सहायता के अन्तर्गत हमको २ करोड़ २३ लाख ११२ रुपये की मलेरिया इरेडिकेशन के लिये सहायता मिली। उसके द्वारा मलेरिया की रोकथाम के लिये युनिट्स चलते हैं, उसके लिये स्कीमें चलती हैं। इसमें कितना घोटाला है उसका एक आइटम मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं।

पहला आइटम तो यह है कि एक बार यह बताया गया था कि दो लाख डी. टी. टी. जिला गंगानगर में बह गया। जिस वर्ष का यह मामला है उस वर्ष गंगानगर जिले में अपेक्षाकृत वर्षा कम हुई थी। और वर्षा आये भी और उसमें बह जाय तो क्यों बह जाय ? दो दो लाख रुपये का माल बह जाता है यह कैसे माना जा सकता है ? वह माल बहा नहीं, मेरे पास इस बात की जानकारी है कि रेड ब्लड जो माल्टा होता है उसमें अगर इसकी

(श्री भैरोंसिंह)

खाद दे दी जावे तो उसके फल बहुत आते हैं वह इसके लिये बेचा गया और बता दिया कि फ्लड में बह गया, यह बिल्कुल गलत है। वह दिखाया जरूर गया कि फ्लड में बह गया। इस प्रकार के इस विभाग के मामले होते हैं।

उदाहरण के तौर पर निवेदन करूं, १९५७–५८ से लेकर १९६५ तक १२ लाख ६६ हजार रुपया गाड़ियों की मरम्मत के लिये खर्च किया गया और जिन गाड़ियों की मरम्मत की गई उनकी कीमत १० लाख ६३ हजार रुपया है। १० लाख ६३ हजार रुपये की गाड़ियों की मरम्मत के लिये १२ लाख रुपये का खर्चा। उसके अलावा टी. सी. एम. द्वारा गाड़ियों के स्पेयर पार्टस जो दिये गये उनकी कीमत २५ हजार २७५ रुपया है। इन गाड़ियों में अधिकारियों ने दौरे खूब किये, मलेरिया का उन्मूलन हुआ या नहीं यह भी सर्व विदित है। मेरे मकान के ऊपर आज से एक महीना पहले से एक बाबू आता है और पूछता है कि आपके घर में किसी को बुखार तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी तो नहीं आ रहा है। मैंने कहा मुझे कुछ बुखार है, तो उसने कहा कि यह मेरे पास इन्जेक्शन है वह लगवाइये। मैंने उसके पास जो सुई थी उसको देखा जिस पर जंग लगा हुआ था। वह सुई मैंने उससे ले ली और फेंक करके घर पर रख दी। आज मैं इत्तिफाक से लाया नहीं हूं। वह सुई कोई इन्जेक्शन लगाने वाली सुई नहीं थी कपड़े सीने वाली सुई थी। वह उससे मेरा ब्लड लेना चाहता था। मैंने कहा मैं इससे ब्लड नहीं दूंगा। उस समय जो मेरे पास डाक्टर बैठे हुए थे उन्होंने भी कहा कि बिना स्टरलाइज किए खून लेगोगे क्या ?

उसने कहा कि मुझे तो ऐसी ही दी हुई है। मैंने उससे यह सुई ले ली और मैंने उसको रसीद दे दी। उसने बताया कि जैसी मुझे दी है वैसी ही मैं लेकर आता हूं और उसी प्रकार का काम करता हूं।

अब इसमें सबसे बड़ी बात उन कारों के बारे में है जिसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि १९५४–५५ में एक ट्रक आया, १९५५–५६ में ४ आयें और एक स्टेशन वैगन १९५६–५७ में ५ जीप और १९५७–५८ में २५ हजार का रिपेयर का खर्चा हो गया। ५ कारों में २५ हजार का खर्चा रिपेयर में हो गया। एक बार एक एकाउण्ट्स की ए.जी. साहब ने जांच की तो उन्होंने अपनी जांच में लिखा है कि सारे अकाउण्ट्स का मैस हो रहा है। आज तक उसका कोई वैरीफिकेशन नहीं हुआ। कहते हैं कि फिजीकल वैरिफिकेशन नहीं हुआ तो कहते हैं कि जरूर होता है। लेकिन फिजिकल वैरिफिकेशन किससे, हुआ ? जो इनवोइसेस टी. सी. एम. से मिलनी चाहिए उसके आधार पर फीजिकल वैरिफिकेशन नहीं किया। उसके आधार पर वहां पर काम नहीं किया और इसका रिजल्ट है कि आपको भी धोखा देते हैं कि हमने फिजिकल वैरिफिकेशन किया है। मैं कहता हूं कि ईमानदारी से और ईमानदार अधिकारियों से फिजिकल वैरिफिकेशन कराया जाये तो बहुत घोटाले मिलेंगे। स्पेयर पार्टस पड़े हैं, स्पेयर पार्टस आप बाजार से खरीदते हैं। आपका वर्कशाप है वहां पर गाड़ियों की रिपेयर न करा कर प्राईवेट वर्कशाप में कराते हैं और लाखों रुपयों की लूट इस प्रकार से चल रही है। टी.सी. एम. से जो सहायता गरीबों की करने के लिए आती है उसका कोई उपयोग नहीं होता और अधिकारी लोग मर्जी आये उसी तरह से खर्च

(श्री भैरोंसिंह)

करते हैं। आप बतायें कि कितना ऑडिट किस किस साल हुआ? क्या ऑडिट भली प्रकार से हुआ? अगर मुझसे पूछा जाय तो ऑडिट भली प्रकार से नहीं हुआ। इस खर्चे को रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और यदि खर्चा नहीं रोक पाये तो यह हमारी बदकिस्मती है।

अब दूसरा विभाग उपाध्यक्ष महोदय, आता है आयुर्वेद का। मैं उसके बारे में विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जो रोगी बिलकुल लाइलाज हो जाता है उसी तरह से यह आयुर्वेद विभाग भी बिलकुल लाइलाज है। यह आयुर्वेद विभाग दूसरों का इलाज करने के लिये है, लेकिन इस विभाग का ही इलाज नहीं होता और जब तक इसका इलाज नहीं हो पायेगा तब तक न वैद्य सुखी होंगे और न रोगी ही सुखी होंगे। आज सबसे बड़ा संकट वैद्यों के संकट का है। वैद्यों के जितने भी स्थानान्तरण होते हैं उससे आज लोग कितने असंतुष्ट होते हैं इसको उप-मंत्री जी स्वयं जानते हैं। माननीय उप-मंत्रीजी ने एक बार कहा था कि जहां तक संभव होगा वैद्यों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा, अगर किसी गांव में कोई वैद्य पापुलर है तो उसको वहीं रख दिया जायेगा। लेकिन वैद्यों का स्थानान्तरण इस निर्दयता के साथ किया जाता है कि वैद्य जिसको ६०, ७० और १०० रुपये तनख्वाह के मिलते हैं उसको आप कभी जयपुर से बांसवाडा, बांसवाडा से कोटा, कोटा से अजमेर और कोटा से रायसिंहनगर भेज देते हैं। वैद्यों के इस प्रकार के ट्रांसफर्स होते हैं कि वह दुखी हैं, उनका मन नहीं लगता और जो सेवा वह कर सकते हैं वह नहीं कर पाते। दवाइयों में घोटाले होते हैं लेकिन कोई जांच करने की कोशिश नहीं करता। न लेबोरेटरी है कि जो दवाखाने में दवायें हैं कम से कम एक बार तो चैकिंग कर लिया जाये कि दवायें जिस नाम से ते हैं उसमें असली तत्व और असली पदार्थ हैं या नहीं। इसकी जांच आज तक आयुर्वेद विभाग ने नहीं की और नहीं करने का कारण यह है कि आयुर्वेद विभाग के मंत्री और उप-मंत्री दोनों के ऊपर डायरेक्टर है। मेडिकल विभाग में पोजीशन दूसरी है कि वहां पर डायरेक्टर मंत्री और उप-मंत्री के नीचे है, लेकिन इस विभाग में जो डाइरेक्टर है उसके नीचे मंत्री और उप-मंत्री दोनों हैं। यह उल्टा रिवाज जरूर है। हो सकता है कि एलोपैथी ट्रीटमेन्ट हो इसलिए यह जरूरी हो कि डाइरेक्टर के नीचे मंत्री और उप-मंत्री हों और आयुर्वेदिक ट्रीटमेन्ट में यह जरूरी हो कि मंत्री और उप-मंत्री को डाइरेक्टर के नीचे रखें।

तीसरा आता है ट्रांसपोर्ट विभाग। यह विभाग राजस्थान का मशहूर विभाग है। मंत्री भी इसके मशहूर हैं। कन्ट्रोल करना भी इसका चाहते हैं लेकिन दुर्भाग्य से इसका कन्ट्रोल नहीं होता और कन्ट्रोल हो भी नहीं सकता और कन्टोल इसलिए नही हो सकता कि विभाग में कन्ट्रोल करने के लिए पक्षपात जब तक है और वह दूर नहीं होगा तब तक कोई भी रोक नहीं सकता। अब पक्षपात के कुछ नमूने मैं इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार और उसका नियुक्त विभाग कई बार यह कहता

(श्री भैरोंसिंह)

है कि जब तक आवश्यकता नहीं होगी और उसके लिये सेंक्शन नहीं होगी तब तक कोई नियुक्ति नहीं की जाये और इस विभाग के अन्दर बहुत बड़ा विवाद चलता है कि इसमें जो एल. डी. सी. या यू. डी. सी. या और दूसरे कर्मचारी हैं जिनको सब-इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर बनाया जाये या नहीं और मैं सन् ५२ से देख रहा हूं कि सरकार की इस संबंध में बार बार नीतियां बदलती हैं। कोई मंत्री आते हैं वे कहते हैं कि क्लर्क सब-इंसपेक्टर हो सकता है और दूसरा मंत्री आता है और उसमें यदि उसका इन्टरेस्ट क्लैश होता है तो वह कहता है कि क्लर्क सब-इंसपेक्टर नहीं हो सकता। यू. डी. सी. को इंसपेक्टर नहीं बना सकते। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट में देखेंगे और सरकार की नीति और रूल्स को देखेंगे तो मालूम होगा कि इसमें बराबर आपको वैरियेशन्स मिलेंगे। माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि इनके आने से पहले जो यू० डी० सी०, एल० डी० सी० थे वह सब इन्सपेक्टर और इन्सपेक्टर थे, लेकिन जब यह आये तो उन्होंने उसको रोक दिया। अब रोक क्यों दिया इसके पीछे ऐसी कुछ बात है कि जो वह स्वयं जानते हैं। लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जमाने में माथुर साहब यह गड़बड़ी हुई कि आपने ६ सब-इन्सपेक्टर्स को नियुक्त किया जिनके लिये कोई एग्जामिनेशन नहीं, कोई एडवर्टाइजमेन्ट नहीं और कोई जगह नहीं। तो यह नियुक्ति कैसे हो गई और किस आधार पर होगई? ८ के तो अपोइन्टमेन्ट लेटर्स मेरे पास हैं। इस में उपाध्यक्ष महोदय, कोई सलेक्शन नहीं, कोई एडवर्टाइजमेन्ट नहीं और कोई पोस्ट सेंक्शन नहीं फिर गवर्नमेन्ट ने ८ व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया, सब-इन्सपेक्टर के नाते मैं पूछना चाहता हूं कि वह सब-इन्सपेक्टर कहां गए

श्री परसराम मदेरणा (उप मंत्री, आबकारी) : टेम्पोरेरी थे।

श्री **मथुरादास माथुर** (योजना मंत्री) : मैं जवाब दूंगा।

श्री **भैरोंसिंह** : टेम्पोरेरी थे, बिल्कुल सही है। इसमें भी लिखा है। लेकिन वह क्यों हुए? वह टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स क्यों हुए? और उसके बाद में जब आप सलेक्शन करने लगे तो आपने एडवर्टाइजमेन्ट किया, एडवर्टाइजमेन्ट के बाद में सिलेक्शन बोर्ड बैठा और बोर्ड के अन्दर कुछ व्यक्ति आये नहीं, इसलिए आपने १२ की पोस्ट को ही डिजाल्व कर दिया और वह अपोइन्टमेन्ट्स क्यों नहीं हुए, क्या आप बता सकते हैं? जिस दिन हमारे आदमी नहीं आए उस दिन वैकेन्सी हो जाए और जिस दिन हमारे आदमी आ जायें तो वेकेन्सी नहीं। यह चलने वाला नहीं है। सरकार बताये कि १२ या ७ का अपोइन्टमेन्ट किया वह कौनसी इमरजेन्सी थी कि आप उन पोस्टों को बाकायदा एडवर्टाइज नहीं करा सकते थे। कौनसी आवश्यकता थी कि जिसके कारण यदि उन सब-इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति नहीं की जाती और फिर मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई हैं उनको किसने जाकर कहा कि ट्रान्सपोर्ट विभाग में जगह खाली हैं और तुम अर्जी देदो। एक ने देदी तो बाकी ४ को कैसे मालूम हुआ और ४ ने दे दी तो पांचवें को कैसे मालूम हुआ। इसका

(श्री भैरोंसिंह)

मतलब यह है कि जिस आदमी की नियुक्ति की जाती है उसके लिए जगह बनाई जाती है। जगह खाली नहीं होती बल्कि किसी पर्टीकुलर आदमी के लिए जगह बनाई जाती है और फिर उसको रखा जाता है। यदि जगह खाली हो तो उसको भरने का जरिया होता है और वह जरिया है पब्लिक सर्विस कमीशन का। लेकिन राजस्थान का रिवाज उल्टा है। राजस्थान में जगह खाली नहीं होती बल्कि जगह बनाई जाती है और किसी पर्टिकुलर परसन को एकोमोडेट करने के लिए बनाई जाती है और उसी प्रकार से यह जगह बनाई गई। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूं कि इस विभाग के अन्दर विभागाध्यक्ष का कन्ट्रोल नहीं रह सकता। मेरी यह मान्यता है कि इसमें जो अधिकारी हैं वे ईमानदार हैं और उनकी इन्टीग्रिटी के बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है लेकिन मुझे बहुत बडी शिकायत है कि वह आदमी पोलिटिक्स में भाग लें, कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें और चन्दे के लिए पैसा वसूल करें।

मैंने आपके आर०टी०ओ और ए०आर०टी० ओ० के लिए कहा आप मानेंगे। मैं आपको एक बैंक का चैक दूंगा जो कि एक आदमी ने दिया है भीलवाड़ा से। उन अधिकारी के बारे में मैंने डाइरेक्टर महोदय से शिकायत की तो उन्होंने सुना नहीं। अब वह क्यों नहीं सुनते वह देखते हैं कि विभाग के अध्यक्ष हैं माथुर साहब और जब वे स्वयं गडबड़ी कहते हैं तो मुझे क्या कहेंगे। अब उनको पता लगा कि माथुर सहाब ने क्या गड़बडियां कीं तो वे सोचते हैं कि एक मंत्री को दबाने के लिए जरूरी है कि मंत्रीजी किस प्रकारकी गड़बड़ी कर रहे हैं। वह गड़बड़ी छोटी हो या बड़ी, इसकी मैं नहीं कहता। यदि मंत्री सावधान होंगे तो अधिकारी भी सावधान होंगे और यदि अधिकारी सावधान होंगे तो उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी सावधान होंगे। मंत्री महोदय इसका जवाब दें कि मैंने आपके हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट को शिकायत की तो उसका एक्शन क्यों नहीं लिया? या तो मुझे झूंठा सिद्ध करो या उनको झूठा सिद्ध करो। यदि वे झूठे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? मुझे अफसोस तो इस बात का है कि सर्विसेज में भी जो अधिकारी हैं और जिनकी इण्टीग्रिटी पर, उनकी ईमानदारी पर हमें नाज है आज वे ही अधिकारी इतने डि-मोरेलाइज होते जा रहे हैं कि वे भी सही बात को करने को तैयार नहीं होते; तो यह राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कार कन्ट्रोल आर्डर के मातहत लोगों को गाड़ियां मिलती हैं। सरकार का कोटा है उस कोटे से लोगों को गाड़ियां दो जाता है। आज तक जो मंत्री थे उन्होंने क्राइटेरिया फिक्स अप कर रखा था सरकार के अन्दर इस प्रकार का सोच रखा था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस प्रकार की व्यवस्था है हालांकि रूल्स में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार ने यह तय किया कि फस्ट कम फस्ट सर्व। लेकिन आज गाडियां किनको दी जाती हैं, जिन पर हमारी कृपा है उनको गाड़ियां दी जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि सरकार ने कान्ता खतूरिया को किस आधार पर कार दी? यह कौनसी सोशियल वर्कर हैं? आज तक हमारी सरकार ने, उस महिला की वर्च्यूज को पहिचानने की कोशिश नहीं की कि वह कैसी सोशियल वर्कर है, किस प्रकार

Page No. 95

(श्री भैरोंसिंह)

के उसके वर्च्यूज हैं, इसको पहचानने की कोशिश नहीं की है। पहले उसको एक फिएट कार दिलाई गई और उसके तीन महीने बाद ही स्टेन्डर्ड कार दलाई गई। फिएट को ब्लेक में बेच दिया और उससे ब्लेक का पैसा कमा लिया और फिर उससे स्टेन्डर्ड कार खरीद ली। इस प्रकार की आपकी स्थिति है। और इतना ही होता तो काफी था, यही समझ लते कि चलो आठ हजार का मामला हो तो है। लेकिन उसको एस. टी. ए. की मेम्बर बनाया गया। आज तक जितने मेम्बर हैं उनमें कोई महिला ऐसी नहीं थी जो एस. टी. ए. की एक्स पर्ट हो। एस. टी. ए. की एक्सपर्ट उनको और कोई महिला नहीं मिली। अगर कोई एक्सपर्ट थी तो वह कान्ता खतूरिया थी जो बीकानेर में पैदा हुई। वह एस. टी. ए. के रिवीजन के मामले ले रही है इसकी मेम्बर एक महिला ही पहले थी। सुमित्राजी उसकी मेम्बर हैं, उनको अनुभव है, उनकी मेम्बरशिप की बात समझ में आ सकती है। सात-आठ वर्ष का एस. टी. ए. का उनको अनुभव है। लेकिन यह जो दूसरी महिला को लाकर आपने एस. टी. ए. में बैठा दिया तो क्या आप एस. टी. ए. में महिलाओं का राज करना चाहते हैं? कार कन्ट्रोल एक्ट के तहत लोगों को गाड़ियां देने की व्यवस्था है। जब इस प्रकार की बातें डाइरेक्टर जानता हो कि मंत्री महोदय का यह वीक पोइन्ट है तो इस वीक पाइन्ट को जितना एक्सप्लायट किया जा सकता हो किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जोधपुर स्टेट के समय में मोनोपोलो सिस्टम था। यह मोनोपोली सिस्टम सन् १९५१ में जो हमारा ट्रांसपोर्ट एक्ट बना तो उसके कारण वह खत्म होगया। इस मोनोपोली एक्ट से जिन लोगों की मोनोपोली थी उनको हटाया गया था। इसमें एक थे शंकरलाल नामक व्यक्ति जोधपुर के। उन पर अस्सी हजार का क्लेम हमारा बनता था। उस एक्ट के मातहत हम उनसे अस्सी हजार रुपये वसूल करने के अधिकारी थे। हमारा कोर्ट के अन्दर केस चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इस अस्सी हजार के क्लेम को कोर्ट से विद्ड्रा किया गया। इसमें हमारा अस्सी हजार तो गया ही और उसको अस्सी हजार दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब दिमाग में यह बात न मालूम कहां से आ गई कि जो केस जोधपुर में चल रहा था, उनके पहले भी कई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए, लेकिन किसी के दिमाग में यह चीज नहीं आई और अब माथुर साहब के दिमाग में यह बात आई कि यह मुकदमा तो फालतू चल रहा है, इसमें सेशन्स कोर्ट में जाने के बदले, हाई कोर्ट में जाने के बदले आउट आफ दी कोर्ट सैटल करना चाहिए, यह आपकी अक्ल में कैसे आया? आखिर सरकार का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। इस जनता के पैसे को आप इस तरह से बर्बाद करें यह बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसी तरह का एक मामला गंगानगर का है, वह भी मोनोपोली का ही है। यह मामला भी चल रहा है। दौलतराम जिसका नाम है। उस मामले में भी आउट आफ कोर्ट कुछ सैटल करने का मामला चल रहा है। सेटलमेन्ट हो गया या नहीं, यह मंत्री महोदय बताएंगे। लेकिन मैं इसको उनके सामने एक प्रश्न के रूप में रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में इसे एक प्रश्न के रूप में यह विश्वास लेकर रखना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसके बारे में बतायेंगे।

(श्री भैरोंसिंह)

इसके अलावा एक और मामला में आपके सामने रख रहा हूं और इस मामले को भी मैं इस आशा से रख रहा हूं कि आप उसे बरख्वास्त करेंगे। इसलिए बरख्वास्त करेंगे कि उसके साथ अन्याय किया गया और उसकी पैरवी भैरोंसिंह कर रहा है। वह एक आफिसर भले ही बरख्वास्त हो जाय, लेकिन बाकी के लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जायगा। इस विश्वास के साथ मैं यह मामला रख रहा हूं। यहांपर एक ए. आर. टी.ओ.है कुन्दनसिंह। उस कुन्दनसिंह के मामले को मैं आपके सामने रख रहा हूं, माथुर साहब। मैं यह नहीं कहता कि आप उसको रि-इन्स्टेट करदें, बल्कि यह कहता हूं कि उसको चार्जशीट दी जाय। उसको चार्जशीट नहीं मिल रही है। ७ जून, १६६५ को उसको सस्पेंड किया गया और आज कौनसी तारीख है, २० फरवरी, १६६५?

एक माननीय सदस्य : आज तो १६ मार्च १६६६ है।

श्री भैरोंसिंह : सॉरी, आज १६ मार्च, १६६६ है लेकिन आज तक उसको चार्ज शीट नहीं दी गई और वह सस्पेन्शन में पड़ा हुआ है। उसको स्टेटमेन्ट आफ एलीगेशन नहीं दिया गया है, इस बात के बावजूद कि उस आदमी ने मंत्री महोदय से कहा, उस आदमी ने डाइरेक्टर को कहा, उसने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठियां लिखीं लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं होती और उसके बाद डाइरेक्टर चिट्ठी लिखते हैं और आपके डाइरेक्टर क्या चिट्ठी लिखते हैं? वैसे तो सरकार का नियम है कि जब तक किसी आदमी को मेजर पनिशमेन्ट का केस नहीं बनता है या वह किसी कॉगनिजेबल ऑफेन्स में गिरफ्तार नहीं हो गया हो तब तक सस्पेन्ड नहीं किया जाय, लेकिन उसको सस्पेन्ड कर रखा है। उसके बारे में बाद में डाइरेक्टर क्या कहते हैं? यह मैं नहीं कहता हूं आपके डाइरेक्टर कहते हैं। वे लिख रहे हैं:

'So far the complaints against Shri K.S. Jhala and his staf is concerned it is not possible at this stage to include these or draft a fresh charge-sheet and statement of allegations in these cases.'

इसमें प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी नहीं हुई, उसको कोई चार्जशीट नहीं दी गई, क्योंकि वह चार्जशीट बनती नहीं है। वह डाइरेक्टर लिखते हैं

'Non-issue of chargesheet for so long a time means unnecessary harassment to these officers.'

जब मामला माथुर साहब तक गया तो वे कहते हैं कि उसको कैसे रि-इन्स्टेट कर सकते हैं। आपने यह नहीं देखा कि उसके साथ हरेसमेन्ट हो रहा है, बिना प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी किए उसको सस्पेन्ड कर रखा है और आप कहते हैं कि अभी कैसे रिइंस्टेट कर दें, मैं आपसे पूछता हूं माथुर साहब कि जब अलवर प्रेस के सुप्रिटेन्डेन्ट का मामला आया, जिसकी इन्क्वायरी कम्प्लीट हो चुकी थी, जिसको चार्जशीट दी जा चुकी थी और चार्ज प्रूव हो गए थे उसको आपने बीचमेंही कैसे रिइंस्टेट करदिया। इनके अलावा भी कई अधिकारी हैं जिनके खिलाफ इससे भी सीरियस एलीगेशन्स हैं, ऐसे ऐसे सीरियस

(श्री भैरोंसिंह)

एलीगेशन्स हैं जिनको मैं दो-तीन दिन बाद सदन में प्रस्तुत करना चाहूंगा, लेकिन वे सस्पेंड नहीं हो सकते। और यह सस्पेंड हो सकता है। किस बिना पर सस्पेंड कर रहे हैं, छः छः महीने बिना कसूर के सस्पेंड रखें। उसका कुसूर क्या है कि छः महीने पहले किसी अधिकारी के पास कोई एप्लीकेशन आई, उसने अपने मातहत अधिकारी के पास जांच के लिए भेज दिया। उस मातहत अधिकारी ने तीन दिन में जांच करके रिपोर्ट करदी। माथुर साहब के पास मामला गया और कागज वहीं पर पड़े रहे। यह देखने की किसी को फुरसत नहीं कि छः महीने तक कागजात कहां पर पड़े रहे। बस ऑर्डर हो गया कि छः महीने तक तुमने जांच पूरी नहीं की इसलिए तुम सस्पेंड। जिसने छः महीने पहले जांच कम्पलीट करके अपनी रिपोर्ट भेज दी वह तो सस्पेंड और कागजात जिसके पास पड़े रहे उसको कुछ नहीं! यह सस्पेंशन और रि-इंस्टेटमेन्ट का चक्र इस तरह से नहीं चलने दिया जायगा, यह कोई खुद के घर का मामला नहीं है, यह कानूनी व्यवस्था का सवाल है। और यह सब इसलिए है कि आप किसी में इन्ट्रेस्टेड हैं। राजस्थान सरकार ने इकोनॉमी की है और उस इकोनॉमी में वह आदमी न हीं आ जाय, उसको बचाने के लिये यह सब किया जा रहा है। इस इकोनॉमी में वह ए. आर. टी. ओ. नहीं आता है, दूसरा आदमी आता है। उस दूसरे आदमी को इफेक्ट न हो इसलिए उस आदमी की, उस ए. आर. टी. ओ. की हत्या की जा रही है। इस तरह का पक्षपात किया जाता है वह नहीं चलने दिया जायगा। यह बात सही है कि यह बदकिस्मती है राजपूतों की, यह बात भी सही है कि यह बदकिस्मती भी राजपूत हैं और यह बात भी सही है कि माथुर साहब राजपूतों के खिलाफ हैं और राजपूतों को वे कभी न्याय पाने का मौका नहीं देंगे। वे यह कभी नहीं चाहेंगे कि राजपूत न्याय प्राप्त कर सकें, उनकी तो हत्या होगी। लेकिन मैं भी माथुर साहब, आपको कह देता हूं कि जो राजपूतों पर आपकी तलवार चल रही है मैं इसको भोंटी करके छोड़ूंगा। आपका जहां दिल आया उसको सस्पेंड कर दिया, जहां मर्जी हुई उसको रि-इन्स्टेट कर दिया। जिस गरीब आदमी की सिफारिश नहीं है उसके लिए कोई कहने वाला नहीं है, उसकी तो हत्या ही होगी, तो यह चलने वाला नहीं है, यह नहीं चलने दिया जायगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस विषय पर आप गंभीरता से विचार करें।

एक बात और भी कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं बस खत्म ही कर रहा हूं। वह कागज भी नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो प्रश्न उठाए हैं उन प्रश्नों के आधार पर अपना कटौती का प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत करता हुआ मंत्री महोदय से कहूंगा कि उनका उत्तर दें।

श्री **मोहनराज** : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री भीमसेन !

Page No. 98

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष, प्रस्तुत मांग के संबंध में मैं अपने इलाके की कुछ समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, सबसे पहले मैं बीकानेर मेडिकल कॉलेज के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बीकानेर मेडिकल कॉलेज में एम. एस. और एम. डी. की क्लासेज की पढ़ाई के बारे में व्यवस्था की मांग काफी अर्से से चल रही है, और इसके बारे में शायद राजस्थान सरकार का यह कहना हो कि भारत सरकार की ओर से हमारे पास इस तरह का कोई इन्डीकेशन नहीं आया। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार से इस बारे में इन्डीकेशन आये या न आये, लेकिन राज्य सरकार को चौथी योजना में इसके बारे में प्रावधान करके भारत सरकार के पास अपनी मांग प्रस्तुत करनी चाहिए। वैसे तो भारत सरकार एम. एस. और एम. डी. के लिये जो रिसर्च डिपार्टमेन्ट खुलता है तो रिसर्च डिपार्टमेन्ट के खुलने के कारण भारत सरकार उस के खर्चे का ७५ पर्सेंट वहन करती है, केवल २५ पर्सेंट जो खर्चा है वह राजस्थान सरकार को वहन करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार शायद यह जवाब दे बीकानेर मेडिकल कालेज में इतने एक्सपीरीयन्स्ड प्रोफेसर नहीं हैं जिनका कि १५ साल का एक्सपीरियन्स हो तो हमारे यहां जयपुर के मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स को वहां ट्रासफर करके इसके बारे में सरकार उचित व्यवस्था कर सकती है। तो इसके बारे में सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्षजी, लूणकरणसर में बीकानेर स्टेट के टाइम से वहां डॉक्टर की व्यवस्था थी, लेकिन वहां तहसील हैडक्वार्टर होते हुए भी और उसका एरिया ४ हजार स्क्वायर मील का होते हुए भी, १ लाख की पापुलेशन उस तहसील में रहती है, तो इतनी बड़ी तहसील के लिए और इतने बड़े क्षेत्र के लिए एक भी डाक्टर की व्यवस्था न हो तो यह उचित बात नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार यह बहाना नहीं बनायेगी कि डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर नहीं भेजेगी। सरकार चाहे तो वहां डॉक्टर भेज सकती है। इसलिए यह बहाना बनाना कि डॉक्टर नहीं है उचित नहीं रहेगा। इतने बड़े इलाके के लिए सरकार को उचित व्यवस्था करनी चाहिए।

इसके अलावा, उपाध्यक्षजी, नापासर में एक डिस्पेन्सरी थी वह बन्द हो गई है और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर में परिवर्तित कर दी गई है। इसके बारे में पंचायत समिति ने अपना एक प्रस्ताव पास किया और सरकार के कथन के अनुसार वहां के नागरिकों ने करीब १० हजार रुपये की लागत की एक बिल्डिंग डिस्पेन्सरी के लिए तैयार करके दी। १९६१ से बराबर प्रश्न चल रहा है कि डिस्पेन्सरी नापासर में नहीं आये। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह डिस्पेन्सरी उस गांव में तत्काल ही स्थानान्तरित करें।

इसके अलावा आर. टी. ओ. है। यह सरकार कह सकती है कि आर. टी. ओ. एक इण्डिपेन्डेन्ट ऑथोरिटी है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस तरह के आदेश देने के लिए कम्पीटेन्ट है कि आर. टी. ओ. जिन रूट्स के लिये परमिट देती है तो कम से कम उस रूट की कितनी आर्थिक क्षमता

Page No. 99

(श्री भीमसेन)

है बस चलाने के लिए इसके बारे में सर्वे करके जितनी आर्थिक क्षमता उस रूट की होती है उतने ही परमिट दें, ताकि बस आपरेटर्स इकोनोमिकली बस चला सकें और जो जनता की सेवा है उसको ठीक ढंग से कर सकें। बीकानेर जिले के अन्दर जितने भी परमिट्स दिये हुए हैं अलग अलग रूट्स पर वे वहां उनकी आर्थिक क्षमता से काफी अधिक दिये हुए हैं। इसलिये वहां बस आपरेटर्स की कन्डीशन बहुत खराब है। तो इसके लिये राजस्थान सरकार को आर. टी. ओ. को भविष्य में ऐसे आदेश देने चाहिए कि रूट की आर्थिक क्षमता जितनी है उससे अधिक परमिट न दें जिससे कि ख्वामख्वाह कम्पीटीशन न हो।

इन्हीं शब्दों के साथ में राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि ये जो छोटी समस्याएं रखी गई हैं इनके बारे में आवश्यक समाधान करें।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य पर इस समय चल रही चर्चा के विषय में मैं सरकार की उस नीति की तरफ आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान में जो जो बने हैं उनके साथ साथ उस नीति में भी परिवर्तन होता है। उसका सम्बन्ध मेरे क्षेत्र से, जयपुर जिले से है। जयपुर जिले के अन्दर डी. एम. एच. ओ. ऑफिस इस सरकार के समय में तीन मर्तबा बदल चुका है और तीनों में जो जो स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान में आये अपने अपने टाइम के अन्दर अलग-अलग स्थानों के ऊपर उन्होंने परिवर्तन किया। जयपुर जिले का डी. एम. एच. ओ. ऑफिस रूरल एरिया में होना चाहिये, इस सही नीति को अपनाते हुए प्रथम टाइम वह किशनगढ़ गया। उसके बाद जयपुर के स्वास्थ्य मंत्री उस समय के थे वे उसको फिर जयपुर ले आये। फिर उसके बाद चर्चा हुई, वाद-विवाद हुआ, रिपोर्ट हुई कोटपुतली और दौसा के लिये बातचीत चली, उसकी रिपोर्ट हुई। दो जगहों का क्लेम हुआ। उस वक्त के स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने दोनों में से सड़क से नजदीक होने के नाते दवाओं का वितरण सही रूप से हो सके दौसा के अन्दर सिलेक्ट किया। वह ऑफिस दौसा में गया। दौसा में वह चल रहा था, ६-७ साल से चल रहा था। अब हमको यह मालूम हुआ है कि गत महीने से उसके लिये फिर यह आदेश हो गया है कि दौसा से हटाकर वापिस उसको जयपुर में ले आया जाय। मैं नहीं समझता, जयपुर के इलाके की जनता समझ नहीं पाती कि आखिर यह क्या चीज है? क्यों इसको फुटबाल बनाया जाता है? इस में सरकार का कितना खर्चा होता है? जब जयपुर शहर के अन्दर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जैसी बड़ी संस्थाएं हैं तो डी. एम. एच. ओ. का ऑफिस जयपुर में ही रहे और रूरल एरिया में न रहे इस में क्या बात है? इस नीति के बारे में चर्चा कर ली, कई बार चर्चा होकर आदेश दे दिये गये उसके अन्दर हजारों लाखों रुपयों का खर्चा होगया और फिर बार बार क्यों यह परिवर्तित होता है? हमने इसके विषय में सवाल भी दिये, मालूम भी करना चाहा तो कोई रूप मालूम नहीं होता, उसका कारण मालूम नहीं होता केवल एक ही बात है कि शहर जयपुर बीच में पड़ता है इसलिये जयपुर में रख दिया जाये। लेकिन जो इस विकेन्द्रीकरण के हामी हैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि आखिर आप एक

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

जयपुर के अन्दर ही सब चीजों को केन्द्रित करके और दूर के एरिया के अन्दर कोई ऑफिस नहीं देना चाहते किसी जगह भी। यह आपकी नीति आपके द्वारा अपनाई गई विकेन्द्रीकरण की नीति के विपरीत है। इस तरह यह कह कर मैं आशा करता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रीजी इस पर विचार करेंगे और इसको कम से कम बतलायेंगे कि डी० एम० एच० ओ० ऑफिस को क्यों बदलने जा रहे हैं ? और जब एक जगह इतने वर्ष तक चल चुका है तो क्यों परिवर्तन करने जा रहे हैं ? उस पर क्या पुन: विचार करके वहीं रखने की कृपा करेंगे ?

इसके बाद अभी कई माननीय सदस्यों ने, उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ सन्टर्स के में बारे कहा। उसके विषय में भी मैं अपने स्थानी जगह की एक समस्या के रूप को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र के अन्दर बढियाल में प्राइमरी हेल्थ सन्टर खोला गया। उसको खुले हुए ७-८ वर्ष होने आ है। पंचायत समिति वजीरपुर की जनता ने चन्दे से १० हजार लगा कर भवन निर्माण करके बिल्डिंग बनवाई और हेल्थ सेन्टर कायम किया गया। जनता एक्सपेक्ट करती थी कि हमारे हां पर अस्पताल बनेगा, सेन्टर बनेगा। जनता ने १० हजार अपना लगाया और आपने भी दिया। आपने सेन्टर भी खोला, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहां डाक्टर नहीं है। कई वर्षों से डाक्टर नहीं पहुंच पाता है। जिस डाक्टर को भेजा जाता है वह यह कहकर वापिस आ जाता है कि वह गांव है छोटा सा वह मेरे जैसे पढे लिखे आदमी के लिये फिट-इन नहीं होता है, तब किस लिये हैल्थ सैन्टर खोलते हैं ? जब आप उनकी बात मानते हैं और उनके दबाव में आकर उनका ट्रान्सफर कर देते हैं और कई वर्षों से वह हैल्थ सैन्टर केवल एक कम्पाउन्डर से चल रहा है। और उसके लिये कोई कारण नहीं बताया जाता है। इस तरह के हैल्थ सैन्टर को रखने से क्या फायदा है ? किसके लिये रुपये खर्च किये जाते हैं ? इसलिये मैं कहता हूं कि इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है ? यदि आपने यह नीति बनाली है कि डाक्टर नहीं है, नहीं रहना चाहिये तो आप जनता को क्यों धोखा देते हैं ? डाक्टर नहीं है तो सैन्टर वहां से हटाइये और जनता से जो १० हजार रुपये वसूल किये हैं वे वापिस करिये, यदि साधन नहीं हैं आपके पास तो। मैं समझता हूं आप यह पसन्द नहीं करेंगे और न पसन्द करना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे खयाल से वहां की जनता भी यह पसन्द नहीं करेगी कि प्राइमरी हैल्थ सैन्टर वहां से हटा दिया जाय जैसा कि आप सुझाव दे रहे हैं।

श्री मथुरेशविहारी माथुर : मैं नहीं सुझाव दे रहा हूं, मैं भी चाहता हूं कि नहीं उठाना चाहिये लेकिन आप व्यवस्था तो करिये। यदि आप असमर्थ हैं डाक्टर को वहां भेज नहीं सकते, कई वर्षों से नहीं भेज सकते, केवल कम्पाउन्डर से हैल्थ सैन्टर चला रहे हैं तो दूसरा कदम लीजिये। तंग आकर हम कहते हैं कि या तो व्यवस्था कीजिये या इसको बंद कीजिये। ऐसे सैन्टर को चलाने से फायदा क्या है ? एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइमरी हैल्थ सैन्टर के पास जीप चाहिये, मैं कहता हूं किये सैन्टरर्स चलते तो हैं ही नहीं, डाक्टर तक नहीं है फिर जीप कायको चाहिये ?

अब मैं संक्षेप में स्वास्थ्य मंत्रीजी से दौसा डिस्पेन्सरी के बारे में एक कहानी कहना

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

चाहता हूं । आपके यहां से डाइरेक्टर महोदय हमारे यहां पर आये और उन्होंने कहा कि इस सेन्टर को बढाने के लिये एक्स रे मशीन चाहिये । बिजली दौसा में आई हुई है । उसके लिये उन्होंने कहा कि फिफ्टी फिफ्टी पर तैयार हैं । फिफ्टी परसेन्ट जनता दे और ५० परसेन्ट विभाग दे हमने इस बात को मंजूर कर लिया । हमने २०,०००) रु० जनता से वसूल करके वार्ड का कमरा बनाया, एक्सरे का कमरा बनाया । फिर हमसे कहा गया कि ३८,०००) रु० में एक्सरे की मशीन आती है इसलिये १७,०००) रु० आप दे दीजिये । हमने १७,०००) रु० दे दिये फिर मशीन खरीदी गई, मशीन वहां पर आई । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतना रुपया खर्च करके जो मशीन वहां पर मंगाई गई वह बंद पडी है । कुछ पार्ट्स सही नहीं होने के कारण वह मशीन काम नहीं करती । आज साल भर होने आया है एक्स रे मशीन के दर्शन ही दुनिया करती है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री): आज कल वह मशीन काम करती है या नहीं ? मेरी सूचना है कि मशीन दुरुस्त हुए ६-७ महीने हुए और काम कर रही है । मेरी सूचना गलत है या आपको तहकीक मालूम है कि काम कब से नहीं कर रही है ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : सत्र आरंभ हुआ था उस वक्त मैंने जानकारी करके प्रश्न दिया था । एक महीना हुआ प्रश्न आया है, आपने जवाब दिया है । २६ फरवरी के बाद यदि दुरुस्त होकर चालू हो गई है तब तो मैं आपके कथन को चैलेन्ज नहीं करूंगा । एक महीना पहले से ८ महीना तक यह मशीन बेकार पडी रही है, वर्क नहीं किया और यह बताया गया कि पार्ट्स नही हैं इसलिये वर्क नहीं कर रही है । यह एक कस्बे की डिस्पेन्सरी का हाल है । ३७,०००) रु० इस पर लगे हैं इसका क्या उपयोग है ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद में मंत्रीजी को हमारे यहां के मेटरनिटी सेन्टर के बारे में बताऊंगा । इसको खुले हुए ८ वर्ष हो गये । ७ वर्ष तक तो वहां पर कोई लेडी डाक्टर नहीं पहुंची । गये सत्र में मैंने इस बारे में काफी प्रश्न किये उसके बाद बडी मुश्किल से लेडी डाक्टर वहां पर पहुंची और ६-७ महीने रही और उसके बाद वह शादी की छुट्टी लेकर चली गई वापिस नहीं लौटी । आप जिसको भी अपोइन्ट करते हैं वही कहती है कि दौसा मुझे पसन्द नहीं आया है और ५-६ दिन रहती है और डाइरेक्टर साहब पुनः उसकी ट्रान्सफर वहां से कर देते हैं । आखिर यह एक कस्बे का हाल है । वहां पर मेटरनिटी सेन्टर खुले ७-८ साल हो गये लेकिन लेडी डाक्टर के बिना वह बेकार है, एक नर्स और दाई के भरोसे चल रहा है । दौसा जो २० हजार की आबादी का कस्बा है उसका यह हाल है ।

एक बात मैं और अर्ज करूंगा बांदीकुई की डिस्पेन्सरी के बारे में । कई बार कहा गया कि इस को रेंज किया जाय, कुछ बेड्स बढाये जांय, इसमें कुछ रद्दोबदल किया जाय, यहां पर वेन्टिलेशन नहीं है, छोटी छोटी बातों के लिये यहां पर अव्यवस्था है, बिजली न होने से अव्यवस्था है । आज इन कस्बों में आप जाकर देखें तो १००-१५० से ज्यादा मरीज वहां नहीं आते और प्राइवेट कम्पाउन्डर्स जो वहां पर प्रेक्टिस करते हैं उनके पास ३००-४०० मरीज जाते हैं । उन कम्पाउन्डर्स

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

की अच्छी प्राइवेट प्रेक्टिस चलती है, एक एक कम्पाउन्डर पांच-पांच सौ रुपये कमाता है। इस सब के लिये आप की जिम्मेदारी है, आप के डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर बड़े कस्बों तक में इन्सपेक्शन करने नहीं जाते हैं और वहां की दुर्दशा को नहीं देखते हैं। आपके डाइरेक्टर हमारे यहां के डॉक्टर को शील्ड करते हैं और जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं। उनके खिलाफ टेबल पर रुपया लेने की शिकायत है। कोई इन्जुरी रिपोर्ट रुपया लिये विना नहीं होती। इन्क्वायरी करने के लिये वहां आने के लिये आपके डिप्टी डाइरेक्टर कोई २५ दफा डेट दे चुके हैं लेकिन नहीं आरहे हैं क्यों कि डाइरेक्टर साहब उनको शील्ड करते हैं। वहां पर पट्टियों तक की व्यवस्था नहीं है। मरीजों से कहते हैं कि पट्टियां घर से लाओ। मुझ से कहा गया कि हमारे यहां पट्टी नहीं है मरीज की इन्जुरी रिपोर्ट के लिये भेजना है तो हमको पट्टी घर से मंगा कर दो। मैं इसको प्रमाणित करने को तैयार हूं, मैं ने लिख कर दिया है।

भीलवाड़ा के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर गांधी मेमोरियल होस्पिटल है वहां पर एक्सपायरी डेट का इन्जेक्शन एक मरीज के लगा दिया जिससे उसकी मृत्यु होगई। २० हजार रुपयों के एक्सपायरी डेट के इन्जेक्शन्स फिकवाये गये, उसकी जांच हो रही है पर अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया..........

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां की कह रहे हैं ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : भीलवाडा में गांधी मेमोरियल होस्पिटल है, वहां पर एक्सपायरी डेट का इन्जेक्शन लगाने से एक मरीज की मृत्यु हो गई। डाक्टर ने बताया कि एक्सपायरी डेट का इन्जेक्शन लगाने से मृत्यु हुई..........

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कब की बात है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : १५, २० रोज हो गये। आखिर आप देखें कि २०-२० हजार के इन्जेक्शन्स एक्सपायरी डेट के कैसे मंगा लिये ? इसी तरह से ४० हजार का गबन दौसा में हुआ, उसको अब सस्पेन्ड किया है लेकिन कोई जांच नहीं, आप इन सब बातों की तरफ ध्यान दें इसलिये अर्ज किया है।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा और श्री दयाचन्द सोन बोलने के लिये एक साथ खड़े हुए)

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु.) : मेरा नाम लिया है बोलने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, दिन भर चिकित्सा के विषय में यहां पर बहस रही उसको सुनने के बाद में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज यहां का जो चिकित्सा विभाग है उसके बारे में ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई अच्छाई उसमें है ही नहीं। राजस्थान के चिकित्सा विभाग के बारे में जो सुनने को

Page No. 103

ी ज्वालाप्रसाद शर्मा)

ाला उससे ऐसा लगता है कि इसको ंद कर दिया जाय तो अच्छा है। एक भी ाननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि सेंकडों ोग जो लोगों की सेवा करते हैं वह अच्छी रते हैं। ह्युमेनिटेरियन ग्राउन्ड पर भी नकी तारीफ में एक भी शख्स ने फूटे मुंह से नकी तारीफ में एक शब्द नहीं निकाला। ों करोड लोगों की चिकित्सा और स्वास्थ्य के ारे में जो लोग सेवा कर रहे हैं उन में से कोई ो अच्छा होगा, ५-१० लोग जितने मेम्बर बोले ें उनमें से किसी ने भी उनकी तारीफ में कुछ नहीं कहा। इतने बडे डिपार्टमेन्ट में ो सकता है कुछ छिपे हुए लोग भी हो सकते ें, कुछ बदतर भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सदन के इस प्रांगण को इसके उपयोग में लायें इससे न तो एन्करेजमेन्ट सेवा करने वालों को मिल सकता है, न एन्करेजमेन्ट आम जनता को मिल सकता है। बल्कि हम इस तरह का वातावरण पैदा करना चाहते हैं कि इस देश में इस तरह की सेवा करने वालों की तस्वीर इस तरह की पेश कर रहे हैं, जैसे मुझे लगता है इलेक्शन नजदीक आ रहा है यह उसी की भूमिका है और उसकी वजह से चर्चा चलाई जा रही है। मुझे अफसोस है कि जहां पर............

श्री दयाचन्द सोन : आपका इलाज तो फ्री हो जाता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तेरे तो पैसा लगता होगा। जो फ्री हुआ है वह तो कानून से हुआ है।

श्री दयाचन्द सोन : मैं कहता हूं कि जरा देहातों में जाकर देखो कि वहां पर क्या हालत है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह तो आप भी समझते हो, फिर भी मैं यह खबर करदूं, आपने एक आध दवा ले ली होगी, मैं ने एक दवा भी नहीं ली है लेकिन फिर भी मैं स्वस्थ हूं। मैंने सरकार से कोई पैसा नहीं लिया है।

श्री दयाचन्द सोन : वह तो आप दोनों इस्तेमाल करते होंगे यहां के।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : क्या इस्तेमाल करता हूं ?

श्री दयाचन्द सोन : दोनों।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : दोनों को इस्तेमाल नहीं करता, वह तुम्हारे लिए रख रखे हैं। और तुम्हारा लीडर गाजवान खा गया, क्या कहते हैं उसे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : खमीरा गाजवान।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : खमीरा गाजवान।

श्री दयाचन्द सोन : वह तो आप भी लेते हो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इन बातों के लिये वक्त नहीं है, मुझे दो कट मोशन पर बोलना है। तो मैं कह रहा था कि यह कहना गलत नहीं होगा कि इन साधनों में कमी और बातें होते हुए भी अपने साधनों के माफिक इस कांग्रेस सरकार में और इस डिपार्टमेन्ट में बहुत बडी तादाद में ऐसे लोग हैं जो आम लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य को आगे बढा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे जो लोग हैं उनको हम लोगों की तरफ से एन्करेजमेन्ट मिलना चाहिये, उत्साह मिलना चाहियें।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

इसके साथ में कुछ सुझाव मिनिस्टर साहब को देना चाहता हूं और पहला यह देना चाहता हूं कि जैसे किसी घर में रोटियां कम हो जाती हैं, तो उस वक्त यही होता है कि रोटियां कम हैं तो सब में बराबर बांट दो। यह नहीं कि दो लडकों को तो वैसे ही मरने दो, इनको एक टुकड़ा भी मत डालो और मां-बाप सारी की सारी रोटी खा जायं। मैं कहना चाहता हूं कि आज इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि डाक्टरों की कमी है। इस बात से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता कि डाक्टरों के नखरे बढ रहे हैं। आप उनकी परवाह नहीं करते हैं तो वे जानते हैं कि हम बाजार में बैठ कर भी कमा सकते हैं। इसलिये इस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने यह समस्या है कि जहां हमें पांच सौ, सात सौ डाक्टरों की और जरूरत है वहां इस वक्त हैं डाक्टर हमारे यहां काम कर रहे हैं उनके साथ २ कोई इस तरह की ज्यादती कर दें तो इस वजह से पांच सौ, सात सौ की बजाय आठ सौ की कमी हो जायगी, इतने लोगों की सेवा से और वंचित हो जायंगे। इसलिये इनको थोडा समझ कर चलना पडता है लेकिन इसके साथ ही मैं यह नहीं कहता कि इनको सब स्थिति को टालरेट करना चाहिए—इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दीजिये, लेकिन उस तरफ इन्हें ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इनकी यह दिक्कत है, इनके पास में डाक्टरों की कमी है। अब जो हमारे यहां पर डाक्टरों की कमी है उसकी पूर्ति करने के लिए यह क्या करते हैं कि इन्होंने डाक्टरों की कमी पूरी करने के लिए कालेज खोले, और डाक्टरों की संख्या बढाई। इससे हम कह सकते हैं कि सरकार इस तरफ कदम उठा रही है। लेकिन आप उन विद्यार्थियों से एग्रीमेंट करते हैं, बौंड लिखवाते हैं कि जो लडके डाक्टर बन कर निकलेंगे उनको इस राज्य में ही सेवा करनी होगी वह राजस्थान गवर्नमेन्ट की सेवा करेंगे। लेकिन उसमें दो लकीर एसी छोड दी जाती है जिसकी वजह से गवर्नमेन्ट उनको फोर्स नहीं कर सकती है। उनको फोर्स करने वाला बौंड नहीं लिखवाते हैं, और आप कहते हैं कि लडके यहां पर मेरिट पर आयें। मैं कहता हूं कि हमारा पैसा खर्च हो और उस पैसे से पांच कॉलेज चलें, लेकिन उन कालेजों से जब लडके डाक्टर बन कर निकलें तो उनको आप बौंड के आधार पर फोर्स नहीं कर सकें कि हमारे यहां ही सर्विस करो। इसलिये जो लडके डाक्टर बन कर निकलते हैं, उसके बाद उनमें से राजस्थान में बहुत कम रहते हैं। मैं समझता हूं कि इसको बन्द करना चाहिए, क्योंकि हमारा पैसा खर्च होता है।

मैं तो कहता हूं कि उन लडकों को पढाओ और फिर चाहे मेरिट हो या डिमेरिट, लेकिन उन लडकों को राजस्थान की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए, जो राजस्थान की सेवा करें और राजस्थान को छोड कर बाहर नहीं जायं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की आप क्यों ढील देते हैं और इस तरह का उनके साथ एग्रीमेंट या बौंड क्यों नहीं करते हैं? अगर उनके साथ इस तरह का बौंड करते हैं तो इससे उन्हें और जनता को दोनों को फायदा मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि मां बाप जो हैं, जो पैरेन्ट हैं वह तो रोटी खा लें और बच्चों को भूखा मार दें—यह बात गलत है। इसलिये मैं सजेस्ट

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
करता हूं कि जितना पैसा खर्च होता है उसका फायदा उनको मिलता है जो राजस्थान की रायल फेमिली के लोग हैं, जो मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर हैं ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): कौनसी फेमिली ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इनमें से एक आध को छोड दीजिये लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनकी जो कान्स्टीट्यूएन्सी है, जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सब में डाक्टर मिलेंगे । एक आध को आप छोड़ दें । कोई हो तो आगे आयें ।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरी कान्स्टीटयूएन्सी में नहीं है । मैंने कोई दस बार लिखा है कि वहां पर डाक्टरों की कमी है लेकिन अभी भी वहां डाक्टर नहीं हैं ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप जनरेलाइज मत करो । आप कहते हो मेरे यहां डाक्टर नहीं हैं । मैं पर्टीक्यूलरली यह नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं गया नहीं हूं । लेकिन अजमेर क्षेत्र में जो मिनिस्टर हैं उनकी कान्स्टीट्यूएन्सी में है—पुष्कर में है, सराधना में है, गोविन्दगढ़ में है, पीसांगन में है ।

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री) : और आपके यहां रामसर में भी है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वहां खोला है, हुजूर खोला है, तीन साल से खोला है; लेकिन उसको कोई डॉक्टर भरने वाला नहीं मिलता, क्योंकि मैं रोयल फेमिली में नहीं आया । बात तो यही है । मैं नहीं कहता कि रामसर में भेजो । मैं तो यह कहता हूं कि सबको आप न्याय दो, आपके दरबार में हम न्याय की मांग करते हैं, वह इसलिये करते हैं कि पांच सात मील पर जो डिस्पेन्सरी हैं उनके लिए आप टी. ए. देकर, कन्वेयन्स देकर यह ऐलान कर दीजिये कि इस डिस्पेन्सरी में सप्ताह में दो रोज डाक्टर मिलेगा । ताकि वहां पर लोग आकर इकट्ठा हो जायं और मेडीकल की सुविधा प्राप्त कर लें । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं—डोंट मोनोपोलाइज । गरीब और अमीर में फर्क करना छोड़ दो और सबको बराबर का न्याय दो । अगर आपके पास पांच सौ डाक्टरों की कमी है तो राजस्थान की दो करोड़ जनता में उसको बराबर शेअर करना चाहिए और अगर आपके पास इफरात है तो कोई बात नहीं । लेकिन यह आपको कोई हक नहीं है कि जनता के पैसे से यह डिपार्टमेन्ट चलायें और जनता को ही सुविधा नहीं मिले । मेरा एक सुझाव यह है और इसके ऊपर अधिक न कहते हुए निवेदन करूंगा कि मुझे अफसोस है इस बात का कि आज यहां पर बहुत सी चीजें आईं, बहुत सी बात आई—वह पैदा क्यों हुई है ? उसकी तरफ मैं इशारा करूं कि कानून के बहुत बड़े आदमी हैं यहां पर फिर भी कानूनी अड़चनें और दूसरी कानूनी बातें हुई—उसमें काम्प्ली-केशन्स क्यों हुए ? मुझे मालूम है कि क्य तरीका निकाला । रमी खेल लो । रमी खेलना आता है तो यह बड़ा अच्छा तरीका है । और रमी कोई मिनिस्टर खेले तो, मिनिस्टर अपने डाक्टर के साथ रमी खेले तो वह जरूर जीतेगा, वह जीतेगा, चाहे जो हो । शनिश्चर लगा हो तो बृहस्पति बैठ जाता है—रमी ऐसा काम करती है । चाहे कुछ नहीं समझे, गधा हो लेकिन रमी में जीतेगा जरूर ।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

वह जीतेगा अगर कोई खेलता है तो। तो वहां खेलने का असर होता है, वहां कानून-आनून नहीं चलता है। उसके बाद में कानून की बुद्धि चली जाती है और उसकी वजह से आपके डिपार्टमेंट में काम नहीं होता है। मेरा खयाल है, आप रमी नहीं खेलते, इसलिए उम्मीद की जाती है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। यह मैं कहना चाहता हूं इस डिपार्टमेंट के सिलसिले में।

इसके साथ ही मैं चतुर्थ श्रेणी के नौकरों के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

(स्वास्थ्य मंत्री द्वारा किसी माननीय सदस्य की ओर संकेत करने पर)

मंत्री महोदय, औरों की ओर तो इशारा हो जायगा, आप मेरी बात सुने। मैं रचनात्मक बात कह रहा हूं।

ये जो आपके मेडीकल स्टोर्स चलते हैं, इनमें आप एक सुविधा और कर दीजिये। ये जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं इनके पास पैसा नहीं होता है, इन बेचारों के सिर पर जब बीमारियां आ जाती हैं तो आप इनके लिए यह रख दें कि पैसे लेने का हिसाब कुछ कागजों में हो जाय, बाद में हिसाब बना लें और डिपाटमेंट्स से वह इकट्ठा कर लें, डिपार्टमेंट से वह वसूल कर लें। इससे इनको सुविधा हो सकती है। यह जो सुविधा दी है, उसमें काउन्टर सेल की सुविधा प्राप्त कर दी, आपके गवर्नमेंट स्टोर्स हैं उन सब फोर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद ही यदि इन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह कर दें तो अच्छा है क्योंकि अचानक किसी से उधार मांगें तो बाजार में तो दवा मिल जाती है लेकिन यहां यह डिफीकल्टी सामने आई है। फिर आपने जो इम्प्रूवमेंट किया है उसमें मैं एक सजेशन और करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट और दूसरी गवर्नमट कन्ट्रीब्यूटरी हैल्थ सर्विस चलाती हैं, उसके अन्दर जो डिस्पेंसरी चलाती हैं, उसी तरह से इनकी तनख्वाह से कुछ काट कर कुछ उसमें एड करके कीजिये। अगर आपको ईमानदारी पैदा करनी है, नहीं तो डाक्टरों की जो भरोंसिह जी ने बातें रखी हैं उस तरह की गड़बड़ी तो इसमें है। अगर आप किसी को सजा नहीं दिलायेंगे तो यह चीज चलती रहेगी। यह तरीका निकाला है, वह मैं समझता हूं कि सब नहीं करते हैं, कुछ ऐसे पैदा हो गये हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं।

(समय समाप्ति सूचक-घंटी)

दूसरे पोइन्ट पर मैं आता हूं, इसको यहीं छोड़ देता हूं। बात यह है कि इस सिलसिले में बहुत कम बहस हुई है और सदन ने इस पर बहुत कम गौर किया है। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट का हाल यह है कि इकोनोमी के नाम पर इसके नाम पर इसके अन्दर जनता के लिए काफी असुविधा पैदा हो गई है। अजमेर से, जिस जगह काफी आमदनी थी, वहां से आर. टी. ओ. आफिस उठा दिया गया है। इस तरह की चीज कायम करके, आर. टी. ओ आफिस को वहां से उठा कर यहां ले आये, इस तरह और दिक्कत पैदा करते रहते हैं। ये जयपुर में आ जायं, यहां पर सेन्टर हो, मैं मंत्री महोदय को कहूं कि यहां पर सिटी बस चलती है। वह सिटी बस सर्विस कैसे काम कर रही है इसका जवाब देने को आप कुछ भी जवाब दे दें। पिछली कई मर्तबा उनका चालान कियागया,

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

लेकिन वे कानून को नहीं मानते। मुझे यह भी पता चला कि सरकार ने उन पर कुछ जुर्माना भी किया मगर उससे क्या असर हुआ उनके परमिट आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। चालान किया तो चालान के जुर्माने के पैसे दे दिये। लेकिन यह परमिट मोनोपोली जयपुर में उसी तरह से उनकी चलती रहेगी और उनको ही परमिट मिलते रहेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सम्मानीय सदस्य यहां बोलते हैं जो कानून के जानने वाले हैं वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। श्री तेजारामजी हैं उनसे भी १७ पैसे वसूल करने की हिम्मत रखते हैं और लेते हैं।

एक माननीय सदस्य: आपका कोई इस पर कट मोशन नहीं है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: मेरा कट मोशन नहीं है, लेकिन मेरा विरोध करने का हक तो है। मैं इसका विरोध तो कर सकता हूं इससे तो आप नहीं रोक सकते। आपका यह पोइन्ट आउट करना आपकी इग्नोरेन्स ऑफ ला की वजह से है।

जो आर. टी. ओ. परमिट देते हैं उनका यह फर्ज होता है कि वे डेट, टाइम, नम्बर आफ सर्विसज, बस स्टेन्ड, जयपुर स्टेट आदि सब दर्ज करने होंगे और उन ठेकेदारों को कानूनों को मानना पड़ेगा। मगर हम देखते हैं कि आज कानून की अवहेलना की जाती है। बसें ओवर क्राउडेड होती हैं। टिकट जो दिये जाते हैं उनके काउन्टर फोलियोज नहीं रखे जाते हैं। (टिकट का नमूना दिखाते हुए) इससे टिकट की बिक्री की चोरी होती है और पैसों का चैकिंग नहीं किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य: काउन्टर फोलियो क्या?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: एक टिकट काट कर देते हैं और दूसरा हिस्सा उसका उसी कापी में रहता है। इससे कोई सबूत नहीं रहता कि कितने टिकट बिके, क्योंकि काउन्टर फोलियो नहीं। इसलिये जो ज्यादा पैसा लेते हैं वे सब उनके घर चले जाते हैं। खुले-चौड़े नागरिकों को लूटने की छूट है। जैसे जैसे स्टेन्ड हो वहां के लिये अलग अलग रेट होनी चाहिये मगर यह बात भी नहीं है एक तरह की रेट है। इसलिये जिस तरह से दिल्ली और दूसरे बड़े बड़े शहरों में अलग अलग बस स्टेन्डों के लिये अलग अलग रेट निर्धारित रहती है उस तरह से कोई यहां पर रेट निर्धारित नहीं है जो मर्जी आवे करें कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन यह काम आपके आर. टी. ओ. कभी पूरा करने वाले नहीं। वे कानून को मानते हैं या नहीं इसकी कोई परवाह करता नहीं। एक ताकत के बल पर ये सब नग्न नाच हो रहे हैं और पिछले तीन वर्षों से मैं बराबर इन बातों को सरकार के ध्यान में लाता आ रहा हूं मगर फिर भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ये बराबर चलते आ रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बहुत ही इम्पोर्टेन्ट बात मैं कहना चाहता हूं। ट्रान्सपोर्ट के सम्बन्ध में जनलेखा समिति ने ठेकेदारों से बकाया की वसूली के बारे में जो रिकमन्डेशन की है उसको मैं पढ़ता हूं वह इस प्रकार है :—

"उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इस मामले में ठेकेदार ने एक फर्म द्वारा

Page No. 108

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
उसके लिए १६ ट्रेक्टर और ट्रेलर रिजर्व रक्खे जाने का पत्र दिखला कर सरकार से उनकी खरीद के लिये अग्रिम राशि ले ली और केवल ८ ट्रेक्टर और ट्रेलर ही खरीदे। इस पर विभाग द्वारा जब शेष राशि जमा कराने के लिये कहा गया तो उसने कोई राशि जमा नहीं कराई और बहाना करता रहा। कुछ समय बाद उसने काम करना भी बन्द कर दिया और उल्टा सरकार पर दावा दायर कर दिया। इस मामले में विधि विभाग की भी यह राय है कि चूंकि ठेकेदार द्वारा धोखा दिया गया है। अतः उसके विरुद्ध फौजदारी मुकद्दमा चलाया जाना चाहिये। समिति चाहती है कि ठेकेदार के विरुद्ध फौजदारी तथा दीवानी मुकद्दमे तुरन्त दायर किये जायें और मामले की विस्तृत जांच कराई जाकर जिस किसी अधिकारी को इस मामले में दोषी पाया जाय उसे उचित दंड दिया जाय।"

श्री मथुरादास माथुर (योजना मंत्री): यह कौनसा ठेकेदार है?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: यह मैंने एक नमूना आपके सामने पेश किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वही फर्म है जिसको कोई छू नहीं सकता। यह दिन दहाड़े आपके लॉ डिपार्टमेन्ट की राय है उसकी परवाह नहीं करता। सिटी बसेज चलती हैं मगर कानून की अवहेलना होती है उसकी कोई परवाह नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके इतने विभाग और उनके अधिकारी क्या करते हैं? आपके ट्रान्सपोर्ट वाले क्या करते हैं? जो लोग आपको टैक्स देते हैं उन टैक्सों को दिन दहाड़े आपको देने की परवाह नहीं करते आप उन पर जुर्माना करते हैं, आपका लॉ डिपार्टमेन्ट लिखता है कि उनके खिलाफ फौजदारी मुकद्दमा चलाया जावे। जनलेखा समिति लिखती है अपनी सिफारिश में कि इन पर फौजदारी और दिवानी मुकद्दमें चलाये जावें। यह वही कम्पनी है (अंकेक्षा प्रतिवेदन १९६५ पृष्ठ ७०, पैरा ७५ पर जिसका जिक्र है और जिसने ४ लाख रुपये १६ ट्रेक्टर्स और ट्रेलर्स के खरीदने के नाम से ले लिये और आधे ही खरीदे। और काम नहीं किया और उल्टा सरकार पर दावा किया। उसके बाद में सरकार ने यह तय किया कि इस कम्पनी पर फौजदारी मुकद्दमा जारी किया जावे। जयपुर जैसी सेन्ट्रल प्लेस पर जिस आदमी का इतना बड़ा दबदबा सरकार में है कि आप उसको छूना नहीं चाहते।

श्री दामोदरलाल व्यास: उस कम्पनी का क्या नाम है, यह तो बतावें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: आप कम्पनी का नाम पूछना चाहते हैं कि उसका क्या नाम है। आप पूछ कर ही रहेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास: उसका नाम आप बतावें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: उस कम्पनी का नाम है कमल एन्ड को०।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक बात यह कहना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेन्ट में गलत इकोनोमी हुई है। अजमेर और नसीराबाद में ३०० गाड़ियां हैं और आर.टी.ओ. का ऑफिस यहां पर जयपुर में है। इसलिये उनको यहां पर आने में बड़ी दिक्कत पड़ती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

कि यह उनके आर. टी. ओ. का आफिस जयपुर में नहीं खुलना चाहिये और अजमेर में रहना चाहिये। आपने यहां पर आफिस इसलिये खोला है कि आपके कुछ मिनिस्टर इसमें इकोनोमी के नाम से इन्ट्रेस्टेड हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोनी। Only five minutes इसके बाद में जवाब शुरू होगा।

श्री दयाचन्द सोनी (बारां-सु.) उपाध्यक्ष महोदय, बारां एक व्यापारी मंडी है। मगर हम देखते आ रहे हैं कि वहां के होस्पिटल में कई वर्षों से लेडी डाक्टर नहीं है। नया बना है पहले तो वहां पर लेडी डाक्टर नहीं थी और कभी रही भी होगी तो दो महीने रह कर चली गई। वहां पर डिलीवरी केसेज बहुत ज्यादा होते हैं। सैकड़ों हजारों गांव के लोग बारां की मंडी होने के नाते वहां पर आते हैं। मगर वहां पर लेडी डाक्टर का इन्तजाम नहीं है। वहां पर एक सेठानी ने ५०-६० हजार रुपये की बिल्डिंग दी और कहा कि मैं यह बिल्डिंग सरकार को दान में देती हूं और वहां पर जच्चाखाना खोला जाना चाहिये, मगर सरकार उस ५०-६० हजार की बिल्डिंग को भी हजम कर गई। एक बार मैंने इसकी चर्चा की कि जो लोग इस प्रकार से ५०-६० हजार रुपये दान के रूप में जिस कार्य के लिये दें और उसका सही तरीके से उपयोग सरकार नहीं करे तो लोगों को सरकार में आस्था नहीं रहती और भ्रम पैदा होता है। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर एक्सरे की मशीन भी बेकार पड़ी है। ८-१० हजार रुपये इसको खरीदने के लिये जनता से इकट्ठे किये थे, वहां पर डाक्टर थे उनके सहयोग से लोगों ने वह रुपया भी दिया था। मगर जो मशीन भेजी गई वह ठीक तरह से काम नहीं करती है और वह यों ही बेकार पड़ी है। उससे एक्स-रे नहीं आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दवाइयों का प्रश्न है, मैं यह कहूंगा कि न तो वहां पर दवाइयों का प्रबन्ध है न डिलिवरी के केसेज आते हैं उनके लिये पूरी व्यवस्था है। गरीब औरतें इसलिये होस्पिटल्स में जाती हैं कि उनको कुछ राहत मिले। घर में खर्च करने के लिये १००) ५०) रु. गरीब लोग कहां से लावें। जब वे होस्पिटल में आती हैं तो उनको बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। १०-२० में से एक आध औरत को डिलीवरी के लिये रखते हैं और बाकी को वापिस भेज देते हैं और जिनको भर्ती करते हैं उनको भी दवाइयें उपलब्ध नहीं होतीं और उन गरीब लोगों को दवाइयें अपने पास से पैसा खर्च करके मंगवानी पड़ती हैं। बड़ी चीज को छोड़िये, छोटे मोटे कपड़े और स्प्रिट भी उनको अपने पैसों से मंगानी पड़ती है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस बात के लिये पूरा प्रयास करें।

(समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

इसके अलावा अन्ता डिस्पेन्सरी में कोई डाक्टर नहीं है। अन्ता एक बहुत अच्छा कस्बा है। मगर वहां पर डाक्टर नहीं है। इसलिये मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि अगर वहां पर डाक्टर रखा जावे तो बहुत उचित होगा।

...... (समय--समाप्ति--सूचक घंटी)

(श्री दयानन्द सोन)

(४.०० म.प.)

दूसरी बात यह है कि जितनी वहां खास खास दवाइयां होती हैं वह कम्पाउन्डर लोग अपने रिश्तेदारों और डाक्टर लोग अपने रिश्तेदारों को इस्तेमाल के लिये दे देते हैं, गरीबों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है । मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जितनी अधिक से अधिक सुविधाऐं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दे सकें वह दें, इन गरीब लोगों को आज किसी प्रकार की सुविधाऐं नहीं मिल रही हैं । यह बड़ा गरीब तबका है । बड़े बड़े अमीर आदमियों का फोकट में इलाज करें और गरीबों के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार करें यह आपकी नीति अच्छी नहीं है ।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : ५ मिनिट से अधिक न हों ।

श्री मुक्तिलाल मोदी !

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज मैडीकल के ऊपर जो काफी देर से वाद-विवाद चल रहा है, मैं यह तो जरूर मानता हूं कि राजस्थान के अन्दर दूसरे प्रांतों की बनिस्पत जो यहां मेडिकल फेसिलिटीज मैं राजस्थान सरकार ने दी हैं, वह बहुत ही ज्यादा हैं । क्योंकि कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, वहां के लोग यहां आकर इलाज कराते हैं । इसका कारण यह है कि राजस्थान सरकार डाक्टरों को जो कम तनख्वाह देती है, जैसे कि आज आर. ए. एस. ऑफिसर्स के ग्रेड फिक्स्ड हैं, इन्जीनियर्स और दूसरे डिपार्टमेंट्स में ग्रेड फिक्स्ड हैं, उन लोगों से डाक्टरों को कम मिलता है । इन्जीनियर्स वगैरह का २५० से ८०० तक का ग्रेड है वह डाक्टरों का ग्रेड नहीं कर रखा है । दूसरे प्रान्तों में जो डाक्टर्स के ग्रेड हैं उनसे हमारे राजस्थान में डाक्टरों के ग्रेड कम हैं, यह भी एक कारण है ।

दूसरा कारण यह है कि दिन-ब-दिन मैडिकल कॉलेज खोलते रहते हैं, पर मैडिकल कॉलेजेज के खोलने से डाक्टरों की कमी होगी, बढ़ेंगे नहीं, बढ़ेंगे ५ साल बाद । क्योंकि मैडिकल कॉलेज खोलते हैं तो पढ़ाने वाले चाहिये तो जो डाक्टर होंगे वे पढ़ायेंगे ।

किस तरह राजस्थान में दूसरे दूसरे प्रान्तों के लोगों का एडमिशन हो जाता है क्या करते हैं कि वे लोग बोंड भर देते हैं, आपका जो बोन्ड का तरीका है वह बिल्कुल गलत तरीका है । राजस्थान सरकार को इन बोंड्स को स्ट्रिक्ट बनाना होगा, जब तक बोन्ड्स का तरीका स्ट्रिक्टली नहीं होगा जैसा कि दूसरे प्रान्तों के अन्दर है कि पास करने के बाद, डाक्टरी पास होने के बाद जब तक गवर्नमेन्ट उनको सर्टिफाई नहीं कर देती तब तक न वे दूसरी जगह सर्विस कर सकते हैं और न प्रेक्टिस ही कर सकते हैं । इस प्रकार की शर्तें हमारे यहां कानून में नहीं रखेंगे तब तक डाक्टर यहां राजस्थान के अन्दर सर्विस नहीं करेंगे, दूसरी जगह चले जायेंगे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष, अभी तो मैं बिल्कुल ही थोड़ा बोला हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : तो राजस्थान सरकार को बोन्ड्स के तरीके में सुधार करके इस प्रकार की शर्त रखनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि राजस्थान के अन्दर मेडिकल और शिक्षा दोनों के ही अन्दर जब तक यह नहीं करेगी...

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : नेपाल में डाक्टरों की कैसी व्यवस्था है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : वहां डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी थोड़े ही है।

श्री मोतीलाल चौधरी : तो भी वहां डाक्टरों की व्यवस्था कैसी है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : ठीक है।

श्री मोतीलाल चौधरी : रूस की ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : हां, रूस की बताता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, रूस के अन्दर ऐसा है; हास्पिटल्स खाली रहते हैं, उन हास्पिटल्स में डाक्टर ज्यादा हैं, पर मरीज हैं ही नहीं। वहां डाक्टर ज्यादा हैं और मरीज हैं ही नहीं और हमारे यहां मरीज ज्यादा हैं और डाक्टर कम हैं, इसका कारण यह है ..

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप उस हॉस्पिटल में मरीज बन कर गये या डाक्टर बन कर ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं मरीज बन कर गया था, असलियत में मरीज बन कर गया था।

श्री भैरोंसिंह : आपका इलाज तो वहां हुआ ही नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आंखें दिखाने गया था।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेल और फीमेल दो हॉस्पिटल्स हैं, कहां गये थे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : राजस्थान सरकार जितनी दवाइयां, इन्जेक्शन्स और डाक्टरी के औजार आदि पर टेन्डर्स से खरीदने पर खर्च करती है, उसके बजाय राजस्थान सरकार को फैक्ट्री खोलनी चाहिये...

श्री उपाध्यक्ष : फैक्टरी काहे की खोलनी चाहिये ? ..

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह) : डाक्टरों की।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दवाइयां बनाने की, इन्जेक्शन्स तैयार करने की और डाक्टरी औजार बनाने की फैक्ट्री राजस्थान सरकार को खोलनी चाहिये। जिससे कि राजस्थान सरकार दवाइयां, इन्जेक्शन्स और औजार टेन्डर काल करके दूसरी जगहों से खरीदती है वह सब चीजें हमारे यहां कारखाने खोल कर मेडिकल विभाग के अन्दर ही बनाई जायं। जब तक राजस्थान सरकार इस प्रकार की चीज नहीं करेगी, बाहर से ही दवाइयां इन्जेक्शन्स और औजार मंगायेंगी तब तक सही मायने में राजस्थान में यह विभाग तरक्की नहीं कर सकता। माननीय सदस्य और और बातें कहते हैं पर यह नहीं कहते कि राजस्थान सरकार जब करोड़ों रुपया इस विभाग पर खर्च कर रही है तो पहले २० लाख रुपया लगा कर, फिर ५० लाख और उसके बाद एक करोड़ रुपया लगा कर हमारे यहां इस प्रकार की फैक्ट्री स्टार्ट करे और दवाइयां

Page No. 112

(श्री मुक्तिलाल मोदी)
इन्जेक्शन्स और सब प्रकार के औजार यहां तैयार करें। फोरेन की फैक्ट्रीज को लोन दिया जाता है, मशीनें मंगाने के लिये लोन दिया जाता है पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि राजस्थान के अन्दर दवाइयां, इन्जेक्शन्स, और औजार व दूसरे आवश्यक सामान बनाने की फैक्ट्री खोली जाय। इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट से जो मैडिकल के सामान के लिये कोटा दिया जाता है उसके लिये भी सरकार की बात होनी चाहिये, मैडिकल विभाग को सूचना होनी चाहिये कि आपके सामान के लिये इतना कोटा दिया है और वह सामान मैडिकल विभाग में आना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आपने काफी महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं, फैक्ट्री वाला सुझाव बहुत अच्छा है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ट्रान्सपोर्ट पर थोड़ा सा कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष : ट्रान्सपोर्ट को रहने दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ट्रान्सपोर्ट पर थोड़ा सा कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, एक मिनिट में कह दीजिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ट्रान्सपोर्ट के बारे में मैं बार बार चिल्लाता हूं कि छोटे छोटे गांवों के लिये कोई परमिट के लिये एप्लीकेशन देता है तो कई महीने लग जाते हैं, कई दफा तो दो दो साल तक निकल जाते हैं तब परमिट बनते हैं। इसमें सुधार किया जाना चाहिये।

दूसरे ट्रान्सपोर्ट विभाग में यह पाबन्दी होनी चाहिये कि सेल्स टैक्स के क्लीयरेंस का सर्टिफिकेट जब तक नहीं होगा तब तक किसी को परमिट इश्यू नहीं किया जायगा।

बस ट्रान्सपोर्ट के बारे में मैं यही दो बातें निवेदन करना चाहता हूं।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के सम्बन्ध में मेरा कटौती प्रस्ताव है। चिकित्सा के सम्बन्ध में सरकार व्यवस्था करने में सफल नहीं हुई है, इससे जनता को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे गरीब लोग बिना इलाज ही मर जाते हैं, उनको दवाइयां तक मुहैया नहीं होती हैं। हमारे नेताओं ने जनता से वायदे किये थे कि सस्ता इलाज होगा, सस्ता न्याय होगा, सस्ता अनाज होगा; उन सब बातों के सम्बन्ध में तो कहने को समय नहीं है, आज इतना ही कहना चाहता हूं कि गरीबों को दवाइयां तक मुहैया नहीं होती हैं। हमारे इलाके में दो साल तक डॉक्टर नहीं भेजा गया, जिससे गरीबों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बाहर जाकर लोग इलाज करवाते हैं।

बेगूं से एक औरत, जिसकी बच्चादानी में से हमल ने जगह छोड़ दी थी उसको हॉस्पिटल में लाया गया, वहां डाक्टर नहीं मिला; बाहर दूसरे अस्पताल में ले गये तो कहा कि हमारे यहां औजार नहीं हैं, दूसरों ने कहा कि इसे चित्तौड़ ले जावो, वहां एक्स्पर्ट हैं। वहां भी उसे

(श्री भीमसिंह बाबेल)

ले जाया गया तो वहां पर भी कहा कि हमारे पास औजार नहीं हैं। फिर भीलवाड़ा ले गये और वहां जाकर वह औरत मर गई। तो मेरा निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ में लाखों रुपया लगाया, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई, पर प्रतापगढ़ में डी० एम० ओ० का आफिस रखा। ठीक है, आप प्रतापगढ़ रखना चाहते हैं मुझे एतराज नहीं है, लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि चित्तौड़गढ़ में एक्सपर्ट्स हैं, भवन बने हुए हैं, लेकिन वहां एक्सपर्ट्स नहीं हैं और जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं।

मैं परसों के दिन यहां के जनरल अस्पताल में गया था अस्पताल में, यह जो बात बता रहा हूं उसमें डॉक्टरों की गलती नहीं है लेकिन ६ बजे बिजली बंद हुई, रात को ढाई बजे तक यह बंद रही और वहां मरीजों को टट्टी-पेशाब करने में और दूसरे कामों में तकलीफ हुई।

आप इस बारे में विचार करें। आप ८००-८०० रु० की दवाइयां अस्पताल में रखते हैं जहां कम्पाउंडर्स रहते हैं। उनसे क्या हो सकता है? चित्तौड़गढ़ के अस्पताल में ८००) रु० की दवाइयों से क्या हो सकता है? इस पर आप विचार करें।

परिवार नियोजन के बारे में एक माननीय सदस्या ने यहां कहा कि गांवों में हमारे डॉक्टर्स नहीं हैं। यहां डेढ़ करोड़ जनता गांवों में रहती है वहां इसका प्रचार नहीं है। आप प्रचार करें। आप इस सम्बंध में शिक्षा का प्रबंध करें जिससे जो पैदाइश बढ़ रही है वह कम हो सके। इसकी ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

श्री मोहनराज (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चिकित्सा व्यवस्था की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे यहां रानी एक बहुत बड़ी मंडी है। वहां आज से १२-१३ साल पहले वहां के सेठ ने २० हजार रुपये देने का वायदा किया था। सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। बाद में जब रुपया कम हुआ तो उन्होंने एक लाख की ऑफर की है, जमीन तैयार है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह पंचायत समिति का हेडक्वार्टर है, हायर सेकंडरी स्कूल है, व्यापार की बहुत बड़ी मंडी है, पांच हजार की आबादी है और आसपास में १७-१८ मील में किसी प्रकार का अस्पताल नहीं है। इस तरह की स्थिति वहां होते हुए भी अस्पताल खोलने में देरी कर दी है।

दूसरा, पाली तहसील में खौड़ बहुत बड़ा गांव है। पांच हजार की आबादी है और वहां पर पचास हजार की लागत से अस्पताल का मकान बनवाया गया था और तत्कालीन मंत्री, श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने उस अस्पताल के भवन का उद्घाटन किया था। मैंने पूरी जानकारी कर ली थी कि तीसरी योजना में एक अस्पताल पाली जिले में खोला जायगा और खौड़ के अन्दर हो खोला जायगा, लेकिन बावजूद कोशिश के भी और जगह तो खोल दिया गया और वहां पर मकान खाली पड़ा है। मैंने निवेदन किया कि अगर वहां कोई प्रावधान नहीं है नया अस्पताल खोलने के लिए, तो हमारे यहां एक कम्पाउंडर ही भेज दो। यह बहुत बड़ा गांव है और १६ मील के आसपास में कोई अस्पताल या औषधालय नहीं है। जब पांच हजार की बस्ती हो, और १६ मील के एरिया में कोई अस्पताल न हो तो वहां पर कम्पाउन्डर भेज कर यदि चिकित्सा

(श्री मोहनराज)

को सुविधा न दे सके तो मेरे ख्याल से जनता परेशानी में रहती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा पाली कस्बे की बात करूंगा। ५-६ दिन पहले मैंने प्रश्न के रूप में निवेदन किया था कि स्वर्गीय माननीय श्री जयनारायण व्यास ने उसका शिलान्यास किया था, आज भी उस भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका। मैं इस संबंध में मेडिकल विभाग के सेक्रेटरी से मिला, उन्होंने कहा कि अगर डायरेक्टर साहब लिखें मेडिकल सेक्रेटरी को कि जनहित के लिए भूमि की आवश्यकता है तो अधिग्रहण के लिए नोटीफिकेशन जारी किया जा सकता है। जब कि सरकार खुद कोशिश कर रही है, हमने लिखा है, पंचायत समिति ने लिखा है, जिला परिषद् ने लिखा है, फिर भी यह कार्य यदि जनहित का नहीं है, तो मेरी समझ में नहीं आता। मेरा निवेदन है कि भवन बनाने के लिए, भूमि अधिग्रहण करने के लिए, वहां पर जल्दी से जल्दी भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही की जाय।

जब पाली में १९६०-६१ में मंत्रि-मंडल की बैठक हुई थी तो उस समय मंत्रि-मंडल ने घोषणा की थी कि फालना स्टेशन पर एक मेटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर खोला जायगा। उसके लिए सेठ चोपड़ा ने एक ट्रस्ट के द्वारा एक राठोड़ भवन भेंट के रूप में दिया। राज्य सरकार ने उस भेंट को स्वीकार किया लेकिन ३ वर्ष हो गए, वहां पर अभी तक मेटरनिटी सेंटर और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर अभी तक नहीं खुला। मुझे मालूम हुआ है कि राज्य सरकार ने स्वीकृति भी दे दी है लेकिन बावजूद स्वीकृति के भी आज तीन साल हो गए, किसी प्रकार की चिकित्सा-व्यवस्था नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार का ध्यान कई बार इस ओर दिलाया जा चुका है कि वह व्यवस्था करे लेकिन अब मैं फिर निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र विचार करें जिससे जनता को लाभ पहुंचे।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि राजस्थान में करीब २०० अस्पताल बिना डाक्टरों के हैं, उनमें से कम से कम १०० अस्पताल गांवों में होंगे। जो प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स हैं वहां या तो बंद कर दें, नहीं तो कम से कम थर्ड क्लास कम्पाउन्डर्स भेज कर मरीजों के ट्रीटमेंट को खराब न करें। मेडिकल बोर्ड ने फैसला किया है कि एम० बी० बी० एस० डाक्टर्स ही रखने हैं। मंत्री महोदय ने गलत कदम उठाया है टेकनीकल के नाम से। हिन्दुस्तान में आज भी बहुत से डॉक्टर्स हैं जो आपकी सर्विस में हैं जो एल० एम० एफ० हैं, लाइसेंस ऑफ मेडिकल फेकल्टी। उस कोर्स को दुबारा यहां शुरू करना चाहिये। भवन बन गया, सामान पहुंच गया, खर्चा हो रहा है लेकिन कम्पाउंडर बैठा हुआ है उसके बदले में आप एल० एम० एफ० का कोर्स दुबारा शुरू करें। चाहे मेडिकल बोर्ड एग्री न करे, लेकिन राजस्थान सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वह कम से कम इस कोर्स को शुरू करके डाक्टरों की कमी को दूर कर सकती है। उसके बाद जब आयुर्वेद शुरू हुआ है तो आपको एलोपैथी अस्पताल नहीं खोलना चाहिए।

Page No. 115

(श्री मोतीलाल चौधरी)

अगर खोलते हैं तो पूरा इक्विपमेंट और डॉक्टर्स दिए जायं।

जहां तक मेरी जानकारी है जिन कम्पाउंडर्स को आप भेजते हैं वे सीनियर नहीं हैं, वे सिर्फ ट्रेनिंग लेकर पांच साल के बाद इन्चार्ज डिस्पेन्सरीज के बन रहे हैं। खास तौर से हमारे स्वास्थ्य मंत्री को, जो बहुत माहिर हैं, उनको भारत सरकार से या मेडीकल बोर्ड से लडना भी पडे तो भी लडना चाहिए। हर हालत में एल० एम० एफ० कोर्स या और कोई कोर्स, जैसे ब्रिटिश राज्य में होता था और आजादी के बाद, मैं भी लुधियाना क्रिश्चियन कॉलेज से डॉक्टर निकले हैं। आपकी सर्विस में बहुत से ऐसे डाक्टर्स हैं। इसलिए डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए ऐसी व्यवस्था करें। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो आयुर्वेद का प्रसार करें और कम से कम गांवों में जरूर दवाइयां दिलवाएं। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक डॉक्टर पूरे न हों तब तक आप इंटरमीजियरी कोर्स की व्यवस्था करें, तो कम से कम गांवों में लोगों को चिकित्सा तो मिले।

हैल्थ मिनिस्टर किस दृष्टिकोण से देखते हैं, मैं वर्तमान मंत्री महोदय के लिए नहीं कहूंगा। आप एलौपेथी का बजट देखिए और आयुर्वेद का भी देखिए। एक ही हॉस्पिटल का बजट पूरे आयुर्वेद के बजट के बराबर हो जाता है, उधर वैद्य गांव-गांव में फिर रहे हैं, उनके लिए आपने कॉलेज तो खोले, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। आपका बजट का कुछ परसेन्टेज उधर ट्रान्सफर कर दीजिये, ताकि गांव के लोगों को दवाई तो मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ-साथ होमियोपैथी के इलाज को बढावा देंगे, ऐसा निर्णय सरकार ने लिया। लेकिन होमियोपैथी की व्यवस्था कुछ नहीं हुई। एलोपैथी के साथ-साथ में आयुर्वेद के साथ सौतेला व्यवहार न करके इसकी व्यवस्था करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आयुर्वेद ने एक औषध का इन्वेन्शन किया है, वह औषध है नारू के लिये। आज दिन तक एलोपैथी इसके विषय में कुछ नहीं कर सकी, जबकि आयुर्वेद वाले इसमें सफल हुए हैं।

मुक्तिलालजी ने एक बात कही। मैंने भी कट मोशन दिया। आयुर्वेद औषधियों का पब्लिक सेक्टर में निर्माण होता है। बाजार से कोई दवाई पर्चेज नहीं करनी पड़ती है। आयुर्वेद औषधि के लिये एलोपैथी के मुकाबले एक्सपेन्डीचर बहुत कम है। रोजमर्रा उन औषधियां की जरूरत पड़ती है मसलन डिस्टिल्ड वाटर, आयोडीन। ये आप बाजार से पर्चेज करते हैं। क्यों नहीं आप इन चीजों को पब्लिक सेक्टर में प्रोड्यूस करें। इससे एक्सपेन्डीचर आपका कम होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार और जनता के बीच में एक प्रकार से क्यों दरार पटक रहे हो। मैं इसको कम से कम पसन्द नहीं करता। राज्य कर्मचारियों को प्रिविलेजेज दें और जनता को न दें। जो केपिटलिस्ट्स गवर्नमेन्ट होती है उसके दिमाग में यह बात जरूर होती है कि कर्मचारियों और जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाय। आज जनता का राज्य है, जनता

(श्री मोतीलाल चौधरी)

मालिक है । उस जनता के जो मालिक हैं उनको दवाई न मिले और राज्य कर्मचारी जो उसका नौकर है उसको सस्ती मिले । सवाई मानसिंह हॉस्पिटल है, उसकी दूकान है, वहां सिर्फ राज्य कर्मचारियों के लिये ही दवाई है, दूसरों के लिये नहीं । या तो आप उसको भी जनता के लिये चलाऊ कीजिये । जनता को एक्सप्लाइट करते हैं । सवाई हॉस्पिटल की दूकान पर दो रुपये में मिलेगी और बाहर जनता को चार रुपयों में । जनता को कम कीमत में दवाई मिले, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिये ताकि जनता को राहत मिले ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं सदन की अनुमति होगी कि जब तक ये दोनों मांगें न पास हो जायं, सदन का समय बढ़ाया जाय ।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया जाता है ।

श्री दौलतराम सारण (उप मंत्री, आयुर्वेद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कटौती प्रस्तावों के जरिये मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २९—पर आयुर्वेद के सम्बन्ध में ८-९ माननीय सदस्यों ने कुछ प्रकाश डाला । उन्होंने कई सुझाव सामने रखे । कुछ ने आयुर्वेद को अच्छा बताया, कुछ ने आयुर्वेद विभाग की गलतियों पर प्रकाश डाला । मैं उस पर तो फिर आऊंगा ।

यह निश्चित है कि मनुष्य सुख की कामना करता है और उसके लिये वह विभिन्न तौर-तरीके अपनाता है । हमारे यहां लोकोक्ति "पहला सुख निरोगी काया" । निरोग शरीर है यह सुख की पहली सीढ़ी है । और उस सुख की सीढ़ी की प्राप्ति के लिये आदमी ने रोग-उन्मूलन, उसकी मुक्ति की चेष्टा की और उसके लिये उसने क[illegible] तरीके निकाले । एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी प्रणालियां उनमें हैं । पीछे वाली तीन प्रणालियां मैंने बतायीं, वे आयुर्वेद विभाग के अन्तर्गत हैं ।

इस सम्बन्ध में आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो न केवल मनुष्य को स्वस्थ रखने की एक सही और निश्चित विधि है, एक निश्चित पद्धति और कार्यक्रम बताती है जो रोग-रहित जीवन प्रदान करती है । आयुर्वेद हमें ऐसी दिनचर्या, ऋतुचर्या बताती है, ऐसे आहार-विहार का क्रम बताती है कि उसका पालन किया जाय तो स्वस्थ रह सकते हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : हृष्टपुष्ट भी होते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : हृष्टपुष्ट से मतलब तोंद फूलना नहीं है । उसकी क्रिया शक्ति से उसका सम्बन्ध है ।

इस दृष्टि से आयुर्वेद हमारे सामने ऐसी चिकित्सा विधि है जो सुगम है, सरल है, सस्ती है और बहुत अधिक उपयोगी है और हमारे देश का वातावरण, हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास के क्रम के साथ उसका सम्बन्ध है, इसलिये आयुर्वेद के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक है ।

माननीय सदस्यों ने जिस आस्था के साथ आयुर्वेद औषधालय खोलने की प्रशंसा की, एलोपैथी के मुकाबले में आयुर्वेद औषधालय और आयुर्वेद औषधि के प्रसार के

Page No. 117

(श्री दौलतराम शारण)

लिये कहा, मुझे सुन कर खुशी हुई और मैं उसके लिये आभार प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है, यह सदन आयुर्वेद की कमियों को दूर करने में सक्रिय रहेगा।

आयुर्वेद विभाग ने कुछ वर्षों में प्रगति की है। यह सब ही जानते हैं कि राजस्थान बना, उसके एकीकरण के साथ आयुर्वेद औषधालयों का भी एकीकरण किया गया। उस समय इन औषधालयों की हालत खस्ता थी। हालत अच्छी नहीं थी। ३५० औषधालय अलग अलग तरीके से आये। वे निश्चित रूप से नहीं चल रहे थे। गंगापुर से आने वाले एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजा और ब्रिटिश काल से भी आयुर्वेद विभाग की हालत आज खराब है। यह शब्द सुन कर मुझे दुःख हुआ। यदि वह आयुर्वेद का जो विकास हुआ है उसकी ओर जरा सा भी दृष्टिपात करते तो यह बात न कहते।

वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : माननीय मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि उस वक्त से प्रगति बता रहे हैं तो मेडीकल कॉलेज कितने खुले ?

श्री दौलतराम सारण : सब बताऊंगा। एक एक बात बताऊंगा। आप तसल्ली से सुनें।

मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान बनने के बाद आयुर्वेद का विकास हुआ। राजस्थान सरकार ने आयुर्वेद की तरफ पूरा ध्यान रखा। यह भी सही है कि एलोपैथी के बारे इसकी तुलना करते हैं तो वह स्थिति हमें नगण्य प्रतीत होती है, लेकिन आयुर्वेद विभाग की दृष्टि से देखें तो स्वाभाविक रूप से मानना पड़ेगा कि आयुर्वेद विभाग ने प्रगति की है।

जहां पहले शिक्षण की निश्चित व्यवस्था नहीं थी, जिसे वैद्य की आवश्यकता हुई तो स्कूल खोल लिया, किसी सेठ ने वैद्यजी को रख लिया पाठ-पूजा के लिये तो प्राइवेट आयुर्वेद शिक्षण भी उन्होंने शुरू करा दिया, लेकिन राजस्थान के बनने के बाद आयुर्वेद शिक्षण की निश्चित व्यवस्था है, दो गवर्नमेन्ट कॉलेज हैं। उनके अपने भवन हैं। अच्छे शिक्षण की व्यवस्था है, अच्छा शिक्षित स्टाफ लगा हुआ है।

प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों को मिला कर राजस्थान के अन्दर भिषगाचार्य और भिषग्वर तक के ६ कॉलेज हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने अपने कॉलेजों में धात्री, कल्पद के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की है, जो दस मास का कोर्स है। जो इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने प्राईवेट धात्री आती है उसको ४०) रुपया मासिक सहायता के रूप में दिया जाता है। अब तक हमारे यहां १४० धात्री प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं और १३५ प्रत्यास्मरण कोर्स में। हमने अपने यहां वैद्य, उपवैद्य, धात्री प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।

जहां तक चिकित्सा का प्रश्न है इसमें औषध-क्रय, निर्माण और वितरण और औषधालय—ये शाखायें हैं। औषध क्रय के सम्बन्ध में एक माननीय सदस्य ने कहा, उन्होंने इसके निर्माण और वितरण के बारे में शिकायतें की, मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं औषध क्रय की व्यवस्था इस प्रकार है। टेन्डर के आधार पर खरीदते हैं। जो न्यूनतम टेन्डर होता है उसको मन्जूर करते हैं। टेन्डर के अन्दर औषधि का नमूना रहता है, अच्छा, अच्छा नमूना लेता

(श्री दौलतराम सारण)

है उस नमूने के मुताबिक नियमों के अन्तर्गत औषधियों के लिये टेन्डर देना पड़ता है । उसके लिये एक कमेटी बनी हुई है । वे चुनाव करके औषधियां खरीदते हैं । इसलिये इसमें गड़बड़ होने की सम्भावना बिलकुल नहीं रहती। अच्छे से अच्छे अधिकारी और प्रामाणिक व्यक्ति इसके सदस्य हैं ।

इसके अलावा जहां तक औषधियों के निर्माण का सवाल है हमारी रसायनशालाओं में राजकीय आधार पर विभागीय नियन्त्रण में औषधियों का निर्माण किया जाता है; उदयपुर, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर में रसायनशालायें हैं जहां अलग अलग तरह की औषधियों का निर्माण किया जाता है । और इन औषधियों को वैद्यों की मांग के मुताबिक भेजा जाता है । हर एक औषधालय का एक औषधि मांग-पत्र लिखा हुआ होता है, उसके मुताबिक आवश्यकता को देखते हुए औषधियों को भेजा जाता है; मांग के मुताबिक औषधियों की सप्लाई की जाती है ।

हमारे यहां तीन श्रेणी के औषधालय हैं अ, ब और स । 'अ' श्रेणी के औषधालय प्रथम श्रेणी व 'ब' औषधालय द्वितीय श्रेणी और 'स' तृतीय श्रेणी के औषधालय होते हैं इन औषधालयों के जो वैद्य मांग पत्र भेजते हैं उसके मुताबिक हम उनको दवाइयां भेज देते हैं । तृतीय श्रेणी के औषधालय का बजट ६००) रुपये का, 'ब' श्रेणी के औषधालय का ६००) रुपये का और 'ए' श्रेणी के औषधालयों का बजट १२००) से लेकर दो हजार तक का है । जयपुर आदि कई बड़े स्थानों पर ये औषधालय हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार औषधियां देते हैं ।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जहां आवागमन का अभाव है जहां न सड़कें हैं, न रेलें हैं और न पोस्ट ऑफिस हैं ऐसे स्थानों पर भी वैद्य लोग तपस्या करते हैं तन्मयता के साथ जनता की सेवा करते हैं; आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रति आस्था रखते हुए सेवा करते हैं । ऐसे स्थानों पर रहने वाले वैद्य का मांग-पत्र आता है, उसके पत्र के अनुसार रसायनशाला से औषधियां वहां पहुंचाने में डाक की अव्यवस्था से कुछ गड़बड़ी हो सकती है, कभी मांग-पत्र भी डाक की अव्यवस्था के कारण देरी से पहुंचता है; वैसी स्थिति में गड़बड़ हो जाती है । इसकी वजह से हो सकता है कहीं कहीं औषधियां देरी से पहुंचें, इस प्रकार की असुविधा से मैं इन्कार नहीं करता । प्रयास हमारा यह रहता है कि निरन्तर औषधि पहुंचाने की व्यवस्था हो । मैंने खुद ने सैकड़ों औषधालयों का निरीक्षण किया है; मौके पर जाकर देखा है, औषधियां बराबर मिलती हैं और जहां औषधियां नहीं पहुंच पाती हैं वहां मैंने पहुंचाने की व्यवस्था के लिये कदम उठाये हैं । जिला शिक्षणालयों में भी दवाइयों का स्टॉक रखने की व्यवस्था की है । अत्यावश्यक स्थिति में वे दी जा सकें इस तरह से हम औषधियां पहुंचाने की बराबर व्यवस्था करते हैं ।

आपको यह सुन कर खुशी होगी कि इस थोड़े से काल में ६४-६५ के आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं । इस अर्से में हमने ४६ लाख ६७ हजार ३२ व्यक्तियों की आयुर्वेद रीति से चिकित्सा की है वह ९,३३,८३३) रु० में जिसका हिसाब लगाया जाय तो प्रति व्यक्ति लगभग २५ पैसा पड़ता है । २५ पैसे के खर्च के आधार पर हम जनता को चिकित्सा सुलभ कराते हैं । हमारा दावा है कि एलो-

Page No. 119

(श्री दौलतराम सारण)

पैथिक ट्रीटमेन्ट से जो परेशान हो जाते हैं जिनको एलोपैथिक डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पाये, ऐसे मरीजों को हमारे वैद्यों ने ठीक किया है। जो लोग यह कहते हैं कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है वे ही कटमोशन में अपने यहां आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग करते हैं। आप यदि इस विभाग का काम ठीक नहीं मानते तो फिर औषधालय खोलन की मांग क्यों करते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आयुर्वेदिक औषधियों की व औषधालयों की उपयोगिता है, उसका यह प्रमाण है। आयुर्वेदिक औषधालयों की उपयोगिता निर्विवाद है, इसमें कोई शक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन औषधालयों की उपयोगिता के कारण ही राजस्थान सरकार का औषधालयों के भवन-निर्माण के अन्तर्गत करीब साठ-सत्तर लाख की लागत के भवन बना कर लोगों ने विभाग को समर्पित किये हैं, लोग भवन बना कर देने के लिये तैयार हैं लेकिन हम अर्थाभाव के कारण उसमें सुविधा देने में असफल रहे हैं, यह आयुर्वेद की लोकप्रियता का प्रमाण है---जो जयपुर की राजधानी से लेकर सुदूर ग्रामों तक फैला हुआ है।

जहां तक आयुर्वेदिक विभाग के सम्बन्ध में शिकायतों का सवाल है। उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में हमारा विभाग जागरूक है, ताकि लोगों को कम से कम कठिनाई हो, इस बारे में विभाग के अधिकारी बराबर देख-रेख करते हैं। औषधालयों के खोलने के बारे में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सलाह से उनके सहयोग से खोलने का निश्चय किया है, जिला परिषद के प्रस्ताव के अनुसार हम यथासम्भव औषधालय खोलने का प्रयास करते हैं।

हमने तीसरी योजना में १४ हजार तक की जन संख्या के क्षेत्र में औषधालय खोलने का रखा था, करीब करीब सब जिलों में तीन-चार को छोड कर सब जगह हमने यह टार्गेट पूरा कर लिया है। इसी प्रकार यह भी निवेदन करना चाहता हूं इस समय राजस्थान में लगभग १५०० औषधालय चल रहे हैं, उनमें से १८ ए श्रेणी के १२८ बी श्रेणी के और १३५४ सी श्रेणी के हैं। इन औषधालयों की उपयोगिता का निर्विवाद प्रमाण यह है कि औषधालयों के खोलने की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है।

मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस विभाग को खर्च के लिये अधिक धन देने की सिफारिश की। अगर वित्त मन्त्री महोदय हमें अधिक पैसा देसकें तो हम और भी अधिक सेवा जनता की करने के लिये तैयार हैं। फिर भी "तैसे पांव पसारिये जैसी लाम्बी सोर", के अनुसार जितना पैसा हमें उपलब्ध है उन पैसों में सब से अच्छी सेवा हम कर रहे हैं, यह मेरा दावा है।

श्री जोरावरसिंह बावेल : तीन-चार जिले कौन से हैं जिनमें आपकी तीसरी योजना के टार्गेट पूरे नहीं हुए।

श्री दौलतराम सारण : अब मैं विभाग की प्रवृत्तियों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हम प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को भी आर्थिक सहायता देते हैं। इसके लिये करीब ढाई लाख रुपया शिक्षण संस्थाओं व औषधालयों में चिकित्सा के लिये वार्षिक

(श्री दौलतराम सारण)

अनुदान के रूप में देते हैं। इसी तरह से शिक्षण प्रशिक्षण और प्रत्यास्मरण चिकित्सा में विभिन्न प्रकार से आयुर्वेदिक विभाग सेवा कर रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने अलग अलग अपने अपने क्षेत्र की शिकायतें रखीं और समस्यायें रखीं। कुछ ने अपने यहां औषधालयों को खोलने की भी मांग रखी। हम नये वर्ष में देख सकेंगे कि जितनी क्षमता हमारी होगी हमारे से जितना सम्भव होगा, जो नियमों के अन्तर्गत आता होगा जन संख्या आदि की दृष्टि से आपकी भावना की पूर्ति करने का निश्चित रूप से प्रयास किया जायेगा।

आयुर्वेदिक विभाग के बारे में यह भी कहा गया कि यहां के संचालक के नीचे मन्त्रीगण हैं। कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि मन्त्री और डाइरेक्टर के बीच राजनैतिक झगड़ा है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, मन्त्री और डाइरेक्टर के बीच राजनैतिक झगडे का सवाल ही नहीं होता। डाइरेक्टर एक सरकारी अधिकारी है और मन्त्री के मातहत है। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि एलोपैथी में डाइरेक्टर मन्त्री के नीचे होता है, लेकिन इसमें संचालक के नीचे मन्त्री होते हैं। यह बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।

श्री मोतीलाल चौधरी : यह आयुर्वेद का मामला है।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी बातें कहने से कोई समस्या का हल नहीं हुआ करता है। न मन्त्री डाइरेक्टर के नीचे है; नीचे और ऊपर तो जैसी भावना है [illegible] जो आपके कायदे-कानून बने हुए हैं, उनके अन्तर्गत उसी व्यवस्था के अनुसार हर विभाग की व्यवस्था है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : नीचे कौन, ऊपर कौन ?

श्री दौलतराम सारण : यह तो अजमेर का मामला अलग है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। ऊपर नीचे तो अजमेर में होता है।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि आयुर्वेद विभाग अपने अल्प साधनों के साथ अच्छी से अच्छी सेवा करने का प्रयास करता है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य आयुर्वेद की जो भी खामियां नजर आयें वे हमारे ध्यान में लाने का कष्ट करें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसी जो भी खामियां हमारे सामने आयेंगी हम उनको बराबर दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारा कभी यह दृष्टिकोण नहीं रहता कि हम किसी को कष्ट पहुंचायें या किसी ऐसी दृष्टि से काम करें जिससे किसी को हानि हो, यह हमारा इरादा कतई नहीं है। हमारा यह इरादा है कि राजस्थान की जनता को अधिक से अधिक चिकित्सा की सुविधायें उपलब्ध हों और आयुर्वेद, यूनानी और एलोपैथी जो भी सिस्टम राज्य सरकार चला रही है उससे उनके जीवन की रक्षा हो, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो और वे दीर्घजीवी हों, सुख प्राप्त करें, पहला सुख निरोगी काया। यह सरकार के साथ आयुर्वेद विभाग का अटल निश्चय है और इस निश्चय में हम सदा लगे रहते हैं।

आपने कहा कि मरीजों के अनावश्यक ट्रान्सफर कर दिये जाते हैं, [illegible]

(श्री दौलतराम सारण)

दिये जाते हैं। एक साधारण तरीके से सब मामले में कह देना सही नहीं है। हो सकता है, किसी जगह किसी वैद्य की शिकायत आई हो, किसी माननीय सदस्य ने ही शिकायत की हो या पंचायत ने शिकायत की हो या पंचायत समिति ने शिकायत की हो या ग्रामीणों ने शिकायत की हो और उस शिकायत के ऊपर या और प्रशासनिक दृष्टि से कोई ट्रान्सफर करना लाजिम हो गया हो अथवा किसी वैद्य की मांग हो अपने घरेलू कारणों से, ऐसा किसी ने चाहा हो और कोई कहीं दूर हो और अपने गृह जिले में आना चाहता हो तो ऐसे प्रार्थनापत्रों पर विचार करके स्थानान्तरण होते हैं। लेकिन आम तौर से कहते हैं और जितना आप समझते हैं उस तरीके से जल्दी जल्दी ट्रान्सफर्स होने की या वैद्यों को तंग करने की कोई मनोवृत्ति विभाग में काम नहीं करती है। ऐसी कोई शिकायत का मौका विभाग नहीं देगा। हम यथा-सम्भव चेष्टा करते हैं कि वैद्य ज्यादा से ज्यादा अपने घरों के नजदीक रहें। लेकिन एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसी को कोटा, किसी को जयपुर से वाड़मेर, किसी को जयपुर से जैसलमर और अलग अलग उन्होंने नाम लिये कि कहां भेजे जाते हैं, लेकिन इसमें हमारी भी कई मजबूरियां हैं। जयपुर में इतने वैद्य हैं कि जो सारे राजस्थान में नहीं हैं और उन सब वैद्यों को जयपुर में नहीं रख सकते। इसलिये जहां भी जगह है वहां उनको भेजना पड़ता है। वाड़मेर और जैसलमेर या और कई जिलों में, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर या उदयपुर हैं, वहां पर वैद्यों की बहुत कमी है। अब वहां शिक्षण संस्था खुली है और अब वहां लोग वैद्य बनने लगे हैं। इस वजह से स्थानीय वैद्य नहीं मिलते हैं और यहां इतने ज्यादा हैं कि यहां के यहां औषधालयों में उनको नहीं रख सकते। इसलिये इन वैद्यों को जहां जगह खाली है, जहां वैद्य स्थानीय नहीं मिलते हैं, वहां भेजना पड़ता है। यथासम्भव हमारा प्रयास रहता है कि वैद्य अपने गृह जिले में रहें या फिर गृह जिलों के आस-पास ही रहें। यह हमारी नीति है और इसी दृष्टिकोण से हम व्यवस्था करते हैं और इसके अतिरिक्त यदि कोई शिकायत आती है तो या हमारी जानकारी में कोई बात आती है तो हम फिर उसकी व्यवस्था करते हैं।

मैं कह सकता हूं कि इस विभाग में पहले कुछ वैद्य ऐसे थे कि जिनको गृह जिलों में नहीं रखा जा सकता था लेकिन हमने धीरे धीरे चेष्टा करके आज से १।। साल पहले उन वैद्यों को जिन जिन को गृह जिलों में कर सकते थे उनको वहां भिजवाया है। इस तरह से हम चाहते हैं कि सुविधा से और ठीक ढंग से अपने पड़ोसियों की वैद्य सेवा करते हैं और दिलचस्पी के साथ काम कर सकें, यह हमारी इच्छा है। अब इतने कर्मचारी हैं उनमें एक-दो कर्मचारी की उनकी अपनी गलती से भी कभी कभी ट्रान्सफर होते हैं, दूसरों के चक्कर में आ जाते हैं और फिर अपने ट्रान्सफर को केंसिल कराने के चक्कर में आ जाते हैं और इधर उधर फिरते रहते हैं, बिना छुट्टियां लिये हुए गैर हाजिर हो जाते हैं और इस तरह की घटनाओं में भी चार्ज लेने और देने में देरी हो जाती है।

एक वैद्य का, हिन्डोन से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया। वह वहां ५ वर्ष से ज्यादा से थे और उनका स्थानान्तरण किया गया। उनको अपने स्थान पर आना चाहिये था। खैर, मैं उसको और देख रहा रहा हूं कि क्या उनके साथ गैर इन्साफी हुई है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : एक बात माननीय मंत्री महोदय बता दें कि जो वैद्य जिस जिले में रहने वाला है उसको वहां भेजना हमने उचित समझा है तो क्या वैद्यों का ट्रान्सफर शुरू में किया था यह उस जिले का था या नहीं और यह जो ट्रान्सफर हुआ यह वाजिब था या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण: एक वैद्य की बात नहीं कहता। आज हमारा निश्चय निवेदन है, वह यह है कि वैद्य को यथा सम्भव उसके गृह जिले में रखने की चेष्टा करते हैं। लेकिन दो-चार जिलों में वैद्य ज्यादा हैं और वे वहां रखे नहीं जा सकते इसलिये उनको समीपस्थ जिलों में भेजना पड़ता है।

श्री श्रवणलाल: आपने कहा तो क्या उन्होंने आपके ट्रान्सफर के मुताबिक चार्ज लिया और चार्ज लेने के बाद में, फिर कुछ दिन बाद में ही उसका ट्रान्सफर जिस जगह से आये थे उस जगह किया गया और उस जगह पर पहुंचने पर उनको कम्पाउन्डर ने चार्ज नहीं दिया। वह बेचारे ८ महीने तक परेशान हुए और आपने पंचायत की मार्फत अपने विभाग के लिये लिख दिया कि वह चार्ज नहीं दे रहा है और आज आठ महीने का वेतन आपके विभाग से नहीं दिया जा रहा है।

श्री दौलतराम सारण: इसकी जानकारी कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (यातायात मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यातायात विभाग की डिमाण्ड को लेकर माननीय सदस्यों ने कुछ ने इस विभाग के अन्दर अनियमितताओं के ऊपर रोशनी डाली है। मुझे कहने के पहले, माननीय उपाध्यक्षजी, आपसे निवेदन करना है कि यातायात विभाग इन १०-१२ वर्षों के अन्दर जितना आगे बढ़ा है और जिस तेजी से इसका विकास हुआ है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब कि राजस्थान बना था और अपनी योजनायें शुरू हुई थीं उस वक्त·······

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): (श्री भीखाभाई के सदन में प्रवेश-पर) आयुर्वेद मंत्री अब आये हैं जब कि उप-मंत्री महोदय पहले ही जवाब दे चुके, क्या वह जवाब देने से डरते थे या क्या बात थी ?

श्री भीखाभाई (आयुर्वेद मंत्री): आप विराजें तो एक घन्टा दे सकता हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा: वे दो घन्टे बैठेंगे आप और आप दोनों बैठे रहिये और सुनते-सुनाते रहिये।

श्री उपाध्यक्ष: एम. एल. ए. क्लब में व्यवस्था कर लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर: उपाध्यक्षजी, १९५१ के अन्दर राजस्थान में ६,८०७ विहीकल्स थीं जो अब ४६,६५८ हो गई हैं। इन वर्षों में राजस्थान की आर्थिक उन्नति हुई और आर्थिक विकास से लोगों की माली हालत ठीक हुई और इस वजह से इस समय राजस्थान के अन्दर जो ५-६ गुना इन १०-१२ वर्षों में हमारे यहां मोटर कारें और दीगर वाहन राजस्थान में रजिस्टर्ड हुए हैं वह अपने आप में, स्वयं अपने आपको कहते हैं कि यातायात विभाग के कन्धों पर बहुत जवाबदारी है और वह दिनों दिन बढ़ती ही जाती है।

Page No. 123

(श्री मथुरादास माथुर)

माननीय उपाध्यक्षजी, यही नहीं बल्कि राज्य सरकार को और आम जनता को योजना फलीभूत करने के लिये यातायात विभाग इस प्रकार हर साल टैक्स के रूप में ज्यादा से ज्यादा धनराशि देता रहा है। १६५६-६० में, उपाध्यक्षजी, इस विभाग की आमदनी ६३ लाख थी और अब इस विभाग की आमदनी १।।। करोड़ है। इस साल के बजट आंकड़ों में १ करोड़ ७७ लाख है यानी पौने दो करोड़ इस साल आमदनी इस विभाग की होगी।

५६-६० की बात है। उससे लगा कर आज तक बराबर यहां तरक्की होती जा रही है और खर्चा इस विभाग में कम होता जा रहा है। १६५६-६० में जो ५.६ परसेन्ट का खर्चा था, उसके एक्सपेन्डीचर और इन्कम को देखते हुए वह ४ प्रतिशत खर्चा रह गया है, बमुकाबले इसके कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्यप्रदेश के अन्दर इस वक्त जो आमदनी होती है, वह क्सपेन्डीचर करते हैं, उसके अन्दर उनका परसेन्टेज ऑफ एक्सपेन्डीचर टू इन्कम १० परसेन्ट है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस विभाग ने कम खर्चा करके राज्य सरकार और जनता के हित के लिये ज्यादा काम किया है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): ऑन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन, सर, आपने जबाब दिया है कि खर्चा कम हुआ आमदनी के मुकाबले। मैं जानना चाहता हूं इस बात को कि जब आपकी आमदनी ज्यादा हुई, इस जोश के अन्दर खर्चा कम किया गया तो क्या इससे सब लोगों की असुविधा नहीं बढ़ गई है? आपने आर. टी. ओ. के दफ्तर कम किए हैं, कलेक्टर को पॉवर्स नहीं दी हैं, लोगों को कितनी असुविधा और नुकसान हो रहा है, इसको भी देखा है?

श्री मथुरादास माथुर : मैं माननीय सदस्य के जजबात को समझता हूं। मैं अभी उनकी बातों का भी जवाब दूंगा। अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके अलावा मैं यह भी सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि इस वक्त राजस्थान के अन्दर जो हमारी मुख्तलिफ स्टेट कैरेजेज दौडती हैं वे ४०,५७४ मील पर दौड़ती हैं। ४०,५४७ मील पर राजस्थान सरकार के परमिट से गाडियां चलती हैं। और यह ४०,५७४ मील ६३८ रूट्स का एरिया है। इन सब नए और पुराने रूट्स को मिला कर करीब एक हजार रूट्स पर करीब चालीस हजार मील पर ३,७०० परमिट दिये गये हैं और इस तरह से राजस्थान के अन्दर रोड ट्रान्सपोर्ट का डेवलपमेन्ट हुआ है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान ही बहुत बड़ा प्रदेश है जिसके अन्दर कि यातायात के साधन सीमित हैं, और रोडवेज की विहिकल्स की कमी होने की वजह से भी सीमित हैं तो इन सब परिस्थितियों में भी हमने सड़कें बना कर इसका विकास किया है और उसकी एक तस्वीर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के यातायात विभाग ने इस बात की पूरी कोशिश की है कि यहां पर यातायात के साधन अधिक से अधिक बढ़ें। माननीय सदस्यों ने जो भी यहां पर कटमोशन्स

(श्री मथुरादास माथुर)
रखे हैं उन कटमोशन्स के अन्दर उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे यहां पर लीकेज बहुत है हमारे टैक्सेज के अन्दर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर, इस साल के टैक्स के फीगर्स तो अभी तक निकले नहीं हैं, अभी तक उनका टेबुलेशन नहीं हुआ है, मगर इस साल के पहले, ३१-३-६५ तक के आंकड़े मेरे पास हैं, उसके अनुसार इस वक्त राजस्थान के इस विभाग के जो टैक्स एरियर्स हैं वे सिर्फ छः लाख रुपयों के एरियर्स हैं। उसमें भी कोई डेढ़, पौने दो लाख रुपया रोडवेज में है, जो राज्य सरकार को मिल जायगा। उसका आपस में हिसाब हो रहा है। कुछ केसेज भी पी. डी. आर. के तहत पैन्डिंग हैं और कुछ विभिन्न कोर्टों में मामले विचाराधीन है। इस तरह से कुल धन-राशि से दो-तीन लाख रुपये की राशि ही दिसम्बर, ६५ तक हमारे टैक्स के एरियर्स की बाकी रहती है और बाकी की वसूली भी बराबर हो रही है। इस तरह दूसरे टैक्सों के एरियर्स के बमुकाबले हमारे इस विभाग के एरियर्स बहुत कम हैं और इस बात को मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता लेकिन हमारे आफिसर्स ने जिस तरह से टैक्सों को वसूल करने में तत्परता दिखाई है वह कम से कम सराहनीय है, इस बात को कहे बिना मैं रह नहीं सकता।

माननीय उपाध्यक्षजी, यह भी कहा गया कि हमने हमारे यहां पर इस वक्त जो रीजन्स हैं और उसके जरिये परमिट देते हैं तो इस तरह से परमिट देकर पूरे यातायात को खतरा पैदा कर दिया है। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि आर. टी. ओ. का आफिस, जिसमें वे खास-तौर से दिलचस्पी रखते हैं, अजमेर से हटा दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करदूं कि जयपुर डिवीजन के आर. टी. ओ. आफिस का हैडक्वार्टर पहले अजमेर रखा गया था लेकिन अब जयपुर में अजमेर का आर. टी. ओ. आफिस खोला गया है। यह बात तो यों हुई कि क्योंकि हमारे यहां पर जो इसके मुस्तलिफ आफिसेज हैं उनके लिए हमने इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया है कि इसमें तीन आर. टी. ओ. हों। एक आर. टी. ओ. जोधपुर में है, एक उदयपुर में है और एक जयपुर में है। इस आर. टी. ओ. के अन्डर में ए. आर. टी. ओज के आफिसेज हैं। ए. आर. टी. ओ. का एक रीजन अभी गंगानगर में बनाया गया है। तो एक तो गंगानगर में ए. आर. टी. ओ. है, एक बीकानेर में है, एक कोटा में है और एक ए. आर. टी. ओ. जयपुर में आर. टी. ओ. आफिस में रखा गया है क्योंकि यहां पर काम ज्यादा है, बहुत बडा आफिस है। तो कुल मिला कर इन रीजन्स के मार्फत हम अपने यहां का इन्तजाम करते हैं।

जैसी लोगों की शिकायत हैं और नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि टैक्स देने के लिये लोगों को दूर दूर से आर. टी. ओ. के यहां जाना पड़ता है। राज्य सरकार इस बात का विचार कर रही है कि टैक्सों की वसूली की व्यवस्था कोई कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो। इसके लिए हमने एक कमेटी बैठाई है जो इस बात की जांच करेगी कि इस व्यवस्था को करने के लिए हमें किन किन कानूनों और रूल्स में तब्दीली करनी पड़ेगी जिससे कि लोगों को कोई असुविधा न हो और सुविधा से ही डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ही यह काम पूरा हो सके। इस पर विचार करने के लिये हमने एक कमेटी बैठा दी है। कमेटी की रिपोर्ट आने पर राज्य सरकार कानूनी नुक्तेनिगाह से इस पर विचार करेगी।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद): आपकी जानकारी के लिये मैं कहना चाहूंगा कि जो आप अजमेर के ऑफिस की बात करते हैं तो वह ऑफिस तो इकोनोमी के नाम पर वहां से उठाया गया। मैं दावे के

मथुरादास माथुर)

ष कहता हूं कि विहिकल्स के लिहाज से वह ऑफिस पहले भी वहां था और हेकल्स के लिहाज से अब भी ए. आर. टी. . ऑफिस मांगते हैं। इसलिये मांगते हैं वहां पर विहिकल्स की तादाद इतनी ादा है कि उतनी दूसरी किसी जगह पर ीं है। आप जब कहते हैं तो आप कोटा, ानगर और न जाने कितने नाम गिना कर त को टाल देते हैं, लेकिन अजमेर को ोइड करते हैं। इसके लिए मेरी प्रार्थना कि वहां के लोगों को दिक्कत है और हां पर ए. आर. टी. ओ. का ऑफिस होना ाहिये।

श्री भैरोंसिंह : इसमें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ा दोष नहीं है। इकोनोमी कमेटी के यरमैन फाइनेन्स मिनिस्टर हैं और अजमेर फाइनेन्स मिनिस्टर ने ही अपने वहां के द को एबोलिश किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपको ता दूं कि वहां पर ए. आर. टी. ओ. का ऑफिस बहुत जरूरी है। और यह जो फाइनेन्स मिनिस्टर ने किया है तो यह तो अच्छा ही किया है क्योंकि जब दूसरों की गर्दन काटनी है तो पहले अपनी गरदन काटना पड़ता है। उन्होंने जो किया वह तो ठीक ही किया, लेकिन यह तो गवर्नमेन्ट के सोचने की बात है। यहां तो देखना यह है कि गवर्नमेन्ट के द्वारा इस तरह की हरकत की जाती है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जजबात रखे हैं तो उनके जजबातों का पूरा ख्याल रखा जायगा, इतना ही मैं निवेदन कर सकता हूं और मेरी भी बराबर इच्छा है और चाहता भी हूं कि और और जगहों पर भी आर. टी. ओज. और ए. आर. टी. ओज. के ऑफिसेज कायम हों। जैसा कि वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हमें इकोनोमी करनी पड़ेगी और इकोनोमी कमेटी ने जो तीन ए. आर. टी. ओज. के दफ्तर खत्म करने की सिफारिश की है उसी के अनुसार यह कमी आई है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इकोनोमी एट दी कोस्ट ऑफ एफिशियेन्सी नहीं हो सकती।

श्री मथुरादास माथुर : यह दलील मैं भी देता हूं और जब जब इकोनोमी कमेटी की मीटिंग होती है तो उसमें मैं भी यही दलील देता हूं और आगे भी देता रहूंगा। उम्मीद करिए कि मुझे इसमें कामयाबी मिले और अगर मुझे ए. आर. टी. ओ. का आफिस और मिल गया तो मैं आपको नजर कर दूंगा। लेकिन यह तो वक्त आएगा तब देखा जाएगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं गारण्टी देता हूं कि इसके लिए फाइनेन्स मिनिस्टर इन्कार नहीं करेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय इसी कटौती को लेकर हमारे यहां पर कुछ ए. आर. टी. ओज. और कुछ हमारे यहां सब-इन्सपेक्टर्स की पोस्ट थीं वे पोस्टें बहुत अर्से से खाली थीं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिये यह किया गया। मैं आपको निवेदन कर दूं कि सब-इन्सपेक्टर्स को मुकर्रर करने का अधिकार डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट को है। न तो यह पी. एस. सी. के पास है, न इसके कागजात अपोइन्टमेन्ट करने के

(श्री मथुरादास माथुर)
पी. एस. सी. के पास जाते हैं, न पी. एस. सी. के द्वारा इसका कोई इन्टरव्यू होता है और न ही गवर्नमेन्ट के पास आते हैं। इसलिये हमारे डाइरेक्टर महोदय ने काम को सुचारू रूप से चलाने के लिये जो दस-बारह पोस्टें उनके पास काफी अर्से से खाली थीं उनमें से ८-९ पोस्टों पर अपोइन्टमेन्ट कर दिया और वह भी तीन महीने के लिये टेम्पोरैरी आधार पर, जब तक कि इसका पूरा सिलेक्शन न हो जाय। पी. एस. सी. में इन पोस्टों के जाने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता क्योंकि उनकी परव्यू के बाहर हैं।

(५ म.प.)

श्री भैरोंसिंह : इसके लिए रूल्स बने हुए हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये इन आदमियों को मुस्तकिल तौर पर रखने के लिए डाइरेक्टर ने सरकार से सलाह लेकर इस बात का फैसला लिया कि एडवर्टाइज-मेन्ट किया जाय। पोस्टें भरने के लिये एडवर्टाइजमेन्ट किया गया। दरख्वास्तें मांगी गईं। दरख्वास्तें आईं और बहुत ज्यादा तादाद में आईं तो इसलिये यह तय किया गया कि इतने आदमी जो मेरे ख्याल में ६००, ६०० या हजार के करीब होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में थे, उनका अगर इन्टरव्यू से सिलेक्शन करेंगे तो मुश्किल होगा, इसलिये इम्तिहान लिया गया और जो सक्सेसफुल हुए उनको इन्टरव्यू के लिये बुलाने का फैसला किया गया। इन्टरव्यू के लिये नोटिस मिले। इन्टरव्यू के लिये कार्यवाही चल रही थी कि राजस्थान सरकार ने एक इकोनोमी कमेटी बनाकर एमर्जेन्सी के वक्त में यह फैसला किया गया कि किसी विभाग में कोई जगह खाली पड़ी हुई हो तो उसको नहीं भरा जाय। यह ब्लेन्केट रूल बन गया था और हमारे पास हुक्म आगया कि कोई जगह खाली हो तो मत भरो। १० पोस्टें खाली थीं भरने वाले थे, इन्टरव्यू लेने वाले थे कि यह हुक्म आ गया तो वे पोस्टें नहीं भरी गईं और जिन आदमियों का टैम्पोरेरी एपोइन्टमेन्ट किया गया था, तीन महीने के लिये किया गया था, तो तीन महीने के खत्म होने के बाद टैम्पोरेरी सर्विस होने के बाद वे ऑटोमेटिकली टर्मीनेट होगई। यह सिलेक्शन होता तो उनमें से कुछ सिलेक्ट हो जाते। वे पोस्टें बन्द कर दी गईं, क्योंकि हमारी सरकार ने अन्दर खाली जगह न भरी जाय। इसके बारे में ट्रेजरी को भी हुक्म दे दिया गया था इकोनोमी के लिये वे पोस्टें नहीं भरी गई।

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन यह नहीं था लेकिन क्वेश्चन यह था कि आपने जो रूल्स बना रखे हैं तो इन टेम्पोरेरी एपोइन्टमेन्ट्स में उन रूल्स को फोलो किया गया या नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : टेम्पोरेरी एपोइन्टमेन्ट्स के लिये कोई रूल्स नहीं हैं। पर्मानेन्ट एपोइन्टमेन्ट के लिऐ रूल्स हैं। उसके लिये पोस्टें एडवर्टाइज की जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : टैम्पोरेरी एपोइन्टमेन्ट के लिये रूल्स नहीं हैं तो कैसे कर दिया ?

श्री मथुरादास माथुर : टेम्पोरेरी एपोइन्टमेन्ट का डाइरेक्टर का डिस्क्रीशन कि तीन महीने के लिये एपोइन्ट कर ले, काम चलाने के लिये।

श्री भैरोंसिंह : वह रूल्स में है ?

श्री मथुरादास माथुर : वह है ?

श्री भैरोंसिंह : उन रूल्स को फोलो किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : डाइरेक्टर ने श्री मन्थ्स के लिये टैम्पोरेरी ले लिया कि बाद में एडवर्टाइजमेंट करके आदमियों को पर्मानेन्टली ले लेंगे । पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्दर भी जो पोस्टें उसके परव्यू में होती हैं और राजस्थान सरकार एपोइंटिंग ऑथोरिटी है तो सिवाय मन्थ्स के लिये वह उन पोस्टों को भर सकती है ताकि काम को चला सके । बाद में उन पोस्टों को एडवर्टाइज करके पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उसको भरना पड़ेगा ।

श्री भैरोंसिंह : एक-एक साल तक वे पोस्टें खाली पड़ी थीं, उस वक्त तो टैम्पोरेरी नहीं लिये गये । वे एक साल तक खाली पड़ी रहीं तो उस वक्त में एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं रही ?

श्री मथुरादास माथुर : जो पहले के डाइरेक्टर थे तो वे ३-४ महीने की छुट्टी पर थे । वे बराबर लिखते रहे कि इन पोस्टों के बगैर काम नहीं चलता है, टैक्सेज बढ रहे हैं और विहिकल्स बढ रही हैं, इसलिये तीन महीने के लिये उन पोस्टों को भर कर एडवर्टाइजमेंट कर दिया । उस तीन महीने के अन्दर एडवर्टाइजमेंट करवाया, और इम्तिहान करवाया और इन्टरव्यू के लिये बुलाने का फैसला किया । इसके बाद में सरकार ने हुक्म कर दिया, एक ब्लेन्केट रूल बना दिया कि कोई जगह नहीं भरेगी । इसका नतीजा यह हुआ कि टैम्पोरेरी पीरियड खत्म हो गया, वर्ना वे रिडक्शन में आते तो आ जाते । इस बीच में यदि उनको तीन महीने के लिये लिया गया है तो यह कोई भ्रष्टाचार नहीं है जब कि कम्पीटीटिव इम्तिहान लेकर सिलेक्शन करने की बात थी । इसलिये मैं कहता हूं कि यह कैबिनेट ने फैसला किया ब्लेन्केट रूल बनाया है । यह न किसी मिनिस्टर ने कहा है और न किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने.........

श्री भैरोंसिंह : माफ करें, यह समझ में नहीं आया कि जो जगह १२ महीने से खाली पड़ी थीं तो उस समय बाकायदा एडवर्टाइजमेंट करके सिलेक्शन नहीं किया जाय तो फिर ऐसी क्या एमर्जेन्सी पैदा हो गई कि एक ही महीने में पोस्टें भर लीं ?

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य को मैंने कहा है कि जो पहले के डाइरेक्टर थे हांडा साहब, वे तीन महीने से बीमार थे और हॉस्पिटल में थे । उसके बाद में जो नये डाइरेक्टर आये तो इन्होंने तकलीफ महसूस की और ८-९ पोस्टें भर कर टैम्पोरेरिली तीन महीने के लिये एडवर्टाइजमेंट कर दिया, इम्तिहान ले लिये और सब कुछ कर दिया गया । जब इतनी बात हो गई तो यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इर्रेग्युलेरिटी की, या उसके पीछे कोई ऐसी बात थी ।

माननीय उपाध्यक्षजी, यहां नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने कमल एण्ड कम्पनी का जिक्र किया और उन्होंने जो कुछ पढ़ कर सुनाया वह मेरे विभाग से सम्बन्धित नहीं है । वह जो ऑडिट रिपोर्ट थी वह इरिगेशन डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित थी । इसलिए उसके बारे में मैं कुछ नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

कहता। कमल एण्ड कम्पनी ने राजस्थान कैनाल वालों को एक ट्रैक्टर बेचा तो यह काम उनका था। वह मेरे से सम्बन्ध नहीं रखता है इसलिए मैं असमर्थ हूं उसका जवाब देने के लिए

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैंने आगाह किया है। सोच-समझ कर जवाब दें, क्योंकि ऐसे मामले चलते रहते हैं। आपका उससे सम्बन्ध नहीं हैं, लेकिन मैंने आगाह किया है कि ये धन्धे होते हैं और वे लोग ऐसे धन्धे करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं उस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में जो कि राजस्थान कैनाल के बारे में है, नहीं कह सकता कि वह गलत है या सही है। वह मिनिस्टर कन्सर्न्ड का काम है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो रिपोर्ट है उसको सच तो मानते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : आप ऑडिट रिपोर्ट को महत्व देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट का जवाब जब डिपार्टमेन्ट से जाता है तो ऑडिट वाले चुप हो जाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट और उसके जवाब दोनों को तोल कर देखा जाय कि वे गलत हैं या हम।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपकी इन्फोर्मेशन के लिए मैं कहूं कि यह मामला पी. ए. सी. की रिपोर्ट में शामिल कर लिया गया है। जब पी. ए. सी. उसको एग्जामिन करती है तो दोनों के जवाबों को देखकर ही अपनी रिपोर्ट में लिखती है। जब ऑडिट रिपोर्ट का जवाब नहीं दे सकते तो आपके विधि मंत्रालय ने कहा है कि केस कर देना चाहिए। वह भी आपकी जानक... में होना चाहिए और लाया गया होगा क्यों... आप विधि मंत्री भी हैं। यह कहें कि वह... आपके जवाब देने की नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन यह सब्जेक्ट नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : सब्जेक्ट में है और डिपार्टमेन्ट भी मेरा नहीं है। ...तक कमल एण्ड कम्पनी की सिटी बस... सवाल है उसकी पहले भी चर्चा हुई थी... निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्... कहा कि एक माननीय सदस्य से ज... किराया लिया गया तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें कि किराया ज्यादा... गया है, मैं बराबर, जो मेरा फर्ज है, ज... जांच करूंगा। मैंने निवेदन कर दिय... जितनी भी रूट्स हैं किराये पर चलने... हों चाहे सिटी बसें हो, चाहे प्राइवेट ब... जिनको कि रूट्स पर चलाते हों तो रो... स्टेच्यूटरी बोडी है वही परमिट देत... वही जुर्माना करती है, वही परमिट कं... करती है। ट्रान्सपोर्ट का इन्सपेक्टर... पार्टी की हैसियत से जो नजर आता है... चैक करता है; तो वह उसके सामने दरर... देता है। वह ऑथोरिटी उसको सुनते ह... दूसरी पार्टी को सुनते हैं। कमल एण्ड क... के लिये कोई हमदर्दी नहीं है... न कोई विरोध है। कमल एंड... पर हम लोगों की शिकायत पर... जुर्माना हो चुका है। इसलिए कमल... कम्पनी के हम राखी बांधने वाले नहीं...

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : ...जो टैक्स वसूल होता है उसके बारे ... चाहते हैं।

Page No. 129

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए यह सोचना कि कमल एण्ड कम्पनी की शिकायत नहीं करते हैं, यह ठीक नहीं हम वक्तन बवक्तन करते रहते हैं। उन पर १५००) रु. जुर्माना भी हो चुका है। इसलिए यह निवेदन करूंगा कि कमल एण्ड कम्पनी हमारा मां जाया बेटा हो इसलिए उसके खिलाफ काम नहीं होता है; यह चीज आपको दिमाग में से निकाल देनी चाहिए।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इसके बाद का जो दूसरा कन्क्लूजन है वह और बता दें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं अभी नहीं बैठ रहा हूं। सब्र तो रहे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं इसी क्वेश्चन पर कहना चाहता हूं कि जिसके ऊपर आप इतना गुमान कर रहे हैं, तो इस कानून तोड़ने वाले को जिसको कि आपने अभी एडमिट किया है १५००) रु. जुर्माना करवाया है, तो फिर उसको परमिट क्यों मिलता है ? क्या कानून तोड़ने के लिए बार बार उसको परमिट मिलता है ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य से मेरा नम्र निवेदन है कि जुर्माने से किसी आदमी को किसी काम के लिए नहीं रोक सकते हैं। परमिट कन्सिल करने का अधिकार भी मेरा नहीं है। परमिट देने का अधिकार भी राजस्थान सरकार व ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट का नहीं वह आर. टी. ए. देती है जो कि एक स्टेच्यूटरी बॉडी है। वही सब कुछ फैसला करती है। तो एक मुस्तगीस की हैसियत से खड़ा होकर अदालत में चला जाता हूं और अपनी बात रख देता हूं। परमिट उनको मिलती है तो आर. टी. ए. से मिलती है। आर. टी. ए. ही उन पर जुर्माना करती है। किसी आदमी पर जुर्माना किसी वक्त में हो जाये तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसको धन्धे से ही खत्म कर दें। आर. टी. ए. बैलेन्स्ड तरीके से सोचती है और फसला करती है।

टिकटों के बारे में यह कहा गया कि काउन्टर फोइल नहीं होता है। ये टिकट (टिकट दिखाकर) मौजूद हैं। इनमें काउन्टर फोइल मौजूद है, नम्बर भी मौजूद है। यहां एक मील, दो मील, तीन मील और चार मील के टिकट हैं और चारों के अलग अलग रंग हैं। चार मील से ज्यादा सिटी बस चलती नहीं है। इस पर ५ पैसे फी मील लिया जाता है ४.२ पैसा कॉम्पोनेन्ट भाड़ा है और .८ पैसे पैसेन्जर टैक्स है, टोटल ५ पैसा लिया हुआ है। काउन्टर फोइल भी मौजूद है। पैसेन्जर टैक्स टैक्सेशन डिपार्टमेन्ट वसूल करता है, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट वसूल नहीं करता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जो टिकट आप दिखा रहे हैं उनको टेबल पर रख दीजिये; जो २५ परसेन्ट टैक्स बढ़ा है, वह इन पर लिखा हुआ है या नहीं या पुराने ही टिकट चल रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : पुराने कैसे चल रहे हैं, मैं कैसे मानूं आपके कहने से।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन टिकटों को रूल्स के माफिक क्यों नहीं छापा जब कि दूसरे लोग छापते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : यह टैक्सेशन डिपार्टमेन्ट के देखने की बात है । टैक्स बराबर छपा हुआ मौजूद है । अभी आपने बताया कि २५ परसेन्ट टैक्स बढ़ गया । बढ़े हुए टैक्स की सील इन टिकटों पर मौजूद है, पुराने टिकट फाड़ नहीं जा सकते । उन पर स्टाम्पिंग लगा हुआ है । पैसेन्जर टैक्स जो इन्क्रीज हुआ है वह स्टेम्पिंग से लगा हुआ है । So much I can say.

यह मैं बता रहा हूं

श्री भीमसेन : आपको बताने के लिये स्टाम्प लगा दिया होगा ।

श्री तेजराम गहलोत (सोजत) : यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि मोटर विहिकल्स एक्ट के माफिक जो स्टेन्ड मुकर्रर किये गये हैं वह भी छपा हुआ होना चाहिये टिकट पर । यदि स्टेन्ड छपे हुए नहीं हैं तो यह कैसे मानते हैं कि यह इस स्टेन्ड से उस स्टेन्ड तक का है ?

श्री मथुरादास माथुर : जो टिकट चल रहे हैं उनमें कोई कानूनी बाधा नहीं है । उनको बढ़ा बताया जा सकता है, एक एक स्टेन्ड का नाम लिखा जा सकता है । जहां तक टैक्स का सवाल है, टिकट पर टैक्स लिखा हुआ है; कानून के अनुसार है, कानून के अनुसार नहीं होता तो आर. टी. ए. के पास शिकायत कर देते और चालान हो जाता । जहां तक कमल एण्ड कम्पनी के खिलाफ शिकायत है उसके बारे में मैंने निवेदन कर दिया, फिर भी उसकी शिकायत आयेगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है ।

श्री भेरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्रीजी ने टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स को लेकर बताया कि रूल्स के अन्तर्गत अपोइन्टमेन्ट हुआ है । मेरे पास रूल्स हैं, जो राजस्थान राज-पत्र दिनांक १३-६-६३ में छपे हैं उसमें रूल नम्बर २७ में टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट के बारे में इस प्रकार बताया है : "A temporary vacancy may be Filled by the appoiuting authority.",

आपने बताया कि एक साल से वेकेन्सी थी । इसमें बताया है, "Temproary Vacancy may be filled. यह टेम्परेरी वेकेन्सी नहीं है । टेम्पोरेरी वेकेन्सी का मतलब यह है कि कोई छुट्टी चला गया है या बीमार हो गया है या ३ महीने से बीमार हो गया है, उसकी जगह किसी को अपोइन्ट किया जाता है तो वह टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट कही जा सकती है । यह परमानेन्ट वेकेन्सी थी टेम्पोरेरी नहीं थी ।

श्री मथुरादास माथुर : वेकेन्सी परमानेन्ट थी, लेकिन भरी गई टेम्पोरेरी तौर पर ।

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : परमानेन्ट वेकेन्सी को आप टेम्पोरेरी के माफिक नहीं भर सकते ।

श्री मथुरादास माथुर : परमानेन्ट अपोइन्टमेन्ट के लिये जो रूल्स हैं वे ही फोलो किये गये थे ।

श्री भेरोंसिंह : रूल्स में ऐसा नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : कॉमनसेन्स का सवाल है ।

श्री भेरोंसिंह : रूल्स का सवाल है, कॉमनसेन्स का नहीं ।

Page No. 131

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास रूल्स नहीं हैं। मैं इसके बिना जिक्र नहीं कर सकता। यदि परमानेन्ट वेकेन्सी के अगेन्स्ट में काम चलाने के लिये, तीन महीनों के लिये काम चलाने के लिये अपोइन्टमेन्ट कर लें तो इर्रेगुलेरिटी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में इसके लिये क्लीयर प्रोवीजन है। आप मेरे से रूल्स ले लीजिये और बता दीजिये किस तरह से है।

श्री मथुरादास माथुर : परमानेन्ट जगह को पी० एस० सी० भरती है, उसको भरने का अधिकार है। हम लोग पी० एस० सी० के एप्रूवल के लिये जाने से पहले ६ महीनों के लिये अपोइंटिंग ऑथोरिटी अपोइन्टमेन्ट कर सकती है। इसमें आपके कहने का मतलब यह था कि इसमें फेवरेटिज्म हुआ है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं हुआ है। टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट दी गई थी अगेन्स्ट परमानेन्ट वेकेन्सी। उसके बाद एडवर्टाइजमेन्ट कराया गया।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात का जिक्र किया, खास तौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के लिये मेरे हृदय में बहुत बड़ी इज्जत है। मुझे एक बात का दुःख हुआ जब उन्होंने कहा कि मैं एन्टी राजपूत हूं। यह चार्ज उन्होंने मेरे पर लगाया है। इसके बारे में वे स्वयं सोचें क्योंकि मैं कभी एन्टी-कम्युनिटी या एन्टी-क्लास का हामी नहीं रहा, मेरे पोलिटिकल व्यूज मेरे पास हैं। मैं एन्टी-फ्यूडल हो सकता हूं। यह आपका बिल्कुल गलत सोचना है। यदि आप यह सोचते हैं तो आप एक साथी और एक सदस्य के प्रति अन्याय कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, खास तौर से मिस्टर झाला का जिक्र करके कहा। मैं इस केस के बारे में इतना ही कहूंगा, मि० झाला, हमारे ए० आर० टी० ओ० हैं वे ५-२-६३ को सस्पेन्ड हुए थे....

श्री भैरोंसिंह : सन् ६५ की बात करें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं उस पर भी आता हूं। वे ५-२-६३ को सस्पेन्ड हुए जिस वक्त मेरे पास यह पोर्टफोलियो नहीं था। सस्पेन्ड होने के बाद उनको चार्ज शीट दी गई। फिर राजस्थान सरकार ने सोचा कि यंग मैन है, मैं कहना चाहूंगा कि यंग मैन के लिये मेरी खुद की हमदर्दी है, आप उनको पूछिये, जिस वक्त उनको सस्पेंड किया उसके बाद उनकी इन्क्वायरी होनी थी। उनका सस्पेन्डेशन रिमूव करके रिइन्स्टेट किया। इन्क्वायरी डिपार्टमेन्टल, इन्क्वायरी कमिश्नर की कम्पलीट होकर आ गई। क्या है, क्या नहीं, यह दूसरा पहलू है। उसके बाद कलेक्टर बीकानेर ने उनकी कम्पलेन्ट की, डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट को लिखा, २-३ चार्ज उनके खिलाफ लगाये। डाइरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट ने उनकी प्राइमाफेसी इन्क्वायरी की, कलेक्टर को पूछा और जो कुछ करना चाहिये था किया। फिर इन्होंने गवर्नमेन्ट को लिख कर भेजा कि यह पहले भी सस्पेन्ड हो चुका है, कलेक्टर बीकानेर ने फिर इसके खिलाफ लिखा है, इसलिये इसको सस्पेन्ड करके दुबारा इन्क्वायरी होनी चाहिये। जब यह बात गवर्नमेन्ट के पास आई, हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट कहता है एक बार पहले भी सस्पेन्ड किया गया था और यंग एज के कारण बहाल कर दिया था, दुबारा फिर शिकायत आई है, इसलिये सस्पेन्ड किया जाय और उसको सस्पेन्ड कर दिया। अब उसको चार्जशीट देनी चाहिये थी। होम डिपार्टमेन्ट से चार्जशीट बन कर अपोइन्टमेन्ट्स

Page No. 132

(श्री मथुरादास माथुर)
डिपार्टमेन्ट में चली गई। अब तक चार्जशीट उनके पास नहीं पहुंची . . .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अपोइन्टमेन्ट्स में कब चली गई ?

श्री मथुरादास माथुर : ३ महीने पहले।

श्री भैरोंसिंह : मैं इतना कह सकता हूं यदि आप नाराज न हों तो कि यह सेन्ट परसेन्ट असत्य है। एक महीने पहले अपोइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट ने उसके सस्पेन्शन को कन्फर्म किया है।

श्री मथुरादास माथुर : कलेक्टर से रिपोर्ट आने के बाद ७-६-६५ को उसका सस्पेन्शन होने के बाद हमारे डिपार्टमेन्ट से एलीगेशन का स्टेटमेन्ट बनकर अपोइन्टमेन्ट्स में चला गया।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह आपके वहां से कब गया ?

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास डेट नहीं है, लेकिन अपोइन्टमेन्ट्स में चला गया।

श्री भैरोंसिंह : सवाल मेरा यह नहीं है कि आपके वहां से कहां चला गया। ९ महीने निकलने के बाद भी इस ऑफिसर को चार्ज शीट नहीं सर्व हुई।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने मान लिया, चाहे किसी की गलती हो, उसको ९ महीनों से चार्जशीट नहीं मिला, इसका मुझे दुःख है। मैंने फाइल मंगाई है, कल फाइल देखूंगा, किस की वजह से डिले हुई है, आगे क्या कार्यवाही करनी चाहिये, यह बाद की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास मि० झाला आये थे। मैंने पूछा कि चार्जशीट क्यों नहीं मिला। मैंने उसी समय टेलीफोन किया कि चार्जशीट मिलनी चाहिये। यदि गुनाह किया है तो सजा मिलेगी। मुझे एक-दो बार और कहा था; मैंने कहा कि चार्जशीट मिलनी चाहिये और उसका जवाब देकर जल्दी ही झगड़े का निपटारा होना चाहिये। मैंने पर्सनली कहा, फिर भी नहीं मिला, इसका मुझे दुःख है। मैं आगे देखूंगा कि आगे क्या करना चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : इसके बारे में रूल्स नहीं है कि जब सस्पेन्ड करते हैं तो उसके कितने दिन में चार्ज-शीट मिल जायगी और कितने दिन में उसका जवाब मिल जायगा ?

श्री भैरोंसिंह : रूल्स हैं।

श्री मथुरादास माथुर : रूल्स हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं . . . .

श्री भैरोंसिंह : रूल्स यही है कि इमी-जियेटली सस्पेन्शन के बाद में चार्जशीट मिलनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेन्ट ऑर्डर यह है कि दो साल के अन्दर किसी ऑफिसर के खिलाफ, जो अन्डर सस्पेन्शन है, इन्क्वायरी कम्प्लीट नहीं हो और उसमें ऑफिसर की वजह से डिले नहीं हुई हो, या कोई दूसरी बात ऐसी नहीं हो जिसमें उसकी गलती रही हो तो यदि दो वर्ष में इन्क्वायरी कम्प्लीट नहीं हो पाये तो गवर्नमेन्ट ऑर्डर है कि उस आफिसर को रिइन्स्टेट किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स यह है कि यदि सात दिन के अन्दर अन्दर चार्ज शीट और स्टेटमेन्ट

(श्री भैरोंसिंह)
ऑफ एलीगेशन न दिया जाय तो सस्पेन्ड करने वाला ग्राफिसर कुसूरवार है ।

श्री मथुरादास माथुर : कोई ऑर्डर इस तरह का नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह ऑर्डर नहीं है । यदि इतनी जवाबदारी लें तो बहुत जवाबदारी आ जायगी ।

श्री भैरोंसिंह : यह है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह ऑर्डर है कि दो साल के अन्दर इन्क्वायरी कम्प्लीट न हो पाये तो उस ऑफिसर को रिइन्स्टेट कर दिया जायगा, यदि उस ऑफिसर की वजह से कोई डिले नहीं हुई हो । यह जानकारी दी है मुझे सस्पेन्शन के लिए ।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी उन्होंने गलत दी है । सस्पेन्शन के रूल्स हैं, उनको हरिदेव जोशी ने, जब वह पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी के चेयरमैन थे, एक एक रूल का ग्रेड वेग्रर में डिस्कस किया है । आप इनसे कहलवा दें कि ऐसा रूल नहीं है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : रूल्स हैं, यह नहीं है कि एक साल यूं ही निकाल दें ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं कह दूं कि मुझे ख्याल नहीं है कि कोई ऐसा रूल है ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो ख्याल है ।

श्री मथुरादास माथुर : आपको ख्याल है क्योंकि आपका ज्यादा सस्पेन्शन होता रहा है । मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो भी सस्पेन्शन के रूल्स हैं उनके अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिले, इस ख्याल से यह प्रोवीजन रूल्स में है । इसलिए आपको गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स का ख्याल होना चाहिए ।

श्री मथुरादास माथुर : हमको ख्याल है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आपको ख्याल है तो पन्द्रह दिन में जिस केस में चार्ज शीट और स्टेटमेन्ट ऑफ एलीगेशन नहीं मिला है, उस केस में जिस ऑफिसर ने सस्पेन्ड किया है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करें ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार के रूल्स हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी इस प्रकार की कार्यवाही से गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स में इतना जबर्दस्त हैवक बना हुआ है, उसके बारे में आपको विचार करना चाहिए ।

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री) : है, भाई, है ।

श्री मथुरादास माथुर : है, तो अच्छी बात है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सब तरफ से आपको इशारा कर रहे हैं कि ऐसा रूल है, और आप कहते हैं कि नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : दिक्कत यही है कि आपको भी याद नहीं है और मुझे भी नहीं है कि यह है या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह : दिक्कत यह है कि आपको मालूम नहीं है । यह रूल है कि विदिन सेवन डेज स्टेटमेन्ट ऑफ एलीगेशन दिया जाय । यह रूल है ।

श्री मथुरादास माथुर : यह नहीं है। मैं पूछता हूं कि अगर ऐसा नहीं करें तो क्या करें। इसलिए इसको देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको डिसिप्लीनरी एक्शन लेना चाहिए उस ऑफिसर के खिलाफ जिसने सस्पेन्ड किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स में यह है कि जब प्राइमाफेसी केस के बारे में सेटिसफाइड हो जाय, तो सेटिसफाइड होने के बाद ही किसी व्यक्ति को सस्पेन्ड किया जाय। यदि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी नहीं हुई है चार्जेज के बारे में, जैसा कि इस केस में है कि उसके बारे में कोई इन्क्वायरी नहीं हुई है, प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी नहीं हुई है और उसके पहले ही सस्पेन्ड हुआ है तो उसको बरी कर दिया जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : इस केस में कलेक्टर ने चार्जशीट भेजी थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सस्पेन्शन के रूल्स में है कि प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी होल्ड होगी और उसमें सेटिसफाइड होने के बाद ही सस्पेन्ड किया जायगा; ये तो रूल्स हैं, वैसे आप करें कुछ भी।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर दूं कि मैंने पहले ही कहा है कि इस केस में डिले हुई है, इस केस का आपने यहां जिक्र किया इसलिए मैं सब बातें तो कैसे बता सकता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस केस में कोई पर्पजफुल पेनेलाइज करने का सरकार का कोई मोटिव नहीं था। यह साफ करने के लिए मैंने कहा। कोई भी ऑफिसर आता है तो उसको सुनते हैं और विचार करने के लिए अपना दिमाग खुला रखते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक कुन्दनलाल के केस को लेकर यहां जिक्र किया गया मैं इसके बारे में निवेदन कर दूं कि इस केस में कन्सल्टेशन बहुत लम्बा किया है। गवर्नमेंट एडवोकेट से राय ली गई है, फाइनेन्स डिपार्टमेंट से राय ली गई है और लॉ डिपार्टमेंट से भी राय ली गई है। इस केस में दोनों पार्टीज ने अपील कर रखी है। गवर्नमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग थी और गवर्नमेंट ने भी कर रखी है। उसी बीच में पार्टी ने कहा कि हमारे इस मामले में गवर्नमेंट जो भी फैसला कर दे वह हमको मंजूर होगा अगर कोई कानूनी तरीके से फैसला कर दिया जाय तो मैं केस विड्ड्रॉ कर लूंगा। इसमें कोई प्रेस करने की बात नहीं है। तो उसके बाद में इसको एग्जामिन किया गया। इसमें पोइन्ट यह है कि जब से हमारे देश में कॉन्स्टीट्यूशन लागू हो गया है तब से मोनोपोली खत्म हो गई है। उसके बाद में भी जो रकम वसूल कर ली गई थी उसका क्लेम था। जब भारत का संविधान लागू हो गया तो फिर मोनोपोली नहीं रही; तो पैसा कैसे ले सकता है। यह भी पोइन्ट है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्ट था, जोधपुर स्टेट के टाइम में इनको मोनोपोली दी थी। इसलिए पिछली बार एडवोकेट जनरल और फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने और लॉ डिपार्टमेंट ने यह ओपीनियन दी कि जो रकम जमा करा दी है, उसको गवर्नमेंट एन्टाइटल्ड नहीं है लेने के लिए। इसके बारे में भैरोंसिहजी इसको ज्यादा बारीकी से एग्जामिन कराना चाहें तो करा सकते हैं। यदि आप इन्ट्रेस्टेड हों तो किसी भी एडवोकेट

श्री मथुरादास माथुर)
सामने, सतीशचन्द्रजी के सामने सारी बातें ...दी जा सकती हैं और वे इसको देख लें।

श्री भैरोंसिंह : मुझे तो एक बात ही ...ता दें। उससे मुझे संतोष हो जायगा। जब ...वर्नमेंट का लेकेज था तो गवर्नमेंट ने अपनी ...रफ से अपील क्यों की ? जब सेशन्स कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दिया तो और जब ...पील के ऊपर अपील की तो फिर यह राय ...ने दे दी कि आउट ऑफ कोर्ट इसे डिसाइड ...या जाय।

श्री मथुरादास माथुर : उसने अपील ... तो काउन्टर अपील गवर्नमेंट ने भी कर दी; ... हम कई बार करते हैं। तो दोनों अपील ...जूद थीं।

श्री भैरोंसिंह : हम तो जीते हुए थे ...र उसने सेशन्स कोर्ट के डिसीजन के ...लाफ अपील की थी, तो Let the court ...ide.

श्री मथुरादास माथुर : उसमें कई ...ज थे।

श्री भैरोंसिंह : जब सेशन्स कोर्ट में जीत ... और एडवोकेट जनरल ने जीता हुआ ...कर अपील पर अपील कर दी। तो आप जीते हुए थे तो आपने यह डिसाइड कर लिया कि हम बाद में हार जायेंगे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : यह हमारी ...शियेन्सी और एमर्जेन्सी की वजह से हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन ...ना चाहता हूं कि इस केस में पोइन्ट यह ...monopoly fee charged after the ...ulgation of the Constitution भारत के संविधान के बनने के बाद में जो फीस वसूल कर ली थीं उसको लेना चाहते थे।

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज करता हूं कि सेशन्स कोर्ट की आपने इन्सल्ट की है। जिस सेशन्स कोर्ट ने गवर्नमेन्ट के फेवर में जजमेंट दिया, उसको आपने नहीं माना और दूसरे...

श्री मथुरादास माथुर : इसमें इन्सल्ट कोई नहीं है। सेशन्स कोर्ट डिसीजन किसी के पक्ष में नहीं दे और फिर ऊपर चले जायं तो कुछ भी हो सकता है। इसमें यह था monopoly rights exist after the promulgation of the constitution, यह पोइन्ट था इसके ऊपर मैं कहने को तैयार हूं कि एडवोकेट जनरल को कन्सल्ट करने के बाद, फाइनेन्स डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट को कन्सल्ट करने के बाद किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : एडवोकेट जनरल को कन्सल्ट नहीं किया है।

श्री मथुरादास माथुर : और आप कहें तो इसे अकाउन्टेन्ट जनरल की सलाह के लिए भेज दूं।

श्री भैरोंसिंह : आप कहते हैं कि एडवोकेट जनरल को कन्सल्ट किया है, यह सही नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं अर्ज करता हूं कि गवर्नमेंट एडवोकेट को किया होगा। मुझे याद है, लॉ डिपार्टमेंट से और फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से कन्सल्टेशन हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लॉ डिपार्टमेंट तो आपको ऐसी राय देता है जैसी एक केस में दो राय दे दीं और बाद में उसको कुम्भाराम जी ने सस्पेन्ड किया।

श्री मथुरादास माथुर : देखिये ऐसा नहीं है कि कोई अपील की हो तो गवर्नमेंट को री-कन्सीडरेशन करना ही नहीं चाहिए। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि कोई मेरिट पर जस्टिस क्लेम करता है तो उसको हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। यह गवर्नमेंट की पॉलिसी है और हमने ओपिनियन लेकर फैसला किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में जो खास खास मुद्दे उठाये गये थे माननीय सदस्यों के द्वारा, उनके बारे में मैंने कह दिया है। एक और हमारे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में परमिट ज्यादा हैं और माइलेज कम मिलता है लोगों को। मैं मानता हूं, हमारे यहां से जो डाइरेक्शन इश्यू हुए थे मोटर विहिकल्स एक्ट के मातहत एस० टी० ए० को, उसमें यह है कि ४० माइल्स एक विहिकल को मिल जाना चाहिए। इस तरीके के डाइरेक्शन्स इश्यू हुए थे। हम अब मानते हैं कि ४० मील कम हैं, क्योंकि रोडवेज ही १२० मील करती है तो किसी विहिकल को ४० मील देने के कोई मायने नहीं और कोई कमा कर खा नहीं सकता। इसके अलावा अब टैक्सेज बढ गये हैं और डीजल के भाव भी बढ़ गये हैं, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के भाव भी बढ़ गये हैं ऐसी स्थिति में सौ मील नहीं मिलते हैं तब तक विहिकल का मेन्टिनेन्स नहीं कर सकता। इसके बारे में विचार करके जो आर० टी० ए० को कार्यवाही करनी चाहिए वह करेगी और जो अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमिट होता है वह नहीं होगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

इसके साथ ही जो फीयेट कार्स एलॉट की गई हैं उसकी सूची भी मैं सदन की मेज पर रख देना चाहता हूं, ताकि जो माननीय सदस्यों को गलतफहमी है कि कान्ता खतूरिया को फीयट कार दी है वह दूर हो जाय। उनको स्टेट कोटा से फीयट कार नहीं दी गई है।

श्री भैरोंसिंह : कौनसे कोटा से ?

श्री मथुरादास माथुर : स्टेट कोटा से जो गवर्नमेन्ट एलॉट करती है, उसमें से नहीं दी गई है और जिनको एलॉट की गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख देता हूं।

श्री भैरोंसिंह : फीयेट गाडी कान्ता खतूरिया को एलॉट नहीं हुई है ?

श्री मथुरादास माथुर : स्टेट कोटा से नहीं हुई है ?

श्री भैरोंसिंह : कोई कोटा से नहीं हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : स्टेट कोटा जो है उसमें दस गाड़ियां हम फीयेट एलॉट करते हैं, दस स्टेन्डर्ड करते हैं और एम्बेसेडर करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : स्टेन्डर्ड गाडी भी नहीं हुई है ?

श्री मथुरादास माथुर : फीयेट एलॉट नहीं हुई है। स्टेन्डर्ड तो हमारे पास पड़ी रहती हैं लेकिन उनको उठाने वाला नहीं है। स्टेट कोटा में इसकी मांग नहीं है। यह हो गया होगा कि पांच छः महीने में पच्चीस तीस गाड़ियां आई होंगी तो दो गाड़ी उठाई गई होंगी। बिजनैसमैन मांगते हैं तो फियट गाडी जो कोटा में से मिलने वाली नहीं है, स्टेन्डर्ड गाड़ी मांगते हैं तो जैसा मैंने कहा कि यह तमाम लेप्स होती हैं और यह हमारे काम में नहीं आती है तो स्टेन्डर्ड गाड़ी तो किसी को दे देते हैं। उसमें डिफिकल्टी नहीं है। केवल फियेट का और

(श्री मथुरादास माथुर)
एम्बेसेडर का झगड़ा है। अब स्टेट कोटा में से भी प्रायोरिटी के हिसाब से देते हैं और जो दी हैं वह प्रायोरिटी के हिसाब से दी हैं। उसमें कोई फेवरेटिज्म का सवाल नहीं है। मैंने सूची रख दी है और आप उनको देख लीजिये। अगर कोई ऐसी बात हो तो आप पिन डाउन कर लीजिये और फिर बताइये इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा।

श्री भैरोंसिह : वह तो रख दीजिये। एक बात और बताइये कि कार कंट्रोल के मातहत यह स्थिति है कि कोई आदमी एक कार खरीद लेता है तो जब तक दो वर्ष पूरे नहीं होंगे तब तक कोई दूसरी कार उसको एलॉट नहीं की जायेगी। आपने स्टेन्डर्ड कार श्रीमती कान्ता खतूरिया को एलॉट करने से पहले जांच की थी कि इनको फियेट कार मिली हुई है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमने किसी को नहीं दी। वास्तव में स्थिति यह है कि पहले उन्होंने सन् ६१ में जब लाइन में खड़े होकर नाम लिखाते और रुपये जमा कराते थे कराये और रूटीन में उनको गाड़ी मिल गई। उसके लिखने के बाद में उस गाड़ी को उन्होंने कुछ समय तक चलाया और बाद में कहा कि इसका एंजिन खराब हो गया है और इसके एंजिन में कुछ डिफेक्ट है उस कारण से उसको सैल कर दी। कंट्रोलर ने भी इस बात को माना कि एंजिन खराब है और उसको बेचने की इजाजत दे दी और उसके बाद में फिर उन्होंने यह कहा कि चूंकि हमारे गाड़ी बिक चुकी है इसलिये स्टेट कोटा से......

श्री भैरोंसिह : उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि गाडी के एक्सीडेन्ट हो गया है। मगर वह एक्सीडेन्ट कहां पर हुआ यह नहीं बताया। कहीं भी अगर एक्सीडेंट हुआ हो तो उस एक्सीडेन्ट की रिपोर्ट तो दर्ज होनी चाहिये थी। मगर कहीं पर भी वह रिपोर्ट दर्ज नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पास तो डीलर की रिपोर्ट है कि गाडी में डिफेक्ट है एक्सीडेन्ट की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। हम तो स्टेट कोटा में से एम० एल० एज०, गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट और जरनलिस्टों को देते हैं, उसमें से किसी पार्टी वर्कर को भी नहीं देते। इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

श्री भैरोंसिह : स्टेन्डर्ड तो कोई भी ले सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : स्टेन्डर्ड तो कोई भी ले सकता है, क्योंकि उनकी डिमान्ड नहीं है। यों ही लेप्स होती है। तो कोई भी स्टेन्डर्ड ले सकता है। मैंने एक गाड़ी झुंझुनूं वालों को दी है। मेरे पास और भी गाड़ियां पड़ी हैं उनको कोई भी लेने आवे मैं देने को तैयार हूं। लेकिन जहां तक एम्बेसेडर और फिएट का प्रश्न है हम स्टेन्डर्ड की तरह से उनको नहीं दे सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिहजी तो लेना नहीं चाहते ?

श्री मथुरादास माथुर : भैरोंसिह जी तो स्कूटर पर ही ठीक रहते हैं।

(सूची सदन की मेज पर रखी गई-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

मेरा ख्याल है कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने कटमोशन्स रखे उनका जवाब मैंने शॉर्ट टाइप में जो कुछ मेरे पास फेक्ट्स और फिगर्स थे उनके आधार पर दिया और उसके साथ साथ ट्रान्सपोर्ट विभाग ने जो तरक्की की

(श्री मथुरादास माथुर)
हूं उसको देखते हुए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मांग को सर्व सम्मति से पास किया जावे ।

श्री दामोदरलाल व्यास (स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्षजी, मैडिकल डिपार्टमेन्ट पर माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये कट मोशन्स के द्वारा, मैं उनका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने कुछ रचनात्मक सुझाव दिये हैं और कुछ अपने अपने क्षेत्रों की कमियां बताई हैं कि उनके यहां पर होस्पिटलों में और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स में डाक्टरों की कमी है, लेडी डॉक्टरों की कमी है। इस प्रकार उन्होंने अपने अपने यहां की डिफिकल्टीज़ कट मोशन के द्वारा बताई। मैं इस समय अलग अलग हर माननीय सदस्य की जो आवश्यकता है, किस अमुक प्राइमरी हैल्थ सेंटर में या डिस्पेंसरी या होस्पिटल में डॉक्टर की कमी है, उसके लिये कोई डेफिनिट कमिटमेंट नहीं कर सकता। इस बात को माननीय सदस्य स्वयं महसूस करेंगे, परन्तु मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि इस पर पूरी तरह से विचार किया जाना चाहिये और पूरा ध्यान देने के बाद में वहां पर उनकी कमी को पूर्ति करने की कोशिश की जावे ।

कुछ मुद्दों पर बहस हुई है, इसलिये मैं आप महानुभावों से कुछ बातें अर्ज करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं उन मुद्दों को लूं या कुछ मुद्दे जो माननीय सदस्यों ने डिपार्टमेंट के लिये रखे हैं, मैं यह बताना ठीक समझता हूं कि मैडिकल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमेशा एक्सपेंड होता है और तीसरी पंच वर्षीय योजना तक इसमें काफी तरक्की हुई है। दो ही हमारे यहां ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो एक्सपेन्ड होते हैं। एक तो एजूकेशन और दूसरा मैडिकल एन्ड हैल्थ ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप इसका परसेन्टेज ऑल इन्डिया बेसिस पर बतावें कि क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं ऑल इन्डिया बेसिस पर बताता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि मैडिकल डिपार्टमेंट में दूसरी पंच वर्षीय योजना में ७५ डॉक्टर पर-मिलियन पोपुलेशन पर और तीसरी में ७० डाक्टर हो गये पर-मिलियन पोपुलेशन पर । यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में डिपार्टमेंट की तरक्की नहीं हुई ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ।

अभी अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो मैडिकल फैसिलिटीज़ राजस्थान में दी जाती हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मैडिकल सुविधाएं राजस्थान में दी जाती हैं वे बमुकाबले और जगहों के बहुत ज्यादा हैं और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे माननीय सदस्य जो बाहर जाकर आये हैं, यदि यहां पर जो मैडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका मुकाबला करें तो उनको मालूम होगा कि जो मैडिकल फैसिलिटीज़ राजस्थान में दी जाती हैं उसके मुकाबले में दूसरी जगह पर बहुत कम हैं । यहां पर आपको फ्री ऑपरेशन, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिसन्स मिलती हैं । आप यह सब फैसिलिटीज़

(श्री दामोदरलाल व्यास)
किसी और जगह नहीं बता सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की फैसिलिटीज दुनिया में कहीं नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : इसका फायदा पैसे वाले उठाते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके माने यह है कि गरीबों के ऑपरेशन नहीं होते और उनको मेडिकल फैसीलिटीज नहीं मिलती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाई मानसिंह अस्पताल में आपने तीन क्वार्टर्स १, २, ३ क्यों खाली छोड़ रखे हैं ? गरीबों के लिये क्यों नहीं देते ? गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के लिये, एम. एल. एज. के लिये रखे हैं। क्या जरूरत है इनकी ? वे क्यों खाली पड़े रहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इसके लिये अलग कहें मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह एक सोचने का तरीका हो गया है। यह मैं नहीं कहता हूं, यह आपके कांग्रेस के सदस्य हैं वे बताते हैं, जो मिनिस्टर होने के लायक हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : दवाइयां मिलती हैं और ऑपरेशन्स होते हैं। क्या वे पैसे वाले के ही होते हैं गरीबों के नहीं होते ? सबके होते हैं। इसलिये अगर यह कहा जाता है कि पैसे वालों को ही दवाइयां मिलती हैं और उन्हीं के ऑपरेशन्स होते हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसी बात कहते हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि जिस प्रकार की मैडिकल फैसिलिटीज यहां पर दी जाती हैं दूसरे किसी भी देश में आपको ऐसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आप देख कर उनका मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप मुकाबला करेंगे दूसरे देशों से तो आपको मालूम होगा कि और जगह जितनी मैडिकल फेसिलिटीज यहां पर हैं किसी दूसरी जगह पर नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप ऑल इन्डिया लेवल पर बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं वही बता रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केवल ७० डॉक्टर्स हैं एक मिलियन पोपुलेशन पर।

श्री दामोदरलाल व्यास : डॉक्टरों की कमी है, इस बात को तो मैं खुद स्वीकार करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यह समझते हैं कि जब डॉक्टरों की कमी है तो वहां पर जहां डाक्टर नहीं हैं मरीजों का इलाज ठीक तरह से होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां डॉक्टर नहीं हैं उनको छोड़िये। मगर जहां पर डाक्टर हैं वहां पर जो फेसिलिटीज हैं वे आपको दुनिया में किसी देश में नहीं मिलेंगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २२५ पंचायत समितियां हैं। ७२ सेन्टर्स में डॉक्टर नहीं हैं, १८८ पंचायत समितियों में डॉक्टर नहीं हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : डॉक्टर नहीं हैं, मैं भी जानता हूं। इस बात को मैं खुद

Page No. 140

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मंजूर करता हूं। मैं यह कहता हूं कि जितने होस्पिटल्स हैं और डिस्पेन्सरीज हैं, प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स हैं इस स्टेट में और जिस प्रकार की मैडिकल ऑपरेशन और मैडिकल की सहूलियतें हमारे यहां राजस्थान में मिलती हैं, Leave aside the doctors जिनमें डॉक्टर नहीं, मगर जिनमें डॉक्टर हैं उनमें जो फैसिलिटीज मिलती हैं वे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में बता दें।

श्री भैरोंसिंह : प्रति व्यक्ति पर दवाइयों का कितना खर्च होता है, यह बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह भी आपको ज्यादा ही मिलेगा।

अब मैं आपको यह अर्ज करना चाहता था कि यह बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहां डॉक्टरों की कमी है, पर यह बात नहीं है कि डॉक्टरों की यह कमी केवल राजस्थान में ही है; सारे देश में डॉक्टरों की कमी है। हां, देश में जो डॉक्टरों की कमी है हमारे यहां उस अनुपात से कुछ ज्यादा कमी है। डॉक्टरों की कमी, टैक्निकल स्टाफ, नर्सेज, कम्पाउन्डर्स वगैरह की कमी है। मैं सदन को बताऊंगा कि हमारे यहां कितनी कमी है और उस कमी को दूर करने के लिये कितने प्रयत्न हम कर रहे हैं।

अभी हमारे यहां डॉक्टरों की एग्जिस्टिंग सेन्क्शन्ड स्ट्रेंथ है १,३१६ की, उसके मुकाबले में ९५७ डॉक्टर्स हैं, ३५९ की कमी है।

इसी तरह कम्पाउन्डर्स, नर्सेज सभी को देखेंगे तो हमारे पास जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन हमने उस कमी की पूर्ति करने के लिये काफी प्रयत्न किये हैं और कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को मालूम है, जहां तक कि मैडिकल कॉलेजेज का सवाल है, जहां पहले एक सवाई मानसिंह मैडिकल कॉलेज था, उसके मुकाबले आज हम ५ मैडिकल कॉलेजेज रन कर रहे हैं।

(राज्य-पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संख्या २५ बढ़ी है, दो मैडिकल कॉलेजेज खोलने के बावजूद संख्या २५ बढ़ी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह गलत है, आपको जो खबरें मिलती हैं वे गलत हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हन्ड्रेड परसेन्ट सही है। आप बताइये कि कितनी संख्या बढ़नी चाहिये थी और कितनी बढ़ी है?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी बताऊंगा।

मैंने जैसा कि अर्ज किया, आज हम ५ मैडिकल कॉलेजेज रन कर रहे हैं। इसी तरह लेडी हैल्थ विजिटर्स, सर्वेलेन्स इन्स्पेक्टर्स, नर्सेज, कम्पाउन्डर्स और टैक्निशियन्स को ट्रेनिंग देने के लिये हमारे यहां अलग अलग इन्स्टीट्यूशन्स हैं, मैं इसमें सदन का समय नहीं लूंगा यह बताने में कि इन्स्टीट्यूशन्स कहां कहां हैं। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि राजस्थान में कई जगह ट्रेन्ड पर्सोनल्स को तैयार करने के लिये हमारे पास इन्स्टीट्यूशन्स हैं जहां हर साल ट्रेनिंग दिलाते हैं।

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि दो मैडिकल कॉलेज बढ़ाने से २५ संख्या बढ़ी है। मैं अर्ज करूंगा कि संख्या २५ बढ़ने की जो बात कही है वह सही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५० हो सकती हैं, ६४-६५ का बतावें। कितनी संख्या बढ़ी, जयपुर में कितनी घटी, यह मेरे पास तैयार हैं।

श्री भवलाल (हिन्डौन-सु.) : केवल ताली बजाने से काम नहीं चलता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो मेडिकल कॉलेज बढ़ाने पर भी २५ संख्या बढ़ी, यह अखबार मौजूद है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिये १९६४-६५ के फीगर्स रखूं, एस. एम. एस. मेडिकल कॉलेज में पचास-पचास स्टूडेन्ट्स अजमेर और जोधपुर के लिये, बीकानेर और जोधपुर कॉलेज में ज्यादा लड़के लिये गये थे........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे क्या मतलब ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह इन्फोर्मेशन इसलिये दे रहा हूं कि लड़के कितने बढ़े। लड़के बढ़ाने का ऑर्डर लास्ट ईयर इसलिये था कि ५०-५० लड़के जोधपुर और अजमेर के अगेन्स्ट में लें। २०० लडके लिये गये; ५० अजमेर के, १५० यहां के १८५ का एडमिशन हुआ। बीकानेर में १५० लिये, १५० रहे। उदयपुर में १५० लिये गये। ७५ और ७५ जोधपुर और अजमेर मेडिकल कॉलेजेज के लिये बढ़ गये। टोटल ५५० लास्ट ईयर में ६३५। पचास-पचास लड़के बढ़ाये गये थे, इसलिये एडमिशन ज्यादा दिया गया था। मेडिकल कौन्सिल ५५० से ज्यादा एडमिशन करने की परमिशन देती नहीं है, क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल्स में उन्हें ट्रेन्ड करना मुश्किल होता है, ज्यादा के एडमिशन के फेवर में नहीं है। पर हमारे शोर्टेज को देखते हुए हमने एडमिशन दिया है ६३५ को।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दो कॉलेजेज खोलने के बाद ८५ लड़के बढ़े ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : तो क्या जादू हो जायगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य, आप गलत मत समझिये, अजमेर में मेडिकल कॉलेज खुला है; हमें खुशी है; सवाल इस बात का है कि दो कॉलेजेज खुलें, दो कॉलेजेज पर इतना बड़ा खर्चा करने के बाद में भी ८५ लड़के बढ़ें। क्या यह संतोष की बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : राजाओं के टाइम में नहीं बढ़े....

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दो कॉलेज खोलन के बाद ८५ लड़के बढ़े। मैं अर्ज करना चाहाता हूं कि मेडिकल कौन्सिल ने जो सेन्क्शन कर रखी है उससे ज्यादा पिछले साल भी लिये थे और ज्यादा इसलिये लिये थे कि दो कॉलेजेज ने पहले एडमिशन कर लिये थे। अब भी जयपुर कॉलेज के लिये बताया कि १५० से १८५ कर रखे हैं। १५० की संख्या बढ़ा नहीं सकते थे, इस बात को समझने की कोशिश कीजिये।

इस तरह से मेडिकल कॉलेजेज.. ..

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : एक क्लेरिफिकेशन देदीजिये। जितने लड़के हमारे मैडिकल कॉलेजेज में पढ़ कर निकलते हैं वे सब लडके हमारे यहां सर्विसेज में आये या बाहर चले गये। कितने लड़के हमारे यहाँ सर्विसेज़ में रहे और कितने लड़के बाहर चले गये, यह बता दीजिये; यह है असली बात तो।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया, मैं खुद कहने ही जा रहा था। आम तौर से लड़के पढ़ कर तैयार होते हैं, जिन पर हम खर्चा करते हैं तो हम उम्मीद करते है कि वे हमारे यहां सर्विस करें, हम उनसे बोन्ड भी लिखाते हैं कि पढ़ कर वे हमारे यहां सर्विस में आयेंगे। पिछले वर्षों में जितने लड़के हमारे यहां से पढ़ कर तैयार होकर निकले, मैं मानता हूं कि बहुत कम हमारे यहां सर्विस में आते हैं हमारी सर्विस में नहीं आते हैं। इसके कई कारण हो सकते है, कुछ कारण तो हमारे यहां की मेलेरीज है, वे दूसरी जगहों से कुछ कम हैं, दूसरी जगहों पर ज्यादा टेम्प्टेशन्स मिल जाते हैं, इसलिये ज्यादा बाहर चले जाते हैं। तो हमने निश्चय किया है कि जो बोन्ड लिखाया है, उसका स्ट्रिक्टली पालन कराया जाय और हम लोग उनको मजबूर करेंगे कि हमारी सर्विसेज़ में आयें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज तक बोन्ड्स का स्ट्रिक्टली पालन क्यों नहीं किया गया? राजस्थान की गरीब जनता द्वारा दिये गये टैक्स के पैसों को उनकी एज्युकेशन पर खर्च किया गया है। राजस्थान में सर्विस करने के लिये, राजस्थान की गरीब जनता को फायदा पहुंचाने के लिये, राजस्थान की गरीब जनता से लिया गया पैसा खर्च करते हैं तो आज तक जो लोग चले गये उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की; जो कार्यवाही करनी चाहिये थी वह क्यों नहीं की?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कह दिया कि इस साल जो बोन्ड लिखाये हैं, बिल्कुल लीगली वेलिड करके लिखाये है, पिछले सालों के बोन्ड्स में डिफेक्ट रह गया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसकी गलती से डिफेक्ट रह गया? जिसकी गलती से डिफेक्ट रह गया, उसके खिलाफ क्यों नहीं सख्त एक्शन लिया गया ?

श्री दामोदर लाल व्यास : यह एन्क्वायरी का विषय है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : इस सिलसिले में मैं एक बात रखना चाहता हूं....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अपनी बात पूरी करलूं, उसमें आपकी वह बात आजाय और आपको वह बात उठानी ही न पडे। पहले मुझे सुन लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को यूनिवर्सिटी डिग्री उसी वक्त दे जब कि वे हमारे यहां प्रेस्क्राइब्ड सर्विस पूरी करलें, इससे पहले यूनिवर्सिटी उनकी डिग्री नहीं दे, हम यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बड़ा मुश्किल है।

श्री दामोदरलाल व्यास : तो हम हर मुमकिन तरीके को काम में लेना चाहते हैं, कि जो लड़के हमारे यहां पास होजायं वे

(श्री दामोदरलाल व्यास)
तीन साल या पांच साल हमारे यहां सर्विस करने के बाद ही जा सकें।

हम इनके पे स्केल्स भी रिवाइज़ करना चाहते हैं, जिससे कि टेम्प्टेशन्स में आकर बाहर नहीं जायें।

श्री भैरोंसिंह : इस कोशिश में आप कब तक सफल हो जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सफल होंगे, वह तो आपके सामने आ जायगा जब सफल होंगे।

अब जहां तक मैडिकल डिपार्टमेन्ट का सवाल है, मनें शुरू में कहा था कि यह बराबर एक्सपेन्ड होता जा रहा है।

देखने की आवश्यकता है कि इन पिछले दस वर्षों के अन्दर जिस तरह से सुविधाओं का प्रसार हुआ है, वह मैं आपको पढकर बताता हूं।

	१६५६	१६६६
१. क्लास १ अस्पताल	५	७
२. क्लास २ अस्पताल	४	८
३. क्लास ३ अस्पताल	४	५
४. अदर हॉस्पिटल्स	२४८	२६१
५. प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स	१३	२२६
६. मैटॉनिटी और चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर्स	४५	७२
७. फैमिली प्लानिंग सेन्टर्स		२८७

अब आप देखिये, कितना विस्तार हुआ है। प्रिवेन्टिव साइड में, चाहे क्यूरेटिव साइड में, देखें इस विभाग की एक्टिविटीज़ बराबर बढ़ती जा रही हैं। चाहे नेशनल इरेडीकेशन प्रोग्राम्स, चाहे मलेरिया, चाहे स्मॉल पॉक्स, बी. सी. जी., ट्रिकोमा ये सब एक्टिविटीज़ काफी सफल हुई हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने मलेरिया के सम्बन्ध में कहा कि क्या मलेरिया इरेडिकेट हो गया, मलेरिया वास्तव में इरेडिकेट हो गया और आपको क्योंकि मच्छर मिलते हैं, तो आप समझते हैं कि मलेरिया है। हर मच्छर मलेरिया पैदा करने वाला नहीं होता है। जो मच्छर मलेरिया पैदा करने वाले होते हैं उनको काफी सफलता के साथ साथ खत्म कर दिया गया है और राजस्थान में मलेरिया का इन्सीडेन्स २८ है। यह बड़ी सफलता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक कटु सत्य कह रहा हूं। मलेरिया हो जाती है तो डॉक्टर्स उस बीमारी को मलेरिया प्रेस्क्राइब नहीं करते। दवाई मलेरिया की देते हैं लेकिन लिखते मलेरिया नहीं जिससे कि आप कह सकें कि मलेरिया का इरेडिकेशन हो चुका है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं तो नहीं कह सकता।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आजकल ऐसे मच्छर पैदा हो रहे हैं कि उनसे बुखार तो नहीं आता, लेकिन पैर रगड़ने पड़ते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको अनुभव कुछ और हुआ होगा। डॉक्टरों की बात मुझे माननी पड़ेगी कि मलेरिया है या और कुछ है।

जहां तक फेमिली प्लानिंग का सवाल है, माननीय सदस्यों ने बहुत सी सलाहें दीं और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह नेशनल नेसेसिटी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और अर्जेन्सी है। इसमें जरूर कोशिश करनी चाहिये। पांच वर्ष के अन्दर इसम काफी प्रगति हमने की है, पर यह भी जरूर मानूंगा कि जो प्रगति होनी चाहिये थी वह लेडी डॉक्टर्स की वजह से हम उसके अन्दर कामयाब नहीं हो पाए। जो फिगर्स मेरे पास हैं वह आपके सामने पेश करता हूं :-

लूप्स इन्सरटेड अपटू ५-३-६६ – १२,१२०
स्टेरीलाइजेशन ऑपरेशन्स– १६,८४८

श्री भैरोंसिह : मन्त्रियों में एक आदमी ने भी स्टेरिलाइजेशन नहीं करवाया।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपकी गलतफहमी है, कई हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन हैं ?

श्री भैरोंसिह : यह भी एक धोखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आप देख लेना।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें सवाई मानसिंह अस्पताल के सम्बन्ध में बताई। इसमें सन्देह नहीं कि चाहे वह सवाई मानसिंह अस्पताल हो या और कोई मैं चाहता हूं कि जितना सुधार हो सके, एक दूसरे का सहयोग कर सकें, वह हमारे राजस्थान के हित में है, जनता के हित में है। यह सही है के डिमान्ड के डिस्कशन के समय कई बातें कही गई, तो मेरे लिए सम्भव नहीं है कि यहां कमिट करूं कि ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि आपका सहयोग मिले तो आपको इस बात में कमी नहीं नजर आएगी, तुरन्त एक्शन लेने में देरी नहीं होगी....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हमारा भी और उनका भी दोनों का सहयोग कहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जब आपके साथ में कहता हूं तो उसमें यह साइड भी आजाता है, दोनों तरफ। सवाई मानसिंह अस्पताल या और अस्पताल उसके लिए कोई न कोई एक तरीका होना चाहिये कि समय पर आप सुझाव दें और फिर उन सुझावों पर एक्शन न लिया जाय, तो आप कुछ कर सकते है, दोष लगा सकते हैं।

यहा डॉक्टरों की कमी की बात कही गई, दवाईयों की कमी के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा, यह शिकायत बहुत सही तो नहीं है कि दवाइयों की आम तौर पर कमी है। दवाइयों का जो स्टैन्डर्ड फिक्स किया गया है, उस लिहाज से सारे राजस्थान के अन्दर वह ऑल-इण्डिया स्टैन्डर्ड से किसी कदर कम नहीं है। यह स्टैन्डर्ड फिक्स किया गया है:

Class I Hospitals (above 300 beds)	Rs. 500/- per bed
Class II Hospitals (Having 150 to 300 beds)	Rs.500/- per bed
Class III Hospitals Having 100 to 150 beds	Rs. 300/- per bed
Class IV Hospitals	Rs. 250/- per bed

Having 50 to 100 beds — Rs. 250/- per bed

Class V Hospitals

Having 20 to 50 beds

Calss VI Hospitals- 150/- having daily out door attendance below 50.

Rs. 2500/- Having daily out door attendance from 50 to 99.

Rs. 4,000/- from 100 to199

Rs. 5,000/- " " 200 to 399

Rs. 8,000/- " " above 400.

Besides this where there is accommodation for indoor patients an extra grant of Rs. 50/- per bed.

Dispensaries- -do-

Aid posts Rs. 1,000/-

Primary Health Centres- Rs. 2,500/- having daily average attendance upto 100

Rs. 4, 000/- " " from 100 to 150

Rs. 5,000/- " above 150.

यह स्टेन्डर्ड ले डाउन कर रखा है जिसको आल-इंडिया स्टैंडर्ड से कम्पेयर करेंगे तो आपको यहां कम नहीं मिलेगा, बल्कि ज्यादा मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने चौथी योजना बनाई है उसमें आपने एस्टीमेट्स दी है, प्लान दिया है सारे का सारा उसमें स्वीकार कर चलें तो भी उस स्टेंडर्ड तक नहीं पहुंचा जा सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास : उस स्टेंडर्ड तक नहीं पहुंच पाए हैं इसलिये कि हमारे यहां टैक्नीकल पर्सोनेल्स की कमी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम दवाइयां भी दूसरों से कम देते हैं, बल्कि ज्यादा देते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जो जेलों के अन्दर कैदियों को डाइट देते हैं, ऐसी रोटी भी अस्पताल में नहीं मिलती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अस्पताल के अन्दर डाइट की कमी हो तो मैं सहयोग चाहूंगा, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा। बल्कि मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विभाग है जिसका आम जनता की सुरक्षा उसकी हैल्थ से संबंध है, इसमें जितना सुधार कर सकते हैं, मिल कर करना चाहिये, इसमें दो राय नहीं। मैं हमेशा इस बात को पसंद करूंगा कि जनता के लोग जो सुझाव दें, जैसा आपने डाइट के लिये कहा, या और कोई दिक्कत हो, जैसे आपने कहा कि सवाई मानसिंह अस्पताल में डाइट को देखा जाय तो कैदियों की डाइट से भी खराब है, तो अगर आपका ऐसा अनुभव है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस मामले में जो भी कुछ कर सकता हूं, एक्शन तुरंत लूंगा और आपसे जानकारी और हासिल करूंगा।

(६ म० प०)

अब कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात को लेकर.... ......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): विजिटर्स कमेटी होस्पिटल में बनायी है। एम. एल. ए. को उसमें रखें। रिश्तेदारों को रख दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : ठहरिये, मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने कहा कि विजिटर्स कौंसिल है। मैंने तो नाम ही आज सुना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : करम फूट गये!

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं खुद ही सोच रहा था कि कोई एक नोन-प्राफिशियल एजेन्सी हो होस्पिटल। इससे पहले मैंने इसके बारे में नहीं सुना था, मुझे बताया भी नहीं गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : है साहब। लास्ट ईयर ही गजट नोटिफिकेशन निकला है।

श्री भैरोंसिंह : डिजॉल्व नहीं हुई है, इसलिये मानते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: But they are defunct and I have not received as a Minister even a single report that they are functioning:

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फंक्शन करती नहीं है इसलिये। ऐसे आदमियों को आप रखते हो इसलिये फंक्शन नहीं करती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सुझाव दिया कि एम. एल. ए. को एसोसियेट करना चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है। मैं कन्सलटेटिव कमेटी बनाऊंगा, ताकि सारे राजस्थान के अस्पतालों की, डिस्पेन्सरियों की जो दुर्व्यवस्था की शिकायतें आती हैं वे दूर की जा सकें।

जयपुर से आने वाले और अन्य माननीय सदस्यों ने बातें रखीं। उन्होंने कहा कि टीचर स्टाफ में कुछ प्रोमोशन में पार्शियलिटी, पक्षपात, फेवरिटिज्म की बात की। हाई कोर्ट की रिट का भी जिक्र किया। सबको मालूम है कि हाई कोर्ट का फैसला हुआ है। ज्युडिशियल जजमेन्ट की रेस्पेक्ट करना यह हमारा कर्तव्य हो जाता है। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करने वाले हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप उसको इम्प्लीमेन्ट कर दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : हाई कोर्ट के फैसलों को इम्प्लीमेन्ट करना हमारा फर्ज है।

मैडिकल स्टोर्स की माननीय सदस्यों ने काफी चर्चा की। माननीय उपाध्यक्षजी, आप इस बात को जानते हैं कि मैडिकल स्टोर्स जिस बैक-ग्राउन्ड में खोले गये मैं उसमें नहीं जाना चाहता। माननीय सदस्य भी महसूस करते हैं कि इन सर्कमस्टान्सेज में ये कामयाब हों तो अच्छा है। मैडीकल स्टोर्स के खोलने के कारण सरकारी कर्मचारियों को दिक्कतें पैदा हुईं, दवाइयां मिलने में मुश्किलात हों; इनके खोलने से हमारी मंशा इतनी ही थी कि आसानी से दवा मिल जाय और कुछ लोगों की वजह से जो खराबी आ रही थी वह मिट जाय, बेजा नुकसान सरकार को उठाना पड़ता था वह भी मिट जाय। शुरू शुरू में इसके सम्बन्ध में दिक्कतें आयीं।

Page No. 147

(श्री दामोदरलाल व्यास)
रश ज्यादा हुआ। स्टोर्स पूरे नहीं खुल पाये। अब हमने जयपुर के लिये पांच स्टोर्स खोलने का निश्चय किया है। तीन इस समय खुले हुए हैं। चौथा पांच-चार दिन में खुल जायेगा और पांचवां १ अप्रेल तक खुल जायगा। मेरा ख्याल है कि इसके पश्चात् दिक्कत नहीं होगी।

वहां क्यू लगा रहता है, यह कहा गया। क्यू रहा है। मैं भी शुरू शुरू में गया था। लेकिन तीन स्टोर्स खोलने के बाद इतना रश नहीं रहेगा। सवाई मानसिंह अस्पताल वाला स्टोर और चांदपोल वाला स्टोर दोनों चौबीसों घंटों चलें, इसके लिये व्यवस्था की जा रही है। यह स्टोर्स हर वक्त चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से किसी ड्रगिस्ट और कैमिस्ट की दूकान पर भी चौबीसों घंटे खुले रहने की व्यवस्था नहीं होगी। कर्मचारियों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज और हमारे आफिसर्स एक दूसरे मिल कर, चीफ सेक्रेटरी ने भी उनसे मिलकर, यह इन्तजाम किया है। एक सवाई मानसिंह अस्पताल, दूसरा गांधीनगर, तीसरा जनाना अस्पताल के पास चांदपोल बाजार में है। चौथा नेहरू मार्केट में और पांचवां चांदी की टकसाल के पास खोल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रामकिशोरजी के पुराने मकान में।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां नहीं। रामकिशोरजी के मकान में दवा की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): राज्य के कर्मचारियों को सस्ती दवाई और जनता को महंगी दवाई, यह क्यों ? आम जनता को प्योरिटी की दवाई नहीं मिलती।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह सवाल आप नया उठा रहे हैं। दवा नहीं मिलती है तो शिकायत कीजिये। मैं एक्शन लूंगा। ड्रगिस्ट्स हैं ही इसीलिए। जब दवा मिलना मुश्किल हुआ तो माननीय सदस्य जानते हैं कि उसके लिये मैंने कोशिश की और दवाइयां बराबर मिलने लग गयी हैं।

श्री भैरोंसिंह : उनको जो दवा चाहिये उनको ही मिल सकती है, आप उनको दवा नहीं ला सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास : ये स्टोर्स सरकारी मुलाजिमान के लिये हैं और दूसरों के लिये नहीं हैं। पांच लाख की बात दोहराना चाहें तो दूसरी बात है।

You may interpret it. Those who are authorised for re-imbursement they will be entitled to get it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक सजेशन है। जिनको दवाइयां रिएम्बर्स होती हैं, जो लोग गड़बड़ करते थे, उन लोगों ने, जब आपने स्टोर्स खोल दिये तो आयुर्वेद से, वैद्यजी से पर्चियां बनाना शुरू कर दिया है। उनका वेरिफिकेशन हो गया। आप आंकड़े ले लीजिये, आपको उनकी जेबों में वैद्यजी की पर्चियां मिलेंगी। जो जिनाइन हैं और गड़बड़ी नहीं करते थे वे लोग तो स्टोर से दवाइयां ले रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके सुझाव के लिये धन्यवाद। आयुर्वेद के लिये भी खोल देंगे। सरकारी मुलाजिमान को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें मिलें, आसानी से मिलें दवाइयां, जितना प्रयत्न हो सकेगा, जितनी दिक्कतें मिटा सकेंगे मिटाने का प्रयत्न

(श्री दामोदरलाल व्यास)

किया जायगा। आपका सहयोग चाहिये। आप इस सिस्टम को कामयाब बनाने की कोशिश करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य कर्मचारी के लिये हर सुझाव को हम उठायेंगे क्योंकि हमको ६७ में राज्य मिलने वाला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : धन्यवाद ! आप तो बहुत दिनों से उम्मीद लगाये बैठे थे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : पैसे वाली बात उठायी, उस पर विचार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्वालाप्रसादजी मुश्किलात की बातें ही उठाया करते हैं। कहते हैं कि उधार दो और हिसाब रखो दवाइयों का।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट में हिसाब चला जायगा। पेमेन्ट एक डिपार्टमेन्ट से दूसरे डिपार्टमेन्ट को है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सुझाव देना आसान है। पूरे स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। कितने डिपार्टमेन्ट्स हैं। बहरहाल यह कामयाब हो जाय, यह मुश्किल काम है। एक मेडीकल स्टोर के लिये इतने डिपार्टमेन्ट्स के आदमियों के लिये बिल बनाना, हिसाब रखना आदि कार्य बड़े मुश्किलात के हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह गवर्नमेन्ट के फायदे में है। जिसके लिये डॉक्टर का सर्टिफिकेट आ जाय उसको दवाई फ्री दे दीजिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं आपकी डिफिकल्टीज को देखते हुए यह सुझाव देना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेन्ट को रिएम्बर्स का रुपया दे दिया जाय और रिएम्बर्समेन्ट होता रहे और डिपार्टमेन्टवाइज जाता रहे. आपको मुश्किलात का पता ही नहीं चलेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जो सुझाव दिया उसको मैं प्राइम-फेसी बहुत डिफिकल्ट मानता हूं। बड़ी मुश्किल है। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है जितना आप मानते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : जैसा बजट स्पीच में शेर आया है "अहले हिम्मत मंजिले मकसूद तक आ ही गये" कम से कम उस मकसूद तक पहुंचिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने बजट की इस शायरी को तो समझ लिया।

उपाध्यक्ष महोदय, और जो इन्डिवी-जुअल मसले उठाये गये हैं उन पर मैं अलग से विचार करूंगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने डिस्पेन्सरीज और हैल्थ सेन्टर्स में डॉक्टर्स नहीं, कुछ जगह बराबर रहते हैं, उसके बारे में अपना मत रखा। हम भी इस बात का फेज प्रोग्राम बना रहे हैं ताकि जब तक डाक्टरों की कमी पूरी नहीं होती है तब तक वाई रोटेशन डॉक्टरों को इधर-उधर करते रहेंगे।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि जहां डाक्टर नहीं है ऐसे प्राइमरी

Page No. 149

(श्री दामोदरलाल व्यास)

हैल्थ सेन्टर्स और डिस्पेन्सरीज को बन्द कर देना चाहिये। मैं यह मानता हूं इस प्रकार करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। पी० एन० आर० सी० के कोर्स में कम्पाउन्डर्स को चार साल की ट्रेनिंग होती है। हमारा यह अनुभव रहा है कि ये कम्पाउन्डर्स बहुत बड़ी बीमारियां तो नहीं, मामूली बीमारियों का इलाज करने के लिये क्षमता रखते हैं, इसलिये इस बात के लिये कि हमारे पास डाक्टरों की कमी है तो इनको बन्द कर दिया जाय, यह उचित नहीं होगा। हमारा तो यह अनुभव रहा है, फर्स्ट ग्रेड कम्पाउन्डर्स ही नहीं, सैकिन्ड ग्रेड कम्पाउन्डर्स से जनता को काफी अच्छी सेवा मिली है। इसलिये मैं समझता हूं, यह आपका सुझाव तो ठीक नहीं रहेगा।

मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो बातें कही थीं। मैं उनके बारे में उनसे विस्तार से बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि एक सरकारी अधिकारी का लड़का जिसके पैर में पोलियो हो गया था, दाहिने पैर में हो गया था, लेकिन उसके बायें पैर का ऑपरेशन कर दिया। मेरी जानकारी में यह बात नहीं आयी। Nobody has brought it to my notice and I don't know anything about it.

यह जो मामला है इसके बारे में पहले पहल आपसे सुना है। कौन डॉक्टर था, किसने इस प्रकार का ऑपरेशन किया, यह सब आपसे जानकारी लेकर आगे जो भी कार्य-वाही करनी होगी वह करूंगा।

दूसरा ऑपरेशन टेबल पर पैसे मांगने की जो बात कही, मैं करीब दस माह से इस विभाग का मंत्री हूं मैंने तो इस प्रकार की बात सुनी नहीं और न किसी ने आकर मुझे कहा भी है। मैं अर्ज करना चाहता हूं I am accessible to everybody. जो कोई पोस्टर्स होते हैं या पर्चे निकलते हैं उनके बारे में मैं नोटिस नहीं लेता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): ज्यादा अच्छा आपके लिये तो यह होगा कि आप अभी इन्कार न करें, कल 'हां' भर लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास: मेरी जहां तक याददाश्त है, ऐसा कोई केस मेरे पास नहीं आया। और मैं जहां तक समझता हूं डिपार्टमेन्ट के पास भी नहीं आया। फिर भी आप जब कहते हैं, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कहता। लेकिन इतना तो मैं अवश्य निवेदन करना चाहता हूं, मैं हर समय किसी भी व्यक्ति की जो कुछ भी शिकायत हो सुनने के लिये तैयार हूं। फिर भी अगर मुझे कोई बात मालूम नहीं है। I shall find it out.

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोई भी शिकायत हो, किसी को भी हो, आपस में सहयोग से रफा करने की कोशिश करूंगा किसी भी प्रकार से दबाने की कोशिश नहीं करूंगा।

श्री दयाचन्द सोनी (बारां-सु): बारां में पचास-साठ हजार की बिल्डिंग जच्चाखाने के लिये बनाकर दी है, उसका क्या कर रहे हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास: जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया, मैं किसी भी पर्टीक्युलर केस के बारे में कहना नहीं चाहता। आज

(श्री दामोदरलाल व्यास)
राजस्थान में कई स्थान ऐसे हैं जहां बिल्डिंग बनाकर दान करने वाले बहुत सारे लोग हैं। वे चाहते यही हैं कि हम बिल्डिंग बना कर दे सकते हैं, बशर्ते कि उस पर उनका नाम लिख दिया जाय। बिल्डिंग उस हालत में ले सकते हैं जब कि उसके लिये वेज एण्ड मीन्स हमारे पास हों, हमारे बजट में प्रोवीजन हो। प्लान का सीलिंग देखकर ही हमें मन्जूरी देनी पड़ती है। चूरू, बीकानेर, झुन्झुनू, सीकर जिले ऐसे हैं जहां न मालूम पैसे का पहाड़ टूट गया है, लाखों रुपयों की बिल्डिंग वे देने के लिये तैयार हैं। सोर्स ऑफ इन्कम का पता नहीं; बहरहाल जो दिक्कत है हमारे वेज एण्ड मीन्स सीमित हैं, इसलिये हम इच्छा होते हुए भी नहीं कर सकते।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। बहुत सी पंचायतों में रहने वाले मकान बना लेते हैं औषधालय खुलवाने के लिये, स्कूल बनाने के लिये, डिस्पेन्सरीज के लिये लेकिन जब हमारे पास आते हैं उसमें साधन प्रोवाइड कराने के लिये, तो हमारे पास बजट में प्रोवीजन नहीं होता। जब प्रोवीजन नहीं तो केवल डिस्पेन्सरी का भवन बना कर देना, केवल नॉन रेकरिंग एक्सपेन्सेज करने से काम नहीं चलता। रेकरिंग एक्सपेन्डीचर तो स्टेट गवर्नमेन्ट को करना पड़ता है, इसकी मंजूरी के बगैर जो भवन इत्यादि बना लेते हैं तो उनका उपयोग नहीं हो पाता।

मैंने किसी भी इन्डिविजुअल केस को नहीं लिया, इन्डिविजुअल केस पर अलग से विचार करूंगा। जनरल कॉमन बातें थी, उनको मैंने अपने भाषण में कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा एक सुझाव है, सिविल असिस्टेन्ट सर्जन्स आपके यहां सैकड़ों की संख्या में हैं, उनको कोई प्रमोशन नहीं। जूनीयर और सीनियर स्पेश्यलिस्ट के लिये आपने कन्डीशन प्रेस्क्राइब कर रखी हैं। पोस्ट-ग्रेजुएट को ही चान्स मिल सकता है। लेकिन सिविल सर्जन्स जो बीस-तीस साल से काम कर रहे हैं, आज उनके लिये संभव नहीं कि वे पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें। बीस-पच्चीस साल के एक्सपीरियन्स को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार टीचर्स के मामले में आपने किया है और इन्टीग्रेटेड स्टेट्स के नॉन मेट्रिकुलेट लोग रेवेन्यू बोर्ड में लिये गये हैं वैसी हालत में इनके लिये कन्सीडरेशन किया जा सकता है।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि टीचिंग स्टाफ के लिये आपके यहां रूल्स बने हुए हैं, अलग सर्विस कन्डीशन की हैं। इस सर्विस में जो अलग क्लीनिकल स्टाफ में काम करते हैं यहां पर लोगों को प्रमोशन मिले, वहां पार्ट-टाइम उनसे काम लेते हैं, इस तरह से क्लीनिकल साइड में ज्यादा एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से एज्यूकेशन सर्विस सेपरेट हुई है, तब से वे अलग माने गये हैं; आप किनको मौका देना चाहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टीचिंग सर्विस अलग हुई है मेडिकल कॉलेजेज की; उस सर्विस में रीडर्स प्रोफेसर्स वे सारे के सारे वहां कॉलेजेज में काम करें। और जहां आपको जरूरत है वहां पार्ट टाइम आते रहते हैं, वे

Page No. 151

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
केवल स्पेशियेलिस्ट के तौर पर बने हुए हैं। उनके लिये मेरा निवेदन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जब से मेडिकल सर्विस कॉन्स्टीट्यूट हुई है वे जो उसमें हैं वे तो उसी में रहेंगे, बहरहाल उनका सीनियर-जूनियर, स्पेशियेलिस्ट के तौर पर प्रमोशन नहीं होगा, वह केडर अलग रहेगा। दूसरे जो क्लीनिकल साइड में हैं वे उसी में रहेंगे।

जहां तक पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स का सवाल है जो सिविल असिस्टेन्ट सर्जन्स हैं वे सी० ए० एम० क्लास वन में होते हैं उनका रनिंग ग्रेड है। इसके अलावा आपके कहने के मुताबिक उनको आगे जूनियर और सीनियर स्पेशियेलिस्ट का चान्स नहीं मिल सकता। उसके लिये पोस्ट ग्रेजुएट की क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। इसके बारे में सोचने का विषय है; उसके बारे में मैं ऑफ हैन्ड कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल आपके कहने के मुताबिक करने में मुश्किलात होंगी। आज जयपुर का मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज चलाता है। कल बीकानेर और जोधपुर में भी ये चालू होंगी। तो इन सब कॉलेजों से जो पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकलेंगे उनका भी तो ख्याल करना पड़ेगा। उनको जूनियर और सीनियर स्पेशलिस्ट के तौर पर प्रॉयोरिटी देनी पड़ेगी। आपने जो सुझाव दिया है उस पर विचार जरूर किया जायगा।

श्री दयाचन्द सोन : बारां अस्पताल के बारे में आपने कुछ नहीं कहा

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने किसी कट मोशन को इन्डिविज्युअल नहीं लिया है।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगूं) : चित्तौड़गढ़ में जो हॉस्पिटल बिल्डिंग बनायी है उसके लिये राज्यपाल महोदय ने कहा था कि उसका इन्तजाम करेंगे, उसका क्या कर रहे हैं ?

श्री दयाचन्द सोन : बारां में पैसा इकट्ठा करके दिया, लेकिन आपने अपना वायदा पूरा नहीं किया।

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रतापगढ़ वालों से पूछेंगे तो वे दूसरी ही बात कहेंगे। इसके बारे में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय होगा वह स्वीकार करेंगे। मैंने आपका सुझाव सुन लिया इस तरह से बहस में जो खास-खास मुद्दे आये उनका जवाब दे चुका हूं। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस मांग को सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब उप-गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

(विराम)

श्री निरंजननाथ आचार्य।
(६.२० म० प०)

श्री सुरजा जाट के विधान सभा भवन के सामने भूख हड़ताल सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव पर शासकीय वक्तव्य

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप मंत्री, गृह) : श्री सुरजा पुत्र रूपा जाट, निवासी शेखावाटी वालों की ढानी ने १७-४-६४ को थाना शाहपुरा में सूचना दी कि कतिपय व्यक्ति गई रात उनकी ढानी में आये व उनके साथ मारपीट करके उनकी लड़की श्रीमती भागली को उठा कर ले गये। श्री सुरजा के अनुसार यह सब काण्ड भूरा जाट के कारण

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

हुआ जिसके साथ श्रीमती भागली का विवाह ८-१० वर्ष पूर्व हुआ था । श्रीमती भागली तीन-चार वर्ष से श्री सुरजा के साथ रहती है । इसके पूर्व वह ५-६ साल तक अपने पति के साथ विवाहित जीवन बिताती रही ।

थाना शाहपुरा में अभियोग क्रम संख्या ५१ दिनांक १७-४-६४ भा० दं० सं० की धाराएं ३४२।४५२।१४७ व ३६६ के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया । सम्बन्धित व्यक्तियों का डाक्टरी मुआयना कराया गया किन्तु उनके कोई ऐसी चोट आना नहीं पाया गया जिससे हस्तक्षेपीय अपराध बनता हो ।

उपरोक्त अभियोग का विधिवत अनुसंधान किया गया और यह पाया गया कि श्रीमती भागली भूरा की पत्नी होकर बालिग थी । इसलिये भूरा पर भा० दं० सं० की धारा ३६६ के अन्तर्गत कोई अपराध करना सिद्ध नहीं हुआ । निम्नलिखित व्यक्तियों का चालान २२-६-६४ को कर दिया गया था :

(१) भूरा, (२) लक्खा, (३) कालू, (४) लादू, (५) हनुमान पुत्र सेवा जाट, (६) भैरू, (७) मुरली, (८) हनुमान पुत्र देवा जाट ।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, शाहपुरा के न्यायालय में यह अपराध विचाराधीन है । श्रीमती भागली को बरामदगी करने के लिये दं० प्र० सं० की धारा १०० जा० फो० के अनुसार वारन्ट जारी किये जाने हेतु एक प्रार्थनापत्र भी प्रस्तुत हुआ, किन्तु कोर्ट ने यह मानते हुए कि श्रीमती भागली को ले जाने के संबंध में अपहरण का अपराध नहीं हुआ है, उक्त वारन्ट जारी करने से इन्कार कर दिया । श्रीमती भागली को बुलाने के लिये, सुरजा के द्वारा बताये स्थानों पर भी दो दफा सम्मन निकाले गये, किन्तु श्रीमती भागली वहां नहीं मिली । भरसक प्रयत्न करने पर भी श्रीमती भागली का कोई पता नहीं लगा । इस मामले में अदालत में कार्यवाही करीब पूरी हो गई है, केवल भागली का बयान शेष है । मुन्सिफ मजिस्ट्रेट महोदय ने श्रीमती भागली की साक्षी पंजीबद्ध करने के लिये आगामी तिथि ४-४-६६ निश्चित की है ।

उपरोक्त अभियोग के अनुसंधान में या उसके विचाराधीन (ट्रायल) में किसी प्रकार की ढील नहीं हुई है । यह उल्लेखनीय होगा कि इस मुकदमें में अदालत में १३ गवाहान के बयान जिनमेंश्रीमती भागली की ३ बहिनों-बरजो, केसरी, छापली-के, जिनका एफ० आई० आर० में भी घटना के समय उपस्थित होना बताया गया है, भी बयान हो गये हैं । इन तीन गवाहान ने पैरवी के केस को कोई मदद नहीं दी ।

श्री सुरजा ने कुछ प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में पहले भी दिये किन्तु उन्होंने कभी यह आरोप नहीं लगाया कि श्रीमती भागली को भगाने में किसी व्यक्ति विशेष का हाथ है । यह स्पष्ट है कि राजनैतिक दलबन्दी के कारण ही यह आरोप अब दो वर्ष पश्चात लगाया जा रहा है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वह जो भागली है वह जिन्दा है या मर गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मरने की सूचना नहीं मिली है ।

श्री भैरोंसिंह : जिन्दा रहने की सूचना है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसका पता नहीं लग रहा है।

श्री भैरोंसिंह : उसके जिन्दा रहने की सूचना है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मरने की सूचना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उसके जिन्दा रहने की सूचना है क्या आपके पास ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसका पता–रसीद नहीं है और मरने की सूचना गवर्नमेंट को बहुत जल्दी मिलती है, वह नहीं है, इसलिये वह जीवित है; ऐसा मानना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न दूसरा है। राजस्थान की पुलिस जिसके ऊपर एक वर्ष में हम ७ करोड़ रुपया खर्च करते हैं, एक आदमी शिकायत करता है कि मेरी लड़की को कोई उठा कर ले गया; लड़की को उठाकर ले जाने वाले के खिलाफ कोर्ट में केस जाता है। इसका मतलब यह है कि जो भी आरोप लगाया है वह किसी हद तक सही है, इसीलिए चालान हुआ है। मामला कोर्ट में चल रहा है और उप-गृह मंत्रीजी कहते हैं कि वह उस लडकी को बरामद नहीं कर सके, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी कि एक लड़की को बरामद नहीं कर सकते कि कैसे गई, कहां गई, पता लग गया या नहीं, अपनी मर्जी से गई, लेकिन आज तक लडकी उनसे बरामद नहीं हुई। और जब तक लड़की नहीं मिलती तब तक पुलिस के लिये और राज्य के लिए दोनों के लिए कलंक है कि वह लड़की को बरामद नहीं कर सके। मुझे उस व्यक्ति ने बताया कि ३ बार दफा १०० के वारन्ट जारी किये, तीन बार थाने में लाया गया, लेकिन उस को शक है कि थाने पर लाने के बाद में भी उसकी बरामदगी नहीं की गई और उसके पास किसी न किसी प्रकार की सूचना जाती रही है। आप यह भी नहीं कह सकते कि जिन्दा है या मर गई और यह भी नहीं कह सकते कि हम बरामद कर लेंगे। जब लड़कियों के उडाने के बाद में आप राजस्थान के अन्दर ही बरामद नहीं कर सकते तो कहां करेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस भागली का संबंध है..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) वह तो भाग ली।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह भागी, आप भी मानते हैं और वह अपने पति के साथ गई। केस अदालत में है और वह कहीं प्रेजुडिस न हो इसलिये मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ३ लड़कियां भूरा जाट की खासा घर में रहने वाली, एफ. आई. आर. में जिनका नाम है, जिनके लिए कहा गया कि इन्होंने भी छुड़ाने में और भगाने में पकडने की कोशिश की। इन तीन लड़कियों के बयानात पुलिस में है और पति के फेवर में है।

श्री भैरोंसिंह : इस पोइन्ट पर आपसे एक मिनट पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइये ....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप पहले मुझे सुन लें।

श्री भैरोंसिंह : आप तो पहले यह बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री भैरोंसिंह) पहले इन को सुन लें।

श्री भैरोंसिंह : यह बात पूछ रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप पहले सुन लें। अभी तो विराम लगाना बाकी है, सेमीकॉलन ही लगाया है।

तो इन लड़कियों के बयानात, उपाध्यक्ष महोदय, पति के फेवर में हैं। केस तो अदालत में चल रहा है और यह एब्डक्शन में नहीं है। सेक्शन १०० सी आर. पी. सी. में जो वारन्ट इश्यू किये गये तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि केस एब्डक्शन का नहीं है, इसलिए वारन्ट नहीं दिया जा सकता। मैं इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि जुडीशियल वर्डिक्ट है और उसके आधार पर जुर्म ३६६ नहीं है। उसके बाद में आप यह सवाल उठा नहीं सकते; न्यायिक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी दिक्कत भी देखी जाये। यह सेक्शन १०० 'रिकवरी ऑफ दी गर्ल्स' का जो प्रश्न है वह एब्डक्टेड करने वाले के लिये है। अब तो वह शहादत होगी और समन जारी किये जा रहे हैं। हम कोशिश करें तो पता लगे। जहां जहां भूरा जाट ने उसका पता दिया शंका, आशंका और भ्रांतियों के आधार पर हमने कोशिश की, और उस गवाह को तलब करने के लिये हमने प्रयत्न किया। हमारा तो मुकदमा ठहरा हुआ है। मुसम्मात आ जायें तो केस खत्म हो जाय। इसलिए जहां तक मैरिट्स आफ दी केस का ताल्लुक है वह सबजुडिस है। और मैं उसमें जाना नहीं चाहता किन्तु माननीय सदस्य को मैं वह बयान दिखा सकता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि बयान देखने के बाद आप ऐसी बात नहीं कहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यह मुकदमा जो थाने में रजिस्टर हुआ था उसी का चालान हुआ है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: थाने में रजिस्टर हुआ है उसी का चालान हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : अब एक बात और पूछना चाहता हूं, बडी इम्पोर्टेन्ट बात है जिन तीन महिलाओं के कोर्ट में बयान हुए हैं वह प्रोसीक्यूशन की तरफ से हुए हैं और प्रोसीक्यूशन विटनेस के बयान आप डायरी में, इनवेस्टीगेशन ऑफिसर की डायरी में होते हैं। तो आप यह मान कर चलते हैं कि पुलिस को कहा था कि एब्डक्शन हुआ है लेकिन कोर्ट में चालान नहीं हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जैसा अर्ज किया कि आप मैरिट्स ऑफ दी केस में नहीं जा सकते। आप शहादत का विश्लेषण कराना चाहते हैं; आप चाहते हैं कि शहादत के मूल्यांकन पर मैं कहूं; मैं मौन रहूंगा और कुछ कहने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने पुलिस डायरी में क्या बयान दिया; प्रोसीक्यूशन को मदद दी या डिफेन्स को मदद दी या होस्टाइल हुई, इस विवेचन में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं मौन रहना मुनासिब समझता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मैं मौन रहने की बात नहीं करता। जब प्रोसीक्यूशन के विटनेस, पुलिस के इनवेस्टीगेटिंग ऑफिसर को एक बात कहते हैं और कोर्ट में दूसरी बात कहते हैं तो प्रोसीक्यूटिंग इन्सपेक्टर ने उनको होस्टाइल डिक्लेयर क्यों नहीं किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके संबंध में प्रोसीक्यूटर की क्या स्थिति है; गवाह की

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
क्या स्थिति है, ये सारे प्रश्न उपाध्यक्ष महोदय, अदालत के निर्णय के हैं।

श्री भैरोंसिंह : अदालत के निर्णय के नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोई गडबडी की है और न्यायालय की धारणा उसके विरुद्ध आ गई है तो मुनासिब कार्यवाही की जायेगी इसलिये मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कोई बात कह सकूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा है कि सेक्शन १०० का वारन्ट इश्यू करने को मनाकर दिया, इसलिये कोर्ट का जुडीशियल वर्डिक्ट हो गया कि किडनैपिंग का केस भी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप भी अच्छे वकील रहे हैं क्रिमिनल के।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्रिमिनल साइड का।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, I know that you are a criminal but does the refusal by a Court to issue a warrant under Sec. 108 Cr. P. C. make it a judicial verdict ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : बस पूछ लिया ?

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, सेक्शन १०० का वारंट था उसमें उन्होंने रिकवरी के पोइन्ट पर यह वर्डिक्ट दिया है कि यह अपहरण का अपराध नहीं है। एक तो यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि यह एव्डेक्शन ३६६ आई० पी० सी० के तहत नहीं आता क्योंकि औरत को उसका खाविन्द लाया है। मैं इन्वेस्टीगेशन की बात कह रहा हूं, साक्षी की बात नहीं कह रहा। जो मुस्तगीस है उसने कहा है कि औरत २०-२१ साल की है, वह औरत बालिग है और उस औरत के सम्बन्ध में लडकियों ने जो बयान दिए हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं वह बात नहीं कह रहा। आप केस के मैरिट पर भी मत कहिए, क्योंकि मामला सब-जुडिस है। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि ३६६ का मामला माना है या नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोर्ट ने तो क्या, पुलिस ने भी नहीं माना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो यह बताइए Does the refusal by a court to issue a warrant under Sec. 108 of Cr. P. C. amounts a judicial verdict of that verdict. इसका जवाब आप 'यस' और 'नो' में दीजिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is a question of Law. No 'Yes' and No 'Not'.

मांग संख्या १६ व ३ चिकित्सा एवं गाड़ियों पर कर

(पूर्वक्रम में–मांग स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक २६-चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,६५,३६,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ११-गाडियों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६७ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७,५४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

सदन की बैठक सोमवार को प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म० प० ६ बज कर ३३ मिनिट पर सोमवार, दिनांक २१ मार्च १९६६ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट १

(क्रमया तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ का उत्तर देखिये)

सूची

उद्योग विभाग द्वारा चूरू जिले में चलाये जा रहे प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा :—

क्रम सं०	नाम प्रशिक्षण केन्द्र मय स्थान के		व्यवसाय का नाम प्रशिक्षण दिया जाता है	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	मासिक वजीफा	अनुदान
१.	कलस्टर टाईप प्रशिक्षण केन्द्र, चूरू	१	लुहारगीरी	१४	३० रु० व	खास चूरू वालों को
		२	खातीगीरी	१४	४० रु०	बाहर से आने वालों को
		३	चर्म उद्योग	१५	मासिक	
		४	टैक्सटाइल व वीविंग	१३		
			योग ..	५६		
२.	समाज कल्याण विभाग की योजना का प्रशिक्षण केन्द्र, सुजानगढ़	१	काष्ठ कला	१५	१५ रु०	प्रशिक्षण समाप्त करने पर प्रत्येक सफल परीक्षार्थी को २००) रु० की सहायता औजार आदि के रूप में दी जाती है।
३.	प्रशिक्षण केन्द्र, सरदार शहर (समाज कल्याण विभाग योजना)	१	काष्ठ कला	८	१५ रु०	,, ,, ,,
४.	प्रशिक्षण केन्द्र, चूरू (समाज कल्याण विभाग योजना)	१	चर्म उद्योग	११	१५ रु०	,, ,, ,,
५.	प्रशिक्षण केन्द्र, राजल शहर (समाज कल्याण विभाग योजना)	१	सिलाई उद्योग	१२	१५ रु०	,, ,, ,,
६.	प्रशिक्षण केन्द्र, रतनगढ़ (पार्ट टाइम) (समाज कल्याण विभाग योजना)	१	सिलाई उद्योग	११	..	.. .. ..

परिशिष्ट १

(कृपया स्तम्भ १८५२ देखिये)

LIST OF FIAT CARS ALLOTTED FROM STATE GOVERNMENT QUOTA

NOVEMBER 64 - JANUARY, 1965

1. Shri N.N. Acharya, Dy. Minister for Homo & Education, Jaipur.
2. Shri Barkatullah Khan, Minister for Health, Jaipur.
3. Shri S.C. Agarwal, M.L.A., Jaipur.
4. Shri P.C. Mishra, S.P., Udaipur.
5. Shri J.S. Mehta, Special Secretary Agriculture, Jaipur.

FEBRUARY—APRIL, 1965

1. Shri Ram Niwas Mirdha, Speaker, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Shri Jaswant Singh, Dy. I.G. Police, Jaipur.
3. Shri Kumbha Ram Arya, Revenue Minister, Jaipur.
4. Shri Bal Krishan Kaul, Finance Minister, Jaipur.
5. Shri Chandan Mal Baid, Dy. Minister, Industries, Jaipur.
6. Shri G. C. Singhvi, Supdt. of Police, A.C.D. Jaipur.
7. Shri R.K. Saxena, Director, Elections Jaipur.
8. Dr. Shurvir Singh, Sr. Specialist, General Hospital, Udaipur.
9. Shri Mathura Dass Mathur Planning Minister, Jaipur.
10. Dr. Sital Raj Mehta, Jr. Specialist, S. M. S. Hospital, Jaipur.

MAY—JULY, 1965

1. Shri B. Mehta, Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
2. Shri R.N. Hawa, Addl. Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
3. Shri Murli Manohar Vyas, Govt. Advocate.
4. Shri L. R. Sarin, Supdt., S.M.S. Hospital, Jaipur.
5. Shri Narain Sinha, Director of Tourism, Rajasthan, Jaipur.
6. Shri C. B. L. Mathur, Executive Engineer.
7. Shri Sant Ram Sharma, Dy. I.G.P., Rajasthan.
8. Shri V. D. Sharma, Education Secretary, Rajasthan, Jaipur.
9. Shri Anil Bordia, Director Education.
10. Shri S.D. Ujwal, Chairman, Revenue Board, Ajmer.

AUGUST—OCTOBER 1965

1. Shri Man Phool Singh, M.L.A.
2. Shri Brijraj, Regional Director, Transport, Survey.

3. Shrimati Kamla Beniwal, Dy. Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. Shri T.N. Chaturvedi, Industries Secretary, Jaipur,
5. Shri S.L. Kakkar, Chairman, R.S.E.B), Rajasthan, Jaipur.
6. Shri Roop Chand Mathur, Addl. Distt. Magistrate, Ajmer.
7. Shri Shish Ram, M.L.A.
8. Shri Digvijai Singh, M.L.A.
9. Shri Narendra Nath Rana, Statesman's Spl. Representative in Rajasthan.
10. Shri Hardeo Joshi, M.L.A.

NOVEMBER, 65—JANUARY, 1966

1. Dr. D.G. Ojha, Principal, Medical College, Bikaner.
2. Shri B.D. Mathur, Chief Engineer, P.W.D. (B&R), Jaipur.
3. Shri Brij Sunder Sharma, Education Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. Shri K.S. Ujwal, Collector, Jhunjhunu.
5. Shrimati Gouri Punia, M.L.A
6. Shri Khem Chand, Secretary, P.W.D. and Power.
7. Shri Dinesh Khare, Chief Editor, Rashtradoot, Jaipur.
8. Shri M.K. Saxena, Supdt. of Police.
9. Shri Roshan Mal Mathur, Revenue Appellate Authority.
10. Dr. Hari Prasad, M.L.A.

FEBRUARY—APRIL, 1966.

1. Shri R.N. Chodary, Chief Engineer, Rajasthan Canal Board, Jaipur.
2. Shri R.S. Agarwal, Budget Officer, Jaipur.
3. Shri G.B.K. Hooja, Member, Board of Revenue.
4. Shri Ram Deo Singh, M.L.A.
5. Shri Raj Kumar Sobhag Singh, M.L.A.
6. Dr. B.L. Rawat, Member, Rajasthan Public Service Commission.
7. Dr. S.C. Mehta, Director of Mobile Surgical Unit.
8. Dr. B.N. Sharma, Principal, Medical College.
9. Dr. J. S. Mathur, P.M. & H.O.
10. Justice Shri I.N. Modi, Rajasthan High Court.
11. Shri R.K. Chaturvedi, Chairman, Revenue Board, Ajmer.
12. Shri C.L. Kochar, Collector, Ganganagar.
13. Shri H.M. Mathur, Collector, Nagour.
14. Dr. (Mrs) E. Peter. Supdt., Zenana Hospital, Jaipur.
15. Shri A.V. Ganeshan, Dy. Secretary Finance.
16. Shri V.N. Kak, Gen. Manager, Hotel Corp.
17. Shri Krishna Gopal Garg, Chairman, Improvement Trust, Ajmer.
18. Shri Manohar Lal Mathur, S.E., Irrigation, Udaipur.

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक १६ मार्च, १९६६)

स्कम्भ संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
३५८७	अंतिम से ३	अ य	अन्य
३५९०	१५	रह	रख
३५९२	१	बह	वह
३५९३	अंतिम से ८	दिम	दिये
३५९७	१३	है	नहीं है
३५९९	१३	छटी	छठी
३६०२	४	चरू	चूरू
,,	अंतिम से ८	बहर	बाहर
३६१०	७-१०	अधुरे	अधूरे
३६१२	२१	मिनिट	मिनिट पहले
३६१८	३	श्रीं पंचायत	पंचायत
३६३०	५	अोटोमेक	एटोमिक
,,	अंतिम से ४	अोटेमिक	एटोमिक
,,	,, २	अटोमिक	एटोमिक
३६३६	१	को	कोई
,,	,, १७	(३)	(२)
३६४७	३	माथुरादास	मथुरादास
,,	१२	एव	एवं
,,	१	अधिसूचन	अधिसूचना
३६५५	शीर्षक	तथा	एवं
३६५६	शीर्षक ६	सख्या	संख्या
३६५७	अंतिम से ३	दिवा	दिया
३६६३	११	arao	area
,,	अंतिम से ४	सख्या	संख्या
३६६६	६	क	के
३६७३	८	अपन	अपने
३६७९	अंतिम से २	अहां	जहां
३७०१	१७	आयर्वेद	आयुर्वेद
३७०५	२०	अवटूबर	अक्टूबर
,,	अंतिम से ७	आम	ग्राम

१	२	३	४
३७०७	७	को कटा	कोकटा
३७०९	१८	पहुचते	पहुँचते
,,	१८	जब	जेब
३७१२	१७	प्राज	—
३७१३	१९	ह	है
,,	अंतिम् से ८	भ र्ी	भर्ती
,,	अंतिम से ४	ख	देख
,,	अंतिम से २	ग	गये
,,	अंतिम	म	मैं
३७१४	११	है	हैं
,,	१७	मे	में
,,	२०	जिए	जिले
३७१६	अंतिम से	उप मंत्रीयो	उप मंत्रियों
३७१७	२	वयवस्था	व्यवस्था
,,	अंतिम से	धनवन्तरी	धन्वन्तरी
३७२०	२	ो	को
३७२२	७	क	दो
३७२३	अंतिम से ३	स्वग	स्वर्ग
३७२५	१०	बातइये	बताइये
,,	अंतिम् से	ारी	सारी
३७२६	अंतिम से १३	सकत	सकते
३७३०	३	प्राप्रशन	आपरेशन
,,	२१	यों	ज्यों
,,	अंतिम	ट्रड	ट्रेंड
३७३३	४	चके	चूके
,,	१०	चहूंगा	चाहूंगा
,,	१५	श्रृद्धा	श्रद्धा
,,	१६	बैधों	वैद्यों
३७३४	३	ग्रोर	ग्रोर
,,	११	मने	मैंने
३७३५	१८	इ ो	इससे
३७४१	२	इसम	इसमें
,,	अंतिम ३	अस्प ाल	अस्पताल

१	२	३	४
३७५६	अंतिम से ११	एक दिन	एक माह
,,	अंतिम से १०	ह	है
३७५५-५६ से ३७७० व आगे के जिन स्कंमों पर यह मुद्रित है ।	शीर्षक	चिकित्सा तथा	चिकित्सा एवं
३७६०	४	हैं	हूं
३७६१	१६	वद्य	वैद्य
३७६२	५	` ते	देते
३७६५	१८	लेकन	लेकिन
,,	अंतिम से ५	कहते	करते
३७६६	अंतिम से १५	जाता है	जाती हैं
३७६७	४	दलाई	दिलाई
३७७०	८	staf	staff
३७७१	२०	इ स्टेटमेन्ट	इस्टेटमेन्ट
३७७२	३	ह	हैं
,,	६	भोटी	भोंटी
३७७३	२	सबंध	संबंध
,,	अंतिम से ६	ट्रासफर	ट्रांसफर
३७७४	अंतिम से ११	नापासर में	नापासर मे
,,	अंतिम से २	परिमिट	परमिट
३७७५	शीर्षक	माच	मार्च
३७७७	८	बतलायंगे	बतलायेंगे
,,	१४	न	ने
,,	१४	सन्टर्स	सेन्टर्स
,,	१५	स्यानो	स्थानीय
,,	१६	आ	आ रहे
,,	२४	हां पर	यहां पर
,,	अंतिम से ६ व ७	ह	है
३७७८	अंतिम से ४	किये सेन्टरर्स	कि ये सेन्टर्स
३७७९	अंतिम से १३	व्यास : (	व्यासं (

१	२	३	४
३७८०	अंतिम से ८	जांय	जायं
,,	अंतिम से ७	ह	है
३७८४	६, १०, ११	दोनें	दोने
,,	११	को	कोई
,,	अंतिम से ८	और	और तमाम
,,	अंतिम से २	चाहिय	चाहिये
३७८५	१८	वक्त हैं	वक्त जो
,,	अंतिम से ४	पूर्तिं	पूर्ति
३७८६	६	एसी	ऐसी
३७८८	अंतिम से ९	क्य	क्या
३७९०	५	गवनेमेन्ट, गवर्नमट	गवर्नमेन्ट, गवर्नमेंट
,,	११	भरोंसिह	भैरोंसिह
३७९१	९	सम्मानीय	सम्माननीय
,,	अंतिम से १०	सविसज	सर्विसेज
,,	अंतिम से ४	जात हैं।	जाते हैं।
३७९२	१६	मर्जी	मर्जी
३७९३	५	विभाग ग	विभाग
,,	अंतिम से ४	करत हैं ?	करते हैं ?
३७९४	५	मुकद्में	मुकद्मे
३७९५-९६	शीर्षक	१३.३६	१९६६
३७९५	शीर्ष	श्री ज्वालाप्रशाद शर्मा	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा
,,	९	श्री दयाचन्द सोनी (बारांब-सु)	श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०)
,,	अंतिम से १२	आर	और
,,	अंतिम से ५	पॅदा	पैदा
३७९७	४	अपन	अपने
३७९७	अंतिम से ७	फॅसिलिटीज में	फेसिलिटीज
३७९८	अंतिम से १२	करन	करने
,,	अंतिम से ३	उपाध्यक्ष,	उपाध्यक्ष:
३७९९	१५	बतात	बताता
,,	अंतिम से ८	भरोंसिह	भैरोंसिह
,,	अंतिम से ५	मुक्ति	मुक्ति
३८००	१	दिखान	दिखाने

१	२	३	४
३८०१	अंतिम से ८	मुक्तिलाल	मुक्तिलाल
,,	अंतिम से ८	ट्रान्सपोर्ट	ट्रान्सपोर्ट
३८०३	११	एक्सपर्ट्स	एक्सपर्ट्स
३८०४	१	श्री मोहनराज	श्री मोहनराज
३८०६	अंतिम	: " पहला	है " पहला
३८११	अंतिम से ५	सारे	साथ
३८१२	अंतिम से १४	हमन	हमने
,,	अंतिम	ोता	होता
३८१६	अंतिम से ६	चोसरसिंह	चौसरसिंह
३८१७	अंतिम से ६	मोतालाल	मोतीलाल
३८१८	अंतिम से १३	हमार	हमारा
,,	अंतिम	जल्दी जल्दी	जल्दी जल्दी कर
३८१९	६	लाजिम	लाजिमी
,,	अंतिम से १२	जैसलमर	जैसलमेर
३८२१	अंतिम से १३	उनकों	उनको
३८२३	अंतिम से १५	क्सपेन्डीचर	एक्सपेन्डीचर
३८२७	शीर्ष	(श्री मथुरादास माथुर)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
३८३०	१	किया गया	किया
३८३५	अंतिम से ७	कन्सिल	कौंसिल
३८३६	७	फसला	फैसला
३८३७	१३	तेजराम	तेजाराम
३८४१	६	सिपार्टमेंट	डिपार्टमेंट
३८४७	अंतिम	fromulgation	promulgation
३८४८	अंतिम से ४	अग्रबाल	अग्रवाल
३८४९	अंतिम	में	मैं
३८५१	अंतिम से ४	हमारे	हमारी
३८५३	अंतिम से ११	को	की
३८५९	११	फीगर्स	फिगर्स
३८६५	२	इसम	इसमें
३८६६	१	के	कि
३८६८	शीर्षक	एवं	तथा
३८६९	१३	प्राफिशियल	आफिशियल
३८७०	शीर्षक	एवं	तथा

१	२	३	४
३८७१	१६	दूसरे मिल कर	दूसरे से मिलकर
३८७२	शीर्षक	एेवं	तथा
३८७४	शीर्षक	एेवं	तथा
३८७६	शीर्षक	एेवं	तथा
३८७८	शीर्षक	एेवं	तथा
,,	१०	ऐक्सपीरियन्स	एक्सपीरिएन्स
३८८०	शीर्षक	एेवं	तथा
३८८२	अंतिम से १२	किंतु	किंतु
३८८४	स्कंभ संख्या	३८८	३८८४
,,	अंतिम मे १०	भगाते	भागने
३८८७	अंतिम से ३	ऐबडेक्शन	एब्डक्शन